अभिव्यक्ति

प्रेरणा

चीजें खुद नहीं होतीं, उन्हें करना पड़ता है।
-जॉन एफ केनेडी

संपादकीय

मानसिक रोगों को लेकर अभी जागरूकता कम है

डब्ल्यूएचओ की ताजा दो रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुनिया के हर परिवार या पड़ोस के परिवार में कम से कम एक सदस्य मानसिक बीमारी का शिकार है। दुनिया की 800 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। भारत के संदर्भ में देखें तो एक परिवार में औसतन 4.4 सदस्य हैं, लेकिन गांवों में, या उत्तर भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में परिवार का आकार काफी बढ़ जाता है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की आबादी-वृद्धि से अधिक तेजी से मानसिक बीमारियों के शिकार लोगों का प्रतिशत बढ़ रहा है। चूंकि यह बीमारी लोगों में फैसले लेने, समसामयिक सामजिक मानदंडों के अनुरूप आचरण करने की क्षमता को बाधित करती है, इसलिए इस कारण वैश्विक जीडीपी में 1 ट्रिलियन डॉलर की कमी आंकी गई है। डब्ल्यूएचओ की चिंता यह है कि विकासशील देश अभी इस खतरे के प्रति सजग नहीं हैं। जहां सम्पन्न देश इसकी रोकथाम-उपचार के लिए प्रति व्यक्ति 65 डॉलर खर्च कर रहे हैं, वहीं गरीब देश मात्र 0.04 डॉलर। मानसिक बीमारियों में डिप्रेशन और एंग्जायटी प्रमुख हैं। डब्ल्यूएचओ आगामी 25 सितम्बर की बैठक में दुनिया के देशों को इसके प्रति सजग करने जा रहा है। इससे पहले वह अपनी अगली रिपोर्ट में देशवार ब्योरा भी देगा, ताकि दुनिया के 144 देश इस संकट को लेकर अपनी स्थिति को समझ सकें।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

धर्मग्रंथों में दी गई सीख और संकेतों को जीवन से जोड़ें

हमारे जीवन में कुछ पुस्तकें जरूर होनी चाहिए। और जब भी कोई उलझन या भटकाव आए, उन पुस्तकों को पढ़ें। फिर वो चाहे गीता हो, महाभारत, रामचरितमानस, भागवत, बाइबिल, कुरान या और कोई पुस्तक। उनमें जो संकेत दिए हैं, पंक्तियों के बीच उनको ढूंढते रहें। ऐसे ग्रंथ पढ़ने का अर्थ ही यह है कि उसका भावार्थ उठाया जाए और उसको जीवन से जोड़ा जाए। आज की पीढ़ी को कुछ बातें आज के उदाहरण से ही समझ में आती हैं। हमारे देश का जो सबसे बड़ा सत्ताधारी दल है, वो जब चौंकाने वाला निर्णय लेता है तो लोगों को लगता है यह बड़ा आश्चर्यजनक है। लेकिन उनके अतीत के राजनेताओं ने कुछ गहरी पुस्तकें लिखी हैं। और जो निर्णय आज लिए जा रहे हैं, उनका वर्णन उन पुस्तकों में हो चुका है। तो ये सबक लेने वाली बात है कि यदि ऊंचाई पर जाना है तो ग्रंथों को पढ़ो। ऊंचाई पर टिकना है तो लगातार उन ग्रंथों में जो सीख दी गई है, जो संकेत हैं- उनको जीवन से जोड़ो। भले ही एक पृष्ठ रोज पढ़ें, पर पढ़िए जरूर। •Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विमर्श• शिष्टाचार को ताक पर रख दिया गया है

हम कैसी राजनीतिक संस्कृति आगामी पीढ़ी को सौंप रहे हैं?

राजनीति

पवन के. वर्मा
पूर्व राज्यसभा सांसद व राजनयिक
pavankvarma1953@gmail.com

बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीतिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल हमारी राष्ट्रीय राजनीति में आ रही गिरावट को ही दर्शाता है। और दुःखद यह है कि यह गिरावट अब आकस्मिक नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप धारण कर चुकी है।

एक समय वैचारिक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र रही राजनीति आज एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने का अखाड़ा बनकर रह गई है। गरिमा और शिष्टाचार को ताक पर रख दिया गया है। ऐसे में हमें ईमानदारी के साथ खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि एक समाज के तौर पर हम इतना नीचे कैसे गिर गए?

इस भाषाई पतन के केंद्र में एक और बड़ी व्याधि है- भारत में नित्य खोखली होती जा रही राजनीतिक संस्कृति। एक वक्त था जब देश के नेताओं की राजनीति में सौम्यता की छाप होती थी। महात्मा गांधी अपने विरोधियों को भी शालीन भाषा में पत्र लिखते थे, नेहरू और वाजपेयी गरिमा और वाकपटुता के साथ विपक्ष से संवाद करते थे। लेकिन अफसोस कि आज हम खुद को अपशब्दों से घिरा पाते हैं।

बिहार में 1990-2005 तक राजद के 'जंगल राज' की यादें आज भी ताजा हैं। उस दौर में कानून, व्यवस्था और नैतिक निष्ठा को सत्ता और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया था। आलम ये था कि शोरूम से नई-नवेली कारें जबरन झपट ली जाती थीं और लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने में डरते थे।

सच्चाई यह है कि अनुकूल अवसर निर्मित होने पर तमाम राजनीतिक दलों ने इस तरह की राजनीति को न केवल अनदेखा किया है, बल्कि यदा-कदा चतुराई भरे तरीके से उसे बढ़ावा भी दिया है।

2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के ठीक बाद उनकी ही एक राज्यमंत्री ने एक सार्वजनिक भाषण में 'रामजादे' शब्द की तुक एक अपशब्द से मिलाते हुए एक आपत्तिजनक और अक्षम्य नारा दिया था। इससे व्यापक घृणा पैदा हुई और माना जा रहा था कि भाजपा उस मंत्री के खिलाफ मंत्रिमंडल से निकालने जैसी कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने अपने शब्दों के लिए खेद जताया था। लेकिन हाल ही में एक भाजपा सांसद ने एक बार फिर लोकसभा में अल्पसंख्यक समुदाय के एक सांसद के खिलाफ अश्लील और नस्लवादी टिप्पणी कर दी। इसके बावजूद न तो स्पीकर ने उन्हें निलंबित किया, ना पार्टी ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की।

दूसरे दल भी बराबर के दोषी हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी अपने भाषणों में प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी भाषा तक का इस्तेमाल किया है, जो कानून के तहत दंडनीय है। जवाब में भाजपा नेताओं ने भी उसी लहजे में जवाब देने में कोताही नहीं बरती और हमें 'जर्सी गाय', 'कांग्रेस की विधवा' और '50 करोड़ की गर्लफ्रेंड' जैसी अशोभनीय बातें सार्वजनिक भाषणों में सुनने को मिलीं।

क्षणिक-उत्साह से पोषित होने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी इसी तरह के अपशब्दों से ग्रस्त होते चले जा रहे हैं। वहीं असंसदीय भाषा से भरी सार्वजनिक बयानबाजी अंततः मुद्दा-आधारित राजनीति से बचने का एक हथकंडा बन जाती है। राजद-कांग्रेस के पास बिहार के लिए अपने एजेंडे में कहने के लिए कोई ठोस बात नहीं है, और ना ही भाजपा के पास है। जब प्रधानमंत्री ने माताओं के अपमान पर पीड़ा जताई तो उन्हें अपनी 'डबल इंजन' सरकार से भी पूछना चाहिए कि बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया है?

क्या यह ऐसी राजनीतिक संस्कृति होगी, जिसमें ताकत ही सबसे प्रबल तर्क होगा? जिसमें भाषा को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा? और जहां सम्मानजनक असहमति की कला अपशब्दों के कोलाहल में कहीं खो जाएगी?

आज 14 करोड़ बिहारियों में से हर तीसरा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताता है। कुछ दिनों पहले तक ही 60 वर्ष से अधिक उम्र की माताएं महज 400 रुपए मासिक पेंशन पाती थीं। बच्चों को पढ़ाने की चाहत रखने वाली माताओं को आज भी ऐसे हालात झेलने पड़ते हैं, जहां स्कूल खंडहर हैं और शिक्षक गैरहाजिर। जिन बेटों को उन्होंने भूखे रह कर पाला, वे नौकरियों के अभाव में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। अपनी मां से वो शायद साल में एक बार ही मिल पाते हैं। कुपोषण के चलते गांवों में 50 वर्ष से अधिक उम्र की अधिकांश माताओं की कमर समय से पहले ही झुक रही है। वे एनीमिया की शिकार हैं और कैल्शियम और पोषक-तत्वों की कमी से परेशान हैं।

हम अपनी आने वाली पीढ़ी को ये किस तरह की राजनीतिक संस्कृति विरासत में सौंप रहे हैं? क्या यह ऐसी संस्कृति होगी, जिसमें ताकत ही सबसे प्रबल तर्क होगा? जिसमें भाषा को हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा? और जहां सम्मानजनक असहमति की कला अपशब्दों के कोलाहल में कहीं खो जाएगी?

(ये लेखक के अपने विचार हैं।)

मुद्दा• कानूनी नकेल से कब तक बचेंगी टेक कम्पनियां

नेपाल में सोशल मीडिया बैन पर भारत के लिए सबक

डिजिटल

विराग गुप्ता
सुप्रीम कोर्ट के वकील
viraggupta@hotmail.com

सोशल मीडिया की वजह से भ्रष्टाचार, वंशवाद, कुशासन के खिलाफ जागरूकता बढ़ती है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में सरकारों के तख्तापलट में तमाम कारणों के अलावा इसने भी भूमिका निभाई है। लेकिन हिंसा, आगजनी और संस्थाओं को ध्वस्त करने के बाद जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जेन-जी के पास गवर्नेंस और नव-निर्माण का रोडमैप नहीं दिखता। महाभारत काल में मूर्च्छित पांडवों को होश में लाने के लिए यक्ष-युधिष्ठिर संवाद हुआ था। उसी तर्ज पर गरीबी, बेरोजगारी, असमानता से निपटने और राष्ट्र-निर्माण में जेन-जी को जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के सबसे बड़े बाजार भारत में इन 4 पहलुओं पर संवाद के साथ ही मुकम्मल कार्रवाई की भी जरूरत है :

टेक कम्पनियां : संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यक्ष के इस प्रश्न का आधुनिक जवाब कुछ ऐसा होता कि फेसबुक, वॉट्सएप, यूट्यूब जैसी मुफ्त में सेवाएं देने वाली कम्पनियों का मुनाफा कहां से आता है? अमेरिका में फेडरल ट्रेड कमीशन की नई रिपोर्ट के अनुसार ये कम्पनियां विज्ञापन, ट्रैकिंग और एआई प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों लोगों के डेटा का गैर-कानूनी इस्तेमाल कर रही हैं। सोशल मीडिया को नियंत्रित करने वाले धन्नासेठों के साथ ट्रम्प ने बैठक की थी। कयास हैं कि चीन के सामने नतमस्तक नेपाली पीएम ओली के तख्तापलट के पीछे टेक कम्पनियों की बड़ी भूमिका है।

डेटा प्रोटेक्शन नियमन : शिकायत अधिकारी की नियुक्ति समेत कई नियमों के पालन के लिए नेपाली सरकार ने दो साल पहले आदेश जारी किया था। पिछले साल टेक कम्पनियों के संगठन ने नियमों के पालन में असमर्थता जताई। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया कम्पनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आदेश दिया। उसके अनुसार सरकार ने इन कम्पनियों को एक सप्ताह में रजिस्ट्रेशन करवाने की चेतावनी जारी की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना और नियमों का पालन नहीं करने वाली फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, वॉट्सएप, लिंक्डइन समेत 26 कम्पनियों को बैन कर दिया था। विद्रोह भड़कने के बाद बैन हटाया गया। सवाल है कि यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन (जीडीपीआर) का पालन करने वाली टेक कम्पनियां नेपाल में नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहीं?

भारत सरकार : ट्रम्प के टैरिफ युद्ध के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी से आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है। लेकिन सरकारी काम में विदेशी ऐप्स के गैरकानूनी इस्तेमाल और समाज को सोशल मीडिया के नशे से मुक्त करने के प्रयास नहीं हो रहे हैं। संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट में फेक न्यूज के खतरे के मद्देनजर सेफ हार्बर कानून पर पुनर्विचार की बात कही गई है। यह दिलचस्प है कि भारत में फेक न्यूज की स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं है। विदेशी कम्पनियों के दबाव की वजह से दो साल पहले पारित डेटा सुरक्षा कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है। सोशल मीडिया के सिक्के का पहला पहलू अभिव्यक्ति की आजादी है। संविधान और लोकतंत्र की इस आत्मा को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि टेक कम्पनियों को बेलगाम छूट के कारण रोजगार खत्म हो रहे हैं और इससे गरीब-अमीर की खाई बढ़ रही है। विदेशी कम्पनियों के लिए कानून में शिथिलता और टैक्स चोरी की छूट, संविधान के समानता के सिद्धांत का बड़ा उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट : सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर

भारत में टेक कम्पनियां कानूनी प्रक्रिया और टैक्स जवाबदेही से बचने के लिए गैर-कानूनी लॉबीइंग कर रही हैं और दूसरे हथकंडे अपना रही हैं। यक्षप्रश्न यह है कि टेक कम्पनियों की बिल्ली के गले में नियमन की घंटी कौन बांधेगा?

अश्लील, हिंसक और आपत्तिजनक सामग्री होती है। कुछेक मामलों में विरोधियों को निशाना बनाने के लिए सिलेक्टिव तरीके से एफआईआर दर्ज करने के बाद गिरफ्तारी भी हो जाती है। कानून का यह दुरुपयोग भाजपा और विपक्ष शासित सभी राज्यों में हो रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए आदेश के अनुसार सोशल मीडिया पोस्ट्स के मामलों में बेवजह की एफआईआर दर्ज करने और मुकदमेबाजी पर पुलिस और अदालतों को रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामलों पर बड़े वकीलों की लम्बी बहस के बाद जमानत मिल जाती है, लेकिन मुकदमेबाजी चलती रहती है। सोशल मीडिया कम्पनियों के नियमन से जुड़े अनेक लम्बित मामलों पर कई सालों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने एक नए मामले में सोशल मीडिया गाइडलाइंस बनाने के लिए सरकार को आदेश दिया है। जज के अनुसार व्यावसायिक मुनाफा कमाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अभिव्यक्ति की आजादी के मौलिक अधिकार की कानूनी ढाल नहीं मिलनी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

13 सितंबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में
इकोनॉमिस्ट ने अपनी कवर स्टोरी में एआई में भारी निवेश के नाकाम होने की स्थितियों पर नजर डाली है। मैग्जीन ने चीनी मुद्रा युआन के डॉलर के मुकाबले बढ़ने पर खबर की है।

The Economist

दैनिक भास्कर — अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

यूरोप की अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे

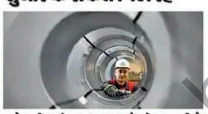

यूरोप की अर्थव्यवस्था खराब दौर से गुजर रही है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस साल तीन सबसे बड़े देशों जर्मनी, फ्रांस और इटली की विकास दर एक प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है। लेकिन अगस्त में अच्छी खबर आई। यूरोपीय मैन्युफैक्चरिंग का इंडेक्स कई वर्षों में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। जर्मनी में कारोबार यूक्रेन युद्ध के बाद सबसे अच्छे दौर में है। स्पेन की इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। वहां मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेस में इजाफा हुआ है। जर्मनी, इटली, स्पेन सहित यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने सैनिक खर्च बढ़ाया है।

ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लिए जन समर्थन में गिरावट

ब्रिटेन में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी को कामगार वर्ग का ज्यादा समर्थन मिलता रहा है। लेकिन स्थिति बदल गई है। एक सर्वे के अनुसार कम आय वाले लोगों के बीच पार्टी के समर्थन में गिरावट आई है। चुनाव होने की स्थिति में 36 लाख रुपए सालाना कमाने वाले सिर्फ 18% परिवार पार्टी का समर्थन करेंगे। 2024 के चुनाव में ऐसे 33% परिवारों ने पार्टी के वोट दिए थे। दक्षिणपंथी, नील फराग की रिफॉर्म यूके पार्टी, ग्रीन पार्टी और लिबरल डेमोक्रेट्स के पक्ष में जा रहे हैं। लेबर को अमीर वोटरों का ज्यादा समर्थन है।

यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका में नए किस्म की ड्रग का कहर

मॉर्फीन, हेरोइन सहित ओपिओइड परिवार की नशीली ड्रग निटाजींस के सेवन से कई देशों में मौतें होने की खबर है। यह फेंटानिल ड्रग से अधिक खतरनाक है। फेंटानिल से अमेरिका में हर साल हजारों मौतें होती हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि निटाजींस हेरोइन से सैकड़ों गुना अधिक ताकतवर हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, यूरोप और पश्चिम अफ्रीका में निटाजींस से प्रभावित लोगों के मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन में 2024 में 333 मौतें इसके ओवरडोज से हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार नशीली दवाएं लगातार बढ़ रही हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर निवेश रिकॉर्ड तोड़ हो रहा, दुनियाभर में कंपनियां डेटा सेंटर्स पर अरबों रुपए खर्च कर रहीं

अच्छे नतीजे नहीं, फिर भी 2028 तक एआई पर 264 लाख करोड़ का दांव

इस साल अमेरिका की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां एआई मॉडल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगभग 35 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगी। विशेषज्ञ मानते हैं, 2028 तक दुनियाभर में डेटा सेंटरों पर खर्च 264 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। इसकी गिनती आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े निवेश में होने लगी है। इतने ऊंचे दांव को देखते हुए सवाल है, इस भारी निवेश का नतीजा क्या होगा? यदि टेक्नोलॉजी कामयाब होती है तब भी कुछ लोग दिवालिया हो जाएंगे। अगर नहीं तो आर्थिक नतीजे गंभीर होंगे। कुछ अध्ययन बताते हैं, एआई से उम्मीद के मुताबिक आय नहीं हो रही है। स्थिति बिगड़ने पर अमेरिका की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी।

एआई में रिकॉर्ड निवेश हो रहा है। कई मामलों में मनुष्य से बेहतर काम करने वाले आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस मॉडल कुछ साल में बन जाएंगे। बड़ी टेक कंपनियां इनके लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हैं। इकोनॉमिस्ट ने जुलाई में लिखा था, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के कारण आर्थिक विकास दर 20% सालाना तक हो सकती है। जाहिर है, कुछ शेयरधारकों को अपार पैसा मिलेगा, लेकिन कई अन्य को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

एआई के संबंध में कुछ संभावित स्थितियों पर गौर करना चाहिए। आज निवेशक सोचते हैं कि बड़े मॉडल चलाने वाली कंपनियां होड़ में जीतेंगी। लेकिन कई कंपनियां छोटे लैंग्वेज मॉडल अपना रही हैं। टेक्नोलॉजी में अड़चनें, बिजली सप्लाई में मुश्किल या मैनेजमेंट की ढील से भी फर्क पड़ सकता है। इन कारणों से कई निवेशक और कर्जदाता भारी निवेश से हाथ खींच सकते हैं। पूंजी की कमी और घाटे की वजह से कुछ कंपनियां बंद हो सकती हैं।

एआई में मंदी आने पर क्या होगा? हालांकि कुछ डेटा सेंटर और नई बिजली क्षमता का दूसरा इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आधे से ज्यादा निवेश सर्वरों और खास चिप्स पर किया गया है। यह कुछ साल में पुराना पड़ जाएगा। अच्छी बात है कि मौजूदा फाइनेंशियल सिस्टम आघात को सहन कर सकता है। पहले भी कई टेक्नोलॉजी में निवेश से भारी नुकसान हो चुका है। 1860 में रेलवे पर निवेश बेकार होने से बैंकों को बहुत घाटा हुआ था। वहीं अब तक डेटा सेंटरों पर ज्यादातर निवेश बड़ी टेक कंपनियों के मुनाफे से हुआ है। एआई स्टार्टअप में बड़ी पूंजी वाले वेंचर और सॉवरेन वेल्थ फंड पैसा लगा रहे हैं। लिहाजा, वे घाटा उठाने में सक्षम हैं।

इसके बावजूद कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। निवेश बढ़ने से जोखिम ज्यादा होगा। कर्ज से लदी कंपनियों की संख्या बढ़ेगी। बिजली कंपनियां एआई को बिजली सप्लाई के लिए अपना निवेश बढ़ाएंगी। इससे कर्ज और बढ़ेगा। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। एक अनुमान के मुताबिक पिछले साल अमेरिकी जीडीपी में एआई का हिस्सा 40 प्रतिशत रहा है। अब तक यह हिस्सेदारी चंद प्रतिशत थी। निवेश कम हुआ या बंद हो गया तो आर्थिक समस्याएं बढ़ेंगी।

शेयर बाजार में गिरावट से निवेशक अपने खर्च में कटौती करेंगे। अभी एआई कंपनियों के बाजार मूल्य आसमान छू रहे हैं। 2000 के दशक की तुलना में शेयर बाजार में सामान्य लोगों की मौजूदगी ज्यादा है। यदि मूल्य नीचे आए तो उनका भरोसा भी टूटेगा। निवेश पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इसके अलावा टैरिफ और ऊंची ब्याज दर से अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ेगी। भारी उछाल की वजह से एआई में मंदी के परिणाम भी उतने ही बड़े होंगे।

95 प्रतिशत कंपनियों को शून्य आय

2022 में चैटजीपीटी की रिलीज के बाद अमेरिका का शेयर बाजार 1854 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। अमेजन, ब्रॉडकॉम, एनवीडिया सहित सिर्फ दस कंपनियों का मूल्य 55 प्रतिशत बढ़ा है। दूसरी तरफ यूबीएस बैंक का कहना है कि एआई से आय निराशाजनक रही है। पश्चिमी देशों की बड़ी एआई कंपनियों की टेक्नोलॉजी से आय 4.40 लाख करोड़ रुपए सालाना है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्टडी में पाया गया कि 95 प्रतिशत कंपनियों को जनरेटिव एआई में निवेश से जीरो रिटर्न मिल रहा है।

बड़े लैंग्वेज मॉडल पर भरोसा कम हो रहा है

बड़े लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं। इस कारण छोटे मॉडल को बढ़ावा मिल रहा है। कई कंपनियां अपनी जरूरत के अनुरुप मॉडल बना सकती हैं। छोटे मॉडल सस्ते हैं। छोटा होने से उन्हें स्मार्टफोन, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट और अन्य डिवाइस में इस्तेमाल कर सकते हैं। एपल और कुछ अन्य कंपनियां क्लाउड आधारित एलएलएम में पैसा नहीं लगा रही हैं। टेक मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पाइंट के मोहित अग्रवाल कहते हैं, आज के छोटे मॉडल पिछले साल के बड़े मॉडल से अधिक सक्षम हैं।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन मुफ्त इलाज की समर्थक है पार्टी

अमेरिका में समाजवाद को समर्पित नई राजनीतिक पार्टी का उदय हो रहा

न्यूयॉर्क के मेयर पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रत्याशी जोहरान ममदानी को विरोधी अलग तरीके से निशाना बना रहे हैं। वे उन्हें डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका (डीएसए) का उम्मीदवार बताते हैं। ममदानी डीएसए की आलोचना नहीं करते पर कहते हैं कि वे डीएसए में नहीं हैं। डीएसए मुफ्त मेडिकल सुविधा, फिलिस्तीन की आजादी, पुलिस बजट में कटौती की मांग करती है।

अमेरिका में दो प्रमुख राजनीतिक दल रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी है। डीएसए तीसरा विकल्प हो सकती है। डीएसए की चेयरमैन मेगन रोमर कहती हैं, हमारे पास जरूरी साधन नहीं हैं। स्टाफ कम होने से हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। डीएसए के लगभग 78 हजार सदस्य हैं। लेकिन उसकी नीतियों का समर्थन करने वाले लोगों की संख्या काफी है। ममदानी 2023 में डीएसए के सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं।

सर्वे एजेंसी गैलप के अनुसार डेमोक्रेटिक पार्टी के दो तिहाई समर्थक समाजवाद के प्रति सकारात्मक धारणा रखते हैं। सिर्फ आधे से कम डेमोक्रेट्स पूंजीवाद को पॉजिटिव मानते हैं। एसोसिएटिड प्रेस के सर्वे में पाया गया है कि पांच में से एक डेमोक्रेट अपनी पार्टी को अच्छा मानता है। तीन में से एक डेमोक्रेट ने पार्टी को कमजोर और बेअसर बताया है।

ट्रम्प समर्थक मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की तरह सोशलिज्म शब्द लोगों को अपील करता है। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के माइकेल कजिन कहते हैं, सवाल उठता है, जब अमेरिकी लोग सोशलिज्म के बारे में बात करते हैं तो उनका क्या अर्थ होता है। इसके अर्थ अलग-अलग हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर बर्नी सेंडर्स और एलेक्जेंड्रिया ओकेसियो कॉर्टेज कहते हैं, यह यूरोपियन सोशल डेमोक्रेसी की तरह है। इसका लक्ष्य सरकार के कल्याण कार्यों का विस्तार है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

फाइनेंस

डॉलर के मुकाबले युआन तेजी से बढ़ रहा

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प की मनमानी व्यापारिक नीतियों, बढ़ते वित्तीय घाटे और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आजादी को खतरों से डॉलर को बहुत नुकसान हो रहा है। जनवरी के बाद उसमें 7 प्रतिशत गिरावट आई है। वहीं चीनी मुद्रा युआन ट्रम्प के नवंबर में राष्ट्रपति बनने के बाद अपने उच्चतम स्तर पर है। चीन में विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं। कई सरकारों ने डॉलर के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है। चीन ने पूंजी के बाहर जाने पर लागू नियंत्रण ढीले कर दिए हैं। व्यापार में साझेदार देशों से युआन में पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है। वैसे, अंतरराष्ट्रीय पेमेंट में डॉलर के 50 प्रतिशत की तुलना में युआन का केवल 4 प्रतिशत उपयोग हो रहा है। लेकिन चीन ने 2022 के बाद पेमेंट दोगुना कर दिया है। चीन का 30 प्रतिशत कारोबार युआन में होने लगा है। 2019 में यह 14 प्रतिशत था। वह 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी युआन में हासिल करता है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

कूटनीति कतर पर इजराइली हमले से संकेत

बावजूद ट्रम्प खाड़ी में अपने मित्र देशों की रक्षा नहीं कर पा रहे

इस वर्ष मई में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने कतर की राजधानी दोहा में एक वादा किया था। उनके पीछे अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी थी। बायीं ओर एमक्यू-9 रीपर ड्रोन और दायीं ओर एफ-15 लड़ाकू जेट विमान था। यह सैनिक ताकत अपने सहयोगियों को राष्ट्रपति के शब्दों पर भरोसा दिलाने के लिए दिखाई गई थी। उन्होंने कहा था, अमेरिका या उसके पार्टनरों की रक्षा के लिए मैं अमेरिकी ताकत का इस्तेमाल करने से कभी नहीं हिचकूंगा। ट्रम्प ने कहा था कतर हमारा निकट सहयोगी है। लेकिन 9 सितंबर को इजराइल ने अमेरिका निर्मित जेट विमानों से दोहा में एक इमारत पर बम बरसाए।

इजराइल का कहना है, हमास के नेता यहां बैठक कर रहे थे। लगता है, इजराइली हमला विफल रहा। हमास के पांच सदस्य मारे गए। बड़े नेता बच गए। हमले से गाजा में युद्धविराम की बातचीत अधर में लटक गई। इससे दो आशंकाएं उभरती हैं- पहली- इजराइल क्षेत्रीय विस्तारवादी है व अमेरिका सहयोगियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है।

7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा 1400 इजराइलियों की हत्या और अपहरण के बाद इजराइल ने हमास के नेताओं को मारने की कसम खाई है। लेकिन अब तक कतर में उन पर हमला नहीं कर रहा था। कतर में हमास का राजनीतिक ब्यूरो है। वहां अमेरिका की सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है।

कतर पर हमले का इजराइली खुफिया एजेंसी मोसाद ने विरोध किया था। कतर छठवां देश है जिस पर इजराइल ने मौजूदा युद्ध के दौरान हमला किया है। 10 सितंबर को यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद दोहा पहुंचे। उन्होंने कतर के अमीर से मुलाकात की। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान के भी पहुंचने की संभावना है। यह पड़ोसी देशों के समर्थन का सार्वजनिक प्रदर्शन है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

स्वच्छ हवाका अधिकार

स्वच्छ हवाके सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयने शुक्रवारको एक विशेष टिप्पणी की है, जो मानव जीवनके लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। साथ ही शीर्ष न्यायालयने प्रदूषण नियंत्रण अभिकरणोंकी कार्यशैलीपर भी सवाल खड़ा कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवईने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरोंके लिए स्वच्छ हवाके अधिकारके सन्दर्भमें दाखिल याचिकापर सुनवाईके दौरान यह भी कहा कि प्रदूषण नियंत्रण नीति केवल राजधानी दिल्लीके लिए नहीं हो सकती, सिर्फ इसलिए कि वे देशके कुलीन नागरिक हैं। अन्य शहरोंके लोगोंको यह अधिकार क्यों नहीं? प्रधान न्यायाधीशका भी कहना विशेष रूपसे महत्वपूर्ण है कि साफ हवाका हक सिर्फ दिल्ली-एनसीआरतक सीमित नहीं रह सकता है, बल्कि यह देशभरके नागरिकोंको मिलना चाहिए। प्रदूषण नियंत्रणकी नीति पूरे भारतके लिए होनी चाहिए। न्यायमूर्ति गवईने कहा कि पिछले वर्ष सर्दियोंमें मैं अमृतसर गया था। वहां प्रदूषण दिल्लीसे भी बदतर था। यदि पटाखोंपर प्रतिबन्ध लगाना है तो पूरे देशमें पाबन्दी होनी चाहिए। पूरे देशमें प्रदूषण रोकनेकी नीतियां लागू करनेकी जरूरत है। शीर्ष न्यायालय उस याचिकापर सुनवाई कर रहा था, जिसमें तीन अप्रैल, २०२५ के आदेशको चुनौती दी गयी है। याचिकामें दिल्ली-एनसीआरमें पटाखोंकी बिक्री, भण्डारण, परिवहन और निर्माणपर पूर्ण प्रतिबन्धके आदेशको बदलनेकी मांग की गयी है। पटाखोंपर पूर्ण प्रतिबन्धके खिलाफ याचिकापर न्यायालयका यह भी कहना है कि प्रतिबन्ध कुछ महीनोंतक सीमित करनेसे कोई मकसद पूरा नहीं होगा। लोग पटाखोंको इकट्ठा करेंगे और उस समय बेचने लगेंगे, जब प्रतिबन्ध लागू होगा। वस्तुत: वायु प्रदूषणको बढ़ानेमें पटाखोंका भी योगदान है। इसके अतिरिक्त पराली जलानेसे भी वायु प्रदूषण बढ़ता है। इससे आम नागरिकोंको काफी परेशानी उठानी पड़ती है। श्वांस और हृदय रोगियोंके लिए यह बहुत ही खतरनाक है। ऐसी स्थितिमें वायु प्रदूषणको बढ़ानेवाले सभी कारणोंपर विचार करते हुए आवश्यक कदम उठानेकी आवश्यकता है। स्वच्छ वायुका अधिकार देशके सभी नागरिकोंका है। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकारके साथ ही आम नागरिकोंकी भी है। दीपावलीका पर्व निकट है और ऐसे अवसरोंपर पटाखे जलानेसे हवा काफी प्रदूषित हो जाती है जिससे श्वांस लेनेमें दुष्कर हो जाता है। इसलिए ऐसे सभी कामोंका बहिष्कार होना चाहिए जिनसे वायु प्रदूषणको बढ़ावा मिलता है। इस सन्दर्भमें सर्वोच्च न्यायालयकी टिप्पणी उचित है और उस दिशामें जन-सहयोगके साथ कार्य करनेकी जरूरत है।

वीआईपी दर्शनपर रोक

उत्तर प्रदेशमें मथुराके बांकेबिहारी मन्दिरमें वीआईपी दर्शनपर रोक उचित और स्वागतयोग्य निर्णय है। शीर्ष न्यायालयसे गठित बांकेबिहारी मन्दिरकी हाई पावर मैनेजमेण्ट कमेटीका वीआईपी दर्शन व्यवस्थापर रोकका आदेश आम दर्शनार्थियोंके हितमें है। स्थानीय कलेक्ट्रेट सभागारमें गुरुवारको कमेटी अध्यक्ष एवं उच्च न्यायालयके सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमारकी अध्यक्षतामें हुई बैठकमें मन्दिर व्यवस्थाको लेकर कई बिन्दुओंपर गहन मंथन किया गया। इसमें वीआईपी दर्शनके लिए लगा कटघरा हटाने, बाहर लाइव स्ट्रीमिंगके जरिये दर्शन कराने और गलियारा निर्माणके लिए ४.७४ एकड़ भूमि अधिग्रहणके लिए समिति गठित करनेके प्रस्तावोंको मंजूरी दी गयी। इन सभी प्रस्तावोंको तत्काल प्रभावसे लागू कर दिया गया। हालांकि वीआईपी दर्शन व्यवस्था खत्म करनेको लेकर कमेटीके सदस्योंने आपत्ति जतायी जिसे सिरेसे खारिज कर दिया गया, क्योंकि दर्शनमें सबसे बड़ी बाधा वीआईपी दर्शन व्यवस्था माना गया। इसका कारण है कि वीआईपी दर्शनके लिए सौ रुपयेमें पर्ची मिलती है, इससे परेशानी बढ़ती है। वैसे भी मन्दिरोंमें आनेवाला कोई श्रद्धालु छोटा-बड़ा अथवा विशिष्ट या साधारण नहीं होता। सभी दर्शनार्थी एक समान होते हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य अपने आराध्यका दर्शन करना होता है। इसमें किसी प्रकारका भेदभाव आस्थापर चोट है। इसे किसी भी रूपमें सही नहीं ठहराया जा सकता है। किसी भी मन्दिरमें वीआईपी दर्शन व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इससे भक्तोंको भारी परेशानी होती है। पैसे लेकर दर्शनकी सुविधा प्रदान करना तो व्यापार हो गया और मन्दिरोंको व्यापारका केन्द्र नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि यह आस्था, श्रद्धा और विश्वाससे सम्बद्ध है। दर्शनका अधिकार सभीको समान रूपसे है। वीआईपी दर्शनपर रोक अन्य मन्दिरोंके लिए भी अनुकरणीय है।

लोक संवाद

कृषिको मिलेगी मजबूती

महोदय,-कृषि क्षेत्र सिंचाई कार्योंके लिए देशकी कुल बिजलीके करीब पांचवें हिस्सेकी खपत करता है। डीजलका बहुत बड़ा हिस्सा भी इसी काममें लगता है। डीजल पम्पकी जगह सौर ऊर्जासे संचालित पम्प लगाकर और ग्रिडसे जुड़े पम्पोंको सौर ऊर्जासे जोड़कर पीएम-कुसुम (प्रधान)मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान) योजना कार्बन उत्सर्जन कम करने, सब्सिडी कम करने और किसानोंको इनपुटकी लागतके उतार-चढ़ावसे बचानेमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजनाका पहला चरण २०२५-२६ में चल रहा है और इसका लक्ष्य है सोलर पम्पों, ग्रिडसे जुड़े पम्पोंको सौर ऊर्जासे जोड़कर तथा बंजर भूमिपर छोटी सौर ऊर्जा परियोजनाओंकी मददसे सिंचाईके लिए ३४.८ गीगावॉट अतिरिक्त सौर ऊर्जा तैयार करना। करीब ३४००० करोड़ रुपयेके आवंटनके साथ योजनाका लक्ष्य १४ लाख सोलर पम्प स्थापित करना और ३५ लाख ग्रिडसे जुड़े कृषि पम्पोंको सौर ऊर्जा संचालित पम्पमें बदलना है। इसमें फीडर स्तरतकको भी सोलरमें बदलना शामिल है। वास्तवमें मांगमें इजाफा हुआ है और यह इस बातको रेखांकित करता है कि सौर ऊर्जाको स्वीकार करने और इसका विस्तार करनेकी अत्यधिक आवश्यकता है। २०२४-२५ में ही भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसीने योजनाके तहत ऋणकी मंजूरीमें २७ फीसदी इजाफा दर्ज किया और ऋण राशि ४७,४५३ करोड़ रुपये पहुंच गयी। ऋण वितरणमें २० फीसदीकी वृद्धि हुई। इस संबंधमें अगस्त २०२४ में कृषि अधोसंरचना निधिमें इसके एकीकरणके बाद नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इस योजनाके दूसरे चरणको शुरू करनेकी काफी संभावनाएं नजर आती हैं। पहले चरणके सबकसे सीख लेते हुए अब केन्द्रीय वित्तीय सहायताकी सीमा हटायी जा सकती है और एग्रोवॉल्टेइक स्थापनाओंको समायोजित किया जा सकता है जहां फसल और सोलर पैनल एक साथ होते हैं। डीजल पम्पको बदलनेसे कार्बन उत्सर्जनमें कमी आयगी और ईंधन कीमतोंके उतार-चढ़ावसे बचनेमें मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा दिनके समय उच्चतम उत्पादन करती है जो सिंचाईकी जरूरतोंके अनुरूप है और इसे अधिक किफायती बनाता है। **-दिव्या शुक्ला, वाया ईमेल।**

पड़ोसी देशोंमें तख्तापलटका खेल

एक वर्ष पूर्व बंगलादेशमें जो हिंसक आन्दोलन हुआ था, उसकी आड़में कठमुल्लोंने हिन्दुओंपर अत्याचार किया था तब वहांके बारेमें भारतमें चिन्ताएं उभरी थीं। किन्तु नेपाल तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमें हिन्दू राष्ट्र ही है, इसलिए वहांके शासन विस्थापनाकी हिंसक अराजकतापर भारतका अत्यन्त चिंतित होना विशेष है।

❑ **विकेश कुमार बड़ोला**

नेपाल सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपमें हिन्दू राष्ट्र ही है, तब वहां शासन विस्थापनाकी हिंसक अराजकता क्यों उत्पन्न हुई और चार-पांच दिन क्यों फैली रही। वहां वामपंथी विचारधाराके नेताओंने नेपालके सार्वजनिक जीवन एवं लोगोंके लिए कुछ नहीं किया। परिणाममें बहुत दिनोंसे सत्तारूढ़ नेताओंके प्रति जन-विद्रोह पनपा और चार-पांच दिन पहले वह चरमपर पहुंच गया। भारतके पड़ोसी देशोंमें स्थापित शासन जनान्दोलन द्वारा उखाड़े जाते रहे हैं। नेपालसे पहले बंगलादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका जैसे देश ऐसी अराजकताएं झेल चुके हैं। दक्षिण एशियाके ये छोटे देश अबतक तो अमेरिका, चीन और रूसके राजनीतिक, आर्थिक एवं रणनीतिक प्रयोजनके लिए शासन विस्थापनकी अराजकताएं झेल रहे थे, किन्तु अब भारतके वर्चस्वको कम या समाप्त करनेके लिए भारतके चहुंओर स्थित छोटे-छोटे देशोंको अस्थिर करनेका कुचक्र किया जा रहा है। इस चक्रव्यूहमें प्रथम भूमिका अमेरिकाकी है। अमेरिकासे आशय वहांके उन डीप स्टेट्स यानी छिपे हुए गुप्त शासकोंसे है जो भारतमें अपनी पसन्दके शासनकी स्थापना करनेमें बार-बार विफल हो रहे हैं। ये डीप स्टेट्स वही हैं जो ट्रम्प शासनके माध्यमसे भारतको अपने डेयरी उत्पाद खरीदनेके समझौते करनेको बाध्य कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या धारी भारत उनके उन सभी उत्पादोंको उनकी शर्तोंपर खरीदनेके अनुबंध कर ले, जो भारतमें धार्मिक-सांस्कृतिक-आध्यात्मिक जीवन पद्धतियोंके अनुरूप पूर्णरूपेण बड़ी मात्रामें अनुचित एवं वर्जित ही होंगे। भारतका नास्तिक जनसमूह तथा इनके राजनीतिक प्रतिनिधि अपने जन-संचारिक ईकोसिस्टमके माध्यमसे अमेरिका स्थित डेयरी तथा अन्य कम्पनियोंके डीप स्टेट्सतक अवश्य ही ये सूचनाएं भेजते रहते हैं कि भारतमें हमारे सत्तारूढ़ होनेपर अमेरिकी उत्पादोंके लिए भारतीय बाजार खोल दिये जायेंगे। इसीलिए अमेरिकी तथा इनके अनुसरणकर्ता यूरोपीय देशोंके डीप स्टेट्स द्वारा भारतीय शासनको अस्थिर करने एवं अपनी पसन्दके शासकको सत्तारूढ़ करनेकी परिस्थितियां निर्मित करनेके लिए नेपाल, बंगलादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तानके माध्यमसे आन्दोलनका वातावरण बनाया जाता रहा है। विगत दस-बारह वर्षोंसे भारतके विभिन्न प्रदेशोंके विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनावोंसे पहले अलग-अलग तरहके विद्रोही गुटोंको यहां-वहां सड़कोंपर बैठाकर धरना-प्रदर्शन किये जाते रहे हैं। जब इस स्वदेशी विधिसे भारतसे लेकर अमेरिकातक फैले डीप स्टेट्सकी मंशा पूरी नहीं हुई तो उन्होंने कभी श्रीलंका, कभी बंगलादेश, कभी अफगानिस्तान तथा कभी पाकिस्तानमें कराये गये अराजक आन्दोलनोंका सहारा लिया और अब वे नेपालमें आन्दोलन कराकर भारतके लिए भूराजनीतिक संकट खड़ा करनेका प्रयास कर रहे हैं। किन्तु भारत अडिग है। भारतीयताकी शक्ति अजेय है। भारतमें या विदेशमें कहीं कोई भी डीप स्टेट या अनेक डीप स्टेट्स हों, वे अंतत: पराजित ही होंगे। शुक्र है कि अबतक उनकी पराजय भारतके संयम एवं धैर्यबंधसे ही हो रही है। जिस दिन भारत, विरोधियोंकी भांति अराजकतापूर्ण ढंगसे आक्रमण करेगा, उस दिन दुनियाकी छिपी हुई मक्कार शक्तियोंको खुलेमें सबके सामने उनके कियेका मृत्युदंड मिल रहा होगा।

जब उग्र आन्दोलनकारियोंको विदेशी शक्तियां अपने स्वार्थके लिए उपयोग कर रही हैं तो फिर ऐसे लोगोंके प्रतिनिधि तख्तापलटके बाद सत्तारूढ़ होनेपर नेपालका प्रतिनिधित्व नहीं कर पायेंगे। वे विदेशी शक्तियोंके हाथोंकी कठपुतली होंगे। अराजक वातावरण निर्मित करके नेपालके जिस कम्युनिस्ट शासनको विस्थापित किया गया है वह भी वर्षोंसे चीनकी कठपुतली था। नेपालको जब चीन या अब गुप्त शक्तिके अनुरूप चलना है तो गहन प्रश्न है कि ऐसेमें नेपालकी आवश्यकता ही क्या है। जिस छिपी शक्तिने नेपाली युवाओंको भड़काया, वे नेपालका भला कैसे कर पायेंगे।

नेपालकी घटनाके सन्दर्भमें एक स्वाभाविक जिज्ञासा ये भी उभरती है कि जब ऐसे देशोंके शासक अपना शासकीय पदाधिकार सुरक्षित रखनेमें असमर्थ हैं और उग्रवादियोंके सामने घुटने टेक भागने एवं अन्य देशमें शरण लेनेको विवश हो जाते हैं तो फिर इन देशोंके अस्तित्वकी आवश्यकता ही क्यों है। यह बात बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा शक्तिशाली देशोंकी मर्जीपर जैसे-तैसे चल रहे सभी देशोंपर लागू होती है। ये बातें बादकी है कि शासन भ्रष्ट है, जनतासे विमुख है और सार्वजनिक कल्याणकी नीतियोंका क्रियान्वयन नहीं कर रहा। पहली विचारणीय बात तो ये है कि जो शासन और शासनके शासक अपने शासकीय धन, साधन, संसाधन तथा अन्य शक्तियों द्वारा उग्रवादियों, हिंसक आन्दोलनकारियोंको रोकनेमें पूर्णत: असमर्थ है अथवा हैं तो फिर उसकी या उनकी आवश्यकता ही क्या है और जिस देशपर वह या वे शासन कर रहा है या कर रहे हैं, उस देश या उन देशोंकी भी क्या आवश्यकता है।

बंगलादेश और नेपालकी भांति हो जानेपर भारत देशके सन्दर्भमें भी यही जिज्ञासा उठेगी। जब नेपालके शासकने अपने सेनाके माध्यमसे अराजकता नहीं रोक पाये है तो फिर नेपाली शासन और नेपाल देशका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। जब उग्रवादियों एवं आन्दोलनकारियोंको विदेशी शक्तियां अपने स्वार्थके लिए उपयोग कर रही हैं तो फिर ऐसे उग्रवादियों-आन्दोलनकारियोंके प्रतिनिधि तख्तापलटके बाद सत्तारूढ़ होनेपर नेपालका प्रतिनिधित्व थोड़े ही कर पायेंगे। वे तो विदेशी शक्तियोंके हाथोंकी कठपुतली होंगे। उग्र आन्दोलन तथा अराजक वातावरण निर्मित करके नेपालके जिस कम्युनिस्ट शासनको विस्थापित किया गया है वह भी वर्षोंसे चीनकी कठपुतली बना था। नेपालने जब पहले चीनके अनुसार और अब किसी नयी डीप स्टेट शक्तिके अनुरूप चलता है तो इस सन्दर्भमें गहन प्रश्न ये है कि ऐसेमें नेपालकी आवश्यकता ही क्या है। जिस छिपी हुई शक्तिने नेपाली युवाओंको भड़काया और अपने ही देशके साधनों-संसाधनोंको जलाने-नष्ट करनेके लिए दुष्प्रेरित किया है, आये वही शक्ति सामने और बना दे नेपालको अपना उपनिवेश। ऐसी शक्तियां द्विअर्थी तंत्र, सत्ता, शासनका खेल क्यों खेल रही हैं। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओंपर जब इनका विशेषाधिकार एवं नियंत्रण है तो फिर ये किससे डर कर अपने तख्तापलट खेलको गुप्त रूपसे खेलनेको विवश हैं। ऐसी स्थितियों-परिस्थितियोंमें तथाकथित छोटे-मोटे देशोंके निकृष्ट एवं दिखावटी लोकतंत्रात्मक शासनसे श्रेष्ठ तो फिर उत्तर कोरियायी शासन तंत्र है, जो बिना लाग-लपेटके अपनी भूमि अपने हिस्सेके भूभागपर अपना शासन चलाता है, जो दिखावटी लोकतंत्रका ठगगीत गानेवाले लोगोंकी दृष्टिमें तो तानाशाह होता है किन्तु वास्तविकता ये है कि ऐसे तानाशाहके रहते बंगलादेश एवं नेपाल जैसी अराजकताएं नहीं हो सकती हैं। अमेरिका जैसे पेशेवर ठग लोकतंत्र तथा नेपाल जैसे खिलौना लोकतंत्रकी तुलनामें उत्तर कोरियायी जैसा सीधा-सपाट एक अर्थकी बात करनेवाला शासन तंत्र ही अधिक शासनसंगत प्रतीत होता है।

नेपालके अर्थतंत्रपर हमला

नेपालकी अर्थव्यवस्था रेमिटेंसपर निर्भर है। बेरोजगारी दर बढ़नेसे युवाओंका भारतके अलावा मलयेशिया एवं खाड़ी देशोंमें पलायन बढ़ा है। हिंसाने नेपालकी अर्थव्यवस्थाको तबाह कर दिया। व्यापार, पर्यटन बुरी तरहसे प्रभावित हुआ।

❑ **डा.अवधेश कुमार**

पिछले कुछ दिनोंसे चल रहे जेनजी आन्दोलनके चलते नेपालमें राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया है। इन जनआन्दोलनकी शुरुआत भले ही सोशल मीडियासे प्रतिबन्ध हटानेकी मांगको लेकर हुई, लेकिन इसकी चिंगारीने संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, प्रधान मंत्री निवास और कांतिपुर जैसे मीडिया हाउसको जलकर खाक दिया। इसे नेपालकी लोकतांत्रिक व्यवस्थापर सीधा हमला कहा जा सकता है। इस संकटसे निबटनेके लिए सेनाको सड़कपर उतरना पड़ा। सत्ता व्यवस्था संचालित करनेके लिए अन्तरिम सरकारके गठनकी कवायद भी शुरू हो गयी है। संविधान बदलनेकी बात की जा रही है। इसका परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन यह जन-आन्दोलन नयी पीढ़ीको नजर अन्दाज करनेवाले दुनियाके लोकतांत्रिक देशोंके सत्ताधीशोंके लिए सबक है। साथ ह नेपालके राजनीतिक संकटके कारणोंकी पड़ताल कर सीख लेनेका सही समय भी। नेपाल दक्षिण एशियाका सबसे युवा लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि यहां १७ साल पहले अर्थात् २००८ के जन-आन्दोलनके चलते राजशाहीका अन्त और लोकतांत्रिक शासन प्रणालीकी शुरुआत हुई। तबसे अबतक १४ सरकारें बदल चुकी हैं। मार्च, २०२४ तक कम्युनिष्ट पार्टी आफ नेपाल (माओइस्ट सेण्टर) के नेता पुष्पकुमार दहन 'प्रचंड' कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपाल (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के सहयोगसे प्रधान मंत्री बने। बजट और अन्य नीतिगत मुद्दोंपर मतभेद होनेके कारण कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपालने अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे प्रचण्ड सरकार अल्पमतमें आ गयी। इसके बाद नेपाली कांग्रेसके समर्थनसे १५ जुलाई, २०२४ को कम्युनिस्ट पार्टी आफ नेपालके नेता केपी शर्मा ओली प्रधान मंत्री तो बन गये, लेकिन भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानत और युवाओंकी अनदेखीके आरोपसे अपनी सरकारको नहीं बचा सके। विश्व बैंककी मानें तो २०२४ में नेपालकी प्रति व्यक्ति आय १४४७ यूएस डालर थी। इसके बावजूद नेपाली राजनेताओंके बच्चोंका आलीशान जीवनशैली देखनेको मिला, जो सोशल मीडियापर नेपो किड्सके नामसे ट्रेड होता रहा। इससे आक्रोशित बेरोजगार युवाओंने जेन-जेड मूवमेण्ट हैशटैगसे लाखों लोगोंको जोड़नेका काम किया।

यह देख नेपाल सरकारने ४ सितम्बरको फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटाक, एक्स सहित २६ सोशल मीडिया प्लेटफार्मपर प्रतिबन्ध लगा दिया। हालांकि इस सन्दर्भमें ओली सरकारका दावा था कि ये प्लेटफार्म नेपाली कानूनके तहत पंजीकृत नहीं थे। नेपाली जनताने इसे अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रतापर हमला बताया और सरकारके खिलाफ लामबंद होना शुरू कर दिया, क्योंकि नेपालकी आबादी तीन करोड़के करीब है, जिनमेंसे ९० प्रतिशत लोग सोशल मीडियाका उपयोग करते हैं। सोशल मीडियाको युवा रोजगार, जनसम्पर्क और जनजागरणका माध्यम मानते हैं। नेपालमें युवा बेरोजगारी २० प्रतिशतसे अधिक है। यहांके लोग प्रतिदिन हजारोंकी संख्यामें रोजगारके लिए विदेशोंमें पलायन करते हैं। इससे आक्रोशित जेन-जेड (१८-२५ वर्षके युवा) ने बंगलादेश, श्रीलंका और इंडोनेशियाके युवा जन-आन्दोलनोंसे प्रेरणा ली और सड़कपर उतर गये। राजधानी काठमाण्डू ८ सितम्बरको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन शुरू हुआ। भीड़ बढ़नेपर स्थिति बेकाबू होने लगी तो पुलिसको गोली चलानी पड़ी। इस दौरान १९ लोगोंकी मौत हो गयी। ४०० से अधिक घायल हुए। इलाजके दौरान भी दर्जनभर घायलोंने दम तोड़ दिया। प्रदर्शनकारियोंने ९ सितम्बरको संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट और सिंह दरबारको आगके हवाले कर दिया। पूर्व प्रधान मंत्री शेर बहादुर देउबा, पुष्पकमल दहल और झलनाथ खनालके घरोंको आग लगा दी। इस दौरान गम्भीर रूपसे झुलसी पूर्व प्रधान मंत्री खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारकी मौत हो गयी। राजनेताओंको विदेश भागनेसे रोकनेके लिए त्रिभुवन हवाई अड्डेमें भी आग लगा दी। प्रदर्शनकारियोंको नेपालकी मीडियापर भी भरोसा नहीं था, तभी तो सबसे बड़े मीडिया हाउस कांतिपुरके सेण्ट्रल बिजनेस पार्क स्थित मुख्यालयमें जबरन घुस गये और कर्मचारियोंको बाहर निकालनेके बाद आगके हवाले कर दिया। इस दौरान कोई घायल तो नहीं हुआ, लेकिन कांपुरकी वेबसाइट्सपर पल-पलकी अपडेट बंद हो गयी। टेलीविजन चैनलपर ब्रेकिंग न्यूजके आनलाइन प्रसारणपर ब्रेक लग गया। यह जन-आन्दोलन काठमाण्डूसे निकलकर पोखरा, वीराटनगर, नेपालगंज, समेत कई शहरोंमें फैलकर बेकाबू होने लगा तो प्रधान मंत्री ओली और राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलने अपने पदसे इस्तीफा दे दिया। गृहमंत्री रमेश लेखक, कृषिमंत्री रामनाथ अधिकारी समेत चार अन्य मंत्रियोंने भी नैतिकताके नाते अपना पद छोड़ दिया। इससे नेपालमें राजनीतिक शून्यता स्थिति उत्पन्न हो गयी।

इतना बड़ा निर्णय जनताने अचानक नहीं लिया। सच जाननेके लिए जड़ोंको खोदना जरूरी है। ललिता निवास जमीन घोटालासे नेपालकी जनता काफी नाराज थी। ललिता निवास करीब १५ एकड़में फैला है। इसी परिसरमें नेपालके प्रधान मंत्रीका आधिकारिक निवास, नेपाली राष्ट्रबैंक मुख्यालय एवं कई अन्य वीआईपीओंके आवास हैं। इसके बावजूद परिसरकी एक-तिहाईसे अधिक जमीनको अवैध तरीकेसे निजी व्यक्तियों और व्यावसायियोंको हस्तान्तरित कर दिया गया, जिसकी कीमत अरबों रुपये बतायी जा रही है। यह घोटाला १९९१ में शुरू हुआ था। जिसकी जांचके लिए २०१७ में तत्कालीन प्रधान मंत्री केपी शर्माने एक समितिका गठन किया। इस मामलेमें १७५ लोगोंके खिलाफ विशेष अदालतमें मामला दर्ज किया गया, जिनमें १३१ लोगोंको दोषी ठहराये जानेके बाद दो-दो वर्ष कारावासकी सजा हुई। तीन पूर्व मंत्रियोंको विशेष अदालतने बरी कर दिया। मार्च २०२५ से यह मामला सुप्रीम कोर्टने विचाराधीन है। इस घोटालाने सरकार और सुप्रीम कोर्टसे जनताके विश्वासको कमजोर किया। नेपालकी अर्थव्यवस्था रेमिटेंसपर निर्भर है। बेरोजगारी दर बढ़नेसे युवाओंका भारतके अलावा मलयेशिया एवं खाड़ी देशोंमें पलायन बढ़ा है। नेपाली युवाओंको रोजगारके सिलसिलेमें भारत आनेपर न तो पाबन्दी है और न तो वीजाकी जरूरत है, लेकिन मलयेशिया एवं खाड़ी देशोंमें बिना वीजाके नहीं जा सकते हैं। वीजा घोटालाने बेरोजगारोंका सड़कपर उतरनेके लिए विवश किया। इसमें सोशल मीडियाके उपयोगपर पाबन्दीने आगमें घीका काम किया। आन्दोलनकारियोंका उद्देश्य सकारात्मक नहीं था, यही वजह रहा कि हिंसाने नेपालको जला दिया। नेपालकी अर्थव्यवस्थाको तबाह कर दिया। कर्फ्यू और हिंसासे व्यापार बंद हुआ, पर्यटन बुरी तरहसे प्रभावित हुआ है। आगे विदेशी निवेश और भी कम होगा। ऐसी स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक देशोंमें उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। इस बातका ध्यान सत्ताके शीर्षपर बैठे लोगोंको रखना चाहिए। लोकतांत्रिक देशोंमें सत्ताधीश बने राजनीतिज्ञोंको नेपाल संकटसे सबक लेना चाहिए क्योंकि लोकतंत्रमें जनता सबसे बड़ी ताकत है, वह सत्ताके सिंहासनपर बैठा सकती है और कार्यकाल पूरा होनेसे पहले जबरिया उतार भी सकती है।

आत्मबोध

आध्यात्मिक चेतना

❑ **श्रीश्री रविशंकर**

मानवीय जीवन पदार्थ एवं चेतना दोनोंका संयोजन है। यदि मानव केवल पदार्थ होता तो आरामकी आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि पदार्थको आराम, बेचैनी, सुख-दुखका अहसास नहीं होता। ऐसा तो केवल उन्हें ही हो सकता है जिनमें चेतना विद्यमान है। परन्तु जीवन केवल चेतना ही नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो हमें पानी, भोजन एवं आरामकी आवश्यकता ही महसूस न होती। चेतना अनुभव करती है एवं स्वयंको मूल्यों द्वारा अभिव्यक्त भी करती है। मूल्य वे भावनाएं हैं जिन्हें न तो शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है और न ही बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है। आध्यात्मिक पथका उद्देश्य ऐसा मूल्य आधारित जीवन जीना है, जो हमारी चेतनामें विद्यमान हैं। इसलिए जीवनको आध्यात्मिक दृष्टिकोणसे समझना एवं पूर्णतया जीवनको जीना अति आवश्यक है। अब सवाल यह उठता है कि वे मूल्य कौनसे हैं। शांति, प्रेम, आनन्द, सुन्दरता, ज्ञान और पदार्थ एवं चेतनाको समझनेकी क्षमता ऐसे मूल्य हैं, जो जीवनको आनन्दमयी बनाते हैं। इस धरापर इनसानका कोई भी कार्य करनेके पीछे उद्देश्य केवल खुशी एवं आराम ही होते हैं। आम तौरपर लोग सोचते हैं कि सुविधा केवल भौतिक प्रगति अर्थात् पदार्थके द्वारा ही संभव है। परन्तु वास्तवमें सुविधा तो आत्माकी विशेषता है। हां, कुछ हदतक यह पदार्थपर भी निर्भर करता है परन्तु अधिकतर यह मनोभाव एवं समझपर निर्भर करता है। आप सुनते हैं, समझते हैं और अपनाते हैं। परन्तु कौन समझ रहा है और कौन अपना रहा है। यह आपके शरीरमें विद्यमान चेतना अर्थात् आत्मा ही है जो कि ज्ञानका अनुभव कर रही है, वह इसे अपना रही है। यह जानकारी आपको देखने, आवाज, सूंघने, स्वाद एवं स्पर्शसे नहीं मिल रही, बल्कि यह तो आपको अंतर्बोधसे ही प्राप्त होती है। आप यह भी कह सकते हैं कि चेतनाके हर स्तरपर जानकारी विद्यमान है। चेतना है परन्तु उसे सीमितताके दायरेमें नहीं बांधा जा सकता। आप चेतनाको माप नहीं सकते। यह तो असीमित है। चेतना ही शांति है अर्थात् आप स्वयं शांति हैं, आप स्वयं सत्य हैं, आप स्वयं ही ऊर्जा हैं। चेतनाको जानना ही ज्ञानको समझना है। यह चेतना ही प्रेमका असीमित स्रोत है और आप स्वयं प्रेम ही हैं। इस बातको समझना और इसे अपने जीवनमें जीना ही आध्यात्मिक जीवन है। जीवनकी ऊंचाइयोंको आध्यात्मिक ज्ञानके द्वारा ही समझा जा सकता है। इस ज्ञानके अभावमें जीवन उदासी, निर्भरता, अज्ञानता, तनाव एवं दुखसे भरा हसूस होता है। आध्यात्मिक ज्ञानका दृष्टिकोण ही जीवनमें उत्तरदायित्व, अपनापन एवं सम्पूर्ण मानव जातिके लिए दयाकी भावनासे भरता है। सच्चे अर्थोंमें आध्यात्मिक ज्ञानका भाव ही जात-पात, धर्म एवं देशकी छोटी सीमाओंको दूर कर सम्पूर्ण मानव जातिके साथ एक अपनेपनका रिश्ता कायम करता है। विभिन्न देशोंके बीच होनेवाली लड़ाइयोंको आध्यात्मिक ज्ञानका भाव एवं ज्ञान होनेपर रोका एवं दूर किया जा सकता है। आध्यात्मिक जीवन जिन्दगीसे दूर भागना बिलकुल नहीं है। इसका अर्थ उत्तरदायित्व लेना है।

आत्मनिर्भर भारतकी दिशामें बड़ा कदम है स्वदेशी चिप

❑ **रोहित माहेश्वरी**

बीते दिनों पहली 'मेड इन इंडिया' चिप, जी हां भारतने ३२-बिट माइक्रोप्रोसेसर सेमीकॉन इंडिया २०२५में लांच की गयी। भारतमें बनी यह पहली स्वदेशी चिप है। इस चिपका नाम है विक्रम। इस चिपको केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णवने लांच किया। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी भी इस अवसरपर मौजूद रहे। किसी भी देशके लिए ये गर्वका क्षण है। केन्द्रकी इस महत्वाकांक्षी परियोजनाके अंतर्गत १८ अरब डालरसे ज्यादाके कुल निवेशवाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देशमें चल रही हैं। यह भारतकी सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरताकी दिशामें एक बड़ा कदम है। यह बताना अहम है कि दुनियाभरमें बनने वाली चिप डिजाइनिंगका २० प्रतिशत काम भारतमें होता है।कुछ साल पहलेतक भारतमें चिप निर्माणको असंभव मान लिया गया था, लेकिन अब इस सालसे भारतमें चिपका कमर्शियल निर्माण होने लगेगा। मतलब डेटा प्रोसेसिंग, स्टोरेज, कंट्रोल्स और कम्युनिकेशन्स जैसे कामोंको अंजाम देने वाला सेमीकंडक्टर न सिर्फ मोबाइल, कम्प्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्सके लिए अहम साबित होगी, बल्कि खेती-किसानीमें भी किसानोंको बड़ी राहत देगी। स्मार्ट सिंचाई, फसलकी निगरानी और मौसम पूर्वानुमान जैसी आधुनिक तकनीकोंमें इसका उपयोग खेतीकी तस्वीर बदल सकता है। कुछ सालोंमें भारत इस चिपका निर्यातक भी बन जायगा। इसरोकी सेमीकंडक्टर लैबने विक्रम प्रोसेसरको बनाया है। यह भारतका पहला स्वदेशी ३२-बिट माइक्रोप्रोसेसर है। यह लांचिंगके दौरान मुश्किल हालातोंमें भी काम करनेके लिए तैयार है। २०२१ में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू होनेके बादसे सिर्फ चार सालमें भारतने सेमीकंडक्टरके क्षेत्रमें एक बड़ा बदलाव किया है। इस सपनेको पूरा करनेके लिए सरकारने ७६,००० करोड़ रुपयेकी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजनाकी घोषणा की है। इसमेंसे लगभग ६५,००० करोड़ रुपये पहले ही दिये जा चुके हैं।अभी चिपके लिए भारत पूरी तरहसे आयातपर निर्भर करता है। अभी दुनियामें ताइवान, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया जैसे देश चिपका निर्माण करते हैं। आटोमोबाइल और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरमें काफी सम्भावनाएं हैं। लेकिन मोबाइल फोन, आईटी और औद्योगिक उपयोग अब भी सबसे ज्यादा कमाईवाले सेक्टर हैं। इन तीनोंसे लगभग ७० प्रतिशततक होती है।

भारत इस क्षेत्रमें एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बननेके लिए उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-२०२५ के उद्घाटन अवसरपर प्रधान मंत्रीने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारतकी सबसे छोटी चिप दुनियामें बड़े बदलावकी नींव रखेगी। हालांकि इस राहमें अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डालरवाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योगमें भारतकी हिस्सेदारी आनेवाले वर्षोंमें ४५ से ५० अरब डालरकी हो सकती है। वर्तमानमें चिपके उत्पादनमें ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशोंका वर्चस्व है। यहांतक कि छोटा-सा देश ताइवान दुनियाके लगभग साठ फीसदीसे ज्यादा सेमीकंडक्टरका उत्पादन कर रहा है, जिसमें करीब नब्बे फीसदी उन्नत सेमीकंडक्टर शामिल हैं। दरअसल कोविड संकटके बाद आधुनिक तकनीक एवं उन्नत उपकरणोंमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाके चलते इस क्षेत्रमें वैश्विक स्तरपर होड़ पैदा हो गयी है। निस्संदेह भारतको चिप उत्पादन क्षेत्रमें एक दिग्गज देश बननेके लिए निरन्तर निवेश, अनुसंधान विकास और विनिर्माणकी आवश्यकता होगी। हालमें प्रधान मंत्रीकी जापान यात्रासे उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करनेमें भारतके लिए मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारतमें चिप उत्पादन परियोजनाओंमें जापानी निवेश बढ़ रहा है। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान विकास एवं व्यापार सुगमताकी स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयातके लिए दूसरे देशोंपर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबावसे मुक्त होकर अपनी आपूर्ति श्रृंखलाको मजबूत बना सकते हैं। सेमीकंडक्टर क्षेत्रमें सफलता हासिल करनेकी दिशामें भारतका एक सशक्त पक्ष यह भी है कि दुनियाके लगभग बीस फीसदी चिप डिजाइन इंजीनियर भारतमें हैं। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी क्षेत्रमें कामयाबीके लिए भारत सरकारने सेमीकंडक्टर परियोजनाके रूपमें एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। सरकार बड़ी घरेलू कम्पनियोंको संबल देनेके लिए डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी डीएलआईके तहत दिये जा रहे लाभके विस्तारके साथ ही, इसके तहत दिये जानेवाले अनुदानको बढ़ानेपर गम्भीरतासे विचार कर रही है। जिसके तहत महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादन परियोजनाओंके लिए केन्द्र एवं राज्योंसे प्रोत्साहनके रूपमें परियोजनाकी कुल लागतका सत्तर फीसदी मिलना जारी रह सकता है। इस योजनाके तहत केन्द्र सरकार पचास फीसदी पूंजीगत सहायता दे रही है। वहीं राज्य सरकारें कुल परियोजना लागतका बीस फीसदी प्रोत्साहन दे रही हैं।इस महत्वाकांक्षी परियोजनाको भारतमें गेम चेंजर टेक क्रांति माना जा रहा है। सेमीकॉन इंडिया २०२५ के उद्घाटन मौकेपर प्रधान मंत्रीने कहा भी कि सरकार इस मिशन और उसको तैयार करनेसे जुड़ी डीएलआई योजनाके अगले फेजपर काम कर रही है। निश्चित रूपसे केन्द्रके प्रयासोंसे भारत चिप उत्पादनके वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियानकी दौड़में तेजीसे आगे बढ़ सकता है।दरअसलए डिजिटल डिवाइसोंका मस्तिष्क कहा जानेवाला सेमीकंडक्टर कम्प्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटेलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करनेमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणोंकी कार्यकुशलता उन्नत चिपकी ताकतपर निर्भर करती है। साधारण शब्दोंमें कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफरपर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरोंका संजाल है। जो कम्प्यूटर करने, मेमोरी प्रबंधन एवं सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइसको उन्नत बनाती है। हमारे देशमें १९६२ के प्रयास किया गया था सेमीकंडक्टरके मैन्युफैक्चरिंगका एक इकोसिस्टम बने, जो पॉलिसी रही उस समय कि वह आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीके नेतृत्वमें आज देशमें सेमीकंडक्टरका एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। भारतमें इनकी बढ़ती मांगसे नौकरियोंके नये अवसर भी पैदा होंगे। साल २०२४-२५ में भारतमें सेमीकंडक्टरकी खपत ५२ अरब डालर की थी। अब २०३० तक इस मार्केटके १३ प्रतिशतकी सालाना दरसे बढ़नेकी उम्मीद है। मतलब हर साल यह मार्केट पहलेसे १३ प्रतिशत बड़ा होता जायगा। प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदीकी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और निर्णायक काररवाईसे भारतने यह उपलब्धि हासिल की है। उम्मीद है कि भारतका स्वदेशी चिप इस सालके आखिरतक बाजारमें आ सकेगी जिसका असर जियोपोलिटिक्सपर तो होगा ही नये रोजगार सृजनका वातावरण भी बनेगा।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

एंटीबायोटिक का बेतहासा दुरुपयोग

यह सर्वविदित है कि भारत में डॉक्टरी सलाह तथा बिना परामर्श के एंटीबायोटिक दवाएं लेना आम बात है। यह जानते हुए भी कि लगातार इन दवाओं के सेवन से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता गहरे तक प्रभावित होती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि रोगों पर ये एंटीबायोटिक दवाएं काम करना बंद कर देती हैं। इस चिंता को हाल में हुए एक अध्ययन ने बढ़ाया है। नये अध्ययन ने एक परेशान करने वाली सच्चाई को उजागर किया है, जो बताता है कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग के पीछे मरीजों की सोच एक प्रमुख कारक है। अधिकांश लोगों की धारणा है कि इन दवाओं के सेवन से वे स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर निजी क्षेत्र के कुछ डॉक्टर भी अक्सर अपने मरीजों को बनाए रखने के लिये ऐसा करते हैं। वास्तव में इस प्रवृत्ति के परिणाम खासे चौंकाने वाले हैं। अध्ययन के मुताबिक भारत में अकेले निजी क्षेत्र में ही सालाना आधे अरब से ज्यादा एंटीबायोटिक दवाएं लिखी जाती हैं। जिनमें बड़ी संख्या में ऐसी दवाइयां होती हैं, जिनकी वास्तव में जरूरत ही नहीं होती। आमतौर पर बच्चों में होने वाले दस्त के मामले में यह दुरुपयोग सबसे ज्यादा है। हालांकि, ज्यादातर मामले वायरल का प्रभाव होते हैं। ऐसी स्थिति में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट और जिंक सकारात्मक परिणाम देते हैं। अध्ययन से पता चला है कि इसके बावजूद 70 फीसदी मामलों में अभी भी एंटीबायोटिक दवाओं से इलाज किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि अतार्किक मांग, कड़े कानूनों का अभाव और डॉक्टरों द्वारा जरूरत से ज्यादा दवाइयां लिखने के कारण एंटीबायोटिक दवाइयों पर मरीजों की निर्भरता बढ़ती चली गई है। कालांतर एंटीबायोटिक दवाइयों पर लगातार बढ़ती निर्भरता के चलते एक घातक चक्र का निर्माण होता है। जो मरीज के शरीर में तमाम तरह के साइड इफेक्ट भी पैदा करता है। वास्तव में इससे बड़ा संकट यह है कि एक समय के बाद ये दवाइयां रोग के खिलाफ काम करना बंद कर देती हैं। कई तरह के रोग बढ़ाने वाले रोगाणु इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं। बहुत संभव है कि किसी महामारी के वक्त व्यक्ति का शरीर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के बावजूद सुरक्षा कवच न दे। निश्चित रूप से इस संकट से बचने का सरल उपचार यही है कि इसका उपयोग कम से कम किया जाए। सरकारों को भी कानून के जरिये इसका नियमन करना चाहिए। हमें इससे जुड़े आसन्न संकट को महसूस करना चाहिए। यह खतरा मरीज की व्यक्तिगत सुरक्षा से कहीं आगे तक विस्तारित है। गंभीर चिंता का विषय यह है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध यानी एएमआर दुनिया में सबसे घातक संकटों में से एक के रूप में उभर रहा है। डराने वाला आंकड़ा यह है कि वैश्विक स्तर पर, यह पहले से ही हर साल लगभग 50 लाख मौतों का कारण बनता है। अकेले भारत में, वर्ष 2021 में 2.5 लाख से ज्यादा मौतें सीधे तौर पर एएमआर से जुड़ी थीं और लगभग 10 लाख से ज्यादा मौतें दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों से जुड़ी थी। खासतौर पर चिंताजनक तथ्य यह है कि वर्ष 2019 में, गंभीर दवा-प्रतिरोधी जीवाणु संक्रमण वाले केवल 7.8 भारतीयों को ही प्रभावी एंटीबायोटिक्स मिले। जो इस उपचार की एक बड़ी कमी को उजागर करता है। जिसके चलते प्रतिरोधी रोगाणु आसानी से फैलते हैं और एक बार ठीक हो सकने वाले संक्रमणों को घातक बना देते हैं। जिसके चलते सर्जरी, कैंसर के इलाज और नियमित देखभाल को कहीं ज्यादा जोखिम भरा बना देते हैं। निश्चित रूप से इस दिशा में जनजागरण अभियान की जरूरत है कि हर छोटे-मोटे रोग के लिये एंटीबायोटिक दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है। जन अभियानों के जरिये एंटीबायोटिक्स से जुड़ी भ्रांतियों को सरकार व सामाजिक स्तर पर दूर करने की जरूरत होगी। इनके अंधाधुंध उपयोग रोकने के लिये कानून से नियमन जरूरी है। साथ ही तर्कसंगत उपचार के लिये किफायती नैदानिक विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध कराने होंगे। साथ ही सरकार सुनिश्चित करे कि जिनको वास्तव में एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत है, उन्हें ये समय पर सहज रूप से मिल सकें। अन्यथा प्रतिरोध की यह मौन महामारी अनगिनत लोगों की जान ले लेगी।

ट्रंप के बदले तेवर के पीछे की असल कहानी क्या है?

अशोक भाटिया,
वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कब क्या कहेंगे, और उनका अगला कदम क्या होगा, ये किसी को पता नहीं होता। जब से ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से वो अपने फैसलों से चौंका रहे हैं। खासकर टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार अपने बयान बदलते रहे हैं। इसी कड़ी में अमेरिका ने एकतरफा फैसला सुनाते हुए भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ थोप दिया है, जिसका भारत लगातार विरोध कर रहा है। वैसे भारत और अमेरिका के बीच बेहतर कारोबारी रिश्ते हैं, मौजूदा समय में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) 131.84 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इस दौरान भारत ने अमेरिका को 86.51 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया, और 45.33 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया।लेकिन टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच थोड़ी दूरियां बढ़ गई हैं। क्योंकि ट्रंप कभी पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं और अगले दिन ही व्यापारिक प्रतिबंध बढ़ा देते हैं, इससे रणनीतिक भरोसा कमजोर होता है। इस बीच एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अपना दोस्त बताया है और कारोबारी मतभेदों को जल्द दूर करने की बात कही है। अब अचानक भारत को लेकर ट्रंप के रुख में लचीलेपन ते कई कारण बताए जा रहे हैं। क्योंकि हाल ही उन्होंने यूरोपीय संघ को भारत पर 100 फीसदी टैरिफ लगाने की सलाह दी थी, जबकि इससे इतर वो भारत से ट्रेड समझौते की बात भी कह रहे हैं, उनकी बदलती चाल एक तरह से भारत के लिए चुनौती भी है। जानकारों का कहना है कि भारत को जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की भारत को लेकर अचानक बदली रणनीति के पीछे व्यक्तिगत फैसला हो सकता है, क्योंकि व्यापारिक तौर कुछ भी नहीं बदला है। उन्होंने कहा कि अचानक इस तरह के बयान देकर माहौल को ठंडा किया जा सकता है, और इसका त्वरित लाभ ट्रंप को मिल जाएगा। लेकिन इसके दूरगामी नुकसान भी हैं। हालांकि सिब्बल का मानना है कि शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से जारी हुई तस्वीरों ने व्हाइट हाउस को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे ट्रंप ने अब भारत के प्रति नरम रुख अपनाया है। इस बदलाव को सिब्बल ने एक सकारात्मक संकेत माना है, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी कि यह रुख फिर अचानक बदल सकता है।

चीन ने पिछले हफ्ते द्वितीय विश्व युद्ध के अंत की 80 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने वाली एक सैन्य परेड में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था, जिसकी निगरानी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, जो वाशिंगटन, डीसी में हजारों मील दूर थे, जिन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि मैं इसे देखूं, और वह वास्तव में था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तियानमेन स्क्वायर में भव्य समारोह के बारे में विस्तार से नहीं बताया। ट्रंप और बाकी दुनिया के लिए चीन का संदेश स्पष्ट थाः कि दुनिया में एक नया शक्ति केंद्र बन रहा है, जो सौ साल पुरानी अमेरिकी आधिपत्य प्रणाली को चुनौती देने के लिए तैयार है। उस दिन ट्रंप ओवल ऑफिस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नोवरत्स्की के साथ मुलाकात कर रहे थे। उस समय उन्होंने चीन की सैन्य परेड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा था। चीन के साथ टैरिफ युद्ध के दौरान की घटनाओं के बारे में ट्रंप के बयान उदासीनता, दुख और चिंता का मिश्रण थे। ट्रम्प परेड के बारे में बेपरवाह दिखाई दिए और कहा कि चीन दो दर्जन से अधिक राष्ट्राध्यक्षों के सामने चीन के शक्ति प्रदर्शन के बारे में चिंतित नहीं था। हालांकि, चीन द्वितीय विश्व युद्ध में अपने योगदान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को श्रेय नहीं देता है। उन्होंने इसकी शिकायत की। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, "कृपया पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक बधाई दें, जबकि आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। कुल मिलाकर, अन्य देशों का एक साथ आना ट्रम्प को असहज कर रहा है।

ट्रम्प को परेड और सैन्य शक्ति के प्रदर्शनों के लिए विशेष प्यार है। पिछले महीने उन्होंने अलास्का में रेड कार्पेट पर पुतिन का अभिवादन किया। स्टील्थ बमवर्षकों और अमेरिकी जेट विमानों ने ऊपर से उड़ान भरी। दो महीने पहले, उन्होंने अमेरिकी सेना की 250 वीं वर्षगांठ को चिह्नित करने के लिए वाशिंगटन में एक सैन्य परेड की मेजबानी की। चीन की नवीनतम सैन्य परेड अपने उच्च तकनीक वाले हथियारों और अनुशासित मार्चिंग के लिए जानी जाती थी। यह एक सामान्य घटना थी। द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए टैंक और क्रांतिकारी युग के सैनिक व्हाइट हाउस के पास कॉन्स्टीट्यूशन एवेन्यू पर इत्मीनान से चल रहे थे। यह ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' नारे पर आधारित एक यादगार कार्यक्रम था। अमेरिका के गौरवशाली इतिहास और इस घटना पर नजर डालते हुए ट्रंप ने 19वीं सदी के उस समय को याद किया। चीन की सैन्य परेड में अपने भविष्य के हथियारों का प्रदर्शन किया गया और वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि चीन ने द्वितीय विश्व युद्ध में फासीवाद और साम्राज्यवाद को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका दावा है कि अगर उस युद्ध ने तथाकथित 'अमेरिकी सदी' की शुरूआत की है, तो चीन अब एक नई विश्व व्यवस्था बनाने में सफल होगा। कार्यालय में ट्रम्प के पहले सहयोगी रहे रिचर्ड विल्की ने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार में चीनी राष्ट्रवादी और अमेरिकी सेनाओं का योगदान चीनी कम्युनिस्ट ताकतों के योगदान से अधिक था। इस सप्ताह चीन की सैन्य परेड संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चिंता का एकमात्र कारण नहीं थी। इसके अलावा अमेरिकी नीति निमार्ताओं के लिए चिंता के कई अन्य कारण भी थे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच, चीन-भारत संबंधों में सुधार का एक प्रमुख कारण ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ हैं। इसने भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति ने दुनिया की आर्थिक और आर्थिक और आर्थिक समस्याओं को प्रभावित किया है। राजनीतिक ध्रुवीकरण बदतर हो गया है। चीन, रूस और भारत, जिन्हें प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, इस बात का एक बड़ा उदाहरण हैं कि कैसे देश बदली हुई परिस्थितियों में एक साथ आ सकते हैं।

बताया जाता है कि दरअसल ट्रंप ने अमेरिकी उद्योग की रक्षा करने और सरकार के लिए नया राजस्व उत्पन्न करने की योजना के हिस्से के रूप में टैरिफ का समर्थन किया है। ट्रंप समर्थित अमेरिका फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी इंस्टीट्यूट में अमेरिकी सुरक्षा के सह-अध्यक्ष रिचर्ड विल्की का कहना है कि कोरियाई, जापानी, फिलिपिनो और वियतनामी अच्छी तरह से जानते हैं कि वास्तविक खतरा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उनकी व्यापार साझेदारी के लिए एक छोटी बाधा नहीं है, बल्कि चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति है। ट्रम्प अक्सर अन्य देशों में संघर्षों और चिंताओं के प्रति उदासीन रहे हैं। यह मदद नहीं करता है। इसके बजाय, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के भौगोलिक रूप से करीब देशों की समस्याओं में रुचि दिखा रहे हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड, पनामा और कनाडा। चीन ने विजय दिवस परेड में दुनिया को अपनी सैन्य ताकत दिखाई, यह प्रदर्शित करते हुए कि ट्रम्प की व्यापार नीतियां संयुक्त राज्य अमेरिका की जीत के बजाय विफलता का जोखिम उठाती हैं। संकेत बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते, एक अपील अदालत ने फैसला सुनाया कि ट्रंप के कई आरोप संघीय कानून की गलत व्याख्या पर आधारित थे; लेकिन ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है, जिसमें रूढ़िवादी न्यायाधीशों का वर्चस्व है, जिन्हें ट्रम्प के समर्थक माना जाता है, लेकिन उन्होंने उन राष्ट्रपतियों के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाया है जो कांग्रेस की मंजूरी के बिना प्रमुख नीतियों को लागू करने की कोशिश करते हैं, इसलिए वह ट्रम्प की फीस पर नरम रुख अपनाएंगे। इसकी संभावना नहीं है। जब व्यापार की बात आती है तो ट्रम्प ने हमेशा अपने मन की बात सुनी है। उन्होंने कई पारंपरिक नीतियों को बदल दिया है और नए व्यापारिक साझेदार बनाए हैं।

ट्रंप ने दावा किया है कि उनकी व्यापार नीति अमेरिका को 'दूसरे स्वर्ण युग' में ले जाएगी। लेकिन चाहे वह तियानमेन स्क्वायर में चीनी सैन्य परेड हो या अमेरिकी अदालतें; ट्रंप के टैरिफ से जो खतरा पैदा हुआ है, वह काल्पनिक नहीं, बल्कि वास्तविक है। भारत के रवैये से ट्रंप की चिढ़ बढ़ती जा रही थी और एक तरफ भारत अमेरिका के दबाव के आगे नहीं झुका और दूसरी तरफ अमेरिका अपने देश में कई समस्याओं से घिरा हुआ था। लेकिन अब उन्हें हकीकत का एहसास हुआ कि उन्होंने पहले कहा था कि हमने चीन की वजह से भारत और रूस जैसे दोस्तों को खो दिया है, लेकिन दो दिन के भीतर ही उन्होंने भारत और मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत और अमेरिका के बीच खास रिश्ता है, लेकिन वह हमेशा मोदी के दोस्त रहेंगे, वह एक महान प्रधानमंत्री हैं। इसे भी जोड़ा गया था। ट्रंप का बदला हुआ लहजा भारत की दबाव वाली विदेश नीति का नतीजा लगता है।

उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन के जरिए दक्षिण का द्वार भेदने की रणनीतिक कोशिश

उमेश चतुर्वेदी
लेखक राजनीतिक समीक्षक एवं स्तंभकार हैं

जगदीप धनखड़ के औचक इस्तीफे से खाली हुए उपराष्ट्रपति पद को नया चेहरा मिल गया है। दक्षिण बनाम दक्षिण की जंग में तमिलनाडु बीजेपी का चेहरा रहे सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति होंगे। राधाकृष्णन तमिलनाडु की तीसरी शख्सियत हैं, जो उपराष्ट्रपति पद पर पहुंचने में कामयाब हुए हैं। इसके पहले तमिलनाडु के सर्वपल्ली राधाकृष्णन और आर वेंकटरमण उपराष्ट्रपति रह चुके हैं।

नरेंद्र मोदी के उभार के पहले तक बीजेपी की छवि ब्राह्मण-बनिया समुदायों की बुनियाद पर टिकी उत्तर भारतीय पार्टी की रही है। मोदी की राजनीतिक छाया में बीजेपी ने इस छवि को काफी हद तक तोड़ने की कोशिश की है। इसके बावजूद तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी प्रभावी नहीं बन पाई है। इनमें भी तमिलनाडु पार्टी के लिए अब भी प्रश्न प्रदेश बना हुआ है। पूर्व अधिकारी और तेज-तर्रार नेता अन्नामलाई के आक्रामक अभियान के चलते राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थक आधार दहाई के आंकड़े में पहुंच चुका है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब साढ़े ग्यारह प्रतिशत और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ करीब बीस प्रतिशत वोट मिला था। शायद यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपना समर्थक आधार बढ़ाने के लिए प्रयोग-दर-प्रयोग कर रही है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना और उन्हें चुनाव जिताना उसी प्रयोग का विस्तार कहा जा सकता है।

सीपी राधाकृष्णन के सामने उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी। राधाकृष्णन कामचलाऊ हिंदी समझ तो लेते हैं, दो-एक लाइनें बोल भी लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की जिम्मेदारी राज्यसभा की कार्यवाही चलाना होगी। राज्यसभा में ज्यादातर सांसद हिंदी भाषी हैं और वे अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, हंगामा भी हिंदी में करते हैं और बहसें भी हिंदी में ही करते हैं। राधाकृष्णन को इन पर पार पाने के लिए मेहनत करनी होगी। वैसे वे कहते रहे हैं कि राजनीति में अखिल भारतीय छवि बनाने के लिए हिंदी बोलना जरूरी है। अब उन्हें कामचलाऊ से कुछ ज्यादा हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी।

नरेंद्र मोदी के उभार के पहले तक बीजेपी की छवि ब्राह्मण-बनिया समुदायों की बुनियाद पर टिकी उत्तर भारतीय पार्टी की रही है। मोदी की राजनीतिक छाया में बीजेपी ने इस छवि को काफी हद तक तोड़ने की कोशिश की है। इसके बावजूद तमिलनाडु, केरल, पंजाब जैसे राज्यों में बीजेपी प्रभावी नहीं बन पाई है। इनमें भी तमिलनाडु पार्टी के लिए अब भी प्रश्न प्रदेश बना हुआ है। पूर्व अधिकारी और तेज-तर्रार नेता अन्नामलाई के आक्रामक अभियान के चलते राज्य में पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी का समर्थक आधार दहाई के आंकड़े में पहुंच चुका है। बीते लोकसभा चुनाव में पार्टी को करीब साढ़े ग्यारह प्रतिशत और गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ करीब बीस प्रतिशत वोट मिला था। शायद यही वजह है कि बीजेपी तमिलनाडु में अपना समर्थक आधार बढ़ाने के लिए प्रयोग-दर-प्रयोग कर रही है। सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाना और उन्हें चुनाव जिताना उसी प्रयोग का विस्तार कहा जा सकता है। सीपी राधाकृष्णन के सामने उपराष्ट्रपति के रूप में कुछ चुनौतियां जरूर रहेंगी। राधाकृष्णन कामचलाऊ हिंदी समझ तो लेते हैं, दो-एक लाइनें बोल भी लेते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन की जिम्मेदारी राज्यसभा की कार्यवाही चलाना होगी। राज्यसभा में ज्यादातर सांसद हिंदी भाषी हैं और वे अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं, हंगामा भी हिंदी में करते हैं और बहसें भी हिंदी में ही करते हैं। राधाकृष्णन को इन पर पार पाने के लिए मेहनत करनी होगी। वैसे वे कहते रहे हैं कि राजनीति में अखिल भारतीय छवि बनाने के लिए हिंदी बोलना जरूरी है। अब उन्हें कामचलाऊ से कुछ ज्यादा हिंदी तो सीखनी ही पड़ेगी। भाजपा ने तमिलनाडु को साधने के लिए रणनीतिक तौर पर खूब कोशिशें की हैं। संसद के नए भवन में तमिल राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना हो या फिर वाराणसी में तमिल-काशी संगम का आयोजन, तमिल जनमानस तक मोदी और बीजेपी की बैठ बढ़ाने की कोशिश का ही प्रतीक है। अक्तूबर, 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था।

भाजपा ने तमिलनाडु को साधने के लिए रणनीतिक तौर पर खूब कोशिशें की हैं। संसद के नए भवन में तमिल राजदंड के प्रतीक सेंगोल की स्थापना हो या फिर वाराणसी में तमिल-काशी संगम का आयोजन, तमिल जनमानस तक मोदी और बीजेपी की बैठ बढ़ाने की कोशिश का ही प्रतीक है। अक्तूबर, 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत का दौरा किया था। उस वक्त जिनपिंग का मोदी ने तमिलनाडु के खूबसूरत पर्यटक स्थल महाबलिपुरम में स्वागत किया था। इस मुलाकात को भी तमिलनाडु की जनता को साधने की बीजेपी और मोदी की कोशिश के रूप में देखा गया था। प्रधानमंत्री मोदी का अरियलूर जिले के गंगैकोंडचोलपुरम का दौरा हो या यहां के नजदीक स्थित बृहदीश्वर मंदिर में पूजा-अर्चना हो, सबका संदेश एक ही है, तमिलनाडु के दिलों में अपनी पैठ बनाना।

सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में बीजेपी का बड़ा चेहरा रहे हैं। 1998 और 1999 में कोयंबटूर से बीजेपी के सांसद रहे सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु में तमिल मोदी के तौर पर भी प्रसिद्ध हैं। राधाकृष्णन राज्य में पिछड़े वर्ग में शामिल गौंडर जाति से आते हैं। दिलचस्प यह है कि इस जाति के वोटर कन्नड़ ब्राह्मण महिला जे जयललिता की अन्नाद्रमुक मुनेत्र कषगम के समर्थक माने जाते हैं। यह बात और है कि अन्नाद्रमुक की अगुवाई कर रहे ई पलानीसामी और बीजेपी के फायरब्रांड नेता अन्नामलाई भी इसी बिरादरी के हैं। इस लिहाज से देखें तो सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने शीर्ष पर बैठा के गौंडर समुदाय को साधने की कोशिश की है। 2010 के विधानसभा चुनावों में अन्नाद्रमुक ने उन्हें पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने का खुला आमंत्रण दिया था लेकिन राधाकृष्णन ने अपनी प्रतिबद्धता नहीं तोड़ी।

आजादी के बाद से ही तमिलनाडु की राजनीति में पिछड़ा और दलित समुदाय का प्रभुत्व रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में अगड़ा समुदाय एक तरह से किनारे पर आजादी के बाद से ही है। बीजेपी की राज्य में सवर्ण जातियों की उत्तर भारतीय पार्टी की छवि है। तमिलनाडु में बीजेपी के उभार की बड़ी बाधा यह वजह भी रही है। गौंडर समुदाय के राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर बीजेपी ने एक तरह से अपनी वह छवि तोड़ने की कोशिश की है। बताने की कोशिश कि वह सवर्ण नहीं, सर्व समाज की पार्टी है। यहां यह भी ध्यान देने की बात है कि केरल के पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सीपी राधाकृष्णन केरल बीजेपी के प्रभारी थे। राधाकृष्णन जिस तिरूपुर इलाके से आते हैं और जिस कोयंबटूर के सांसद रहे हैं, वह केरल का नजदीकी है। इस लिहाज से मान सकते हैं कि बीजेपी ने उनके जरिए केरल को भी साधने की कोशिश की है।

तमिलनाडु और केरल में अगले साल अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। तमिलनाडु में जिस गठबंधन के पास पैंतीस प्रतिशत वोट होगा, उसकी जीत सुनिश्चित है। पिछले आम चुनाव में अन्नाद्रमुक को करीब साढ़े बीस प्रतिशत वोट मिले थे। अन्नाद्रमुक के साथ राज्य में उसका गठबंधन बन चुका है। राधाकृष्णन के चेहरे के सहारे बीजेपी अपने गठबंधन के वोट प्रतिशत की बढ़त करने की तैयारी में है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

"समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है, मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं।" - धीरूभाई अंबानी

स्वाभाविक साझेदारी

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वाराणसी में शिखर वार्ता के दौरान अहम समझौतों के साथ मॉरीशस को करीब छह हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को मंजूरी द्विपक्षीय साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंचने को ही दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय साझेदारी को एनहैन्स्ड स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। लेकिन, मॉरीशस के प्रधानमंत्री की ताजा यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का मॉरीशस को परिवार-तुल्य बताना दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों का पुनःस्मरण कराता है। गौरतलब है कि मॉरीशस, जो हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है, भारत का एक करीबी पड़ोसी भी है। यह भावना प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भी प्रतिबिंबित होती है, जब वह कहते हैं कि मॉरीशस, भारत के पड़ोसी प्रथम और विजन महासागर का एक अपरिहार्य स्तंभ है। दोनों देशों के बीच खास रिश्तों का मुख्य कारण यह भी है कि मॉरीशस की करीब तेरह लाख आबादी में 70 फीसदी हिस्सेदारी भारतीय मूल के लोगों की है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री फिलहाल 16 सितंबर तक भारत में ही हैं। शिखर वार्ता के दौरान, शिक्षा, अनुसंधान, जल विज्ञान, विद्युत, अंतरिक्ष अनुसंधान और समुद्री सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में कुल सात समझौते हुए, जो 'विकास-साझेदारी' और 'रणनीतिक सहयोग' का संगम कहे जा सकते हैं। अमेरिका की अतार्किक टैरिफ नीति के चलते वैश्विक समीकरणों ने जो नए मोड़ लिए हैं, उनमें भारत और चीन के बीच आई नजदीकी भी है। हालांकि, चीन के रिकॉर्ड के मद्देनजर सतर्क भारत यह नहीं भूल सकता कि पिछले कुछ वर्षों से चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में मॉरीशस जैसे विश्वसनीय साझेदारों का समर्थन भारत के लिए क्षेत्रीय संतुलन बना सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मॉरीशस में यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च किए गए थे और अब स्थानीय मुद्रा में ही कारोबार होने के फैसले से डॉलर के वर्चस्व को यकीनन चोट पहुंचेगी। भविष्य में भारत-मॉरीशस सहयोग हिंद महासागर में स्वतंत्र और संतुलित शक्ति संरचना का आधार बन सकता है, जो भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को भी दर्शाता है। हालांकि, दोनों देशों को इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए घोषणाओं के कार्यान्वयन पक्ष पर ध्यान देना होगा। परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्ति और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि यह सहयोग सही मायनों में विकास का माध्यम बने।

आखिर अमेरिका की समस्या क्या है

ट्रंप के विवेकहीन सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के बारे में जो शब्द कहे हैं, उन्हें शायद भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं। अमेरिका के बर्बर इतिहास को देखते हुए, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन वह और उनके राष्ट्रपति शायद यह नहीं समझ पा रहे कि दुनिया अमेरिका के बिना रह सकती है, लेकिन अमेरिका दुनिया के बगैर नहीं रह सकता।

वीरेंदर कपूर
लेखक एवं शिक्षाविद

पिछले छह महीनों से मैं यह सोच रहा था कि अगर रूस, भारत और चीन एकसाथ आ जाएं, तो क्या होगा? यह एक काल्पनिक प्रश्न था। भारत और चीन को एकसाथ जोड़ने में रूस भूमिका निभाएगा। लेकिन तब यह मुझे दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन ट्रंप ने इसे संभव कर दिखाया। मुझे अमेरिकी संरक्षणवादी रियायत का व्यक्तिगत अनुभव हुआ, जो इस प्रकार है-लगभग दो दशक पहले, मैं दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता था। एक ब्रिटिश कंपनी का सीईओ (एक श्वेत ब्रिटिश) मंच पर मेरे बगल में बैठा था। वह काफी शर्मिंदा दिख रहा था। दरअसल, एक अमेरिकी कंपनी के सीईओ ने अपने वक्तव्य के दौरान यूरोपीय लोगों का, खासकर ब्रिटिश विरासत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं खुद को यह कहने से नहीं रोक पाया, 'अगर वह सार्वजनिक रूप से इस तरह से आपका मजाक उड़ा सकता है, तो बाकी दुनिया क्या सोचेगी?'

ब्रिटिश सीईओ ने कंधे उचकाते हुए कहा- 'ओह! यही तो अमेरिकी अहंकार है।' यह 20 साल पहले की बात है। ट्रंप और उनके साथी अब पूरी ताकत से जुट गए हैं। कल्पना के घोड़े पर सवार ट्रंप के विवेकहीन मुख्य सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से भारत की तेल खरीद की आलोचना की और इसे 'मोदी का युद्ध' करार दिया। अब उन्होंने यह कहकर अपनी नासमझी का नवीनतम उदाहरण पेश किया है कि 'ब्राह्मण अन्य भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।' दरअसल, जेलेंस्की भारत से विधिवत संसाधित रूसी तेल खरीदकर रूस को वित्तपोषित कर रहे हैं। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म, नैफ्टोरिनोक के अनुसार, जुलाई में यूक्रेन के डीजल आयात में किसी भी अन्य देश से अधिक भारत का हिस्सा 15.5 फीसदी था। दैनिक शिपमेंट औसतन 2,700 टन रहा, जिससे यह इस साल भारत के सबसे ज्यादा मासिक ईंधन निर्यात आंकड़ों में से एक बन गया।

दुनिया को पता होना चाहिए कि ये अमेरिकी कहां से आए हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि अमेरिकियों ने रेड इंडियंस (मूल अमेरिकियों) से जमीन कैसे छीनी। उन्होंने न केवल उनकी बस्तियों को जला दिया और उन्हें संगीनों एवं गोलियों से मार डाला, बल्कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया, जो अकल्पनीय था, उन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया था। अमेरिकियों द्वारा इन्सानों की खरीद-फरोख्त होती थी। वे कुछ डॉलर के लिए अश्वेत गुलामों को संपत्ति की तरह बेचते थे। उन पर अत्याचार करते थे। उन्होंने यातना के नए-नए तरीके ईजाद किए-जो नरसंहार से भी कहीं ज्यादा भयानक थे। उनकी सजा का एक भयावह तरीका सार्वजनिक रूप से जलाना था। जाहिर है, गोरे अमेरिकियों की कोई संस्कृति नहीं है।

हालांकि, 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन एक श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और उसकी हत्या के बाद शुरू हुआ था, जो कुछ समय तक चला। लेकिन यह तो अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार का एक छोटा-सा हिस्सा भी नहीं था। अमेरिकियों को अब भी लोगों पर अत्याचार करना पसंद है। अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों की तुलना में अश्वेत अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हैं। अधिकांश अश्वेत वयस्कों ने बताया कि उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी, उन्होंने उस देश की प्रगति में योगदान दिया। इसकी पुष्टि अश्वेत खिलाड़ियों द्वारा अमेरिका के लिए जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या से भी होती है। मोटे तौर पर अमेरिकी जनसांख्यिकी श्वेत अमेरिकियों की ओर झुकी हुई है। श्वेतः 57.8 फीसदी, हिस्पैनिक या लैटिनोः 18.7 फीसदी, अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकीः 12.1 फीसदी और मूल अमेरिकी/अलास्का लगभग 1.12 फीसदी। फिर भी, अन्य लोगों का योगदान कहीं ज्यादा है। अमेरिकी फिल्म उद्योग और संगीत क्षेत्र में भी अश्वेतों का योगदान अमूल्य है।

आखिर अमेरिकी नेतृत्व के साथ समस्या क्या है? दरअसल, वह हिटलर की तरह अहंकार में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। 1939 में भी एक सितंबर को जर्मनों ने पोलैंड पर हमला किया था और द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत की थी। अब ट्रंप ने दुनिया के लिए टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। हिटलर पागल हो गया था और अपनी मर्जी से संधियां तोड़ता था और किसी भी सलाहकार की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने बहुत सारे मोर्चे खोल दिए थे। जर्मनी दुनिया के खिलाफ था, लेकिन कम से कम इटली और जापान उसके बड़े समर्थक थे। अमेरिका, जिसे ट्रंप महान बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब अलग-थलग पड़ गया है। जैसा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कहते हैं, 'फिलहाल दुनिया में एक देश की कमी दिखती है।' वह यह भी कहते हैं कि दुनिया अमेरिका के बिना रह सकती है, लेकिन अमेरिका दुनिया के बगैर नहीं रह सकता। अमेरिकी सांड बेकाबू होकर बेचारे अमेरिकियों को मार रहा है-उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने एक मनमौजी नेता को चुना। अब वह अपने चाटुकारों के जरिये हमें बता रहा है कि सारा पैसा ब्राह्मणों के पास है और बाकी देश को कुछ नहीं मिल रहा। इन्हें यह भी नहीं पता कि अंबानी परिवार मोध बनिया समुदाय से है, जो भारत के गुजरात राज्य का एक हिंदू वैश्य (व्यापारिक) समूह है। गौतम अडानी गुजराती जैन समुदाय से हैं। आनंद महिंद्रा पंजाबी हिंदू खत्री समुदाय से हैं। टाटा और गोदरेज पारसी हैं। उन्हें हमारी 5,000 साल पुरानी सभ्यता में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं और राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं। इसलिए अमेरिकियों को कोई हक नहीं है कि वे हमें उपदेश दें।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है। उसकी एकमात्र ताकत हाईटेक और हथियार उद्योग है। उसकी तकनीकी ताकत बाहरी लोगों, खासकर भारत के पास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी हवाई शक्ति का लोगों ने जो प्रदर्शन देखा, उसे देखकर कोई भी उनसे विमान नहीं खरीदेगा। यह 1945 नहीं, बल्कि 2025 है। यदि हैदराबाद से लूला कॉफी का निर्यात न हो, तो अमेरिकियों को कॉफी सूंघने को भी न मिले। और अभिजात्य अमेरिकी बिना कॉफी पिये, कुछ सोच भी नहीं सकते। सीआईए को अब किसी और हुकूमत को गिराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान अमेरिका की रक्षा करें।

पर्यावरण

नहीं चेते, तो हालात और गंभीर हो जाएंगे

पंजाब में 1988 के बाद आई सबसे खतरनाक बाढ़ की भौगोलिक वजहें ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं।

सीमा जावेद

देश का आधा हिस्सा असाधारण बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। पंजाब 1988 के बाद से सबसे भीषण जल प्रलय का सामना कर रहा है। रिकॉर्ड-तोड़ बारिश और असामान्य तापमान ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में केवल 24 घंटों में सामान्य से एक हजार फीसदी से अधिक बारिश हुई। पंजाब में 1988 के बाद से सबसे खराब बाढ़ आई है, जिसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ और लगातार बारिश के कारण हजारों गांव जलमग्न हो गए। भारत के पंजाब में मानसून का मौसम आम तौर पर जून के अंत से सितंबर तक चलता है और दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा संचालित होता है। ऐतिहासिक रूप से, मानसून मध्यम वर्षा लाता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी होती है और वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब हिंद महासागर और अरब सागर, दोनों ही बहुत गर्म हो रहे हैं और इनमें समुद्री हीटवेव पैदा हो रही है। इन सागरों के गर्म होने से अब हवा में नमी की मात्रा बहुत अधिक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ने बताया है कि 1951-2015 के दौरान हिंद महासागर की सतह के तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। इससे समुद्री सतह से वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और वायुमंडल में नमी भी अधिक घुल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अधिक तीव्र और अनियमित होता जा रहा है। इस साल मानसून ने भारत और पाकिस्तान के साझा पंजाब क्षेत्र में भयंकर बाढ़ ला दी है।

मानसून के चरम मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ आम तौर पर उत्तर की ओर लौट जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और उल्टे पश्चिमी विक्षोभ का मानसून से टकराव हो गया। ऐसी अंतर्क्रिया असामान्य है। आईएमडी ने भी पुष्टि की है कि उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में लगातार हुई अत्यधिक वर्षा मुख्य रूप से मानसून प्रणाली और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव के कारण हुई, जिससे पंजाब, हरियाणा सहित कई उत्तरी राज्यों में बाढ़ आ गई।

जेट स्ट्रीम-ऊपरी वायुमंडल में हवा की संकरी, तेज धाराएं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर दुनिया भर में चलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग इन धाराओं को तेजी से 'लहरदार' बना रही है, जिसका अर्थ है कि यह घुमावदार है और एक स्थिर पथ पर नहीं चल रही है। अध्ययनों से पता चला है कि लहरदार जेट स्ट्रीम दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाओं को जन्म दे रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम ने पश्चिमी विक्षोभों को असामान्य रूप से उत्तरी भागों में मोड़ दिया। इस बार के मानसून ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान मौसमी पैटर्न को गहराई से प्रभावित कर रहा है।

भारी बारिश और बढ़ते तापमान के संयोजन ने देश के विभिन्न हिस्सों को गंभीर चुनौतियों का सामना कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते उचित नीतियों और ठोस अनुकूलन रणनीतियों पर काम नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं से स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझें और इससे निपटने के लिए सामूहिक और टिकाऊ कदम उठाएं, ताकि देश के विविध पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अरस्तु ने दुनिया देखकर तर्क की खोज की। चैटजीपीटी, प्रशिक्षण सेट में मौजूद तर्कों के आधार पर दुनिया के हर सवाल का जवाब देता है।
-स्टीफन वोल्फ्राम

सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आते

आप किसी उल्लेखनीय चीज के बारे में सोचते हैं, वह भले ही बहुत ही अनोखा विचार क्यों न हो, लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते, तो वह हमेशा आपके विचारों में या किताबों में ही रहेगी, उपलब्धियों की सूची में नहीं।

रॉबर्ट ए. हेनलेन

जीवन धारा

सैद्धांतिक रूप से हर चीज तब तक असंभव लगती है, जब तक उसे पूरा न कर लिया जाए। इसी तरह, जब आप किसी उल्लेखनीय चीज के बारे में सोचते हैं, वह भले ही बहुत ही अनोखा विचार क्यों न हो, लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते, तो वह हमेशा आपके विचारों में या किताबों में ही रहेगी, उपलब्धियों की सूची में नहीं। अधिकांश लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, यदि उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो उन्हें यह तब तक असंभव लगेगा, जब तक कोई दूसरा एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई न कर ले।

मुझे दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में मानव जाति की सुरक्षा के लिए हमें अन्य ग्रहों पर बस्तियां स्थापित करनी होंगी। भले ही हम इस धरती को अभी नष्ट न करें, एक दिन यह ग्रह अपने संसाधनों को खो देगा। अगर हम चाहते हैं कि मानव जाति अगले तीस अरब साल तक जीवित रहे, तो हमें और जगह चाहिए। हमें अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी हमें अपनी पूरी प्रजाति को सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूं। जैसा कि लुईस कैरोल की किताब *थ्रू द लुकिंग ग्लास* में एलिस कहती हैं, 'आपको एक ही जगह पर बने रहने के लिए भी पूरी तेजी से दौड़ना पड़ता है।' इसका मतलब है कि दुनिया काफी तेज गति से बदल रही है, तकनीक, कला, और विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि उनके साथ बने रहने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतना ही लगता है कि और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि समय की गति बहुत तेज है।

हरेक इन्सान के जीवन में एक ऐसा समय आता है, जब उसे किसी नतीजे के लिए अपनी जान, अपनी दौलत और अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने का फैसला करना पड़ता है। जो इस चुनौती में नाकाम होते हैं, वे बस शारीरिक रूप से बड़े हो चुके बच्चे होते हैं, और कुछ नहीं हो सकते। वास्तविक परिपक्वता तभी आती है, जब हम इन जोखिमों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, बिना संघर्ष के कोई महान उपलब्धि संभव नहीं होती। और यही वह बिंदु है, जहां से सच्ची प्रगति की यात्रा आरंभ होती है। एक यात्रा जो न केवल व्यक्तिगत, बल्कि समस्त मानवता के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है।

जब एआई नौकरी के इंटरव्यू लेता है

अगंभीर उम्मीदवारों की छंटनी के लिए मशीन द्वारा इंटरव्यू लेना समझ आता है, पर विशिष्ट कौशलों की पहचान तो मनुष्य ही कर सकता है।

नताली रोचा

सैन एंटोनियो में मार्केटिंग पेशेवर चौवन वर्षीय जेनिफर डन कुछ माह पहले मार्केटिंग की नौकरी के लिए रिक्रूटर फर्म द्वारा आयोजित साक्षात्कार देने पहुंचीं। वह अपनी नई भूमिका और अपने नियोक्ता के संबंध में जानने को लेकर काफी उत्सुक थीं। इसके बजाय, एलेक्स नाम के एक वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिक्रूटर ने उन्हें साक्षात्कार का समय तय करने के लिए मोबाइल पर एक संदेश भेजा।

तय समय पर डन के पास एलेक्स का फोन आया, डन ने पूछा, 'क्या आप इन्सान हैं?' एलेक्स ने कहा, 'नहीं, मैं इन्सान नहीं हूं। लेकिन, मैं यहां साक्षात्कार प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हूं।' अगले बीस मिनट तक डन ने एलेक्स के सवालों के जवाब दिए। हालांकि, एलेक्स उनके ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे सका। डन के अनुसार, एआई रिक्रूटर बातचीत में दोस्ताना भाव लाना चाह रहा था, लेकिन उन्हें यह सब अजीब लग रहा था। शायद इसीलिए उन्होंने साक्षात्कार पूरा होने से पहले ही फोन काट दिया।

आप सोचते हैं कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा, लेकिन यह सबसे पहले रिक्रूटर बनकर चुनौती पेश कर रहा है। ये स्वायत्त रिक्रूटर, जिन्हें एजेंटिक एआई के नाम से जाना जाता है, एआई का नया स्वरूप हैं। नौकरी खोजने के कुछ पहलू-जैसे रिज्यूमे की जांच और मीटिंग निर्धारित करना-समय के साथ तेजी से स्वचालित होते गए हैं, लेकिन साक्षात्कार लंबे समय से इस प्रक्रिया का वह हिस्सा माना जाता था, जिसमें मानवीय पुट की सबसे ज्यादा दरकार होती है। अब एआई इस क्षेत्र में भी दखल दे रहा है, जिससे नौकरी ढूंढने का सफर और भी अधिक हताशा भरा हो गया है। कंप्यूटर साइंस व गणित में स्नातक 22 वर्षीय चार्ल्स व्हिटली, जो एआई के साथ दो बार साक्षात्कार दे चुके हैं, का कहना है कि एआई साक्षात्कारकर्ता के साथ बात करना 'बहुत ही असहज महसूस' होता है। एक इंटरव्यू में तो एआई की आवाज को अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए हम्म, ओह जैसे शब्द डाले गए, लेकिन ये डरा ज्यादा रहे थे। दरअसल, नियोक्ताओं को अधिक उम्मीदवारों से बात करने में मदद करने और मानव रिक्रूटरों का बोझ कम करने के लिए रोबोट साक्षात्कारकर्ता विकसित किए हैं। युवाओं को वित्तीय निवेश सिखाने वाली ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकुवर स्थित गैर-लाभकारी संस्था प्रोपेल इंपैक्ट ने जनवरी में रिबन एआई के साक्षात्कारकर्ता का उपयोग शुरू किया। संस्था की कार्यकारी निदेशक शेरलिन चोक ने बताया कि इससे संस्था को अपने फेलोशिप कार्यक्रम के लिए 500 आवेदकों की स्क्रीनिंग करने में मदद मिली, जो पिछले साल के 150 आवेदकों से कहीं ज्यादा है। इससे समय की बचत हुई और आवेदकों को भी सहूलियत हुई। हालांकि, ऑनलाइन जॉब बोर्ड जिपरिक्रूटर की कॅरिअर विशेषज्ञ सैम डीमेस कहती हैं कि भर्ती प्रक्रिया से इन्सानों को बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एआई में पूर्वाग्रह हो सकता है और किसी उम्मीदवार के अनुभव, कौशल और नौकरी के लिए उपयुक्तता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के लिए उस पर भरोसा नहीं जता सकते।

57 वर्षीय एमिली रॉबर्ट्सन-यिंगस्ट जैसे लोगों के लिए यह बुरी खबर है। अप्रैल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट मार्केटिंग के उपाध्यक्ष पद के लिए ईव नाम के एआई ने उनका साक्षात्कार लिया, जिसमें एमिली को अपना कैमरा चालू रखना था और स्क्रीन के एक छोटे से कोने में उन्हें ईव दिख रहा था।

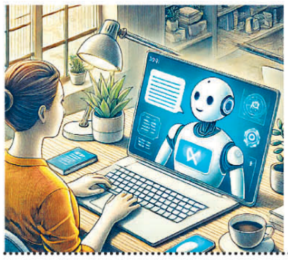

एआई गार्डेल्स

ये एआई सिस्टम को नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। गार्डेल्स ऐसे अदृश्य फिल्टर होते हैं, जो तत्काल पकड़ लेते हैं कि एआई सिस्टम कहां गलती करने वाला है, ताकि उसे रोक दिया जाए। यदि एआई कोई ऐसी जानकारी या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हो-जैसे घृणास्पद भाषण, हिंसा को बढ़ावा देना, या गलत जानकारी देना, तो गार्डेल्स उसे रोक देते हैं या संशोधित कर देते हैं। गार्डेल्स एआई की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एआई आउटपुट से समाज को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 110 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 13 सितंबर 2025

शांति की आशा

कुकी-मैतेई में विश्वास बहाली की ज़रूरत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर जा रहे हैं। उनकी यह यात्रा बहुप्रतीक्षित थी। दो साल से ज्यादा वक्त से यह राज्य अशांत है। छिटपुट हिंसा का दौर अब भी जारी है। पीएम के दौरे और विकास परियोजनाओं के ऐलान से शांति व स्थायित्व बहाल करने में मदद मिल सकती है।

जानमाल का बड़ा नुकसान । मणिपुर का मौजूदा संकट मार्च 2023 में वहां के हाईकोर्ट के उस आदेश से शुरू हुआ था, जिसमें राज्य सरकार से मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने पर जल्द विचार करने को कहा गया था। इसके कुछ दिनों बाद ही कुकी और मैतेई समुदाय के बीच जातीय हिंसा भड़क उठी। इसमें 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों विस्थापितों की तरह रहने को मजबूर हैं।

पीएम का मणिपुर दौरा

आम सहमति । इस संघर्ष ने राज्य की दो प्रमुख जनजातियों के बीच अविश्वास को और गहरा कर दिया है। मामले की जटिलता यह है कि कुकी और मैतेई ही नहीं, कई दूसरी जनजातियां भी हैं, जिनको वार्ता का हिस्सा बनाए बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के जाने से इस दिशा में ठोस पहल होगी।

अराजकता पर लगाम । पीएम मोदी राजधानी इंफाल के साथ चुराचांदपुर भी जाएंगे। हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में चुराचांदपुर है। पीएम के दौरे का ऐलान होने के बाद भी यहां से पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ कुछ लोगों की झड़प की खबरें आई थीं। इससे जाहिर होता है कि कुछ अराजक तत्व शांति बहाली की कोशिशों को पटरी से उतारना चाहते हैं।

भरोसे की जरूरत । राज्य के लोगों को यह भरोसा दिलाने की जरूरत है कि सरकार किसी एक समुदाय या वर्ग के साथ नहीं, पूरे मणिपुर के साथ है और उनकी सामूहिक भलाई के लिए काम कर रही है। दरअसल, निवर्तमान सीएम एन बीरेन सिंह को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि उन्हें लेकर कुकी समुदाय आश्वस्त नहीं था। यह भी आरोप लगे थे कि उन्होंने हिंसा से निपटने के लिए जरूरी तत्परता नहीं दिखाई।

संवेदनशीलता की जरूरत । मणिपुर का सामाजिक तानाबाना बहुत नाजुक है। यहां पहले भी कुकी-पाइते और मैतेई-पंगल संघर्ष हो चुका है। केंद्र की एक्ट-ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा होने और म्यांमार से लगती अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण मणिपुर में ज्यादा संवेदनशीलता व सावधानी बरतने की जरूरत है।

अंतर्दृष्टि

दुनियावी यात्रा से थोड़ी अलग होती है हमारी आत्मा की राह

सुंदर चंद ठाकुर

बहुत कुछ हमने जाना, बहुत कुछ समझा, बहुत दूर चले, पर जब जीवन के शोर से थककर भीतर की ओर झांकते हैं, तब एक धीमी-सी आवाज सुनाई देती है। यह आवाज न मन की है, न बुद्धि की। यह आत्मा की पुकार है, जो अक्सर हमारी दुनियावी चाहतों, शोरगुल और दूसरों की अपेक्षाओं के नीचे दब जाती है। मन चाहता है सफलता, सम्मान। शरीर चाहता है सुख, सुविधा, आराम। पर आत्मा... आत्मा सिर्फ एक चीज चाहती है - सच्चाई। वह जानना चाहती है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और किस दिशा में बढ़ना है।

बहुत से लोग जीवन की उसी राह पर चलते हैं, जो सबने तय कर रखी है। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, विवाह, परिवार, प्रतिष्ठा - यह सब जरूरी हो सकता है, पर आत्मा की राह इससे अक्सर अलग होती है। आत्मा की यात्रा कोई सीधी-सादी सड़क नहीं होती। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कुछ होने के बावजूद अधूरे लगते हैं। उनके पास पैसा है, सम्मान है, पर आंखों में चमक नहीं है, बातों में आत्मा नहीं है। क्योंकि शायद वे आत्मा की राह से भटक गए हैं। आत्मा की राह अक्सर डरावनी लगती है, क्योंकि वह अकेली होती है। उस पर तालियां नहीं बजतीं, उस पर 'लाइक' और 'फॉलो' नहीं मिलते। पर जो उस राह पर चलने का साहस करते हैं, वे भीतर से कुछ और ही बन जाते हैं। धीरे-धीरे उनके जीवन से एक ऐसी ऊर्जा फूटती है, जो दूसरों को भी खींचती है। कभी-कभी आत्मा की राह हमें बाहरी रूप से सफल नहीं बनाती, पर वह हमें सच्चा बनाती है। और सच्चा होना इस दुनिया में सबसे बड़ी सफलता है।

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में सत्य के लिए खड़े हुए थे, तब वह कोई प्रसिद्ध नेता नहीं थे। पर उनकी आत्मा ने उन्हें खड़ा कर दिया। मीरा जब कृष्ण की भक्ति में सबकुछ छोड़कर निकल पड़ी थीं, तो समाज ने उन्हें पागल कहा। लेकिन उनकी आत्मा शांत थी, क्योंकि वह अपनी राह पर थीं। इसलिए जीवन में एक बार तो ठहर कर पूछिए - क्या मैं उस राह पर चल रहा हूं, जो मेरी आत्मा चाहती है? या मैं बस मन और समाज के कहे अनुसार दौड़ रहा हूं? आत्मा की राह पर चलना तपस्या है। यह आत्म-अन्वेषण है। जब हम इस राह पर चलते हैं, तो भले ही दुनिया की भीड़ में खो जाएं, अपने आपको पा लेते हैं। जीवन छोटा है। समय बहता जा रहा है। हर दिन अगर आत्मा की पुकार को अनसुना किया जाए, तो भीतर एक शून्य बनने लगता है। और यह शून्य तब तक नहीं भरता, जब तक हम वह राह न पकड़ लें, जो हमारे जन्म की असली वजह से जुड़ी हो। तो आज, अभी, इसी पल बस थोड़ी देर रुकिए। शांति से बैठिए। अपने भीतर सुनिए - क्या कोई धीमी-सी पुकार आ रही है? अगर हां, तो जान लीजिए - वही आपकी आत्मा की राह है। और उस पर चलना ही असली जिंदगी है।

ऑफ़ दि ट्रैक

मंगल का दिल

दिलीप लाल

नासा के इनसाइट लैंडर से मिली नवीनतम सिस्मिक तरंगों की जानकारी से पता चला है कि मंगल ग्रह के अंदर एक ठोस आंतरिक कोर मौजूद हो सकता है, जिसका रेडियस लगभग 600 किलोमीटर है। यह मंगल की कुल मोटाई का लगभग पांचवां हिस्सा है। इस खोज से वैज्ञानिकों को मंगल के अंदरूनी ढांचे और उसकी विकास प्रक्रिया को बेहतर समझने में मदद मिली है। 2018 से 2022 तक इनसाइट ने हजारों मार्सक्वेक के कंपन मापे। जब ये सिस्मिक तरंगें ग्रह के भीतर से गुजरती हैं, तो विभिन्न परतों की सीमाओं पर मुड़ती या परावर्तित होती हैं। इससे ग्रह के अंदर छुपे तत्वों और संरचनाओं का पता चलता है। इन तरंगों के अध्ययन से पता चला कि मार्स का कोर मुख्य रूप से लोहा और निकल से बना हो सकता है। इसमें हल्के तत्व जैसे ऑक्सिजन, सल्फर और कार्बन भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि, कुछ वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि इस डेटा की अन्य तरीकों से भी जांच होनी चाहिए। पृथ्वी में ठोस और तरल कोर के बीच ऊर्जा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, लेकिन मंगल के ठोस कोर के साथ भी उसका व्यापक चुंबकीय क्षेत्र क्यों समाप्त हो गया, इसे समझाने के लिए नए सिद्धांतों की जरूरत होगी। यह रिसर्च मंगल ग्रह के आंतरिक रहस्यों को समझने का रास्ता खोलती है।

हिंदी भाषा के विस्तार में फिल्मों का अहम योगदान रहा है

सिनेमा ने साहित्य से क्या लिया

मनोज भावुक

विदेशों में हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता का एक कारण हिंदी सिनेमा भी है। बहुत-से लोग हिंदी इसलिए सीखते हैं कि वे यहां बनी सुंदर फिल्मों को देख सकें। एक समय राज कपूर के विदेशों में बहुत फैन थे। आज भी शाहरुख खान के बहुत-से फैन हैं।

भाषा से आत्मीयता नहीं। दक्षिण भारत की फिल्मों में जिस तरह वहां के साहित्य की महान कृतियों के फिल्मांकन हुए हैं, उस तरह हिंदी फिल्मों में तो नहीं हुए हैं। अंग्रेजी या दूसरी किसी भाषा में लिखे उपन्यास और कहानी पर हिंदी में ज्यादा फिल्में बनी हैं। हिंदी सिनेमा के एक बड़े आलोचक ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि इस समय के अधिकांश हिंदी फिल्म निर्देशक अगर कोई साहित्य पढ़ते हैं तो वह अंग्रेजी, स्पैनिश या दूसरी भाषा के हैं। हिंदी सिनेमा के अधिकतर स्क्रिप्ट अंग्रेजी में लिखे जाते हैं। संवाद भी प्रायः रोमन लिपि में होते हैं। कहने का अर्थ है कि कुछ अपवाद छोड़ दें तो निर्देशक से लेकर कलाकार तक हिंदी सिनेमा से अपनी कला और पेट की भूख मिटाते हैं, पर हिंदी भाषा से उनका कोई आत्मीय संबंध नहीं हो पाता।

रोमन या देवनागरी । मैं टीवी उद्योग में लगभग डेढ़ दशक से हूं। अपना अनुभव बताता हूं। रियलिटी शोज की अधिकांश एंकरिंग टेलीप्रॉम्पटर देखकर होती है। रोमन में स्क्रिप्ट स्क्रॉल होता है, उसे एंकर पढ़ते हैं। एक नेशनल टीवी चैनल में बतौर स्क्रिप्ट राइटर मैंने जब स्क्रिप्ट देवनागरी में लिखना शुरू किया तो कुछ लोगों ने ना-नुकर किया। उनका कहना था कि रोमन में पढ़ना आसान होता है। लेकिन जब रोमन में स्क्रिप्ट देने लगा, तो देवनागरी के लिए आग्रह आने लगा। इस बार तर्क था कि देवनागरी में कन्फ्यूज़न की गुंजाइश नहीं रहती, रोमन की वजह से कई बार अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

रिश्तों के बदलते समीकरण

- हिंदी साहित्य और सिनेमा का रिश्ता कमजोर हुआ है हाल में
- रोमन में हिंदी से नहीं बनती आत्मीयता
- पुराने दौर में हिंदी की कई अनमोल कृतियां उतरीं परदे पर

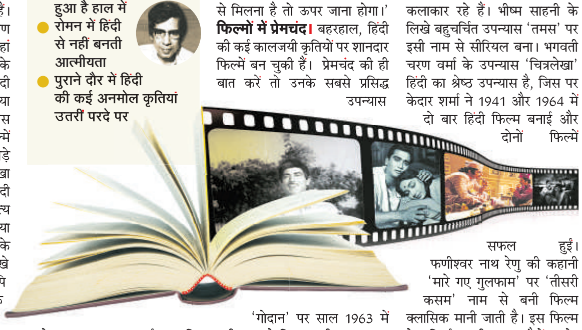

ओरिजिनल राइटर से मीटिंग । टीवी चैनल से जुड़ा एक और प्रसंग याद आ रहा है। एक निर्माता अपने सहायक के साथ सीरियल का प्रॉजेक्ट लेकर एक चैनल के दफ्तर गए। वहां शानदार एसी रूम में एक अंग्रेजीदां मैम बैठी थीं। उम्र निर्माता की बेटी के बराबर होगी, मतलब 25 से 30 के बीच। कहानी सुनकर वह हामी भरतीं तो बात आगे बढ़ती। नैरेशन के बाद उन्होंने अंग्रेजी में प्रश्न किया कि इसके ओरिजनल लेखक कौन हैं? निर्माता ने कहा - प्रेमचंद। वह बोलीं, 'कहानी तो हमको अच्छी लगी, पर मैं चाहती हूं कि इसके ओरिजिनल राइटर के साथ भी एक बार मीटिंग हो जाए।' निर्माता मुश्किल से हंसी रोक कर बाहर आए। फिर सहायक से कहा, 'इससे मैं क्या बताता कि प्रेमचंद से मिलना है तो ऊपर जाना होगा।'

फिल्मों में प्रेमचंद। बहरहाल, हिंदी की कई कालजयी कृतियों पर शानदार फिल्में बन चुकी हैं। प्रेमचंद की ही बात करें तो उनके सबसे प्रसिद्ध उपन्यास 'गोदान' पर साल 1963 में इसी नाम से फिल्म बनी। राजकुमार और कामिनी कौशल उसमें मुख्य भूमिका में थे। इसी फिल्म के लिए गीतकार अंजान ने 'हिया जरत रहत दिन रैन हो रामा' और 'होरी खेलत नंदलाल' जैसे गीत लिखे। प्रेमचंद के लोकप्रिय उपन्यास 'गबन' पर इसी नाम से 1966 में फिल्म बनी, जिसमें सुनील दत्त और साधना का अभिनय था। इस फिल्म के निर्देशक थे कृष्ण चोपड़ा और ऋषिकेश मुखर्जी। प्रेमचंद की कहानी 'शतरंज के खिलाड़ी' पर इसी नाम से फिल्म बनी 1977 में। निर्देशक सत्यजीत रे की इस फिल्म को उस साल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। सत्यजीत रे ने ओमपुरी और स्मिता पाटील को लेकर फिल्म 'सद्गति' भी बनाई।

एक उपन्यास, दो फिल्म । भीष्म साहनी का हिंदी सिनेमा से एक विशेष रिश्ता था। उनके भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के लब्धप्रतिष्ठ कलाकार रहे हैं। भीष्म साहनी के लिखे बहुचर्चित उपन्यास 'तमस' पर इसी नाम से सीरियल बना। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास 'चित्रलेखा' हिंदी का श्रेष्ठ उपन्यास है, जिस पर केदार शर्मा ने 1941 और 1964 में दो बार हिंदी फिल्म बनाई और दोनों फिल्में सफल हुईं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी 'मारे गए गुलफाम' पर 'तीसरी कसम' नाम से बनी फिल्म क्लासिक मानी जाती है। इस फिल्म के निर्माता गीतकार शैलेंद्र थे।

साहित्य से सार्थकता । 1978 की सफलतम फिल्मों में से एक 'पति पत्नी और वो' कमलेश्वर की लिखी कहानी पर थी। वही इस फिल्म के स्क्रीनप्ले लेखक थे। ऐसे और भी नाम दिए जा सकते हैं। यह इस बात का उदाहरण है कि कोई भाषा अगर सिनेमा के सहारे विस्तार पाती है तो सिनेमा भी अपनी भाषा के साहित्य से जुड़कर सार्थकता पाता है।

(लेखक भोजपुरी साहित्य और सिनेमा के जानकार हैं)

www.nbt.in

चलती कार में दिखे जो सपने

सफेद रंग की मिड साइज कार में ड्राइवर की सीट पर वह तनकर बैठा था। कुछ यूं कि पीठ झुकी तो उसका स्वाभिमान भी झुक जाएगा। वह एक टैक्सी एग्रीगेटर कंपनी से जुड़ा था। रोजी-रोटी का जरिया यही टैक्सी थी। महेश नाम का वह शख्स कानपुर से एक फैक्ट्री में काम करने कुछ बरस पहले दिल्ली-NCR आया था। उसने गांव के एक रसूखदार शख्स की दिल्ली-NCR में चलने वाली फैक्ट्री जॉइन कर ली।

महेश ने बताया कि उस नौकरी में बहुत कम पैसे मिलते थे। फैक्ट्री मालिक का बर्ताव भी अच्छा नहीं था। उस नौकरी में महेश कुछ पैसा बचा भी नहीं पाते थे कि घर भेज पाएं। इन हालात से तंग आकर आखिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदलने की सोची। दोस्तों से मशविरा किया। उनमें से एक दोस्त दिल्ली में छोटा खोमचा चलाता था। उसने कुछ पैसों की बचत कर रखी थी। उस दोस्त ने महेश को कहा कि तुम अपना कोई धंधा शुरू करो, मुझसे जितना बन पड़ेगा, मदद करूंगा। दोस्त की इस बात से महेश की बड़ी मुश्किल हल हो गई। वह अपनी कार खरीदकर टैक्सी एग्रीगेटर कंपनियों से जुड़ना चाहते थे। टैक्सी चलाते हुए महेश यह सब मुझे बताए जा रहे थे। मैंने पूछा कि रोज कितने घंटे टैक्सी चलाते हैं? उन्होंने बताया- अभी मैं 26 वर्ष का हूं, इसलिए खूब मेहनत करता हूं। यही तो कमाने का समय है। महेश ने यह भी कहा कि फैक्ट्री में जितना पैसा मिलता था, अब उससे उनकी आमदनी चार से पांच गुना बढ़ गई है। पैसे घर तो भेज ही रहे हैं, अब इरादा एक और टैक्सी लेने का है ताकि आमदनी और बढ़ सके। यह सब बताते हुए वह अपने उस दोस्त को भी याद करते रहे, जिसकी बदौलत वह यह काम शुरू कर पाए थे। दोस्त से जो उधार मिला था, वह उन्होंने साल भर में ही चुका दिया। यह बताते हुए उनकी पीठ थोड़ी और तन गई। जो उनकी खुद्दारी की गवाही दे रही थी। महेश की बातें सुनकर मुझे यह तो पता लग चुका था कि उनकी आंखों में फिलहाल अधिक से अधिक पैसे कमाने का इरादा है। लेकिन ऐसी कहानी तो हर किसी की होती है। ज्यादातर लोग पैसे कमाने की धुन में लगे हैं। वे अपना, घर-परिवार और बच्चों को बेहतर भविष्य देना चाहते हैं।

खुद अपनी आंख से

मृत्युंजय राय

मैंने पूछा- मान लीजिए, आपने एक और कार खरीद ली और उसके बाद कुछ और कारें। लेकिन आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं? महेश बोले- मैं और मेरे दोस्तों का ध्यान अभी सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने पर है। फिर हम लोगों ने कानपुर में अपने गांव के पास एक जमीन का टुकड़ा देख रखा है। मेरे चार करीबी दोस्त हैं, हम रिटायरमेंट साथ में गुजारना चाहते हैं। चारों का घर एक-दूसरे के करीब होगा और खाली समय में दुख-सुख बांटेंगे। महेश का यह सपना अब मेरी आंखों में आ बसा था, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इनसेप्शन के किसी दृश्य की तरह।

चलते-चलते...

एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि ऑक्टोपस के सामने की चार भुजाएं खोज और जांच के लिए उपयोग होती हैं, जबकि पीछे की चार भुजाएं चलने-फिरने में मदद करती हैं। फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी की टीम ने यह खोज की, जो सॉफ्ट रोबोटिक्स के विकास में सहायक साबित हो सकती है। इससे robots का लचीलापन और नियंत्रण बेहतर होगा।

AI Image

कम आबादी बुरी नहीं

बायोलॉजिस्ट Paul Ehrlich ने 1968 में चेताया था कि इंसानी आबादी जिस तरह बढ़ रही है, एक दिन भूख से करोड़ों लोग मरेंगे। हालांकि कई देशों को अब जनसंख्या घटने की चिंता सता रही है, लेकिन क्या यह चिंता करने वाली बात है?

5 पॉइंट

1 कम फर्टिलिटी रेट
दो तिहाई आबादी ऐसे देशों में है, जहां प्रजनन दर- replacement rate 2.1 से नीचे है। दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, जर्मनी जैसे देशों, यहां तक कि चीन को भी आबादी घटने का डर सता रहा है।

2 UN का अनुमान
संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि दुनिया की जनसंख्या 2084 में 10.3 अरब पर पहुंचेगी और फिर घटेगी। लेकिन, मौजूदा ट्रेंड जारी रहे तो 2065 तक जनसंख्या 9.6 अरब पर पहुंचकर गिरना शुरू हो जाएगी।

3 एकदम गिरावट नहीं
आंकड़े जाहिर करते हैं कि आबादी एकदम से नहीं घटने वाली। अब लोग पहले से ज्यादा उम्र तक स्वस्थ रह रहे हैं, उम्र बढ़ गई है और काम करने की क्षमता भी। इसका मतलब कि लेबर फोर्स इतनी जल्दी कम नहीं होगी।

4 बेहतर इस्तेमाल
विकसित देश भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। कम आबादी का मतलब होगा ज्यादा मौके। देश अपनी ह्यूमन कैपिटल का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे, वर्क फोर्स में ज्यादा महिलाएं होंगी।

5 समृद्धि संभव
देशों का सबसे बड़ा डर है कि आबादी घटेगी तो इकॉनमी सुस्त पड़ जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा हो। जापान का उदाहरण है, जहां जीवन स्तर बेहतर हुआ है। हां, कुछ बदलाव करने होंगे। *- प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय*

बंटवारे में सिंधियों ने अपनी भाषा खो दी

*पिछले दिनों रूपा पब्लिकेशन से स्व. सरला कृपलानी की 'सिंधीबानी' नाम से एक किताब आई। यह किताब सिंधी भाषा, संस्कृति, खान-पान का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे लिखने में उनकी बेटी मंजीत कृपलानी ने भी उनकी मदद की थी। सिंधी भाषा व संस्कृति पर NBT के **राहुल पाण्डेय** ने मंजीत कृपलानी से बात की। पेश हैं अहम अंश :*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

मंजीत कृपलानी अपनी मां के साथ

■ आपकी माताजी बंटवारे से ठीक पहले सिंध से इंदौर आईं, फिर जब शादी हुई तो पाकिस्तान वापस गईं, और फिर मुंबई आ गईं। इस कहानी और इसकी वजहों पर कुछ रोशनी डालेंगी?

मेरी मां कराची और मेरे पिता हैदराबाद, सिंध (पाकिस्तान) के थे। मां के दादाजी सिंध में कृषि मंत्री थे। उन्हें आभास हुआ कि देश में कुछ असामान्य हो रहा है और स्थिति सुरक्षित नहीं है। इसलिए, उन्होंने मुंबई और इंदौर के बारे में विचार किया। अंततः उन्होंने इंदौर को चुना और अपनी पत्नी, मेरी मां और उनके बड़े भाई को वहां भेज दिया। मेरी मां ने इंदौर में होल्कर के कॉलेज में दाखिला लिया। मेरे पिता तब मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे थे। उनकी शादी मुंबई में ग्रीस होटल में हुई, जहां अब ताज होटल के टॉवर्स हैं। शादी के बाद वे हैदराबाद, सिंध चले गए। मम्मी कराची की एक आधुनिक लड़की थीं, जो फ्रॉक और टोपी पहनकर इंदौर में साइकिल चलाती थीं। कराची एक कॉस्मोपॉलिटन और आधुनिक शहर था। लेकिन जब वे पाकिस्तान वापस गईं, तो माहौल बदल चुका था। मेरी मां की किताब में एक अध्याय है- 'आया पीर, भागा मीर,' जो इस बदलाव का गवाह है। बाद में मेरे दादाजी मुंबई आ गए, फिर मेरे चाचा आए। मेरे पिता एक अस्पताल चला रहे थे, पासपोर्ट जब्त हो गया था। एक दिन उनके कंपाउंडर ने कहा कि आपको जाना होगा। मैं आपका अस्पताल संभाल लूंगा। खैर, पासपोर्ट वापस मिला, फिर मम्मी के मामा ने ट्रैवल की व्यवस्था की। हम मुंबई आ गए।

■ उन्होंने सिंधी अल्फाबेट के 52 अक्षरों और उनकी सांस्कृतिक महत्ता को कैसे संरक्षित किया? 17 साल तक कहावतें इकट्ठा करने की प्रक्रिया बहुत कठिन रही होगी...

मेरी मां ने सिंधी भाषा के 52 अक्षरों को संरक्षित किया। सिंधी विश्व की सबसे समृद्ध वर्णमालाओं में है। उन्होंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की थी। लेकिन उनकी नानी ने कहा कि उन्हें सिंधी सीखनी चाहिए। मेरी नानी और दादी दोनों सिंधी कहावतों का बहुत उपयोग करती थीं। मुंबई आने के बाद मेरी मां को लगा कि यह दुनिया उनकी कराची और सिंध की पुरानी, प्यार भरी दुनिया से बहुत अलग है। उन्हें अपनी सिंधी संस्कृति की बहुत याद आती थी। इसलिए, उन्होंने बच्चों की कॉपी में इन कहावतों को लिखना शुरू किया। मेरी मां ने कुल 400 कहावतें इकट्ठा कीं। कुछ कहावतें ऐसी थीं, जिनका अंग्रेजी में कोई समकक्ष नहीं मिला। हमने कहा कि इसे देवनागरी लिपि में भी लिखना होगा, ताकि सभी भारतीय इसे समझ सकें। इस प्रक्रिया में 10 साल और लग गए। मैंने भी किताब को संपादित किया। फिर हमने इसे निजी तौर पर प्रकाशित किया और परिवार-मित्रों के बीच बांटा। किताब की लॉन्चिंग के दौरान हुई सामुदायिक बैठक में राम जेठमलानी जैसे लोग शामिल हुए। उन्होंने भी कहा कि यह किताब बहुत मूल्यवान है। किताब में तीन लिपियां हैं- सिंधी, देवनागरी में सिंधी और अंग्रेजी। मसलन, एक कहावत है, पढ़ी पाण ना जाणे, मारे किताबी। यानी नाच ना आवे, आंगन टेढ़ा। या एक और है, थोरे खटिए, घणी बरकत- यानी, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा।

■ सिंध की विविध संस्कृतियों ने भी तो काफी कुछ प्रेरणा दी होगी?

पारंपरिक सिंधी व्यंजन रेगिस्तान से प्रेरित और व्यावहारिक है। ये व्यंजन हम आज भी बनाते हैं। लेकिन दूसरी पीढ़ी को इनकी जानकारी कम है। इसलिए, मम्मी ने किताब में सिंधी व्यंजनों की रेसिपी शामिल कीं, ताकि लोग संस्कृति को जीवित रख सकें। सिंधियों में कोई जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि वर्ग व्यवस्था थी। आमिल लोग शिक्षित और पेशेवर थे। 'आमिल' शब्द उर्दू-फारसी से आया है, जिसका अर्थ है 'खुद को आबाद करने वाला।' हमारे नाम, जैसे कृपलानी, शिवदासानी इस वर्ग से जुड़े हैं। भवानी जैसे कबीले भी थे, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था जैसा कुछ नहीं था।

> **सिंधियों में कोई जाति व्यवस्था नहीं, बल्कि वर्ग व्यवस्था थी। आमिल लोग शिक्षित और पेशेवर थे। 'आमिल' शब्द उर्दू-फारसी से आया है, जिसका अर्थ है 'खुद को आबाद करने वाला।' हमारे नाम, जैसे कृपलानी, शिवदासानी इस वर्ग से जुड़े हैं। भवानी जैसे कबीले भी थे, लेकिन हिंदू जाति व्यवस्था जैसा कुछ नहीं था**

■ सिंधवर्की सिस्टम क्या है और इसके बारे में ट्रांसलेशन के दौरान कौन सी नई बातें पता चलीं?

जब अंग्रेज आए, तो उन्हें सिंध का काम, जैसे कढ़ाई और हस्तशिल्प, बहुत पसंद आया। भाई-बंद वर्ग के व्यापारियों ने इसे विदेशों में बेचना शुरू किया। सिंधवर्की सिस्टम में एक सेठ होता था, जो अपने साथ चार-पांच प्रशिक्षुओं (अप्रेंटिस) को ले जाता था। ये प्रशिक्षु सेठ के साथ काम सीखते थे, जैसे आज की इंटर्नशिप। बाद में यही प्रशिक्षु सेठ बन जाते थे। यह सिस्टम सदियों से आज भी चला आ रहा है। बंटवारे के बाद ये लोग अपने कंधों पर सिंध का काम लेकर साउथ अमेरिका, नाइजीरिया, और अन्य जगहों पर बस गए और बड़े व्यवसायी बने।

■ सिंधियों ने बंटवारे में क्या-क्या खो दिया?

बंटवारे के बाद सिंधियों ने अपनी भाषा खो दी। उनकी संस्कृति, जैसे पहनावा, गीत और परंपराएं, भी धीरे-धीरे लुप्त हो गईं। लोग नहीं जानते कि 'मस्त कलंदर' जैसे गीत सिंधी हैं, जो झूलेलाल से जुड़े हैं। झूलेलाल हमारे प्रमुख देवता हैं। हम उनकी जयंती जिस भव्यता से मनाते थे, वह भी आज कम हो गई है।

रीडर्स मेल

▸ मोटापे का शिकार होता बचपन

महोदय, दुनिया भर में बच्चों के स्वास्थ्य पर जंक फूड का बढ़ता खतरा गंभीर चिंता का विषय बन गया है। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट 'फीडिंग प्रॉफिटः हाउ फूड एन्वायरनमेंट्स आर फेलिंग चिल्ड्रन' में बताया गया है कि पहली बार मोटापे की चपेट में आए बच्चों की संख्या कम वजन वाले बच्चों से अधिक हो गई है। रिपोर्ट के अनुसार, 5 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 18.8 करोड़ बच्चे मोटापे से जूझ रहे हैं, जबकि कम वजन वाले बच्चों की दर 9.2% और मोटे बच्चों की दर 9.4% पाई गई है। वर्ष 2000 में जहां लगभग 13% बच्चे कम वजन के और केवल 3% मोटे थे, वहीं अब यह आंकड़ा उलट चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह बदलाव खानपान में आई गिरावट को दर्शाता है। जंक फूड, मीठे पेय और स्नैक्स की आसान उपलब्धता बच्चों को पोषण से वंचित कर रही है। इससे हृदय रोग, टाइप-2 डायबिटीज और कैंसर का खतरा बढ़ा रहा है। एम्स के अध्ययन से भी सामने आया कि भारत में 5% से 15% बच्चे मोटे हैं।

अमृतलाल मारू 'रवि', ईमेल से

▸ बदलती डिजिटल दुनिया

नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन से उपजे गुस्से ने हालात को बदल कर रख दिया है। नेपाल इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। कई सालों के भ्रष्टाचार, असमानता और नेताओं के विशेषाधिकार के खिलाफ लोगों में विरोध की चिंगारी पहले से धधक रही थी जिसको बढ़ाने में इस बैन ने घी का काम किया। यह घटना दिखाती है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण अब सिर्फ नेपाल ही नहीं बल्कि दुनिया भर की सरकार की साझा रणनीति बनती जा रही है। कई देशों का उदाहरण देखें तो यह साफ है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कई कारणों से नियंत्रित करना अब ग्लोबल इश्यू बनता जा रहा है, जो भविष्य में डिजिटल दुनिया को कहीं न कहीं प्रभावित करेगा।

दीपा सिन्हा, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई): सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगढ़ जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं बाथा 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं बाथा 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं बाथा 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं बाथा 5.00 रुपये।

THE HINDU

द्विअर्थी

भारत को ट्रम्प प्रशासन लगातार अविश्वसनीय लग रहा है

हफ्तों व्यापार की यात्रा के बाद वार्ताकारों को दिल्ली बुलाने के बाद, अमेरिकी प्रशासन ने कहा है कि उसने भारत-अमेरिका संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के लिए वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और भारतीय व्यापार दल को वाशिंगटन आमंत्रित किया है।

एफटीए। यह घोषणा अमेरिका द्वारा एफटीए की घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक टिप्पणियों और सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए पिछले चार महीनों से चल रहे तनाव के थमने का संकेत दिया। गुरुवार को, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो और भारत में श्री ट्रंप के राजदूत सर्जियो गोर ने भी उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच संबंध सुचारू रहेंगे, जल्द ही एक व्यापार समझौते की घोषणा की जाएगी और इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा। व्यापार, वीज़ा, निर्वासन और अन्य मुद्दों पर भारत के ख़िलाफ़ अमेरिका की दंडात्मक कार्रवाइयों के बावजूद, श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होंगे।

ऑपरेशन सिंदूर, युद्ध विराम और पाकिस्तान के साथ उनके व्यवहार पर ट्रम्प की टिप्पणियों के बाद, नई दिल्ली भी आगे बढ़ने के लिए तैयार दिखाई दी, श्री गोयल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिका के साथ भारत की सक्रिय भागीदारी की पुष्टि की। हालांकि, भारत द्वारा रूसी तेल के आयात पर ट्रम्प प्रशासन की अन्य टिप्पणियां इस कार्य में बाधा डाल सकती हैं।

श्री गोर ने कहा है कि भारत द्वारा आयात रोकना अमेरिका की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है, जबकि वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत को अमेरिकी व्यापार समझौते के लिए रूसी तेल खरीदना "बंद करना होगा"। इस बीच, रिपोर्टों से पता चलता है कि श्री गोर ने कहा है कि भारत द्वारा आयात रोकना अमेरिका की "सर्वोच्च प्राथमिकता" है।

ट्रम्प ने व्यक्तिगत रूप से यूरोपीय संघ से भारत और चीन पर "100% प्रतिबंध" लगाने के लिए कहा है ताकि रूस यूक्रेन संघर्ष को रोक सके।

अमेरिका का दोहरा रवैया सरकारी और उद्योग जगत के उन लोगों को निराश करेगा जिन्होंने मोदी-ट्रंप के बीच तनाव कम होने और व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने पर राहत जताई थी। 50% के साथ, भारत और ब्राज़ील को सबसे ज़्यादा अमेरिकी टैरिफ़ का सामना करना पड़ रहा है, और भारतीय कपड़ा-टाइल निर्यातकों को ऑर्डर रद्द होने का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन के अनुसार, टैरिफ़ का मतलब भारत के सकल घरेलू उत्पाद में आधे प्रतिशत का नुकसान हो सकता है, और नौकरियों का नुकसान भी चिंता का विषय होगा। सिद्धांत रूप में, अगर सरकार को रूसी तेल की कीमतों में कटौती की अमेरिकी माँगों पर अंतिम चेतावनी नहीं दी गई होती, तो सरकार उन पर विचार कर सकती थी। हालाँकि, अगर नई दिल्ली ऐसा करने के लिए इच्छुक भी होती, तो वाशिंगटन अपने अशिष्ट शब्दों वाले आदेशों से चुनाव को और भी कठिन बना रहा है।

हालाँकि मोदी सरकार ने पहले ईरानी और वेनेजुएला के तेल आयात को रोकने की अमेरिकी माँगों को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 2025 में रूस के साथ इसे दोहराना ज़्यादा जटिल है। हालाँकि तेल प्रतिबंधों और उच्च टैरिफ़ की लागत वहन की जा सकती है, लेकिन अभी झुकने की लागत और उसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा को होने वाला नुकसान कहीं ज़्यादा भारी लग सकता है।

घोटाला स्थान

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को धोखाधड़ी वाली सामग्री को सक्रिय रूप से हटाना चाहिए

पी डिजिटल अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए असंगत संसाधनों की आवश्यकता हो सकती है, और हैदराबाद का एक हालिया मामला इसकी वजह बताता है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो देखने के बाद, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक निवेश योजना का समर्थन करती दिखाई दीं, एक सेवानिवृत्त डॉक्टर को ₹20 लाख से अधिक का निवेश करने के लिए राजी किया गया। यह वीडियो एक डीपफेक था। धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफॉर्म को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए, इसी तरह के वीडियो, अन्य सार्वजनिक तस्वीरों के साथ, प्रसारित किए गए हैं। इस तरह के घोटाले व्यापक आबादी की सीमित तकनीकी साक्षरता, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग में नियामक कमियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से उत्पन्न डीपफेक के नए उपयोग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सीमित प्रतिक्रिया का फायदा उठाते हैं। स्मार्टफोन की व्यापक पहुँच के बावजूद, कई उपयोगकर्ता अभी भी ऑनलाइन हेरफेर की पहचान नहीं कर पाते हैं, और वे त्वरित लाभ के वादे और लाभ के मनगढ़ंत सबूतों से और भी प्रेरित होते हैं। शिकायतें अक्सर तभी होती हैं जब रिटर्न वापस लेने के प्रयास रोक दिए जाते हैं। जन जागरूकता अभियान असमान और अक्सर सामान्य रहते हैं, जिससे कई लोग धोखाधड़ी के तेजी से परिष्कृत रूपों का उपयोग करने वाले घोटालों की चपेट में आ जाते हैं। भारत सहित अधिकांश देश अभी भी इन्हें पारंपरिक प्रतिभूतियों के समान स्पष्टता के साथ वर्गीकृत नहीं करते हैं, जिससे ऐसा माहौल बनता है जहां धोखेबाज दंड से बचकर काम करते हैं।

कई विदेश में स्थित हैं, पर्स की जटिल श्रृंखलाओं के ज़रिए काम करते हैं, और रातोंरात गायब हो सकते हैं। हालाँकि पुलिस इकाइयों ने क्षमता विकसित कर ली है, लेकिन उनकी पहुँच राष्ट्रीय सीमाओं तक ही सीमित है।

सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म, जो इन घोटालों के प्रमुख माध्यम हैं, अक्सर निष्क्रिय प्रतिक्रिया देते हैं। हालाँकि इंस्टाग्राम जैसी कंपनियाँ घोटालों से बचने और रिपोर्टिंग तंत्र प्रदान करने के बारे में सलाह प्रकाशित करती हैं, लेकिन धोखाधड़ी वाले वीडियो और खाते तब तक सुलभ रहते हैं जब तक उन्हें हटा नहीं दिया जाता। प्लेटफ़ॉर्म की नीतियाँ सक्रिय पहचान के बजाय उपयोगकर्ता की आत्म-सुरक्षा पर ज़ोर देती हैं। इसका मतलब है कि घोटाले इतने लंबे समय तक चलते हैं कि वे पीड़ितों को हटाने के अनुरोधों पर कार्रवाई होने से पहले ही फँसा लेते हैं। वैश्विक सामग्री का पैमाना मैन्युअल समीक्षा को धीमा कर देता है, जबकि स्वचालित मॉडरेशन प्रणालियाँ हेरफेर किए गए वीडियो का पता लगाने में सीमित रहती हैं। चूँकि वे निजी संस्थाएँ हैं जो उपयोगकर्ता की सहभागिता से बचती हैं, इसलिए प्लेटफ़ॉर्म निरंतर निगरानी से बचना पसंद करते हैं जिसमें उपयोगकर्ता के अपलोड की घुसपैठ भरी जाँच शामिल हो सकती है।

नतीजा यह है कि डीपफेक घोटालों को प्रणालीगत कमज़ोरियों के बजाय व्यक्तिगत घटनाओं के रूप में देखा जाता है। तीन उपाय ज़रूरी हैं। पहला, सरकारों को पंजीकरण, प्रकटीकरण और सीमा पार सहयोग के मानक निर्धारित करने चाहिए ताकि धोखाधड़ी वाली योजनाओं के संचालन की गुंजाइश सीमित हो। दूसरा, तकनीकी साक्षरता को सार्वजनिक नीति की प्राथमिकता माना जाना चाहिए। जागरूकता अभियान निरंतर चलने चाहिए और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समर्थित होने चाहिए, न कि पुलिस इकाइयों द्वारा समय-समय पर चलाए जाने वाले अभियानों तक सीमित रहने चाहिए। तीसरा, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को धोखाधड़ी वाली सामग्री को सक्रिय रूप से हटाने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इनके बिना, ऐसे घोटालों में भारी मानवीय और भौतिक लागत आएगी।

आरटीआई का 'सूचना देने से इनकार करने के अधिकार' में परिवर्तन

Shailesh Gandhi

एक पूर्व केंद्रीय है जानकारी आयुक्त

टी सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि लोकतंत्र में, जिसे "जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए" शासन के रूप में परिभाषित किया गया है,

"जनता", सरकार के पास मौजूद सभी जानकारी स्वाभाविक रूप से नागरिकों की है। सरकार जनता की ओर से इस जानकारी के संरक्षक के रूप में कार्य करती है। नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उन्हें वैध बनाते हैं, जो बदले में नौकरशाही को वैध बनाते हैं।

इसलिए, आरटीआई के तहत डिफ़ॉल्ट मोड यह है कि सभी जानकारी नागरिकों के साथ साझा की जानी चाहिए।

हालाँकि, इस अधिनियम में राष्ट्रीय संप्रभुता जैसे कुछ हितों की रक्षा के लिए हमेशा विशिष्ट छूट शामिल रही हैं। एक महत्वपूर्ण छूट अधिनियम की धारा 8(1)(j) है, जो "व्यक्तिगत जानकारी" से संबंधित है।

मूल धारा 8(1)(जे) एक विस्तृत थी सूचना के अधिकार और व्यक्तिगत निजता के बीच संतुलन बनाने के लिए बनाया गया यह प्रावधान। इसमें यह प्रावधान था कि अगर किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी का सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं है या वह "किसी व्यक्ति की निजता पर अनुचित आक्रमण" करती है, तो उसे देने से इनकार किया जा सकता है, जब तक कि उसके प्रकटीकरण में व्यापक जनहित न हो।

इस मूल प्रावधान का एक प्रमुख पहलू एक प्रावधान था जो एक अग्निपरीक्षा है। इसमें कहा गया था: "यह प्रावधान है कि जो सूचना संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं की जा सकती, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।" इसका अर्थ यह था कि यदि संसद या राज्य विधानमंडल को सूचना देने से इनकार नहीं किया जा सकता, तो उसे किसी आम नागरिक को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

इसका उद्देश्य सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को यह समझने में मार्गदर्शन देना था कि क्या सार्वजनिक गतिविधि, निजी गतिविधि या गोपनीयता का उल्लंघन है, विशेष रूप से "गोपनीयता" को परिभाषित करने में कठिनाई को देखते हुए (यहां तक कि न्यायमूर्ति के.एस.

पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने स्वीकार किया कि यह मामला-दर-मामला आधार पर विकसित होगा। सरकार अपने कर्तव्यों के सामान्य क्रम में नियमित रूप से किसी व्यक्ति से जानकारी एकत्र करती है, और ऐसी जानकारी को आमतौर पर गोपनीयता का उल्लंघन नहीं माना जाता है और इसलिए इसे साझा किया जाना चाहिए।

हालाँकि, अगर इससे उसकी निजता का हनन होता है, तो इसे नियमित रूप से नहीं लिया जाना चाहिए। सूचना के मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होने चाहिए। यहाँ, निजता से संबंधित केवल दो शब्द हैं: 'शालीनता' या 'नैतिकता'। यदि प्रकटीकरण से शालीनता या नैतिकता का उल्लंघन होता है, तो इसे संसद और नागरिकों को प्रदान नहीं किया जाना चाहिए।

'व्यक्तिगत जानकारी' की अस्पष्टता डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम, आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में संशोधन करता है - धारा 8(1)(जे) में एक बड़ा बदलाव, जिससे इसकी लंबाई घटकर छह शब्द रह जाती है। यह महत्वपूर्ण संक्षिप्तीकरण अधिकांश सूचनाओं को अस्वीकार करना आसान बना देता है। मुख्य चिंता "व्यक्तिगत जानकारी" की व्याख्या को लेकर ही है।

नागरिकों और मीडिया को चुनौती देने की जरूरत है

डिजिटल पर्सनल डेटा सुरक्षा

अधिनियम में संशोधन अधिकार की धारा 8(1)(जे)

जानकारी

(आरटीआई) अधिनियम

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है, एक संशोधित आरटीआई अधिनियम के तहत "व्यक्तिगत जानकारी" की स्पष्ट और सुसंगत परिभाषा, विशेष रूप से नए डेटा संरक्षण कानून के साथ इसके संबंध में। दो परस्पर विरोधी विचार हैं: पहला है प्राकृतिक व्यक्ति व्याख्या: एक दृष्टिकोण यह मानता है कि "व्यक्ति" को उसके सामान्य अर्थ में समझा जाना चाहिए, जो एक "सामान्य व्यक्ति" या प्राकृतिक व्यक्ति को संदर्भित करता है। दूसरा है डीपीडीपी विधेयक परिभाषा। दूसरा, समान रूप से मान्य दृष्टिकोण, "व्यक्ति" की व्याख्या डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक में परिभाषित के रूप में करता है। डीपीडीपी विधेयक की परिभाषा विस्तृत है, जिसमें "हिंदू अविभाजित परिवार, एक फर्म, एक कंपनी, [और] व्यक्तियों और राज्य का कोई भी संघ" शामिल है।

यदि बाद वाली परिभाषा को अपनाया जाता है, तो "लगभग सब कुछ व्यक्तिगत जानकारी है"। सूचना का एक बड़ा हिस्सा किसी व्यक्ति से संबंधित साबित हो सकता है। इस प्रकार, कानून अधिकांश सूचनाओं को अस्वीकार करने का एक तरीका प्रदान करता है। आरटीआई को सूचना अस्वीकार करने के अधिकार में बदल दिया गया है। यह एक 'आरडीआई' बन जाता है। यह व्यापक व्याख्या पारदर्शिता की भावना के लिए एक बुनियादी खतरा है। जटिलता को और बढ़ाते हुए, डीपीडीपी विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जो संघर्ष के मामलों में अन्य सभी कानूनों को दरकिनार कर देता है। यह चिंताजनक है क्योंकि डीपीडीपी विधेयक उल्लंघनों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है जो ₹250 करोड़ तक हो सकता है।

इससे पीआईओ के लिए एक असहनीय स्थिति पैदा हो जाती है। अधिकांश सरकारी सूचना अब डिजिटल हो गई है, इसलिए पीआईओ (भारतीय मूल के व्यक्ति) इस बात से आशंकित हैं कि सूचना देने में हुई गलती गंभीर वित्तीय दंड का कारण बन सकती है। यह डर पीआईओ को सूचना देने के बजाय सूचना देने से इनकार करने की गलती करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, जिससे प्रभावी रूप से "सूचना देने से इनकार करने का अधिकार" पैदा होगा। डीपीडीपी अधिनियम को आरटीआई अधिनियम का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, हालाँकि अन्य अधिनियमों का अतिक्रमण करना स्वीकार्य हो सकता है।

भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना इन संशोधनों के व्यावहारिक निहितार्थ सार्वजनिक जवाबदेही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए गंभीर हैं। इस लड़ाई में पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण हथियार है, खासकर जब अन्य भ्रष्टाचार-विरोधी तंत्र अप्रभावी साबित हुए हों।

पहला, सार्वजनिक निगरानी का नुकसान। नागरिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध सर्वोत्तम निगरानीकर्ता हैं। अगर सूचना देने से इनकार किया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र बुरी तरह प्रभावित होता है। भारत की बहुस्तरीय सरकारी एजेंसियाँ, जैसे सतर्कता विभाग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और लोकपाल, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल रही हैं।

दूसरा है आवश्यक जानकारी से इनकार। "व्यक्तिगत जानकारी" के व्यापक दायरे का मतलब है कि सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण दस्तावेज़ भी रोके जा सकते हैं—किसी नागरिक की अपनी संशोधित मार्कशीट को "व्यक्तिगत" कहकर अस्वीकार किया जा सकता है। "भूत कर्मचारियों" और "भूत कार्ड" से निपटने के लिए पेंशन लाभार्थियों का विवरण साझा करने वाले राजस्थान के उदाहरण का अब अंत हो जाएगा। एक साधारण आदेश भी

किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किसी भी जानकारी को "व्यक्तिगत जानकारी" मानकर अस्वीकार किया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 90% से ज़्यादा जानकारी अस्वीकार की जा सकती है।

तीसरा है बेलगाम भ्रष्टाचार। संशोधन "भ्रष्ट होना आसान बना देता है"। फर्जी कर्मचारियों या भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़ी जानकारी "व्यक्तिगत जानकारी" के अंतर्गत आती है। इसे छिपाया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार 'फलता-फूलता रहेगा और बेरोकटोक चलता रहेगा'।

यद्यपि आरटीआई अधिनियम (धारा 8(2) में "व्यापक जनहित" खंड अभी भी मौजूद है, लेकिन इसका व्यावहारिक अनुप्रयोग अत्यंत दुर्लभ और कठिन है।

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए "व्यापक जनहित" प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। यह आवश्यकता केवल तभी लागू होती है जब सूचना पहले से ही छूट प्राप्त हो।

ऐसे 1% से भी कम आदेश होंगे जहाँ छूट स्वीकार की जाती है, लेकिन प्रकटीकरण व्यापक जनहित पर आधारित होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी अधिकारी के लिए यह एक बेहद चुनौतीपूर्ण निर्णय होता है, जिसमें प्रकटीकरण के व्यापक जनहित के मुकाबले किसी व्यक्ति को होने वाले संभावित नुकसान को तौलना होता है।

इसलिए, संशोधन के बाद पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस खंड पर निर्भर रहना काफी हद तक निरर्थक है।

उदासीनता और कार्रवाई का आह्वान: इन संशोधनों की गंभीरता के बावजूद, पिछले आरटीआई बदलावों, जैसे कि आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल से संबंधित बदलावों की तुलना में, इन पर जनता और मीडिया में कोई खास विरोध नहीं देखा गया है। यह उदासीनता इस संशोधन के "डेटा सुरक्षा की आड़ में" होने के कारण हो सकती है, जिससे यह आम नागरिक के लिए कम ख़तरनाक लगता है। एक आम धारणा यह भी है कि किसी व्यक्ति की अपनी जानकारी, चाहे उसकी प्रासंगिकता कुछ भी हो, साझा नहीं की जानी चाहिए, जिससे 'अहंकार हावी हो जाता है' वाली मानसिकता को बढ़ावा मिलता है।

डीपीडीपी विधेयक की धारा 8(2) और 44(3) "हमारे लोकतंत्र पर एक बहुत ही मौलिक प्रतिगमन" और "हमारे मौलिक अधिकारों पर एक बहुत ही मौलिक हमला" है।

चार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला, मीडिया और नागरिक सहभागिता - देश भर में व्यापक सार्वजनिक चर्चा होनी चाहिए।

दूसरा, राजनीतिक जवाबदेही - नागरिकों को राजनीतिक दलों से उनके चुनावी घोषणापत्रों में यह आश्वासन मांगना चाहिए कि इन संशोधनों को वापस लिया जाएगा। तीसरा, जनमत - मीडिया के सहयोग से मज़बूत जनमत का निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा, गंभीरता की पहचान - यह मुद्दा किसी भी अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बहस जितना ही ध्यान देने योग्य है, क्योंकि सूचना के मौलिक अधिकार से समझौता किया जा रहा है।

अगर नागरिक चुप रहेंगे, तो वे अपनी आज़ादी और लोकतंत्र को ख़तरे में डाल देंगे। सामूहिक कार्रवाई से इन बदलावों को उलटा जा सकता है।

भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या नागरिक और मीडिया आरटीआई अधिनियम की अखंडता को बचा सकते हैं।

संपत्ति के अधिकार, आदिवासी और लैंगिक समानता का अंतर

शालिनी साबू

जूनियर फेलो हैं, प्रधानमंत्रियों संग्रहालय और पुस्तकालय, तीन मूर्ति हाउस, नई दिल्ली

मैं 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए हुए एक महीने से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है।

भारत की मूल आबादी के अधिकारों पर विचार करें। 17 जुलाई, 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद यह प्रस्ताव और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। राम चरण एवं अन्य बनाम सुखराम एवं अन्य में, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पैतृक संपत्ति में बेटियों के बहिष्कार को समानता के उनके मौलिक अधिकार का हनन माना। इस प्रकार, लैंगिक समानता के लेंस के माध्यम से एक आदिवासी महिला के संपत्ति अधिकारों के मुद्दे को देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गहरे लैंगिक अन्याय का विषय है कि अधिकांश आदिवासी महिलाओं (पूर्वोत्तर को छोड़कर जहाँ कुछ जनजातियों में मातृवंशीय प्रथा है) के पास पैतृक संपत्ति में उन्हें वैधानिक अधिकार देने वाले कानून नहीं हैं।

समान हिस्से की दलील इस मामले में, अपीलकर्ता-वादी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला धैया के कानूनी उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने अपने नाना, भज्जू उर्फ भजन गोंड की संपत्ति का विभाजन मांगा था।

उन्होंने दावा किया कि उनकी माँ (छह बच्चों में से एक - पाँच बेटे और एक बेटी), बराबर के हिस्से की हक़दार थीं। वाद का कारण अक्टूबर 1992 में तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने बँटवारा करने से इनकार कर दिया। अपीलकर्ता-वादी ने मुकदमे की संपत्ति के स्वामित्व और बँटवारे की घोषणा की माँग करते हुए निचली अदालत का रुख किया, जिसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि गोंड जनजाति में ऐसी कोई प्रथा नहीं है जहाँ महिला उत्तराधिकारियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाता हो।

प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के बाद और ट्रायल कोर्ट, फिर याचिका के समक्ष आया

यह गहरे लैंगिक अन्याय का मामला है कि अधिकांश आदिवासी महिलाओं को पैतृक संपत्ति में वैधानिक अधिकार नहीं हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय। जहाँ तक अपीलकर्ता-वादी की इस दलील का सवाल है कि उन्होंने हिंदू परंपराओं को अपनाया है और इसलिए उन्हें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार ये अधिकार दिए जाने चाहिए, यह माना गया कि चूँकि अभिलेखों में कोई साक्ष्य नहीं था, इसलिए निचली अदालत और प्रथम अपीलीय अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया था। हालाँकि, इसने दहिया के कानूनी उत्तराधिकारियों को संपत्ति में बराबर का हिस्सा देते हुए कहा कि रीति-रिवाजों की आड़ में महिला उत्तराधिकारी को संपत्ति में अधिकार देने से इनकार करने से लैंगिक भेदभाव और बढ़ेगा - जिसे कानून को खत्म करना चाहिए।

मधु किश्वर एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य (1996) मामले में , एक याचिका में बिना वसीयत के उत्तराधिकार के मामले में महिला और पुरुष आदिवासी सदस्यों के बीच समानता का मुद्दा उठाया गया था। यह प्रथागत कानूनों से संबंधित था जो महिलाओं को भूमि या संपत्ति के उत्तराधिकार से वंचित करते थे। सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के फैसले ने समानता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले प्रावधानों को रद्द करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इससे मौजूदा कानून में अव्यवस्था पैदा होगी।

अनुसूचित पाँच क्षेत्र वाले राज्यों के कानून: विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में, अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी अपने प्रथागत कानूनों द्वारा शासित होते हैं। खेती में महिलाओं का योगदान पुरुषों की तुलना में अधिक होने के बावजूद, अनुसूचित पाँच क्षेत्र वाले राज्यों (जिनमें छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा भी शामिल हैं) में प्रचलित कोई भी आदिवासी प्रथागत कानून महिलाओं को पैतृक संपत्ति में भूमि का उत्तराधिकार अधिकार नहीं देता है। अखिल भारतीय कृषि जनगणना 2015-16 की रिपोर्ट दर्शाती है कि अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में से 16.7% के पास भूमि है, जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुषों (83.3%) के पास भूमि है।

यह भी तर्क दिया जाता है कि आदिवासी समाज में ज़मीन एक सामुदायिक संपत्ति है, जहाँ कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं हो सकता। लेकिन, ऐसा कम ही होता है कि

जनजातीय भूमि की बिक्री या अधिग्रहण से प्राप्त धनराशि गांवों की ग्राम सभा को जाती है।

आदिवासी महिलाओं के गैर-आदिवासी पुरुषों से विवाह करने और भूमि अधिग्रहण का भय महिलाओं को भूमि उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित करने का एक और कारण है। इस तथ्य को समझना ज़रूरी है कि वन भूमि की तरह गैर-आदिवासियों को हस्तांतरित होने के बावजूद भूमि की प्रकृति स्वदेशी ही रहती है।

किसी भी कस्टम को मापदंडों की परीक्षा पास करनी होगी जैसे कि प्राचीनता, निश्चितता, निरंतरता, तर्कसंगतता और सार्वजनिक नीति के अनुरूपता, ताकि उसे कानून में बदला जा सके। न्यायालय इनके आधार पर किसी प्रथा की वैधता की पुष्टि कर सकता है। प्रभा मिंज, पुत्री स्वर्गीय सरन लिंडा बनाम (ए) मामले में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हुई।

मार्था एक्का पत्नी स्वर्गीय अजीत एक्का (2022), जहां झारखंड उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक रूप से राज्य में उरांव जनजाति की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के पक्ष में फैसला सुनाया क्योंकि प्रतिवादी यह साबित करने में विफल रहा कि झारखंड के उरांव समुदाय में कोई ऐसी प्रथा थी जहां बेटियों को पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार के अधिकार से लगातार वंचित किया गया है।

एक अलग अधिनियम की मांग। सर्वोच्च न्यायालय ने 9 दिसंबर, 2022 को कमला नेती (मृत) तृतीय वर्ष बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी मामले में आदिवासी महिलाओं के संपत्ति अधिकारों पर एक सशक्त रुख अपनाया, जो आदिवासी महिलाओं में संपत्ति अधिकारों में लैंगिक समानता की शुरुआत का जश्न मनाने की दिशा में उठाए गए शुरुआती कदमों में से एक था। यदि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2(2) आदिवासी महिलाओं को इसके दायरे से बाहर रखती है, तो आदिवासियों के लिए एक अलग आदिवासी उत्तराधिकार अधिनियम क्यों नहीं बनाया गया? हिंदुओं और ईसाइयों की तर्ज पर आदिवासी कानूनों का संहिताकरण भी इस मुद्दे को काफी हद तक सुलझाने में मदद कर सकता है।

द टटर्सटूदएडिटर

नेपाल संभवतः अपने सबसे बुरे राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। युवाओं के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, कर्फ्यू और बाधित सेवाएँ नाज़ुक स्थिति को दर्शाती हैं। भारत को शांति, लोकतंत्र और शीघ्र चुनावों का समर्थन करते हुए सावधानीपूर्वक कूटनीति अपनानी चाहिए, और किसी भी तरह के हस्तक्षेप की आशंका से बचना चाहिए। नेपाल में स्थिरता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

हम्माद नूरी, मुंबई

भारत को इस बात से सावधान रहना चाहिए नेपाल में - वास्तव में, पड़ोस में - हो रहे घटनाक्रमों पर चिंता व्यक्त की। नई दिल्ली को यथासंभव सभी सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेपाल का प्रतिनिधित्व एक लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। वर्तमान परिदृश्य में मुद्दों को सुलझाने के लिए सेना कोई इकाई नहीं है।

मानस अग्रवाल, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश

'जेन जेड' के नेतृत्व में हो रहे विरोध प्रदर्शन, जवाबदेही की मांग कर रही एक बेचैन पीढ़ी का संकेत हैं। हालांकि यह अनिश्चित है कि इसे सफलता मिलेगी या नहीं, लेकिन यह आंदोलन सफल नहीं हो रहा है। महत्वहीन। इसने युवाओं की उस शक्ति को दर्शाया है जिसमें वे एक ऐसे भविष्य की मांग कर सकते हैं जिसमें वे विश्वास कर सकें। यह ज़रूरी है कि इस प्रकार की 'ऊर्जा' को पोषित किया जाए।

Vaibhav Kochar, Ludhiana, Punjab

इन विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व 'जेन ज़ेड' ने किया, यानी 'डिजिटल नेटिव्स' की वह पीढ़ी जो इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ पली-बढ़ी है। उपेक्षापूर्ण, आत्मसंतुष्ट और यहाँ तक कि नींद में चलने वाली सरकार को जल्द ही सचेत होना पड़ेगा। बाद में नहीं। जब विरोध के रास्ते बंद कर दिए जाते हैं या उन पर रोक लगा दी जाती है, तो जनता अपनी भड़ास निकालती है - और वह भी एक विस्फोट के रूप में।

आर. थॉमस पॉल, बेंगलुरु

यह विडंबना ही है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जिन्होंने इजरायल के प्रबल समर्थक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए तुरंत नामित किया था, ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि श्री ट्रंप का 'नोबेल लक्ष्य' धराशायी हो जाए। कतर पर इज़राइल के हमले के बाद। यह अमेरिका के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकता है क्योंकि इससे अरब देशों के बीच पश्चिम एशिया में अमेरिका की सार्थक भूमिका निभाने की क्षमता पर विश्वास का एक और संकट पैदा हो सकता है। यह स्पष्ट है कि लोकतंत्रों में घरेलू राजनीतिक ज़रूरतों को विदेश नीति के कदमों से जोड़ने वाली हानिकारक प्रवृत्तियाँ घुस आई हैं। इसे समाप्त करने की आवश्यकता है।

Girija Kumar, चेन्नई

'मद्रास निर्मित'

मैं इसका अनुसरण कर रहा हूँ 'मेड ऑफ चेन्नई' कॉलम - विभिन्न क्षेत्रों में मशहूर हस्तियों और उपलब्धि हासिल करने वालों की पुरानी यादों पर।

लेकिन अपनी स्थापना के बाद से द हिन्दू के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक इसके पाठक हैं, जो अपने समर्थन में अडिग रहे हैं।

शायद यह दैनिक समाचार पत्र पाठकों और मद्रास के विकास के बारे में उनकी यादों को प्रस्तुत कर सकेगा।

ए.वी. नारायणन, चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 13 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

मॉरीशस के साथ सहयोग

भारत और मॉरीशस ने फैसला किया है कि अब दोनों देश स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की दिशा में संजीदगी से बढ़ेंगे। वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और मॉरीशस महज पार्टनर नहीं, बल्कि परिवार हैं। पिछले साल मॉरीशस में यूपीआई और रूप कार्ड की शुरुआत हुई थी और अब दोनों देशों ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने का मन बनाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा मॉरीशस की संप्रभुता के पक्ष में रहा है, और मुक्त, खुला, सुरक्षित, स्थिर तथा समृद्ध हिन्द महासागर हमारी साझी प्राथमिकता में रहा है। मॉरीशस, भारत की पड़ोसी प्रथम और विजन महासागर का एक अहम स्तंभ है। इस हिन्द महासागरीय देश के साथ सात करार हुए हैं।

करीब छह हजार करोड़ रुपये के विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की गई है ताकि मॉरीशस अपने बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर सके। माना जा रहा है कि पैकेज से मॉरीशस में रोजगार की स्थिति बेहतर होगी। भारत की इच्छा है कि मॉरीशस इतना समृद्ध हो ताकि हिन्द महासागर में अपनी समुद्री स्थिति को खासी मजबूत कर सके। भारत और मॉरीशस के बीच उनके नागरिकों के बीच सहोदर भाव से खास मजबूती मिलती है। भारतीय संस्कृति का यह देश विस्तार सरीखा दिखलाई पड़ता है। वहां की आबादी का बड़ा हिस्सा उन लोगों का है, जिनके पूर्वज उन्नीसवीं शताब्दी में बिहार और उत्तर प्रदेश से 'गिरमिटिया' श्रमिक के रूप में इस पूर्वी अफ्रीकी देश पहुंचे थे। वहां उन्हें कृषि खासकर ईख की खेती में लगाया गया। मॉरीशस की प्रगति में भारतीय मूल के इन लोगों ने उल्लेखनीय योगदान दिया। बाद के कालखंड में इनके वंशज मॉरीशस में नीति-नियंता की भूमिका में उभरे। देश की बागडोर उन्होंने संभाली। मौजूदा प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के पूर्वज भी भारत से वहां पहुंचे थे। आज भारतीय मूल के मॉरीशस के नागरिक दोनों देशों को खास आयाम दे रहे हैं। भारत ने शुरू से ही मॉरीशस के प्रति सहयोगी भाव रखा है। उसे आर्थिक सहयोग के मामले में प्राथमिकता पर रखा है। भारत तकनीकी लिहाज से मजबूत आधार रखता है, और मॉरीशस को सहयोग में तकनीकी पहलू को अच्छे से जोड़ सकता है। स्वास्थ्य भी ऐसा ही एक क्षेत्र है, जिसमें भारत की प्रगति और उपलब्धियों से मॉरीशस लाभान्वित हो सकता है।

न हों पक्षपाती

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों को राज्य सरकारों के लिए सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों वाली राष्ट्रपति संदर्भ पीठ द्वारा केरल सरकार से सहमति व्यक्त की गई कि दोनों संवैधानिक प्राधिकारियों के बीच कार्य संबंध सहयोगात्मक होने चाहिए। केरल ने अदालत को बताया कि राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत आठ विधेयक सात से तेईस महानों तक लंबित रहे। दस दिन तक दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने अपना फैसला बहरहाल सुरक्षित रख लिया। केंद्र की तरफ से जवाब में कहा गया कि अनुच्छेद 200 के प्रावधान एक के तहत लौटाए गए विधेयक के साथ राज्यपाल का संदेश पुनर्विचार के दायरे को तय करेगा जिस पर मूल विधेयक संख्या अंकित होगी। आरोप है कि वे बगैर संदेश के इसे अंतहीन तौर पर रोके रहते हैं। बेशक, राज्यपाल को संवैधानिकता की

जांच करने का अधिकार है, मगर अधिनियम बन जाने के बाद भी यह न्यायिक समीक्षा के लिए खुला होगा। राज्यपाल अक्सर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करते हैं। इन आरोपों-प्रत्यारोपों पर लगाम कसना टेढ़ी खीर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत अदालत से मांगी गई राय के बाद यह बहस तेज हो गई। मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा कि न्यायिक सक्रियता को न्यायिक आतंकवाद में नहीं बदलना चाहिए। यदि लोकतंत्र का एक पक्ष कर्त्तव्य निर्वहन करने में विफल रहता है तो संविधान का संरक्षक न्यायालय शक्तिहीन होकर निष्क्रिय नहीं रह सकता। कहना गलत नहीं कि राज्यपाल के काम पर शीर्ष अदालत का परमादेश जारी करना उचित नहीं ठहराया जा सकता। मगर विपक्षी दलों की सरकारों की असहमतियों की सुनवाई की अनदेखी भी न्यायोचित नहीं है। राज्यपाल विधानमंडल का अंग है, जिनकी सहमति विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून बनाने में राज्यपालों की सहमति महत्त्वपूर्ण चरण है पर सैद्धांतिक सहमति की आवश्यकता भी कम महत्त्व नहीं रखती। उन परिस्थितियों को लेकर व्यवस्था देनी जरूरी है, जहां स्थिति खतरनाक हो रही हो या मध्य मार्ग स्पष्ट होता न दिख रहा हो। राज्यपालों की भूमिका रोजमर्रा के प्रावधानों में महत्त्व नहीं रखती। उन्हें नियंत्रण के साथ संतुलन बनाने के प्रति निष्पक्ष, चैतन्य और सतर्क दिखना चाहिए।

कटाक्ष/ कबीरदास

अहो रूपम्, अहो ध्वनिः

अब क्या ये विरोधी भगवा परिवार वालों की घर के अंदर की बातों में भी टांग अड़ाएंगे? मोदी जी ने मोहन भागवत के जन्म दिन पर लेख लिख कर, जरा सी बधाई क्या दे दी, भाई लोग उसमें भी इरादे और मंसूबे खोज लाए हैं। कहते हैं कि यह तो भागवत जी को मक्खन लगाए जाने का मामला है। मोदी जी को डर लग रहा है कि हफ्ते भर बाद, उनके जन्म दिन पर भागवत जी कहीं उन्हें पचहत्तर साल वाला शॉल न ओढ़ा दें; बधाई और विदाई, एक साथ। पचहत्तर साल वाले शॉल से डर सब को लगता है, गला सब का सूखता है!

सब झूठ। यह सब विपक्ष वालों की कोरी अफवाह है। मोदी जी के भागवत जी का प्रशस्ति गान करने का, पचहत्तर साल वाले शॉल का कुछ लेना-देना ही नहीं है। वास्तव में पचहत्तर साल वाले शॉल का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। उल्टे, भागवत जी ने तो दो हफ्ते पहले ही साफ कर दिया था कि वह किसी पचहत्तर साल वाली शॉल को नहीं जानते। उन्होंने पहले जो कहा था, वह तो सिर्फ मजाक था। वैसे भी ऐसी तो कोई पचहत्तर साल वाली शॉल बनी ही नहीं है जो मोदी जी को ओढ़ाई जा सकती हो और उन्हें भी। पचहत्तर साल वाली शॉल तो छोड़िए, उनके लिए तो पचहत्तर की गिनती भी नहीं बनी है। पचहत्तर की गिनती आएगी ही नहीं; चौहत्तर पर ही रुकी रह जाएगी या आगे टाप कर आगे निकल जाएगी। दोनों भाई न पचहत्तर के होंगे और न शॉल ओढ़ने का दिन आएगा। मोदी जी पर तो वैसे भी उम्र का कोई कायदा लागू नहीं होता है, न पचहत्तर का और न पचासी का। उम्र की गिनती उन पर लागू होती है, जो बायोलॉजीकल हों। नॉन-बायोलॉजीकल की भी उम्र होती है क्या? हजारों-लाखों साल की कोई गिनती कर सकता है क्या? पचहत्तर साल पर अवतार को कोई रिटायर्ड करता है, क्या?

सिंपल सी चीज है-जन्म दिन की बधाई। मोदी जी हरेक को देते हैं, दुश्मनों तक को। भागवत जी को भी दी है। जब ब्याह होगा, तो बधाए भी गाए ही जाएंगे। बधाए गाने का भागवत जी का नंबर भी जल्द आएगा। भागवत जी चाहें तो पद्य का भी सहारा ले सकते हैं-नरेंदर तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, भागवत कवि बन जाए सहज संभाव्य है!

अनमोल वचन

जिनका चित्त विकार उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों में भी अस्थिर नहीं होता, वे ही सच्चे धीर पुरुष होते हैं।
-कालिदास

बदलाव की आहट

नक्सली क्षेत्र

योगेश कुमार गोयल

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 11 सितम्बर को सुरक्षा बलों द्वारा किए गए ऑपरेशन में बड़े पैमाने पर सफलता हासिल हुई है, जिसमें सीसी सदस्य मनोज उर्फ बालकृष्ण सहित दस दुर्दांत नक्सली मारे गए। यह मुठभेड़ शोभा और मैनपुर थाना क्षेत्र के जंगलों में हुई जिसमें एक करोड़ के इनामी तेलंगाना के वारंगल निवासी 58 वर्षीय मोडेम बालकृष्ण के मारे जाने की पुष्टि स्वयं एसपी निखिल राखेचा ने की। नक्सलियों के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई के महत्त्व को समझने के लिए हालिया महीनों में छत्तीसगढ़ और देश भर में नक्सलियों के खिलाफ हुए अभियानों की समीक्षा जरूरी है।

मई माह में नारायणपुर-अबूझमाड़ क्षेत्र में लगभग पचास घंटे चले ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने डेढ़ करोड़ के इनामी और माओवादियों के महासचिव नंबाला केशव उर्फ बसवराजू को मार गिराया था। उसकी मौत के बाद नक्सलियों ने लगभग छह करोड़ के इनामी देवजी उर्फ संजीव उर्फ पल्लव को संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया जबकि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सचिव पद की जिम्मेदारी भीषण माओवादी कमांडर माडवी हिडमा को दी गई। देवजी, जो करीमनगर (तेलंगाना) के दलित परिवार में जन्मा, बीते साढ़े तीन दशकों से नक्सलवाद से जुड़ा है। उस पर देश के विभिन्न राज्यों में छह करोड़ रुपये से अधिक का इनाम घोषित है। इसी प्रकार माडवी हिडमा, बस्तर के बीजापुर जिले के पुवर्ती गांव का निवासी, नक्सलियों की रणनीति और बड़े हमलों के लिए कुख्यात है।

बीते डेढ़ वर्ष में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने 453 नक्सलियों को मार गिराया है जबकि 1602 ने आत्मसमर्पण किया और 1591 को गिरफ्तार किया गया। औसतन रोजाना छह नक्सलियों को पकड़ा जा रहा है, और एक से ज्यादा को मुठभेड़ में मार गिराया जाता है। गृह मंत्रालय के अनुसार, 2024 में देश भर में सुरक्षा बलों ने 290 नक्सलियों को मार गिराया, 1090 को गिरफ्तार किया, और 881 ने आत्मसमर्पण किया। 2025 के पहले चार महीनों में ही 148 माओवादी ढेर हुए, 104 की गिरफ्तारी हुईं और 164 ने आत्मसमर्पण किया। अकेले बस्तर क्षेत्र में अनेक बड़े ऑपरेशन हुए हैं, जिनमें 29 नक्सलियों को कांकेर जिले (16 अप्रैल 2024) में, 31 को बीजापुर जिले (9 फरवरी 2025) में मारा गया।

सुरक्षा अभियानों की आक्रामक रणनीति के चलते नक्सली संगठनों की रीढ़ टूट रही है, और उनका जनसमर्थन तेजी से कमजोर पड़ रहा है। आंकड़ों की गणना करें तो पिछले

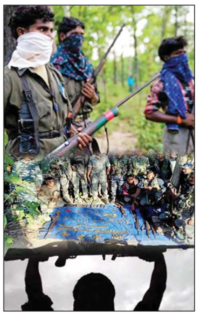

एक वर्ष में देश भर में सुरक्षा अभियानों के दौरान कुल 357 नक्सलियों की मृत्यु हुई जिनमें 136 महिला नक्सली, चार केंद्रीय कमेटी सदस्य और 15 राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं। दंडकारण्य क्षेत्र में ही 281 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा जैसे राज्यों की जमीनी हकीकत यह है कि अब माओवादी सीमित क्षेत्रों में छिपे हैं जबकि पहले देश के 38 जिले पूरी तरह नक्सल प्रभावित थे, अब यह संख्या घट कर छह जिलों तक सीमित रह गई है।

केंद्र सरकार का उद्देश्य मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त करना है। इसके लिए दोहरी नीति अपनाई जा रही है-सख्त सुरक्षा कार्रवाई और बहुआयामी विकास योजनाएं। छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए देश की सबसे बेहतर पुनर्वास नीति लागू की गई है, तीन साल तक प्रति माह दस हजार रुपये प्रोत्साहन राशि, कौशल विकास प्रशिक्षण, स्वरोजगार, नकद इनाम, कृषि या शहरी भूमि का आवंटन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि अब बंदूक की जगह किताबों का स्थान है, और सड़कों की गूंज सुनाई दे रही है। 'नियद नेल्ला नार' योजना के तहत बस्तर के दूरदराज गांवों में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कार्ड, किसान क्रेडिट, प्रधानमंत्री आवास, मोबाइल टावर, वन अधिकार पट्टों जैसी सुविधाएं सुलभ कराई जा रही हैं। अधिकारियों के मुताबिक, अबूझमाड़ के रेकावाया गांव में पहली बार स्कूल खुल रहा है, जहां कभी नक्सली स्वयं स्कूल चलाते थे। बंद पड़े करीब पचास स्कूल दोबारा चालू किए गए हैं, नये भवन तैयार हो रहे हैं, और शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधाएं सुदूर इलाकों में पहुंच रही हैं। इसी तरह, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर तक योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, स्कूल, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य शिविर सक्रिय किए गए हैं।

नक्सलवाद का विश्लेषण किया जाए तो बीते छह दशकों में उसने भारत के लोकतंत्र को बार-बार चुनौती दी है। 2004-14 के बीच तेरह हजार से अधिक हिंसक घटनाएं, सैकड़ों सुरक्षाकर्मियों तथा नागरिकों की मृत्यु हुई लेकिन 2014 से 2024 के बीच इन घटनाओं में उल्लेखनीय गिरावट आई है। हिंसक घटनाएं घटकर लगभग आधी रह गई हैं, सुरक्षाकर्मियों की मौतें 73 प्रतिशत और नागरिकों की मौतें 70 प्रतिशत कम हुई हैं। हालांकि नक्सलियों की विचारधारा लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका को अस्वीकार करती है, वे हिंसा को जनता की आवाज बता कर खुद को वैध ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों, सरकार और समाज तीनों की जिम्मेदारी और मुस्तैदी बढ़ जाती है। नक्सल समर्थक शहरी नेटवर्क, एनजीओ, वकीलों, शिक्षकों आदि पर भी सरकार कठोर कार्रवाई कर रही है। शहरी नेटवर्क को खत्म करने और वैचारिक आतंकी ढांचे को धराशायी करने के लिए पुलिस, सुरक्षा बल और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से अभियान जारी हैं।

स्पष्ट है कि राष्ट्र अब नक्सलवाद के अंतिम दौर की ओर है। विकास और सुरक्षा की समन्वित नीति, लगातार अभियानों, पुनर्वास योजनाओं और जनता की सोच में बदलाव ने नक्सली नेतृत्व, कैडर और संरचना को लगातार कमजोर किया है। यदि यही गति बनी रही तो मार्च, 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित करना संभव हो जाएगा। इस खूनी विचारधारा से देश को मुक्ति दिलाना ही लोकतंत्र की सच्ची विजय है, वह लोकतंत्र, जिसने दशकों तक हिंसा, विद्रोह और आतंक से जूझते हुए आज विकास, शिक्षा और स्थायी शांति की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाया है।

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

सुरक्षा अभियानों की आक्रामक रणनीति के चलते नक्सली संगठनों की रीढ़ टूट रही है, और उनका जनसमर्थन तेजी से कमजोर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र, ओडिशा जैसे राज्यों की जमीनी हकीकत यह है कि अब माओवादी सीमित क्षेत्रों में छिपे हैं जबकि पहले देश के 38 जिले पूरी तरह नक्सल प्रभावित थे, अब यह संख्या घट कर छह जिलों तक सीमित रह गई है। केंद्र सरकार का उद्देश्य मार्च, 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से पूर्णतया मुक्त करना है। इसके लिए दोहरी नीति अपनाई जा रही है-सख्त सुरक्षा कार्रवाई और बहुआयामी विकास योजनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि अब बंदूक की जगह किताबों का स्थान है, और सड़कों की गूंज सुनाई दे रही है

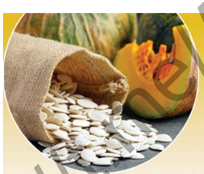

बढ़ते कोलेस्ट्रॉल से राहत दिला सकते हैं कद्दू के बीज

- कोलेस्ट्रॉल एक तरह की चर्बी होती है, जो शरीर में थोड़ी मात्रा में जरूरी होती है, लेकिन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, तो दिल की नलियों में जमा होकर खून के बहाव में रुकावट पैदा कर सकती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना जरूरी हो जाता है। दवाइयों के साथ-साथ कुछ प्राकृतिक चीजें भी इसमें मदद कर सकती हैं, और कद्दू के बीज उन्हीं में से एक हैं
- अमेरिकन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, कद्दू के बीजों में काफी मात्रा में फाइबर होता है, जो पाचन क्रिया को ठीक करता है और आंतों में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है
- ध्यान रखें कि किसी भी चीज की तरह कद्दू के बीज का सेवन भी सीमित मात्रा में करें क्योंकि ज्यादा खाने से नुकसान हो सकता है। रोजाना 20-30 ग्राम यानी मुट्ठी भर कद्दू के बीज खाना शरीर के लिए पर्याप्त होता है

(मीडिया इनपुट्स)

श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल। अगर भारत इस प्रकार की प्रतिकूल स्थितियों से सुरक्षित रह पाया है तो उसमें हमारे लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती की बेहद अहम भूमिका रही। ऐसे में हमें और सतर्क रहना होगा कि ये संस्थान किसी भी तरह कमजोर न पड़ें।

तवलीन सिंह, पत्रकार
@tavleen_singh

शांति की पहल कितनी कारगर

मणिपुर | **प्रमोद भार्गव**

फरवरी, 2023 में मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच दंगों की शुरुआत हुई थी। अब जाकर यहां स्थायी शांति की दिशा में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से कुकी समुदायों के संगठनों के बीच समझौते पर सहमति बन पाई है। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (केएनओ) और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यूपीएफ) ने एक साल के लिए सभी ऑपरेशन निलंबित करने का फैसला लिया है। इससे राज्य में शांति की उम्मीद जगी है।

इससे पहले मणिपुर में खूनी संघर्ष के चलते संबंधित पक्ष अपनी शर्तें मनवाने पर अडिग थे। लेकिन अब कुकी-जो के दोनों प्रमुख संगठनों और केंद्र व राज्य सरकार के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो गए हैं। बावजूद कहना मुश्किल है कि स्थायी शांति बनी रहेगी? कुकी गुटों ने मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने पर सहमति जताई है, जो मैतेई समुदाय की प्रमुख मांग थी। वरना इसके पहले कुकी संगठन अलग पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे थे। यह चुनौती बड़ी थी, जिसे स्वीकारा जाना कठिन था।

उम्मीद है कि टकराव और हिंसक संघर्ष की स्थिति समाप्त होगी। हालांकि इस समझौते के सामानांतर मणिपुर में नगाओं की संस्था ने मुक्त आवागमन के साथ भारत-म्यामार सीमा पर बाड़बंदी का विरोध करते हुए कारोबारी प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। इस वक्तव्य के बाद कुकी-जो परिषद ने कहा है कि समझौते को मैतेई बस्तियों और कुकी-जो के क्षेत्रों के बीच के बफरजोन में किसी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाए। अब लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना सरकार का काम है। 13 सितम्बर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मिजोरम पहुंच रहे हैं। उम्मीद है कि उसके एक दिन पहले मोदी मणिपुर जा सकते हैं। प्रधानमंत्री यकीनन दोनों समुदायों को साधने की कोशिश करेंगे। मणिपुर में हिंसा भड़कने के बाद उनका यह पहला दौरा होगा। विपक्ष प्रधानमंत्री के मणिपुर नहीं जाने पर तल्ख टिप्पणी करता रहा है। 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। उसके बाद से गृह मंत्रालय के साथ केएनओ और यूपीएफ के प्रतिनिधियों से बातचीत चल रही थी। फलतः सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (एसओएस) त्रिपक्षीय समझौता संभव हुआ। समझौता एक साल के लिए लागू रहेगा।

याद रहे कि कुकी गुटों के साथ 2008 में ही एसओएस पर समझौता हुआ था, जिसे हर साल बढ़ाया जाता था। लेकिन हिंसा के चलते 2024 में इसे बढ़ाया नहीं गया और अब नई शर्तों के साथ एसओएस पर समझौता हुआ है। समझौते के तहत मैतेई समुदाय की प्रमुख आपत्तियों के सामाधान भी तलाशे गए हैं। इसके तहत कुकी गुटों को अपने शिविर ऐसे स्थलों से हटाने होंगे जो मैतेई समुदाय से सटे हुए हैं। दरअसल, मैतेई समुदाय आरोप लगाता रहा है कि कुकी अपने शिविरों से मैतेइयों पर हमले करते रहते हैं। इन गुटों को यह भी सत्यापित करना होगा कि उनके गुटों में कोई विदेशी नागरिक तो शामिल नहीं है। इन गुटों के पास जो भी मारक हथियार हैं, उन्हें बीएसएफ और सीआरआरपीएफ के नजदीकी शिविरों में जमा करना होगा। इन शर्तों पर पालन के लिए संयुक्त निगरानी समिति बनाई जाएगी।

फरवरी, 2023 में राज्य सरकार ने पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों से अवैध प्रवासियों को बाहर करने की शुरुआत की थी। इन क्षेत्रों की नगा और कुकी समुदाय की 34 जातियां, जनजाति की श्रेणी में अधिसूचित हैं। अतएव इनके लिए चिन्हित भूभाग पर किसी गैर-जनजातीय समुदाय के लोग काबिज नहीं हो सकते हैं। विडंबना रही कि जिन लोगों को प्रवासी बता कर विस्थापन का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्हें इस इलाके के मूल निवासी कुकी समुदाय ने अपना बताया। किंतु सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए कुकियों की बेदखली का सिलसिला तो बनाए ही रखा, साथ ही मैतेई समुदाय को जब जनजाति का दर्जा मिल गया, तब उन्हें बलपूर्वक नगा और कुकी समुदाय के लोगों को आरक्षित भूखंडों पर भी काबिज होने से नहीं रोका। विवाद की असली जड़ यही विरोधाभास है।

यह जातीय हिंसा इस हद तक भड़की कि अनेक निर्दोष महिलाओं पर बर्बर अत्याचार के साथ जघन्य रेप के मामले भी सामने आते रहे। करीब 250 लोग इस हिंसा में अपने प्राण गंवा चुके हैं। ज्यादातर मैतेई हिन्दू होने के साथ वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हैं। इनमें से कुछ मतांतरित मुसलमान भी हैं जबकि नगा और कुकियों में से 90 फीसद धर्मांतरित ईसाई हैं। इस लिहाज से विवाद धार्मिक रंग में बदल कर हिंसक हो गया था। इसे धार्मिक रंग देने में ड्रग माफिया ने भी आग में घी डालने का काम किया। समूचे पूर्वोत्तर भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निर्यातित नशे का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। यहां प्रत्येक माह हेरोइन बड़ी मात्रा में पकड़ी जाती है। यहां अफीम की खेती भी खूब होती है। बहरहाल, पूर्वोत्तर के एक बड़े भूभाग में विकास का वातावरण बना है।

(लेख में विचार निजी हैं)

एक जमा एक | **संत राजिन्दर**

गणित का एक सूत्र है, जिसमें हमें महारत हासिल करने की जरूरत है, लेकिन हमें स्कूल में यह नहीं पढ़ाया जाता। स्कूल में हम सीखते हैं कि एक जमा एक दो होता है, लेकिन अध्यात्म में हम सीखते हैं कि एक जमा एक बराबर एक होता है यानी हमारी आत्मा जब परमात्मा से मिलती है, तो वो दो नहीं एक हो जाती है। प्रभु के साथ इस एकता का अनुभव करना तभी संभव है, जब हम महसूस करते हैं कि हम सब एक ही हैं। इस दिव्य अनुभव को हम केवल ध्यान-अभ्यास द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सारी उम्र सोचते रहते हैं कि हम और परमात्मा अलग हैं। हमारा यही द्वैत हमें परमात्मा से मिलने से रोकता है। हमारा अहंकार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम परमात्मा से ही नहीं, बल्कि दूसरों से भी अलग हैं। जब हम अपना अहंकार खो देते हैं, तभी आध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं, और उतना ही अधिक हम खुद को परमात्मा के करीब पाते हैं। जैसे-जैसे हमारा अहंकार कम होता जाता है, वैसे-वैसे हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है कि हम सब एक हैं। जब हम ध्यान-अभ्यास के माध्यम से अपनी रूहानी यात्रा पर जाते हैं, तो हमें अनुभव होता है कि हमारे अंदर परमात्मा का वही प्रकाश है, जो अन्य जीवों में है। ऐसा जीवन जिसमें हमारे अंदर सभी लोगों के लिए प्यार और सम्मान की भावना हो, परमात्मा की एक खास बख्शीश है। जब हम परमात्मा को याद करने के लिए ध्यान-अभ्यास पर बैठते हैं, तो खुद को आत्मिक रूप में अनुभव करते हैं। जब हम अपने अंदर उस आध्यात्मिक चेतनता से जुड़ते हैं, तब हमारे अंदर एक बड़ा बदलाव आता है। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, जैसा हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ करें। जब हम अपना द्वैत खो देते हैं, तो हम परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हम अनुभव करते हैं कि केवल एक ही परमात्मा है, जो कई हिस्सों में विभाजित है। आइए! हम प्रति दिन ध्यान-अभ्यास में समय व्यतीत करें क्योंकि इससे न केवल हमारा अपना आध्यात्मिक विकास होगा, बल्कि पूरे विश्व में शांति का भी प्रसार होगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर इस अनुभूति को प्राप्त कर लेता है कि एक जमा एक बराबर एक होता है, तो यह दुनिया एक दिन शांति और प्रेम का स्थल बन जाएगी।

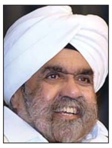

रीडर्स मेल

दूसरों का दुख भी समझना चाहिए

कुछ दिन पूर्व मैं मधुपुर की एसबीआई ब्रांच गया था। भीड़ अधिक थी, मैं लाइन में खड़ा हो गया। 40 मिनट बाद आठवें नंबर पर पहुंचा। तभी बगल में महिला लाइन में एक वृद्ध महिला को अन्य महिलाएं कह रही थीं-पीछे जाइए, पीछे। हम लोग भी बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। वृद्ध महिला ने कहा-लाइन में बहुत देर से खड़े-खड़े मेरा पैर दुखने लगा था तो मैं सामने लगी सीट पर बैठ गई थी। अब मैं काउंटर पर पहुंचने वाली हूं, तो खड़ी हो गई। लेकिन किसी भी महिला ने उस वृद्धा की बात नहीं सुनी, यह देखते हुए भी कि वो महिला थक जाने के कारण लाइन छोड़ कर कुर्सी पर बैठी हुई थी। मुझसे उस वृद्ध महिला का दुःख देखा नहीं गया। मैं भी काउंटर पर पहुंचने वाला था, मेरे आगे और तीन लोग थे। मैंने उस महिला से जाकर कहा कि आप मेरे आगे (पुरुष लाइन में) लग जाइए और अपना काम करा लीजिए। इस क्रम में मेरे और बैंक में तैनात सुरक्षाकर्मियों के बीच हल्की कहासुनी भी हो गई, लेकिन वे लोग हमें कुछ नहीं कह सके। मैंने देखा कि वह वृद्ध महिला पैसे निकालने आई हुई थीं। उन्होंने पैसे निकाले और धीरे-धीरे दीवार के सहारे बाहर निकल गईं। खुशी से उनकी आंखें भर आईं और उन्होंने मुझे खूब आशीर्वाद दिया। यह सब देख कर मैं सोचता रहा कि आजकल लोग खुद में इतने मशगूल हो चुके हैं कि दूसरों का दुःख नजर ही नहीं आता।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

लागू हो 'एक देश, एक बोर्ड'

देश में अभी साठ से अधिक स्कूली बोर्ड हैं। उन सभी स्कूली बोर्ड में कई स्तरों पर भिन्नताएं हैं, सभी बोर्ड के अलग-अलग पाठ्यक्रम हैं, उनकी मूल्यांकन पद्धति भी अलग-अलग है, एवं परीक्षा की अवधि भी अलग-अलग होती है। अलग-अलग बोर्ड में विद्यार्थियों के प्राप्तांक में भिन्नता पाई जाती है। कोई बोर्ड नंबर देने में उदार होते हैं, तो कोई बोर्ड कठोर होते हैं। इन भिन्नताओं की वजह से राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आश्चर्य का विषय है कि केंद्रीय स्कूल शिक्षा बोर्ड के स्तर पर भी भिन्नता पाई जाती है। छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सभी बोर्ड के पाठ्यक्रम में एकरूपता एवं मूल्यांकन में एक समानता होनी चाहिए। आज एक देश-एक बोर्ड के सिद्धांत को लागू करना चाहिए।

हिमांशु शेखर, गयाजी

सोशल मीडिया की अनदेखी भारी

नेपाल में सोशल मीडिया को बैन करने से गुस्साए लोगों ने हिंसक रुख अपना कर तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी कर सरकारी आवासों, और राजनीतिक दलों के दफ्तरों पर हमला बोल दिया। बदलते परिवेश में सोशल मीडिया एक जरूरत बन चुका है। बड़ी-बड़ी कंपनियां, ब्रांड, शिक्षण संस्थान और बिजनेस सोशल मीडिया पर अपना प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। सोशल मीडिया को बैन करना लोगों को दुनिया से अलग करने, काटने जैसा है। नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है, और सेना ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाल ली है। फिर भी हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे हैं। नेपाल सरकार को सोशल मीडिया के बारे में दोबारा सोचना चाहिए और जनता के हित में निर्णय लेना चाहिए।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 30
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

https://t.me/AllNewsPaperPaid

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

लहूलुहान होता अमेरिका

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लाडले चार्ली किर्क की सनसनीखेज हत्या से पूरा देश सन्न है। इस घटना ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे को एक बार फिर उजागर कर दिया। चार्ली किर्क ने युवा रिपब्लिकन मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और वे इजराइल के कट्टर समर्थक भी थे। चार्ली किर्क ट्रम्प के करीबी सर्कल में प्रभावशाली थे और वे ट्रम्प के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियान का प्रमुख चेहरा बन चुके थे। चार्ली किर्क यूटा वैली यूनिवर्सिटी में मास शूटिंग्स पर सवालों के जवाब दे रहे थे तभी अचानक उनकी गर्दन में गोली लगी और उनकी तुरन्त मौत हो गई। यह भी एक संयोग है कि उनकी हत्या 9/11 हमले की बरसी के दिन की गई। चार्ली किर्क ने कई विवादास्पद बयान दिए। 2 सितम्बर को उन्होंने एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका को भारत के लोगों के लिए और वीजा देने की जरूरत नहीं। अमेरिका पूरा भर चुका है। अब अपने लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। चार्ली किर्क को ठीक उसी तरह से गोली मारी गई जैसे डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारी गई थी लेकिन वे बाल-बाल बच गए थे।

पिछले एक साल के भीतर ही अमेरिका 5 बार ऐसी हाई प्रोफाइल हत्याओं या हत्या के प्रयासों का गवाह बन चुका है। इस सूची में स्वयं ट्रम्प, मिनेसोटा के पूर्व हाऊस स्पीकर मेलिसा हॉर्टमैन और उनके पति और दक्षिणपंथी निक का नाम शामिल है। अमेरिका में राजनीतिक हिंसा की घटनाओं से इस बात पर बहस छिड़ गई है कि यदि अति विशिष्ट लोग ही सुरक्षित नहीं तो आम लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं। इसी बीच अमेरिका के टेक्सास राज्य के डलास शहर में स्थित एक मोटल में भारतीय मूल के नागरिक कर्नाटक के चन्द्रा नागमल्लैया का उसी मोटल के कर्मचारी ने सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के समय नागमल्लैया की पत्नी और बेटे मौजूद थे। वाशिंग मशीन के इस्तेमाल को लेकर हुए झगड़े में हत्यारे ने नागमल्लैया का सिर काटकर उसे पार्किंग तक लात मारी और सिर को कूड़ेदान में डाल दिया। हत्यारा क्यूबा का नागरिक बताया जाता है। एक सप्ताह पहले हरियाणा के जींद के 26 वर्षीय युवक कपिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसका कसूर केवल इतना था कि उसने एक अमेरिकी को सड़क के किनारे पेशाब करने से रोका था। इससे गुस्साए अमेरिकी ने पिस्टल निकाल कर उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं।

एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी नागरिकों के पास लगभग 39.3 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। यह संख्या अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। स्कूलों में गोलीबारी की घटनाओं के बाद अमेरिका में बंदूकों पर रोक लगाने की बहस कई बार तेज हुई। देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। लोगों का कहना है कि बंदूक से मरने वालों की संख्या आतंकवाद से मरने वालों से कहीं ज्यादा है। गन कल्चर के विरोध में समय-समय पर आवाजें उठती रही हैं लेकिन नेशनल राइफल एसोसिएशन और बंदूक लॉबी इतनी प्रभावशाली है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियां अब तक कोई कदम नहीं उठा सकीं।

अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका असहिष्णु हो चुका है और आत्मघाती बंदूक संस्कृति लोगों को लहूलुहान कर रही है। अमेरिका में बंदूक संस्कृति देश के दूसरे संशोधन के तहत नागरिकों को हथियार रखने के अधिकार और ऐतिहासिक तथा सामाजिक कारणों से जुड़ी है, जहां लोग सुरक्षा, खेल और आत्मरक्षा के लिए बंदूकों का उपयोग करते हैं। अमेरिका में बंदूक संस्कृति ब्रिटिश राज के समय से ही चल रही है। जब लोगों को खुद अपनी सुरक्षा करनी पड़ती थी। अमेरिका के स्कूलों, क्लबों और रेस्तरांओं में गोलीबारी की घटनाओं में लोगों की मौत की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इस वर्ष अब तक अमेरिका में बंदूक हिंसा की 146 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। अमेरिका में बंदूकें दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हैं और बंदूकें रखना समाज में स्टेट्स सिम्बल बन चुका है।

एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में अमेरिका में लगभग 16.17 मिलियन (1.61 करोड़) बंदूकों की बिक्री हुई। यह पिछले साल (2023) की तुलना में 3 फीसदी की कमी को दर्शाता है। 2020 में कोविड-19 महामारी, सामाजिक अशांति और राष्ट्रपति चुनाव के कारण बंदूकों की बिक्री में रिकॉर्ड उछाल आया था। उस साल अनुमानित 21.8 मिलियन (2.18 करोड़) बंदूकें बेची गईं। जब भी चुनाव होते हैं या बंदूक नियंत्रण को लेकर कोई कानून बनने की चर्चा होती है, तो बंदूकें खरीदने वाले लोग अक्सर ये सोचकर ज्यादा बंदूकें खरीद लेते हैं कि कहीं भविष्य में खरीद पर प्रतिबंध न लग जाए। मास शूटिंग (गोलीबारी की बड़ी घटनाएं) जैसी घटनाओं के बाद कुछ लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए बंदूकें खरीदते हैं। जबकि इससे बंदूक नियंत्रण की मांग भी बढ़ती है। आर्थिक अस्थिरता के दौरान भी लोग सुरक्षा के लिए बंदूकें खरीदना पसंद करते हैं।

एक अनुमान के अनुसार अमेरिकी नागरिकों के पास लगभग 39.3 करोड़ से ज्यादा बंदूकें हैं। यह संख्या अमेरिका की आबादी से ज्यादा है। स्कूलों में गोलीबारी की घटनाओं के बाद अमेरिका में बंदूकों पर रोक लगाने की बहस कई बार तेज हुई। देश के कई शहरों में प्रदर्शन भी हुए। लोगों का कहना है कि बंदूक से मरने वालों की संख्या आतंकवाद से मरने वालों से कहीं ज्यादा है। गन कल्चर के विरोध में समय-समय पर आवाजें उठती रही हैं लेकिन नेशनल राइफल एसोसिएशन और बंदूक लॉबी इतनी प्रभावशाली है कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टियां अब तक कोई कदम नहीं उठा सकीं। बंदूक लॉबी दोनों पार्टियों को वोट के साथ-साथ काफी धन भी देती हैं, इसलिए अमेरिका में सरकारें बदलती रहीं लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया। दूसरा पहलू यह भी है कि अमेरिका में रंग और नस्लभेद आज भी मौजूद है। अमेरिका में बंदूक चलाकर जान लेने की प्रवृत्ति में नस्लभेद भी दिखाई देता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरह से अप्रवासियों के खिलाफ घृणा का वातावरण बना रहे हैं उससे भी घृणा अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि अमेरिका के लोग आखिर पुलिस प्रशासन पर भरोसा क्यों नहीं करते। उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी अपराध से खुद को सुरक्षित रखने का सबसे अच्छा उपाय खुद हथियार रखना है। दुनिया भर को शांति और सद्भाव का संदेश देने वाला अमेरिका खुद लहूलुहान हो रहा है। इसके बारे में फैसला वहां की सत्ता को ही करना है।

मजबूत भविष्य और स्वस्थ भारत...

चलो ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार लाते हैं,
'सशक्त नारी, सशक्त परिवार' अभियान को सफल बनाते हैं,
नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाते हैं,
और एक उज्जवल भविष्य की नींव जमाते हैं,
गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण दिलाते हैं,
मजबूत भविष्य और स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ाते हैं...!!

गीता पाढा

भारत की वोट क्रान्ति और चुनाव आयोग

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

भारत के बहुत से राजनैतिक पंडितों का मत है कि देश में स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान हुई वोट क्रान्ति का सही मूल्यांकन स्वतन्त्रता के बाद नहीं हुआ है जिसकी वजह से भारत के लोगों को मिली राजनैतिक स्वतन्त्रता व बराबरी का मूल्यांकन भी समुचित तरीके से नहीं हो सका है। भारत के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मिला एक वोट का अधिकार एक ऐसी अहिंसक क्रान्ति थी जिसके जरिये भारत में राजा व रंक का न केवल भेद मिटा बल्कि हर गरीब आदमी को स्वतन्त्र भारत में संप्रभुता का अधिकार भी प्राप्त हुआ क्योंकि उसके एक वोट की कीमत किसी राजा के वोट के बराबर थी। इसकी मार्फत वह इस स्वतन्त्र देश के भाग्य का निर्माता तो बना ही साथ ही अपने भाग्य का निर्माता भी बना। वह अपने वोट की ताकत से सत्ता बना भी सकता था और बिगाड़ भी सकता था। हर पांच साल बाद इसका उपयोग करके वह अपनी मनपसन्द की सरकार का गठन करता था जो उसी के प्रति जवाबदेह होती थी।

यह कल्पना महात्मा गांधी की थी क्योंकि वह भारतीयों के मन से गुलामी की भावना को जड़ से दूर करना चाहते थे। मगर इस अधिकार को पाने के लिए भारत के लोगों ने कड़ा संघर्ष किया और हमारी पुरानी पीढ़ियों ने अंग्रेजों की जेलों की यातनाएं सही व लाठी-डंडे व गोलियां तक खाईं। अंग्रेज तो समझते थे कि भारत जैसे विभिन्न जातीय समूहों व वर्गों तथा सम्प्रदायों वाले जमघट के बने समुच्य के लोगों को अपना संविधान तक लिखने का सऊर नहीं है। महात्मा गांधी ने उनकी इस चुनौती को स्वीकार किया और 1928 में स्व. मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में एक संविधान लिखने वाली समिति का गठन किया जिसमें उस समय के भारत के लगभग सभी मान्य समूहों को शामिल करने की कोशिश की गई। मगर जिन्ना की मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और वह इसमें शामिल नहीं हुई जबकि बहुत से मुस्लिम नेता इसमें व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हुए।

इस समिति के सदस्यों में पं. जवाहर लाल नेहरू भी थे और नेता जी सुभाष चन्द्र बोस भी। समिति ने जो अपनी रिपोर्ट दी वह अंग्रेजों की आंखें खोल देने वाली थी। समिति ने सबसे पहले भारत को अंग्रेजों की अवधारणा के विरुद्ध एक संघीय ढांचे का देश बताया जिसमें राज्यों व केन्द्र के बीच समन्वय स्थापित करने के विभिन्न प्रावधान बताये। राज्यों व केन्द्र सरकार के अधिकारों की सूची का बंटवारा किया और सबसे ऊपर भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को बिना किसी भेदभाव के एक वोट का अधिकार देने की अनुशंसा की।

नागरिकों को मौलिक अधिकार देने की बात इसकी रिपोर्ट में कही गई। इसके बाद 1931 में कराची में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। इस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ कि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिये जायेंगे और स्वतन्त्र भारत में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वास्तव में यह ऐसा सिंह नाद था जिसकी आवाज से तत्कालीन ब्रिटिश संसद भी हिल उठी थी। इसके हाऊस आफ लार्डस में 1932 में दो अंग्रेज विद्वानों ने कहा कि भारत ने ऐसे अंधे कुएं में छलांग लगाने का फैसला कर लिया है जिसके

बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि उसमें क्या है। इस पर महात्मा गांधी ने प्रतिक्रिया दी कि भारत के लोग अनपढ़ और गरीब हो सकते हैं मगर वे मूर्ख नहीं हैं क्योंकि उनका व्यावहारिक जीवन सामान्य ज्ञान से भरा होता है। गांधी की यह भविष्यवाणी कालजयी साबित हुई क्योंकि स्वतन्त्र भारत के चुनाव इतिहास में हम देखते हैं कि हर चुनाव में भारत के लोगों ने परिपक्वता का परिचय दिया और भारत को स्थिर व दूरदर्शी सरकारें दीं। बेशक कुछ समय के लिए राजनैतिक अस्थायित्व का भी वातावरण रहा मगर वह लम्बे समय तक नहीं चल सका।

भारत की एक और विशेषता है कि यहां राजनैतिक नेतृत्व की विश्वसनीयता कभी खतरे में नहीं आयी। यदि इस पर कुछ समय के लिए प्रश्नचिन्ह लगा भी तो लोगों ने इसका परिमार्जन अपनी राजनैतिक चतुराई से करने में सफलता भी प्राप्त की। यह सब कार्य भारत के लोगों को मिले एक वोट के अधिकार के बूते पर ही हुआ। परन्तु वर्तमान में भारत में बहस इसी एक वोट के अधिकार को लेकर हो रही है और चुनाव आयोग विवाद के केन्द्र में बना हुआ है। भारत में चुनाव आयोग का गठन ही इसीलिए किया गया जिससे लोगों का एक वोट का अधिकार अक्षुण्य बना रहे लेकिन यह काम चुनाव आयोग मतदाता सूची की मार्फत ही करता है और फिलहाल खबरें मिल रही हैं कि चुनाव आयोग पूरे देश में मतदाता सूची का सघन पुनर्रीक्षण करना चाहता है। इसने हाल ही में बिहार में भी ऐसा ही अभियान चलाया था जो बहुत अधिक विवादास्पद रहा। विवाद का प्रमुख कारण यह रहा कि चुनाव आयोग मतदाताओं की नागरिकता की जांच करने का प्रयास कर रहा था जो कि उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है।

भारत चूंकि संविधान से चलने वाला देश है और संविधान कहता है कि मतदाता या किसी भी भारतीय की नागरिकता की पहचान करने का अधिकार केवल गृह मन्त्रालय को ही है। चुनाव आयोग का मुख्य काम यह देखना है कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर भारतीय का नाम भी मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके लिए वह मतदाता से उसकी पहचान पूछ सकता है मगर उसके भारतीय होने पर सवालिया निशान नहीं लगा सकता क्योंकि कोई भी वयस्क नागरिक केवल तभी मतदाता बन सकता है जब वह चुनाव आयोग के समक्ष यह कसम खाता है कि वह भारत का जायज नागरिक है। उसकी नागरिकता को चुनौती देने का काम राज्य का है।

बिहार में नागरिकों की पहचान के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि वह उनके आधार कार्ड को पुख्ता सबूत माने और उसके आधार पर उनके निवास का प्रमाण जाने। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश केवल बिहार तक ही सीमित होकर रह जायेगा ऐसा नहीं है क्योंकि संविधान की नजर में हर राज्य के नागरिक के अधिकार एक समान ही होते हैं। अत: यदि चुनाव आयोग राष्ट्रीय स्तर पर मतदाता सूची का सघन पुनर्रीक्षण कराने की तैयारी कर रहा है तो उसे आधार कार्ड को एक पहचान मानने के लिए तैयार रहना होगा। चुनाव आयोग को यह भी विचार करना होगा कि भारत के नागरिकों को एक वोट का अधिकार दिलाने के लिए गुलाम भारत में ही महात्मा गांधी ने क्रान्ति कर दी थी। चुनाव आयोग का भी यह कर्त्तव्य बनता है कि वह किसी भी भारतीय से उसका वोट देने का अधिकार तभी छीनने का प्रयास करे जबकि सारे सबूत उसके अपने पक्ष में बोलते हुए लगें। क्योंकि स्वतन्त्र भारत में चुनाव आयोग को ही नागरिकों के एक वोट के अधिकार का संरक्षक बनाया गया है। यह अधिकार बहुत पवित्र भी है क्योंकि इसी के आधार पर भारत में सरकारों का गठन होता है। महात्मा गांधी साधन और साध्य की पवित्रता पर बहुत जोर दिया करते थे। चुनाव आयोग को भी इस सिद्धान्त को ध्यान में रखना होगा।

कॉर्पोरेट के 'एकांतवास' की राह पर सुप्रीम कोर्ट

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

कॉर्पोरेट मानव संसाधन प्रथाओं से प्रेरणा लेते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई सभी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सप्ताहांत में एकांतवास के लिए रणथंभौर ले गए हैं। वे अपने परिवारों के साथ बाघ अभयारण्य गए हैं। यह यात्रा मुख्य न्यायाधीश गवई के निर्देश पर आयोजित की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के इतिहास में पहली बार हुई है। एकांतवास की अवधारणा कॉर्पोरेट कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को उनके कार्यस्थल से दूर

एक अनौपचारिक माहौल में एक-दूसरे के साथ घुलने-मिलने का अवसर देने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के बीच बेहतर समझ को बढ़ावा देना और बाहरी दुनिया के हस्तक्षेप के बिना केंद्रित तरीके से मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करना है। यह दिलचस्प है कि मुख्य न्यायाधीश गवई ने इस अवधारणा को न्यायपालिका की स्थिर, औपचारिक दुनिया में लाने के बारे में सोचा है।

यह स्पष्ट नहीं है कि इस अवकाश के लिए कोई निर्धारित एजेंडा है या नहीं, लेकिन जब देश की सर्वोच्च अदालत के 34 न्यायाधीश एक साथ मिलते हैं, तो न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे बातचीत में उठना लाजमी है। राजस्थान में बाघ अभयारण्य को न केवल दिल्ली से निकटता के कारण, बल्कि इसके एकांत वातावरण के कारण भी चुना गया था ताकि दोनों राज्यों के बीच घनिष्ठ कार्य संबंध विकसित हो सकें।

क्या पीएम मोदी के जन्मदिन पर भागवत भी देंगे तोहफा ?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरएसएस के सरसंघचालक को जन्मदिन का तोहफा दिए जाने से भाजपा में चर्चा है। यह पहली बार है कि देश के सबसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन किसी भाजपा नेता ने पार्टी के वैचारिक स्रोत, संगठन के प्रमुख की सार्वजनिक रूप से इतनी प्रशंसा की है। भागवत की प्रशंसा से

भरा मोदी का लंबा ब्लॉग एक्स पर पोस्ट किया गया था और 11 सितंबर को आरएसएस प्रमुख के ऐतिहासिक 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश भर के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। यह लेख भागवत के जीवन और उनके कार्यकाल पर प्रकाश डालता है। प्रधानमंत्री ने उन्हें एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में सराहा, जिन्होंने तेजी से हो रहे बदलावों के दौर में आरएसएस को नई गति दी है। भागवत पर इतना ज़ोर देना बेहद असामान्य है क्योंकि संघ परिवार पारंपरिक रूप से व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करने से हिचकिचाता है। आरएसएस के लिए विचारधारा हमेशा से ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है, हालांकि संगठन के मुखिया को हिंदू अविभाजित परिवार के मुखिया जैसा सम्मान और आदर

दिया जाता है। भाजपा हलकों में इस बात को लेकर चर्चा है कि क्या आरएसएस प्रमुख 17 सितंबर को मोदी के 75वें जन्मदिन पर उन्हें कोई उपहार देंगे और अगर देंगे, तो वह उपहार क्या होगा?

क्या ममता से टकराने की हिम्मत दिखा सकेगा चुनाव आयोग

हालांकि चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची का विवादास्पद पुनरीक्षण अभी पूरा नहीं किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले अपने राज्य में इसी तरह की तैयारी के लिए पहले ही मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने पिछले महीने चुनाव आयोग पर पहला हमला यह कहकर किया था कि वह किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटने देंगी। हालांकि ममता बनर्जी चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के अपने निर्धारित काम से नहीं रोक सकतीं। हालांकि, चुनाव आयोग को बंगाल में एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है जिसका सामना उन्हें बिहार में नहीं करना पड़ा।

चुनाव आयोग के लिए पुनरीक्षण कार्य करने वाले ब्लॉक स्तरीय अधिकारी आमतौर पर स्कूल शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और अन्य होते हैं, जो सभी राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। यहीं पर हितों का टकराव शुरू होता है। बिहार में वर्तमान में भाजपा-जद(यू) एनडीए सरकार है। स्वाभाविक रूप से, इसने चुनाव आयोग के काम में बाधा नहीं डाली और आयोग को मतदाता सूची में शामिल लोगों के

नामों की जांच करते समय बीएलओ के काम की निगरानी करने की पूरी छूट मिली थी। हालांकि, पश्चिम बंगाल बनर्जी का क्षेत्र है और उन्होंने चुनाव आयोग को स्पष्ट कर दिया है कि बीएलओ उनके आदेश और नियंत्रण में हैं। दोनों के बीच अभी से टकराव शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने राज्य के बीएलओ को अपने आदेशों का पालन करने के लिए बढ़े हुए मासिक वेतन के रूप में एक प्रलोभन दिया है।

बनर्जी ने बीएलओ को यह याद दिलाते हुए चेतावनी दी है कि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने तक वे उनकी सरकार के प्रति जवाबदेह हैं। राजनीतिक हलकों में उत्सुकता से यह देखने की उत्सुकता है कि यह टकराव किस प्रकार सामने आता है और क्या आयोग बिहार शैली की एसआईआर के साथ बनर्जी के प्रभुत्व में दखल देने का साहस दिखा सकेगा।

साउथ एशिया में 'स्प्रिंग'

अर्जुन चोपड़ा

दक्षिण एशिया के देशों में जबरदस्त उथल-पुथल का दौर जारी है, जिससे भू-राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, उससे 2011 के अरब स्प्रिंग की यादें ताजा हो गई। पहले बंगलादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया, अब जेन जेड के आंदोलन ने नेपाल में तख्ता पलट कर दिया। इससे पहले श्रीलंका के आर्थिक संकट के चलते सत्ता परिवर्तन हुआ। इन देशों में जनविद्रोह के कई कारण रहे लेकिन इन जन बगावत के पीछे वैश्विक शक्तियां भी जिम्मेदार रहीं। दक्षिण एशिया कहां जा रहा है, यह एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में सत्ता और तख्ता पलट तो एक नियमित परम्परा की तरह चल पड़ा है। भारत में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हैं और लोकप्रिय सरकार में लोगों का विश्वास है।

इस कड़ी में जब हम दक्षिण एशियाई वसंत की बात करते हैं, तो हम दक्षिण एशियाई क्षेत्र पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि जैसे देशों में विद्रोहों, विरोध प्रदर्शनों या आंदोलनों की एक सम्भावित या वास्तविक लहर के बारे में सोचते हैं जो मौजूदा राजनीतिक ढांचों को चुनौती देते हैं, या वर्तमान शासन व्यवस्था के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं। ये आंदोलन हमेशा अरब वसंत के समान पैटर्न की तरह समान कुंठाओं से प्रेरित होते हैं। जैसे भ्रष्टाचार, राजनीतिक उत्पीड़न, आर्थिक मुद्दे या असमानता यह आक्रोश राजनीति व्यवस्था पर बदलाव के लिए चोट करता है।

इस कड़ी में श्रीलंका में 2022 में एक बड़ा आर्थिक संकट देखा गया जो राजनीतिक अशांति में बदल गया। देश को खाद्य, ईंधन और दवाओं की भारी कमी के साथ-साथ आसमान छूती मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ा। यह आंशिक रूप से सरकारी कुप्रबंधन और खराब आर्थिक नीतियों के कारण था। 2022 की शुरूआत में राष्ट्रपति मोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर नागरिक सड़कों पर उतर आए। संसद पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था। परिणाम यह निकला कि विरोध प्रदर्शन इतने व्यापक और तीव्र हो गए कि राजपक्षे अंतत: देश छोड़कर भाग गए और उनकी सरकार गिर गई। श्रीलंका का संकट महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि आर्थिक कुप्रबंधन दक्षिण एशिया में राजनीतिक स्थिरता को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकता है।

पाकिस्तान में राजनीतिक विरोध और अस्थिरता की बात करें तो वहां राजनीतिक भ्रष्टाचार, सैन्य प्रभाव और आर्थिक अस्थिरता के खिलाफ पिछले कुछ वर्षों में कई प्रोटैस्ट हुए हैं। 2022 में इमरान खान का अपदस्थ होना और इसके बाद पूर्व क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान को अविश्वास प्रस्ताव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। उनके समर्थकों, जिनमें से कइयों ने उनके अपदस्थ होने को सैन्य और विदेशी शक्तियों से जुड़ी एक बड़ी साजिश का हिस्सा माना, ने उनकी सत्ता में वापसी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इन विरोध प्रदर्शनों ने पाकिस्तानी राजनीति में नागरिक सरकार, सैन्य प्रतिष्ठान और जनता के बीच गहरे विभाजन को उजागर किया। इसी तरह 2014 में भी इमरान खान और राजनेता ताहिर-उल-कादरी के नेतृत्व में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसका उद्देश्य नवाज शरीफ की सरकार को सत्ता से हटाना था और उस पर चुनावों में भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। हालांकि इससे सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन इसने राजनीतिक परिदृश्य को हिलाकर रख दिया। आज भी वहां लोकतंत्र खतरे में है।

बंगलादेश में पिछले कुछ दशकों में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन एक नियमित घटना रही है। अवामी लीग (एएल) और बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के बीच अक्सर टकराव होता रहा है। सन् 2013 में शाहबाग आंदोलन के दौरान युवा कार्यकर्ता शाहबाग में एकत्रित हुए और 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तान के साथ सहयोग करने के आरोपी युद्ध अपराधियों के लिए मृत्युदंड की मांग और भारी उठा-पटक हुई। जबकि इससे पूर्व 2018 में ढाका में हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और एक सड़क दुर्घटना में दो छात्रों की मौत के बाद सुरक्षित सड़कों की मांग की। ये विरोध प्रदर्शन जन सुरक्षा, शिक्षा और भ्रष्टाचार के प्रति सरकार की उपेक्षा की व्यापक आलोचना में बदल गया। शेख हसीना देश छोड़कर आज पुराने मित्र भारत की 'शरण' में हैं लेकिन वहां जनाक्रोश पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कहा जा सकता।

सच्चाई तो यह है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में राजशाही और अधिनायकवाद के विरुद्ध जन विद्रोहों का इतिहास रहा है। 1990 का जन आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसने नेपाल के राज्य को लोकतांत्रिक सुधार लागू करने और कुछ शक्तियां त्यागने के लिए सफलतापूर्वक मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई।

याद करो जब वहां 2006 में एक ओर आंदोलन के परिणामस्वरूप राजशाही का खात्मा हुआ और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। आज की तारीख में वहां जेन जेड सरकार के खिलाफ तख्ता पलट के लिए सड़कों पर हैं। वहां अंतरिम सरकार के गठन की तैयारियां भी चल रही हैं लेकिन आंदोलनकारियों का जेन जेड ग्रुप दोफाड़ हो चुका है।

यद्यपि अरब स्प्रिंग के परिणामस्वरूप कुछ देशों (जैसे ट्यूनीशिया और मिस्र) में शासन परिवर्तन हुए लेकिन परिणाम मिश्रित रहे। कुछ राष्ट्र लोकतंत्र की ओर बढ़े, जबकि अन्य गृहयुद्ध या अधिनायकवादी शासन में उतर गए। दक्षिण एशिया में, ऐसे आंदोलनों को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है तथा आंदोलनकारी सीधे सरकार से टक्कर ले रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता हिंसा या कुछ मामलों में सैन्य हस्तक्षेप का कारण बन सकती है। ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया स्प्रिंग केवल सत्ता परिवर्तन की दास्तान नहीं बल्कि जनता की आवाज की बुलंदी का भी उदाहरण है जो लोकतंत्र बहाली की मांग करती है और इसमें परिवर्तन की आहट या उम्मीद भी दिखाई देती है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com
स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अमर उजाला

नई दिल्ली ■ शनिवार, 13 सितंबर 2025

प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ■ आगरा

तानाशाह युद्ध शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने लोगों पर नियंत्रण के लिए बाहरी शत्रुओं की जरूरत होती है। -रिचर्ड पर्ले

स्वाभाविक साझेदारी

मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम और प्रधानमंत्री मोदी के बीच वाराणसी में शिखर वार्ता के दौरान अहम समझौतों के साथ मॉरीशस को करीब छह हजार करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज को मंजूरी द्विपक्षीय साझेदारी के एक नए स्तर पर पहुंचने को ही दर्शाती है। उल्लेखनीय है कि मार्च में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय साझेदारी को एनहैन्स्ड स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया था। लेकिन, मॉरीशस के प्रधानमंत्री की ताजा यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी का मॉरीशस को परिवार-तुल्य बताना दोनों देशों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक संबंधों का पुनःस्मरण कराता है। गौरतलब है कि मॉरीशस, जो हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर एक महत्वपूर्ण द्वीपीय राष्ट्र है, भारत का एक करीबी पड़ोसी भी है। यह भावना प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन में भी प्रतिबिंबित होती है, जब वह कहते हैं कि मॉरीशस, भारत के पड़ोसी प्रथम और विजन महासागर का एक अपरिहार्य स्तंभ है। दोनों देशों के बीच खास रिश्तों का मुख्य कारण यह भी है कि मॉरीशस की करीब तेरह लाख आबादी में 70 फीसदी हिस्सेदारी भारतीय मूल के लोगों की है। मॉरीशस के प्रधानमंत्री फिलहाल 16 सितंबर तक भारत में ही हैं। शिखर वार्ता के दौरान, शिक्षा, अनुसंधान, जल विज्ञान, विद्युत, अंतरिक्ष अनुसंधान और समुद्री सुरक्षा इत्यादि क्षेत्रों में कुल सात समझौते हुए, जो 'विकास-साझेदारी' और 'रणनीतिक सहयोग' का संगम कहे जा सकते हैं। अमेरिका की अतार्किक टैरिफ नीति के चलते वैश्विक समीकरणों ने जो नए मोड़ लिए हैं, उनमें भारत और चीन के बीच आई नजदीकी भी है। हालांकि, चीन के रिकॉर्ड के मद्देनजर सतर्क भारत यह नहीं भूल सकता कि पिछले कुछ वर्षों से चीन हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। ऐसे में मॉरीशस जैसे विश्वसनीय साझेदारों का समर्थन भारत के लिए क्षेत्रीय संतुलन बना सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष मॉरीशस में यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च किए गए थे और अब स्थानीय मुद्रा में ही कारोबार होने के फैसले से डॉलर के वर्चस्व को यकीनन चोट पहुंचेगी। भविष्य में भारत-मॉरीशस सहयोग हिंद महासागर में स्वतंत्र और संतुलित शक्ति संरचना का आधार बन सकता है, जो भारत की विदेश नीति की परिपक्वता को भी दर्शाता है। हालांकि, दोनों देशों को इस साझेदारी को मजबूत करने के लिए घोषणाओं के कार्यान्वयन पक्ष पर ध्यान देना होगा। परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्ति और पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि यह सहयोग सही मायनों में विकास का माध्यम बने।

आखिर अमेरिका की समस्या क्या है

ट्रंप के विवेकहीन सलाहकार पीटर नवारो ने भारत के बारे में जो शब्द कहे हैं, उन्हें शायद भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं। अमेरिका के बर्बर इतिहास को देखते हुए, उनसे ऐसी उम्मीद भी नहीं है। लेकिन वह और उनके राष्ट्रपति शायद यह नहीं समझ पा रहे कि दुनिया अमेरिका के बिना रह सकती है, लेकिन अमेरिका दुनिया के बगैर नहीं रह सकता।

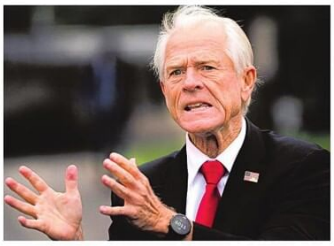

वीरेंदर कपूर
लेखक एवं शिक्षाविद

पिछले छह महीनों से मैं यह सोच रहा था कि अगर रूस, भारत और चीन एकसाथ आ जाएं, तो क्या होगा? यह एक काल्पनिक प्रश्न था। भारत और चीन को एकसाथ जोड़ने में रूस भूमिका निभाएगा। लेकिन तब यह मुझे दूर की कौड़ी लगती थी, लेकिन ट्रंप ने इसे संभव कर दिखाया। मुझे अमेरिकी संरक्षणवादी रियायत का व्यक्तिगत अनुभव हुआ, जो इस प्रकार है-लगभग दो दशक पहले, मैं दिल्ली में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में वक्ता था। एक ब्रिटिश कंपनी का सीईओ (एक श्वेत ब्रिटिश) मंच पर मेरे बगल में बैठा था। वह काफी शर्मिंदा दिख रहा था। दरअसल, एक अमेरिकी कंपनी के सीईओ ने अपने वक्तव्य के दौरान यूरोपीय लोगों का, खासकर ब्रिटिश विरासत का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मैं खुद को यह कहने से नहीं रोक पाया, 'अगर वह सार्वजनिक रूप से इस तरह से आपका मजाक उड़ा सकता है, तो बाकी दुनिया क्या सोचेगी?'

ब्रिटिश सीईओ ने कंधे उचकाते हुए कहा- 'ओह! यही तो अमेरिकी अहंकार है।' यह 20 साल पहले की बात है। ट्रंप और उनके साथी अब पूरी ताकत से जुट गए हैं। कल्पना के घोड़े पर सवार ट्रंप के विवेकहीन मुख्य सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से भारत की तेल खरीद की आलोचना की और इसे 'मोदी का युद्ध' करार दिया। अब उन्होंने यह कहकर अपनी नासमझी का नवीनतम उदाहरण पेश किया है कि 'ब्राह्मण अन्य भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।' दरअसल, जेलेंस्की भारत से विधिवत संसाधित रूसी तेल खरीदकर रूस को वित्तपोषित कर रहे हैं। यूक्रेनी तेल बाजार विश्लेषण फर्म, नैफ्टोरिनोक के अनुसार, जुलाई में यूक्रेन के डीजल आयात में किसी भी अन्य देश से अधिक भारत का हिस्सा 15.5 फीसदी था। दैनिक शिपमेंट औसतन 2,700 टन रहा, जिससे यह इस साल भारत के सबसे ज्यादा मासिक ईंधन निर्यात आंकड़ों में से एक बन गया।

दुनिया को पता होना चाहिए कि ये अमेरिकी कहां से आए हैं। ज्यादातर लोग यह नहीं जानते होंगे कि अमेरिकियों ने रेड इंडियंस (मूल अमेरिकियों) से जमीन कैसे छीनी। उन्होंने न केवल उनकी बस्तियों को जला दिया और उन्हें संगीनों एवं गोलियों से मार डाला, बल्कि उन लोगों के साथ कुछ ऐसा किया, जो अकल्पनीय था, उन्होंने उनका सब कुछ छीन लिया था। अमेरिकियों द्वारा इन्सानों की खरीद-फरोख्त होती थी। वे कुछ डॉलर के लिए अश्वेत गुलामों को संपत्ति की तरह बेचते थे। उन पर अत्याचार करते थे। उन्होंने यातना के नए-नए तरीके ईजाद किए-जो नरसंहार से भी कहीं ज्यादा भयानक थे। उनकी सजा का एक भयावह तरीका सार्वजनिक रूप से जलाना था। जाहिर है, गोरे अमेरिकियों की कोई संस्कृति नहीं है।

हालांकि, 'ब्लैक लाइव्स मैटर' आंदोलन एक श्वेत पुलिसकर्मी द्वारा एक अश्वेत व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार और उसकी हत्या के बाद शुरू हुआ था, जो कुछ समय तक चला। लेकिन यह तो अश्वेतों के साथ दुर्व्यवहार का एक छोटा-सा हिस्सा भी नहीं था। अमेरिकियों को अब भी लोगों पर अत्याचार करना पसंद है। अमेरिका में श्वेत अमेरिकियों की तुलना में अश्वेत अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति कमजोर हैं। अधिकांश अश्वेत वयस्कों ने बताया कि उन्हें अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ा। फिर भी, उन्होंने उस देश की प्रगति में योगदान दिया। इसकी पुष्टि अश्वेत खिलाड़ियों द्वारा अमेरिका के लिए जीते गए ओलंपिक पदकों की संख्या से भी होती है।

मोटे तौर पर अमेरिकी जनसांख्यिकी श्वेत अमेरिकियों की ओर झुकी हुई है। श्वेतः 57.8 फीसदी, हिस्पैनिक या लैटिनोः 18.7 फीसदी, अश्वेत या अफ्रीकी अमेरिकीः 12.1 फीसदी और मूल अमेरिकी/अलास्का लगभग 1.12 फीसदी। फिर भी, अन्य लोगों का योगदान कहीं ज्यादा है। अमेरिकी फिल्म उद्योग और संगीत क्षेत्र में भी अश्वेतों का योगदान अमूल्य है।

आखिर अमेरिकी नेतृत्व के साथ समस्या क्या है? दरअसल, वह हिटलर की तरह अहंकार में अपनी मर्जी चलाना चाहता है। 1939 में भी एक सितंबर को जर्मनों ने पोलैंड पर हमला किया था और द्वितीय विश्वयुद्ध की शुरुआत की थी। अब ट्रंप ने दुनिया के लिए टैरिफ युद्ध शुरू कर दिया है। हिटलर पागल हो गया था और अपनी मर्जी से संधियां तोड़ता था और किसी भी सलाहकार की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने बहुत सारे मोर्चे खोल दिए थे। जर्मनी दुनिया के खिलाफ था, लेकिन कम से कम इटली और जापान उसके बड़े समर्थक थे। अमेरिका, जिसे ट्रंप महान बनाने की कोशिश कर रहे थे, अब अलग-थलग पड़ गया है। जैसा कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली कहते हैं, 'फिलहाल दुनिया में एक देश की कमी दिखती है।' वह यह भी कहते हैं कि दुनिया अमेरिका के बिना रह सकती है, लेकिन अमेरिका दुनिया के बगैर नहीं रह सकता।

अमेरिकी सांड बेकाबू होकर बेचारे अमेरिकियों को मार रहा है-उनकी गलती बस इतनी है कि उन्होंने एक मनमौजी नेता को चुना। अब वह अपने चाटुकारों के जरिये हमें बता रहा है कि सारा पैसा ब्राह्मणों के पास है और बाकी देश को कुछ नहीं मिल रहा। इन्हें यह भी नहीं पता कि अंबानी परिवार मोध बनिया समुदाय से है, जो भारत के गुजरात राज्य का एक हिंदू वैश्य (व्यापारिक) समूह है। गौतम अडानी गुजराती जैन समुदाय से हैं। आनंद महिंद्रा पंजाबी हिंदू खत्री समुदाय से हैं। टाटा और गोदरेज पारसी हैं। उन्हें हमारी 5,000 साल पुरानी सभ्यता में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी ओबीसी हैं और राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हैं। इसलिए अमेरिकियों को कोई हक नहीं है कि वे हमें उपदेश दें।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में डूबी हुई है। उसकी एकमात्र ताकत हाईटेक और हथियार उद्योग है। उसकी तकनीकी ताकत बाहरी लोगों, खासकर भारत के पास है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिकी हवाई शक्ति का लोगों ने जो प्रदर्शन देखा, उसे देखकर कोई भी उनसे विमान नहीं खरीदेगा। यह 1945 नहीं, बल्कि 2025 है। यदि हैदराबाद से लूला कॉफी का निर्यात न हो, तो अमेरिकियों को कॉफी सूंघने को भी न मिले। और अभिजात्य अमेरिकी बिना कॉफी पिये, कुछ सोच भी नहीं सकते। सीआईए को अब किसी और हुकूमत को गिराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। भगवान अमेरिका की रक्षा करें।

edit@amarujala.com

पर्यावरण

नहीं चेते, तो हालात और गंभीर हो जाएंगे

पंजाब में 1988 के बाद आई सबसे खतरनाक बाढ़ की भौगोलिक वजहें ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती हैं।

सीमा जावेद

देश का आधा हिस्सा असाधारण बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में है। पंजाब 1988 के बाद से सबसे भीषण जल प्रलय का सामना कर रहा है। रिकॉर्ड-तोड़ बारिश और असामान्य तापमान ने भारत को झकझोर कर रख दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में केवल 24 घंटों में सामान्य से एक हजार फीसदी से अधिक बारिश हुई। पंजाब में 1988 के बाद से सबसे खराब बाढ़ आई है, जिसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ और लगातार बारिश के कारण हजारों गांव जलमग्न हो गए। भारत के पंजाब में मानसून का मौसम आम तौर पर जून के अंत से सितंबर तक चलता है और दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा संचालित होता है। ऐतिहासिक रूप से, मानसून मध्यम वर्षा लाता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।

वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से समुद्र के तापमान में बढ़ोतरी होती है और वायुमंडलीय स्थितियों में बदलाव होता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते अब हिंद महासागर और अरब सागर, दोनों ही बहुत गर्म हो रहे हैं और इनमें समुद्री हीटवेव पैदा हो रही है। इन सागरों के गर्म होने से अब हवा में नमी की मात्रा बहुत अधिक है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, पुणे ने बताया है कि 1951-2015 के दौरान हिंद महासागर की सतह के तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जो वैश्विक औसत से अधिक है। इससे समुद्री सतह से वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है और वायुमंडल में नमी भी अधिक घुल रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून अधिक तीव्र और अनियमित होता जा रहा है। इस साल मानसून ने भारत और पाकिस्तान के साझा पंजाब क्षेत्र में भयंकर बाढ़ ला दी है।

मानसून के चरम मौसम के दौरान पश्चिमी विक्षोभ आम तौर पर उत्तर की ओर लौट जाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और उल्टे पश्चिमी विक्षोभ का मानसून से टकराव हो गया। ऐसी अंतर्क्रिया असामान्य है। आईएमडी ने भी पुष्टि की है कि उत्तर भारत और देश के अन्य हिस्सों में लगातार हुई अत्यधिक वर्षा मुख्य रूप से मानसून प्रणाली और पश्चिमी विक्षोभ के टकराव के कारण हुई, जिससे पंजाब, हरियाणा सहित कई उत्तरी राज्यों में बाढ़ आ गई।

जेट स्ट्रीम-ऊपरी वायुमंडल में हवा की संकरी, तेज धाराएं, जो पश्चिम से पूर्व की ओर दुनिया भर में चलती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग इन धाराओं को तेजी से 'लहरदार' बना रही है, जिसका अर्थ है कि यह घुमावदार है और एक स्थिर पथ पर नहीं चल रही है। अध्ययनों से पता चला है कि लहरदार जेट स्ट्रीम दुनिया भर में चरम मौसम की घटनाओं को जन्म दे रही है, जिसमें भारत भी शामिल है, जहां उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम ने पश्चिमी विक्षोभों को असामान्य रूप से उत्तरी भागों में मोड़ दिया। इस बार के मानसून ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु परिवर्तन केवल भविष्य की चुनौती नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान मौसमी पैटर्न को गहराई से प्रभावित कर रहा है।

भारी बारिश और बढ़ते तापमान के संयोजन ने देश के विभिन्न हिस्सों को गंभीर चुनौतियों का सामना कराया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते उचित नीतियों और ठोस अनुकूलन रणनीतियों पर काम नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में चरम मौसमी घटनाओं से स्थिति और गंभीर हो सकती है। अब समय आ गया है कि हम जलवायु परिवर्तन के खतरों को समझें और इससे निपटने के लिए सामूहिक और टिकाऊ कदम उठाएं, ताकि देश के विविध पारिस्थितिकी तंत्र, आजीविका और जनजीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अरस्तु ने दुनिया देखकर तर्क की खोज की। चैटजीपीटी, प्रशिक्षण सेट में मौजूद तर्कों के आधार पर दुनिया के हर सवाल का जवाब देता है। -स्टीफन वोल्फ्राम

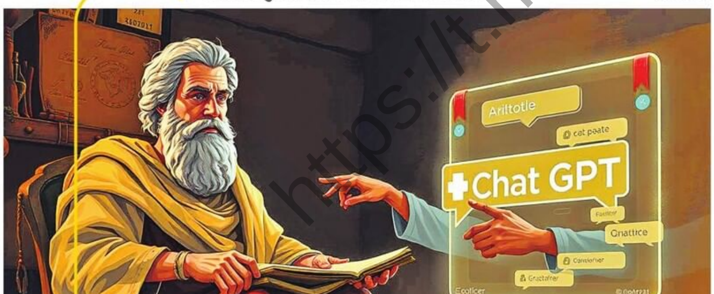

सिर्फ सोचने से बदलाव नहीं आते

आप किसी उल्लेखनीय चीज के बारे में सोचते हैं, वह भले ही बहुत ही अनोखा विचार क्यों न हो, लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते, तो वह हमेशा आपके विचारों में या किताबों में ही रहेगी, उपलब्धियों की सूची में नहीं।

रॉबर्ट ए. हेनलेन

जीवन धारा

सैद्धांतिक रूप से हर चीज तब तक असंभव लगती है, जब तक उसे पूरा न कर लिया जाए। इसी तरह, जब आप किसी उल्लेखनीय चीज के बारे में सोचते हैं, वह भले ही बहुत ही अनोखा विचार क्यों न हो, लेकिन यदि आप उस पर अमल नहीं करते, तो वह हमेशा आपके विचारों में या किताबों में ही रहेगी, उपलब्धियों की सूची में नहीं। अधिकांश लोग भी इसी तरह से सोचते हैं, यदि उन्हें एवरेस्ट पर चढ़ना है, तो उन्हें यह तब तक असंभव लगेगा, जब तक कोई दूसरा एक बार एवरेस्ट की चढ़ाई न कर ले।

मुझे दृढ विश्वास है कि भविष्य में मानव जाति की सुरक्षा के लिए हमें अन्य ग्रहों पर बस्तियां स्थापित करनी होंगी। भले ही हम इस धरती को अभी नष्ट न करें, एक दिन यह ग्रह अपने संसाधनों को खो देगा। अगर हम चाहते हैं कि मानव जाति अगले तीस अरब साल तक जीवित रहे, तो हमें और जगह चाहिए। हमें अपने अंडों को एक ही टोकरी में नहीं रखना चाहिए, यानी हमें अपनी पूरी प्रजाति को सिर्फ एक ग्रह तक सीमित नहीं रखना चाहिए। मैं इस पर बहुत मेहनत करता हूं। जैसा कि लुईस कैरोल की किताब *थ्रू द लुकिंग ग्लास* में एलिस कहती हैं, 'आपको एक ही जगह पर बने रहने के लिए भी पूरी तेजी से दौड़ना पड़ता है।' इसका मतलब है कि दुनिया काफी तेज गति से बदल रही है, तकनीक, कला, और विज्ञान इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि उनके साथ बने रहने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। मैं जितनी मेहनत करता हूं, उतना ही लगता है कि और मेहनत की जरूरत है, क्योंकि समय की गति बहुत तेज है।

हरेक इन्सान के जीवन में एक ऐसा समय आता है, जब उसे किसी नतीजे के लिए अपनी जान, अपनी दौलत और अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने का फैसला करना पड़ता है। जो इस चुनौती में नाकाम होते हैं, वे बस शारीरिक रूप से बड़े हो चुके बच्चे होते हैं, और कुछ नहीं हो सकते। वास्तविक परिपक्वता तभी आती है, जब हम इन जोखिमों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे, बिना संघर्ष के कोई महान उपलब्धि संभव नहीं होती। और यही वह बिंदु है, जहां से सच्ची प्रगति की यात्रा आरंभ होती है। एक यात्रा जो न केवल व्यक्तिगत, बल्कि समस्त मानवता के लिए परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकती है।

जब एआई नौकरी के इंटरव्यू लेता है

अगंभीर उम्मीदवारों की छंटनी के लिए मशीन द्वारा इंटरव्यू लेना समझ आता है, पर विशिष्ट कौशलों की पहचान तो मनुष्य ही कर सकता है।

नताली रोचा

द न्यूयॉर्क टाइम्स

सैन एंटोनियो में मार्केटिंग पेशेवर चौवन वर्षीय जेनिफर डन कुछ माह पहले मार्केटिंग की नौकरी के लिए रिक्रूटर फर्म द्वारा आयोजित साक्षात्कार देने पहुंचीं। वह अपनी नई भूमिका और अपने नियोक्ता के संबंध में जानने को लेकर काफी उत्सुक थीं। इसके बजाय, एलेक्स नाम के एक वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रिक्रूटर ने उन्हें साक्षात्कार का समय तय करने के लिए मोबाइल पर एक संदेश भेजा।

तय समय पर डन के पास एलेक्स का फोन आया, डन ने पूछा, 'क्या आप इन्सान हैं?' एलेक्स ने कहा, 'नहीं, मैं इन्सान नहीं हूं। लेकिन, मैं यहां साक्षात्कार प्रक्रिया को सहज बनाने के लिए हूं।' अगले बीस मिनट तक डन ने एलेक्स के सवालों के जवाब दिए। हालांकि, एलेक्स उनके ज्यादातर सवालों का जवाब नहीं दे सका। डन के अनुसार, एआई रिक्रूटर बातचीत में दोस्ताना भाव लाना चाह रहा था, लेकिन उन्हें यह सब अजीब लग रहा था। शायद इसीलिए उन्होंने साक्षात्कार पूरा होने से पहले ही फोन काट दिया।

आप सोचते हैं कि एआई आपकी नौकरी छीन लेगा, लेकिन यह सबसे पहले रिक्रूटर बनकर चुनौती पेश कर रहा है। ये स्वायत्त रिक्रूटर, जिन्हें एजेंटिक एआई के नाम से जाना जाता है, एआई का नया स्वरूप हैं। नौकरी खोजने के कुछ पहलू-जैसे रिज्यूमे की जांच और मीटिंग निर्धारित करना-समय के साथ तेजी से स्वचालित होते गए हैं, लेकिन साक्षात्कार लंबे समय से इस प्रक्रिया का वह हिस्सा माना जाता था, जिसमें मानवीय पुट की सबसे ज्यादा दरकार होती है। अब एआई इस क्षेत्र में भी दखल दे रहा है, जिससे नौकरी ढूंढने का सफर और भी अधिक हताशा भरा हो गया है। कंप्यूटर साइंस व गणित में स्नातक 22 वर्षीय चार्ल्स व्हिटली, जो एआई के साथ दो बार साक्षात्कार दे चुके हैं, का कहना है कि एआई साक्षात्कारकर्ता के साथ बात करना 'बहुत ही असहज महसूस' होता है। एक इंटरव्यू में तो एआई की आवाज को अधिक स्वाभाविक बनाने के लिए हम्म, ओह जैसे शब्द डाले गए, लेकिन ये डरा ज्यादा रहे थे।

दरअसल, नियोक्ताओं को अधिक उम्मीदवारों से बात करने में मदद करने और मानव रिक्रूटरों का बोझ कम करने के लिए रोबोट साक्षात्कारकर्ता विकसित किए हैं। युवाओं को वित्तीय निवेश सिखाने वाली ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकुवर स्थित गैर-लाभकारी संस्था प्रोपेल इंपैक्ट ने जनवरी में रिबन एआई के साक्षात्कारकर्ता का उपयोग शुरू किया। संस्था की कार्यकारी निदेशक शेरलिन चोक ने बताया कि इससे संस्था को अपने फेलोशिप कार्यक्रम के लिए 500 आवेदकों की स्क्रीनिंग करने में मदद मिली, जो पिछले साल के 150 आवेदकों से कहीं ज्यादा है। इससे समय की बचत हुई और आवेदकों को भी सहूलियत हुई। हालांकि, ऑनलाइन जॉब बोर्ड जिपरिक्रूटर की कॅरिअर विशेषज्ञ सैम डीमेस कहती हैं कि भर्ती प्रक्रिया से इन्सानों को बाहर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एआई में पूर्वाग्रह हो सकता है और किसी उम्मीदवार के अनुभव, कौशल और नौकरी के लिए उपयुक्तता का पूरी तरह से मूल्यांकन करने के लिए उस पर भरोसा नहीं जता सकते।

57 वर्षीय एमिली रॉबर्ट्सन-विंगस्ट जैसे लोगों के लिए यह बुरी खबर है। अप्रैल में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोडक्ट मार्केटिंग के उपाध्यक्ष पद के लिए ईव नाम के एआई ने उनका साक्षात्कार लिया, जिसमें एमिली को अपना कैमरा चालू रखना था और स्क्रीन के एक छोटे से कोने में उन्हें ईव दिख रहा था। ईव ने एमिली और जॉब के बारे में आधा दर्जन से ज्यादा सवाल पूछे। करीब एक घंटे बाद उन्होंने ईव से भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के बारे में पूछा, तो वह कोई जवाब नहीं दे सका। इसको लेकर एमिली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि वह यह सोचने के लिए मजबूर हो गईं कि क्या वह एक प्रयोग भर थीं? उन्होंने कहा, 'क्या मेरा सिर्फ एआई एजेंट को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया गया या फिर कोई नौकरी भी थी?' हालांकि, कुछ लोगों ने एआई साक्षात्कारकर्ताओं के साथ अपने अनुभव को अच्छा बताया। 21 वर्षीय कॉलेज छात्र जेम्स गु ने फरवरी में प्रोपेल इंपैक्ट के जरिये ग्रीष्मकालीन विश्लेषक पद के लिए एक रोबोट साक्षात्कारकर्ता से बात की। उसने कहा कि एआई से बात करने में ज्यादा स्वतंत्रता महसूस हो रही थी और एआई भी उसके बारे जानने में दिलचस्पी ले रहा था। जेनिफर डन कहती हैं कि बीते दो महीनों के दौरान उन्होंने नौ साक्षात्कार दिए, लेकिन अपने पहले मशीनी इंटरव्यू के बारे में उन्होंने कहा कि यदि विकल्प दिया जाता है, तो वह आगे कभी भी एआई को साक्षात्कार नहीं देना चाहेंगी। उन्होंने कहा, 'यह मुझे बनावटी लगता है।'

एआई गार्डेल्स

ये एआई सिस्टम को नैतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। गार्डेल्स ऐसे अदृश्य फिल्टर होते हैं, जो तत्काल पकड़ लेते हैं कि एआई सिस्टम कहां गलती करने वाला है, ताकि उसे रोक दिया जाए। यदि एआई कोई ऐसी जानकारी या प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है, जो निर्धारित नियमों का उल्लंघन करती हो-जैसे घृणास्पद भाषण, हिंसा को बढ़ावा देना, या गलत जानकारी देना, तो गार्डेल्स उसे रोक देते हैं या संशोधित कर देते हैं। गार्डेल्स एआई की विश्वसनीयता बढ़ाने के साथ ही यह भी सुनिश्चित करते हैं कि एआई आउटपुट से समाज को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे।

©The New York Times 2025

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

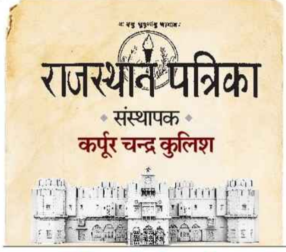

प्रवासी भारतीयों पर हमले रोकने के उठाए जाएं कदम

टेक्सास में वॉशिंग मशीन को लेकर हुए मामूली विवाद ने मानवता को तार-तार कर दिया। भारतीय मूल के 50 वर्षीय चंद्रमौली नागमल्लैया का सिर उनकी पत्नी और बेटे के सामने धड़ से अलग कर दिया गया। मोटल मैनेजर नागमल्लैया पर उनके सहकर्मी का यह हमला क्या सिर्फ व्यक्तिगत आक्रोश था या अमरीकी समाज में भारतीय वर्चस्व के खिलाफ जहर?

प्रवासी भारतीय अमरीकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, फिर भी स्थानीय लोग उन्हें उनके रोजगार में बाधा मानते हैं। यह निर्मम हत्या ही नहीं, प्रवासियों के सपनों को कुचलने की साजिश भी है। अमरीका में भारतीयों पर नफरत का सिलसिला पुराना है। 1907 के बेलिंगहैम दंगे हों या 1980 के दशक में न्यू जर्सी के 'डॉटबस्टर्स' गिरोह द्वारा भारतीयों पर हमले। यूरोप में भी हालात बेहतर नहीं। कनाडा में 2019-22 के बीच दक्षिण एशियाई लोगों के खिलाफ नफरत अपराध 143 प्रतिशत बढ़े, जहां भारतीय छात्रों को सड़कों पर गालियां दी जाती हैं। ब्रिटेन में 2023-24 में हिंदू मंदिरों पर हमले दोगुने हो गए, जबकि फ्रांस और जर्मनी में भारतीय पेशेवरों को 'आर्थिक चोर' कहकर धमकाया जाता है।

ये मामले साबित करते हैं कि पश्चिमी समाज में भारतीयों की सफलता ही उनसे नफरत की बड़ी वजह बन जाती है। स्थानीय लोगों की विफलता का दोष प्रवासियों पर डाल दिया जाता है। दुनिया के शीर्ष देशों- अमरीका, यूएई, मलेशिया, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, आस्ट्रेलिया आदि में करीब 3.43 करोड़ भारतीय रहते हैं। ये प्रवासी न केवल 135 अरब डॉलर के रेमिटेंस भेजते हैं- जो भारत की जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है, बल्कि मेजबान देशों की अर्थव्यवस्थाओं को भी मजबूत करते हैं। फिर नफरत क्यों? उनकी मेहनत में स्थानीय लोगों को नाकामी क्यों दिखाई देती है? वे किसी देश पर 'कब्जा' नहीं कर रहे, बल्कि अर्थव्यवस्था को साझा कर रहे हैं। कल्पना कीजिए, अगर हर देश के लोग अपने ही बॉर्डर में कैद हो जाएं तो ग्लोबल वर्किंग कल्चर मर जाएगा। विभिन्न देशों के लोग बिना घुले-मिले, बिना सीखे, कैसे प्रगति करेंगे? भारतीय आईटी विशेषज्ञ अमरीका को सिलिकॉन वैली देते हैं, तो अमरीकी इंजीनियर भारत को स्पेस टेक सिखाते हैं। यूएई के निर्माण में भारतीय मजदूर पसीना बहाते हैं, बदले में गल्फ के निवेश भारत आते हैं। यह आदान-प्रदान दुनिया की जीडीपी का 10-15 प्रतिशत बढ़ाता है।

विश्व बैंक के अनुसार, प्रवास से वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 3 प्रतिशत बूस्ट मिलता है। अगर यह रुका, तो इनोवेशन ठप, ट्रेड गिरेगा और गरीबी फैलेगी। अमरीकी टेक इंडस्ट्री 40 प्रतिशत भारतीयों पर निर्भर है। यूरोप की हेल्थकेयर में वे 20 प्रतिशत योगदान देते हैं। अगर इसे रोका गया तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा। संस्कृतियां खत्म हो जाएंगी और सीखना-सिखाना बंद हो जाएगा। यह समय है कि पश्चिमी सरकारें आईना देखें। ऐसी नफरतों को कानूनों की सख्ती से कुचला जाए, तभी सुधार होगा।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता- 'शक्ति'-किसकी? सर्वभूतेष- सभी भूतों की। नर की-मादा की-जड़ सृष्टि की भी। प्रत्येक पुरुष की। प्रत्येक प्राणी पुरुष है- प्रत्येक प्राणी स्त्री है। हर प्राणी स्वयं ही स्वयं की शक्ति भी है।

स्त्रैण भाव में है माधुर्य

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

शरीर ही ब्रह्माण्ड

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन।
निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्।। (गीता 2.45)
अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा।। (गीता 7.4)
जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्।। (गीता 7.5)
एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय।
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा।। (गीता 7.6)

सारांश यह है कि प्रकृति और पुरुष दोनों मिलकर सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, संचालित करते हैं। प्रकृति ब्रह्म का स्वभाव है। अतः प्रकृति ब्रह्म ही है। सः त्री- वही त्रिगुणमयी प्रकृति (स्त्री) है। अग्नि भी बिना सोम के अस्तित्व में नहीं रह सकता, सोम (ऋत) भी बिना आधार के नहीं रहता। दोनों साथ रहते हैं। यही अर्द्धनारीश्वर है। हर पुरुष स्त्री है, हर स्त्री भी भीतर पुरुष ही है। बाहर में पुरुष भोक्ता दिखाई देता है, भीतर स्त्री भोक्ता है। संकल्पित होकर जीना पौरुष है।

या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता- 'शक्ति'-किसकी? सर्वभूतेष- सभी भूतों की। नर की-मादा की-जड़ सृष्टि की भी। प्रत्येक पुरुष की। प्रत्येक प्राणी पुरुष है- प्रत्येक प्राणी स्त्री है। हर प्राणी स्वयं ही स्वयं की शक्ति भी है।

या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्ति-रूपेण संस्थिता- भ्रान्ति ही माया है- पुरुष स्वयं को स्त्री नहीं समझता, स्त्री स्वयं को पुरुष नहीं मानती। एकांगी दृष्टिकोण ही भ्रान्ति है। मैं पुरुष हूं- स्त्री को पुरुष नहीं मानता। स्त्री पुरुष को कुछ सीमा तक स्त्री मानती है, उसको भोग सकती है। मूल में यही भ्रान्ति है। विश्व ईश्वर की कृति है- ईश्वर ही अपने अंश रूप से विश्व बना है।

मौलिक अग्नि-यजुराग्नि-सत्याग्नि है- ब्रह्म है। ऋक्- साम ही पुर हैं। यजुः पुरुष है। इसी से यज्ञाग्नि का विकास होता है। स्वयंभू ब्रह्माग्नि, सूर्य देवाग्नि, पृथ्वी भूताग्नि बन जाता है। ब्रह्म ही मूल प्रकृति है, अतः प्राणाग्नि/प्राकृताग्नि कहलाती है। यज्ञाग्नि वैश्वानर अग्नि है। मौलिक अग्नि में ताप-दाह नहीं होता। वैश्वानर (यज्ञाग्नि) में ताप होता है।

चारों अग्नियों से चार प्रकार का पानी उत्पन्न होता है। पानी उत्पन्न करना अग्नि का स्वाभाविक धर्म है। ब्रह्माग्नि से अम्भ, देवाग्नि से मरीचि, भूताग्नि से 'मर' नामक पानी पैदा होता है। वैश्वानर से श्रद्धा नामक पानी पैदा होता है। प्राणाग्नि के ताप से पसीने निकलते हैं। सिर- ब्रह्मरंध्र पर स्वयंभू की प्रतिष्ठा है। परिश्रम से इसके वाग् भाग पर आघात होता है, पानी (अंभः) पैदा होता है।

सूर्य शुक्राग्नि है। प्रेम-शोक दोनों से अग्नि क्षुब्ध हो जाता है। चन्द्रमा मंथी (मंथन करने वाला) है। क्षुब्ध अग्नि से मन पिघलता है। इसका प्रधान स्थान चक्षु है। मन चान्द्र है। चन्द्रमा सोमरसमय है, अब् मूर्ति है। यदि सौर अग्नि का इस पर आघात होता है तो चान्द्रमन द्रुत होता है। प्रेम का उद्रेक होने से प्रेमरस कहते हैं। इसका पांच भागों में प्रवाह होता है–श्रद्धा, वात्सल्य, स्नेह, काम और रति। श्रद्धा, वात्सल्य तथा स्नेह तीनों में दोनों ओर चेतन अवस्था रहती है। जड़ वस्तु से प्रेम 'काम' है। चारों की समष्टि रति है। रति के दो ही अधिकारी हैं–ईश्वर और स्त्री।

यजुः के वाक् भाग से जो तत्त्व उत्पन्न हुआ वह अग्नि की भांति ऋजु (सीधा-ऊपर गति करने वाला) न होकर व्याप्त हो गया- फैल गया। इसे 'आप' कहा गया। इसी अप् तत्त्व में पांच बल (जाया-धारा-आप-जीवन-ऋत) पैदा होते हैं। आत्मा की रक्षा के कारण ऐसा होता है। इच्छा ही प्राण का उद्गम है। प्राण ही आप का कारण बनता है (इच्छा)। पानी उत्पन्न कर प्रजापति आपोमण्डल के गर्भ में प्रविष्ट हो जाता है–तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्। इच्छा शक्ति से शुक्र तत्त्व पैदा होता है- पानी में प्रजनन शक्ति आती है। पानी से ही पृथ्वी बनती है, औषधि में शुक्र प्रवेश करता है। प्रजा उत्पन्न करता है। इसको जायाबल कहते हैं। शुक्ररूप यह पानी मातरिश्वा की प्रेरणा से अग्नि को अपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लेता है। अब यह अग्निधर्मा पानी प्रजनन धर्मा है। स्त्री स्वयं जाया है। सौम्या है। सोममय जायाबल ही स्त्री का उपादान कारण है। अग्नि पुरुष है। वही जायाबल से वेष्टित गर्भगत शोणित है। स्त्री का गर्भगत शोणित शुद्ध अग्नि है।

शुक्र सोमरूप जाया है। इसका उष्मा भाग पुरुष है। पुरुष भी जाया है। आत्मा सर्वप्रथम पुरुष शरीर में- शुक्र में, गर्भधारण करता है। प्राणी का यह प्रथम जन्म है। सर्वांग शरीर का शुक्र- पुरुषाकृति से युक्त होकर ही शोणित में आहुत होता है। प्राणी शुक्र द्वारा माता के गर्भाशय में प्रतिष्ठित होता है। उपादान कारण को ही शुक्र कहते हैं, अतः शुक्र व शोणित दोनों ही शुक्र हैं- जाया हैं।

पुरुष यदि स्वयं के पुरुष भाग को ही विकसित करता है, तो वह एकांगी होकर आक्रामक- उष्ण प्रकृति वाला हो जाएगा। उसका शरीर बलप्रधान होता जाएगा। उसके स्त्रैण गुण लुप्त होते चले जाएंगे। श्रद्धा-वात्सल्य-स्नेह-काम-रति ये पांचों ही भाग अल्पतम रह जाएंगे। यह भी चेतना नहीं रहेगी कि किसी स्त्री में पुरुष तत्त्व-पौरुष भी होता है। उसे पूर्णतया निर्बला- अबला मानकर आक्रामक हो उठेगा। पुरुष का अहंकार हावी ही रहेगा। ठीक इसके विपरीत यदि कोई स्त्री पौरुष भाव को विकसित करती जाए, तो ये सारे गुण-दोष उसमें भी दिखाई पड़ेंगे। उसमें भी स्त्री सापेक्ष गुणों का अभाव ही रहेगा। वह केवल शरीर मात्र से मादा होगी, स्त्री-सापेक्ष अन्य सौन्दर्य-माधुर्य-करुणा के गुण वहां अल्पतम होंगे। ऐसे में वह पुरुषों के बीच सहज रूप से रह सकती है। उसका अहंकार- त्रियाहठ-प्रतिशोध- ईर्ष्या जैसे दोष प्रभावी रहेंगे। पौरुषेय स्वच्छन्दता की उसमें प्रधानता होने लगेगी।

पुरुष को संतुलन के लिए अपने स्त्रैण भाग का भी, पौरुष भाव के समान विकास करना चाहिए। सेवा-भक्ति रूप में प्रेम-माधुर्य का विकास निरन्तर अभ्यास के द्वारा बनाए रखना चाहिए। पत्नी के पौरुष भाग को भी विकास के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप दोनों का आत्मविश्वास पोषित होगा। परस्पर सौहार्द भाव बढ़ेगा। जिससे जीवन के प्रति पूर्णता का भाव विकसित होता जाएगा। जीवन में नया सवेरा होगा।

-क्रमशः

gulabkothari@epatrika.com

क्यूआर कोड को स्कैन कर आप आलेख सुन भी सकते हैं।

स्त्री: देह से आगे
विषय विवेचन

अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में ***गुलाब कोठारी*** के संबोधन का वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

बुक इनसाइट

द रेडिकल फंड

जॉन फैबियन विट की नई किताब द रेडिकल फंड अमरीकी इतिहास की एक अनकही और बेहद प्रभावशाली कहानी को सामने लाती है। यह पुस्तक दिखाती है कि कैसे दूरदर्शी लोगों के एक छोटे समूह और एक करोड़ डॉलर की फंडिंग ने बीसवीं सदी की शुरुआत में अमरीका की दिशा बदल दी।

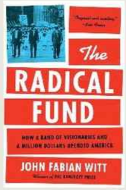

किताब का केंद्र बिंदु वह रेडिकल फंड है, जिसके जरिए सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार और मजदूर आंदोलनों को बल मिला। यह फंड उस दौर में सामने आया जब अमरीका गहन असमानताओं, नस्लीय भेदभाव और राजनीतिक दमन से जूझ रहा था। लेखक ने विस्तार से बताया है कि यह धन कैसे संगठनों, वकीलों और आंदोलनों तक पहुंचा और किस तरह इसने अमरीकी समाज को नई ऊर्जा दी। विट की लेखन शैली शोधपूर्ण व रोचक है। यह किताब इतिहास को नए नजरिए से देखने का मौका देती है।

आर्ट एंड कल्चर

पारंपरिक कला के लिए जरूरी जड़ता से मुक्ति

प्रसार भारती के 'वेव्स ओटीटी' पर आने वाली सीरीज 'पैठणी- द क्वीन ऑफ साड़ी' कहने को तो बात सिर्फ पैठणी की करती है, लेकिन कला की दुनिया से आपका सरोकार है तो यह समझने में देर नहीं लगती कि पैठणी के बहाने यह इस तरह की तमाम कलाओं पर बात कर रही है, जो बाजार और समय के दबाव में अपनी मूल पहचान से दूर होकर लुप्त हो रही हैं। पैठणी का एक कलाकार कहता है, करघा नहीं चलता, करघे के साथ धीरज, आदत और वक्त भी उसके धागों में चलता है। आज के जमाने में लोग बहुत तेजी से चलते हैं। कहा जाता है आमतौर एक पैठणी साड़ी को बनाने में उस पर की जाने वाली कलाकारी के अनुसार तीन महीने से सालभर तक का समय लग सकता है। पैठणी रेशम के धागों और सोने-चांदी के तारों की जरी को हाथ के करघे पर बुनकर तैयार की जाती है, इसके डिजाइन में मोर और तोते को खास तौर पर चित्रित किया जाता है। हाथ से बनाए जाने के कारण ही हरेक पैठणी दूसरे से अलग होती है।

विनोद अनुपम
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त कला समीक्षक
@patrika.com

इस सीरीज में पैठणी की एक बुजुर्ग कलाकार कहती है कि हर धागा एक रिश्ता है, जिसे बहुत संभालकर रखना पड़ता है। हाथों के साथ मन में कोमलता न हो तो आसानी से टूट जाते हैं। मुश्किल यह है कि अब करघे के बजाय मशीन पर सोने चांदी की जगह नकली तारों से पैठणी एक दिन में चार बन रही हैं। जाहिर है कीमत में कई गुना अंतर के कारण यह नकल पैठणी की परंपरागत पहचान के सामने अब यह एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो रही है लेकिन ऐसे कलाकार आज भी हैं, जिनके लिए पैठणी सिर्फ साड़ी नहीं, दो हजार साल पुरानी पहचान है। उसके हर रंग में अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं की यादें जुड़ी हैं। कहानी महारके येवला शहर में शुरू होती है, जो वास्तव में पारंपरिक पैठणी के निर्माण के लिए विख्यात है। बगैर किसी टिप्पणी के शहर के विस्तार को दिखाते हुए निर्देशक भास्कर विश्वनाथन पतली गलियों, सूनी सड़कों और पुराने मकानों से बहुत कुछ कह जाते हैं। दुनिया की सबसे महंगी साड़ियां बनाने वाले शहर का विकास की गति में इस तरह पीछे छूट जाना, कहीं न कहीं अपनी पारंपरिक कला के प्रति हमारी निरपेक्षता को भी प्रदर्शित करता है।

इस सीरीज में विदेश से आया युवा अर्जुन असली पैठणी को तकनीक के सहारे पारंपरिक कलाकारों के साथ एक बार फिर बाजार में उतारने के अभियान में जुट जाता है। वास्तव में चाहे पैठणी हो या मिथिला पेंटिंग या फिर कोई लोकगाथा-लोकगीत जितनी जरूरी पारंपरिक पहचान है, उतनी ही जरूरी जड़ता से मुक्ति भी। समय के साथ चलकर ही कोई कला कालजयी बनती है। 'पैठणी- द क्वीन ऑफ साड़ी' के रूप में स्क्रीन पर पारंपरिक कला के प्रति ऐसी चिंता उम्मीद देती है।

भू-राजनीति | वैश्विक मंच पर नई ध्रुवीयता का निर्माण हो रहा

पश्चिम का ढलता सूरज: शक्ति संतुलन के नए युग की आहट

समय की धारा अनवरत गति से बहती है और इस बहाव में कभी कोई शाश्वत नहीं रहता। यह ध्रुव सत्य है कि जो कभी महाशक्ति रहे हों, वे भी इतिहास की करवटों में धूल-धूसरित होकर समय की गहराइयों में गुम हो गए। ग्रीस, रोम, मौर्य, गुप्त या मुगल साम्राज्य- सभी की शौर्यगाथा आज इतिहास की पुस्तकों में ही कैद हैं। आज जब यह प्रश्न उठता है कि क्या पश्चिम के दिन सचमुच ढलान की ओर हैं, तो यह केवल राजनीतिक या आर्थिक विश्लेषण का विषय नहीं रह जाता, बल्कि यह एक ऐतिहासिक विवेचन और दार्शनिक मंथन का भी आयाम बन जाता है।

नृपेन्द्र अभिषेक नृप
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

पश्चिम, विशेषकर अमरीका और यूरोप, पिछले चार-पांच शताब्दियों से वैश्विक प्रभुत्व के केंद्र में रहे हैं। उपनिवेशवाद की भयावह लकीरों ने जिस प्रकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका की आत्मा को कुचला। उसने पश्चिमी देशों को अकूत धन, संसाधन और सामरिक शक्ति प्रदान की। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और बाद में अमरीका ने अपने सैन्य और औद्योगिक सामर्थ्य से विश्व के अधिकांश हिस्सों पर आधिपत्य स्थापित किया। आज अमरीका, जो स्वयं को विश्व का प्रहरी और 'लोकतंत्र का रक्षक' कहता रहा है, आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्तरों पर अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था अपार उत्पादन शक्ति के बावजूद चीन के सामने पिछड़ती दिखाई दे रही है। बीते दो दशकों में चीन ने जिस तीव्र गति से औद्योगिक विकास किया है, उसने अमरीका के वर्चस्व को सीधी चुनौती दी है। यूरोप की स्थिति और भी विचित्र है। यूरोप के साम्राज्यवादी देश, जिन्होंने कभी भारत, अफ्रीका और अरब को अपना गुलाम बनाया था, आज स्वयं अमरीकी संरक्षण के बिना अपने अस्तित्व को सुरक्षित नहीं मानते। ब्रेक्जिट के बाद यूरोप की आर्थिक एकता में दरार पड़ी और रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप की निर्बलता को और उजागर कर दिया। यूरोप न तो रूस का प्रतिरोध कर पा रहा है, न ही अमरीका से स्वतंत्र होकर अपनी राह चुन पा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि पश्चिमी शक्ति-संतुलन के सामने भारत और एशियाई देश कहां खड़े हैं। एक समय था जब भारत स्वयं ब्रिटेन की दासता में जकड़ा हुआ था, किंतु आज वही भारत पश्चिम के सामने मजबूती से खड़ा है। अमरीका और यूरोप भारत को अपने सामरिक गठजोड़ों में शामिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, क्योंकि उन्हें भली-भांति ज्ञात है कि एशिया का भविष्य भारत और चीन के हाथों में निहित है। परंतु भारत की नीति संतुलित है- वह रूस, अमरीका और यूरोप तीनों से अपने संबंध बनाए रखते हुए स्वतंत्र विदेश नीति की धारा को साधने में विश्वास रखता है।

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या विश्व बहुध्रुवीय युग में प्रवेश कर चुका है? यदि हां, तो पश्चिम का एकध्रुवीय साम्राज्य सचमुच समाप्त हो रहा है। यह यथार्थ है कि अमरीका और यूरोप अब भी प्रभावशाली रहेंगे, किंतु वे अकेले विश्व की दिशा तय करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। भारत, चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश वैश्विक मंच पर नई ध्रुवीयता का निर्माण कर रहे हैं।

हालांकि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि पश्चिम के दिन लद चुके हैं। यदि अमरीका और यूरोप समय रहते अपनी नीतियों को बदल लें, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति छोड़कर साझेदारी का मार्ग चुनें, तो वे भविष्य में भी प्रभावी रह सकते हैं। दुनिया बहुध्रुवीय हो रही है, जहां एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका की आवाज भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण होगी जितनी अमरीका और यूरोप की।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड** स्कैन करें

डिज्नी के सिंड्रेला कैसल की प्रेरणा

अलकाजार दे सेगोविया

***स्पेन** का अलकाजार दे सेगोविया केवल एक किला नहीं, बल्कि इतिहास की अद्भुत कहानी है। कहा जाता है कि डिज्नी के सिंड्रेला कैसल की प्रेरणा इसी अद्भुत स्थापत्य से मिली थी। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित यह दुर्ग प्राचीनकाल से सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है। इस किले को आज जिस भव्य रूप में दुनिया देखती है, उसका श्रेय जाता है किंग जॉन द्वितीय को। उन्होंने पुराने- जर्जर दुर्ग का पुनर्निर्माण कराया था।*

आपकी बात

अराजकता की स्थिति चिंताजनक

वैश्विक परिदृश्य में देखें तो कई देशों में जनविद्रोह के कारण अराजकता की स्थिति बनी हुई हैं। यह चिंताजनक है। इजरायल-हमास संघर्ष, रूस-यूक्रेन युद्ध, अमरीका-ईरान-इजरायल विवाद, फ्रांस का ताजा घटनाक्रम शांतिपूर्ण विश्व के लिए अशांति का दुखद संदेश हैं। शक्तिशाली देशों के निजी हितों और प्रतिस्पर्धा की वजह से ऐसी स्थितियां बन गई हैं।

- **भंवरलाल सारण**, बालोतरा

रोग फैलने की आशंका बढ़ी

भारी मानसून की वजह से देश के कई हिस्सों में तबाही मच गई है। गांवों और शहरों में पानी भरने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। बाढ़ ने जलस्रोतों को भी दूषित कर दिया है, जिससे रोग फैलने की आशंका बढ़ गई है।

- **लहर सनाढ्य**, उदयपुर

युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिले

युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। उनको सही नेतृत्व और दिशा न मिले तो स्थिति भयावह हो सकती है। युवाओं को शिक्षा, रोजगार और देश के विकास में अपनी ऊर्जा लगानी चाहिए।

- **गजेंद्र चौहान**, कसौदा

आज का सवाल

महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

हिंदी दिवस (14 सितंबर) विशेष | संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष भी घोषित किया है

सहकार से समृद्धि : हिंदी में विकास का एक नया विमर्श

बिरेन्द्र पाण्डेय
भाषाविद एवं स्तंभकार
@patrika.com

हिंदी दिवस सिर्फ एक भाषाई पर्व नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और भावनात्मक एकात्मता का उत्सव है। इस वर्ष इसका महत्त्व और बढ़ गया है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को 'अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष' घोषित किया है। यह एक अर्थगर्भित संयोग है कि 'सहकार से समृद्धि' का राष्ट्रीय दृष्टिकोण और हिंदी दिवस का उत्सव, दोनों हमें यह स्मरण कराते हैं कि विकास की स्थिरता व समावेश तभी संभव है जब वह जनभाषा में व्यक्त हो और सामूहिक सहयोग से आगे बढ़े।

सहकारिता-भारतीय जीवन का आधार: भारतीय दर्शन की आत्मा सह-अस्तित्व और एकात्मता में है। ऋग्वेद का मंत्र 'संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्' सहकारिता के इसी भाव को रेखांकित करता है। हमारे गांवों की परंपरा सदियों से सहकारी ढांचे पर आधारित रही है- पंचायतें, सामूहिक कृषि, जल-संरक्षण व हस्तशिल्प उत्पादन सब इसी की मिसाल हैं।

सिर्फ नारा नहीं, भविष्य की रणनीति

जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, सहकार से समृद्धि सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीति है। इसका उद्देश्य छोटे किसानों, कारीगरों और महिला समूहों को बाजार से जोड़ना, ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देना व वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाना है। यह लक्ष्य तभी सफल हो सकता है जब विकास का संवाद हिंदी जैसी जनभाषा में हो।

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का स्वप्न रखा था- एक ऐसा भारत, जहां हर गांव आत्मनिर्भर व संगठित इकाई बने। गांधीजी, विनोबा भावे और मजदूर संगठक दत्तोपंत ठेंगड़ी जैसे नेताओं ने इस विचार को जन-जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी को माध्यम बनाया। स्वाधीनता संग्राम में सहकारिता और हिंदी ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया।

हिंदी-सहकारिता की जनभाषा: भारत के अधिकांश सहकारी संस्थान हिंदी भाषी क्षेत्रों में कार्यरत हैं। जब समितियों और बैंकों में संवाद हिंदी में होता है तो पारदर्शिता और सहभागिता दोनों बढ़ती हैं। 1965 के राजभाषा अधिनियम और उसके बाद की नीतियों ने सहकारी संस्थानों में हिंदी प्रयोग को मजबूती दी। आज नाबार्ड, इफको, नाफेड जैसे संस्थान वेबसाइट से लेकर मोबाइल ऐप तक हिंदी में सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं।

ग्राम विकास से राष्ट्र निर्माण: सहकारिता का सफर ग्राम से राष्ट्र तक फैला है- कृषि में बीज और उर्वरक वितरण, दुग्ध उत्पादन में अमूल मॉडल, और वन उत्पाद सहकारी समितियां इसकी जीवंत मिसाल हैं। इन क्षेत्रों में हिंदी ने संवाद को सरल और योजनाओं को प्रभावी बनाया है।

डिजिटल सहकारिता और हिंदी : 21वीं सदी में सहकारिता तकनीक से जुड़ रही है। ई-गवर्नेंस पोर्टल, ई-नाम (राष्ट्रीय कृषि बाजार), इफको किसान ऐप और नाबार्ड ई-लर्निंग पोर्टल- सब हिंदी में उपलब्ध हैं। एआइ आधारित चैटबॉट किसानों को मौसम, ऋण व बीमा की जानकारी हिंदी में दे रहे हैं।

लोकतांत्रिक भागीदारी का माध्यम : सहकारी संस्थाएं 'एक सदस्य, एक मत' के सिद्धांत पर चलती हैं। यह लोकतंत्र का सबसे जमीनी रूप है। जब यह प्रक्रिया हिंदी में होती है तो किसान, महिला श्रमिक तक सक्रिय निर्णयकर्ता बन जाते हैं।

वैश्विक महत्त्व: वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श सहकारिता की आत्मा है। जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों से निपटने में सहयोग और साझेदारी का भारतीय मॉडल मार्गदर्शक बन सकता है। हिंदी इसे विश्व पटल पर संप्रेषित करने की क्षमता रखती है। हिंदी दिवस और अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का यह संगम हमें यह बोध कराता है कि भारत की जड़ें सहकारिता में हैं और उसकी आत्मा हिंदी में। जब सहकार से समृद्धि का मंत्र हिंदी के माध्यम से जन-जन तक पहुंचेगा, तभी विकास वास्तव में सबका और सबके लिए साकार होगा।

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

बार-बार धमकियां

पहले दिल्ली उच्च न्यायालय और उसके बाद बॉम्बे उच्च न्यायालय को मिली धमाके की धमकी बहुत चिंता की बात है, जिसका इशारा है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। पूजा-उत्सवों का समय आ रहा है और ऐसे समय में पहले भी सुरक्षा को लेकर चिंता रही है। इस बार, जिस तरह से सीधे उच्च न्यायालयों को निशाना बनाने की साजिश हुई है, उससे पता चलता है कि ई-मेल से धमकी देने वाले अपराधियों की मंशा कितनी खतरनाक है। न्याय के जिन मंदिरों में लोग न्याय की तलाश में जुटे थे, वहां बम खोजने की नौबत आ गई। दोनों उच्च न्यायालयों के परिसरों को खाली करा लिया गया। जब अचानक न्यायिक कामकाज ठप्प हो गया, तब हड़कंप की स्थिति बन गई और बम निरोधक दस्ते सक्रिय हो गए। हालांकि, यह अच्छी बात है कि उच्च न्यायालयों के परिसरों में व्यापक तलाशी के बाद कुछ भी चिंताजनक नहीं मिला है। ऐसे में, खुफिया एजेंसियों की जिम्मेदारी बढ़ गई है। धमकी कहां से आई? किसने दी? उसका मकसद क्या था? इन तमाम सवालों के जवाब खोजना जरूरी है। इतना तो पता है कि ई-मेल से धमकी मिली है, पर धमकी देने वाले तक पहुंचना होगा।

ई-मेल से धमकी भेजने वाले का जुड़ाव पहली नजर में तमिल राजनीति से लग रहा है। विशेष रूप से स्टालिन परिवार को निशाना बनाने या डराने की धमकी दिख रही है। सावधानी से जांच की जरूरत है। धमकी में तमिल राजनीति को घसीटने की साजिश वास्तव में जांच एजेंसियों को भटकाने का प्रयास हो सकती है। धमकी में क्या-क्या कहा गया है, इसके विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय यह जानना ज्यादा जरूरी है कि धमकी के पीछे कौन है? अगर धमकी देने वाला तमिलनाडु की स्थानीय राजनीति को प्रभावित करना चाहता है, तो फिर उसने उच्च न्यायालय को क्यों निशाने पर लिया? कहीं निगाहें और कहीं निशाना की यह आतंकी शैली गंभीर बात है। धमकी को महज झूठी मानकर हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना चाहिए। ऐसी धमकियों की परिपाटी लोगों की चिंताओं को बढ़ा रही है। धमकियों की जांच को अधूरे में नहीं छोड़ना चाहिए। यह सुरक्षा एजेंसियों का मखौल उड़ाने जैसा है, अतः एजेंसियों को युद्ध जैसी मुद्रा में सक्रिय होते हुए जांच को वाजिब अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।

आए दिन मिल रही धमकियां सुरक्षा एजेंसियों का मखौल उड़ाने जैसा है, अतः एजेंसियों को युद्ध-मुद्रा में सक्रिय होते हुए जांच को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए।

ऐसी धमकियों का सिलसिला गौरतलब है। अभी 9 सितंबर को ही राष्ट्रीय राजधानी स्थित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और दिल्ली के मुख्यमंत्री सचिवालय को बम की धमकी मिली थी। बीती 28 अगस्त को दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित जीसस ऐंड मैरी कॉलेज सहित लगभग 20 कॉलेजों को बम की धमकी वाले ईमेल मिले थे। उसके पहले स्कूलों को भी ऐसी ही धमकी एकाधिक बार मिल चुकी है। हां, यह सही है कि धमकी देने वालों का साइबर ज्ञान अच्छा है, लेकिन इस ज्ञान की काट हमारी सुरक्षा एजेंसियों के पास जरूर होनी चाहिए। अगर हम धमकियों की तहकीकात पूरी नहीं करेंगे, तो यह हमारी विफलता होगी। आने वाला दौर ऐसी ही साइबर चुनौतियों का है, साइबर संसार का कोई भी कोना हमारी एजेंसियों की पकड़ या नजर से अछूता नहीं रहना चाहिए। धमकी देने वालों के डिजिटल फुटप्रिंट ऐसे नहीं होने चाहिए कि हमारी पकड़ में न आएं। अगर हमारी एजेंसियां इस मोर्चे पर अमेरिका या इजरायल से जरूरी तकनीकी मदद ले सकती हैं, तो हिचकना नहीं चाहिए। इन देशों के साथ हमारे समझौते पहले से ही हैं, यह अपनी सुरक्षा के तमाम वैश्विक समझौतों का लाभ उठाने का समय है।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 13 सितंबर, 1950

विकास योजना

लन्दन में राष्ट्रमंडल के अर्थ मंत्रियों का सम्मेलन होने वाला है। ऐसा एक सम्मेलन कुछ महीनों पहले आस्ट्रेलिया में हुआ था और उसमें राष्ट्रमंडलीय देशों ने कुछ लाख पौंड दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी एशिया के अल्प-विकसित देशों की सहायता के लिए सुलभ करने का तय किया था।

उनसे यह मांग की गई थी कि वे अपनी योजनाओं का खाका राष्ट्रमंडलीय देशों के अगले सम्मेलन में प्रस्तुत करें, ताकि उन पर विचार करके सहायता की रकम निर्धारित की जाये। तदनुसार भारत ने कहते हैं छः वर्षीय विकास योजना बनाई है और उस पर लगभग 18 अरब 40 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें भारत अपने आन्तरिक साधनों से 10 अरब 30 करोड़ रुपये जुटाने की आशा करता है और शेष 8 अरब 10 करोड़ रुपये उसे बाहर के देशों से मिलना चाहिए, तभी वह अपनी छः वर्षीय विकास योजना को कार्यान्वित कर सकता है। आंतरिक साधनों से भारत 10 अरब 30 करोड़ रुपये कैसे जमा कर सकेगा, इसका भी एक मोटा अनुमान तैयार कर लिया गया है। उसके अनुसार, 350 करोड़ रुपये नये करों से, 120 करोड़ रुपये सरकारी खर्च में कमी करके, 150 करोड़ रुपये राज्य द्वारा संचालित उद्योगों की आमदनी बढ़ाकर, 300 करोड़ रुपये जनता से कर्ज लेकर और 110 करोड़ रुपये रेलवे के घिसाई कोष से प्राप्त किया जायगा।

जहां तक सरकारी खर्च में कमी करने का प्रश्न है, हम बहुत आशावान नहीं हैं। जिस शाही ढंग से अंग्रेजी सरकार खर्च करती थी, राष्ट्रीय सरकार ने उसमें कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किया। रक्षा व्यय पहले से अधिक हो रहा है। इसके लिए काश्मीर का प्रकरण और पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत कुछ उत्तरदायी हैं। कुछ आकस्मिक घटनायें ऐसी हो रही हैं, जिनके कारण अकल्पित रूप में खर्च बढ़ जाता है। फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम और अधिकतम वेतन में बेहद अन्तर है और युद्ध काल में सरकारी नौकरों की जो अंधाधुंध भर्ती कर ली गई थी, काम न रहने पर भी कर्मचारियों की उस सेना को कायम रखा जा रहा है। सरकार की मशीनरी इतनी धीमी हरकत करती है कि खर्च में कमी करने की अनेक योजनायें तैयार हुईं और वे अभी तक आलमारियों की शोभा बढ़ा रही हैं।

हिंदी के विस्तार को गहराई भी मिले

प्रियदर्शन | वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार

गरीब आदिवासी-दलित घरों के बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, इनकी भाषा हिंदी है। ये बच्चे भाषा और साहित्य का चरित्र भी बदलेंगे और हिंदी को नए सिरे से स्थापित कर पाएंगे।

हिंदी का विस्तार इन दिनों हिंदी प्रेमियों को पुलकित कर रहा है। कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से जुड़े चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी जैसे जो एप आ रहे हैं, वे सब हिंदी में जानकारी दे रहे हैं, गूगल हिंदी में सूचनाएं दे रहा है, इंटरनेट पर हिंदी का प्रसार बढ़ रहा है, हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में डब हो रही हैं, बॉलीवुड की हिंदी फिल्में सात समंदर पार झंडे गाड़ रही हैं, दुनिया के सभी महादेशों में अब हिंदी बोलने वाले लोग और लिखने वाले लेखक मिल जाते हैं। दुनिया के कई बड़े विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग खुल रहे हैं और हिंदी के लेखकों पर काम हो रहा है।

भोपाल में 'विश्व रंग' नाम की एक संस्था सालाना जलसे कराती है, जिसमें 50 से ज्यादा देशों के सैकड़ों लेखक शामिल होते हैं। दो साल पहले मॉरीशस में हुए इसके आयोजन में भी दुनिया के हर कोने से लोग पहुंचे हुए थे। अब तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक में ऐसी संस्थाएं सक्रिय हैं, जो वहां हिंदी पर केंद्रित नियमित आयोजन कराती हैं। दुनिया के कई शहरों में रेडियो स्टेशनों पर हिंदी के कार्यक्रम अलग से होते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम मेधा से जुड़ी कंपनियां लगातार हिंदी पर काम कर रही हैं। तकनीक की दुनिया में हिंदी के लिए तन्मयता और गंभीरता से काम कर रहे विशेषज्ञ बालेंदु शर्मा दाधीच ने एक कार्यक्रम में विस्तार से बताया था कि हिंदी में अनुवाद को बेहतर करने के लिए कैसे-कैसे उपक्रम हो रहे हैं।

हिंदी के विस्तार की बात यहीं खत्म नहीं होती। इसमें चलने वाले टीवी चैनल सैकड़ों नहीं, हजारों की संख्या में हैं। इनमें सैकड़ों समाचार चैनल हैं। मुख्यधारा की पत्रकारिता से अलग होकर कई लोग यू-ट्यूब पर अपना काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। इसे हिंदी की नई ताकत बताया जा रहा है। हिंदी के पांच सबसे बड़े अखबारों का कुल प्रसार एक करोड़ से ऊपर का है। इन सबको जोड़ें, तो पता चलेगा कि हिंदी करोड़ों लोगों को रोजगार भी दिला रही है। यह उन सरकारी नौकरियों से अलग है, जहां हिंदी विभागों और अनुवाद विभागों में सालाना हजारों नौकरियां सृजित होती हैं।

हिंदी के प्रकाशन की दुनिया भी बहुत तेजी से फैली है। हर साल लाखों किताबें छप और बिक रही हैं। इनमें बड़ी तादाद साहित्यिक प्रकाशनों की है। जो लोग हिंदी किताबें न बिकने का रोना रोते हैं- जो बहुत हद तक वास्तविक भी है- उनके लिए एक ताजा सूचना यह हो सकती है कि इस महीने हिंदी के एक लेखक विनोद कुमार शुक्ल को हिंद युग्म प्रकाशन 30 लाख रुपये की रॉयल्टी देने जा रहा है।

बेशक, जो पारंपरिक और प्रसिद्ध प्रकाशन संस्थान हैं, उनके यहां से प्रकाशित किताबों को यह रॉयल्टी नहीं मिल पाती, लेकिन कुछ प्रकाशनों ने हिंदी का जो नया ब्रांड खड़ा किया है, उसे वह युवाओं तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। याद कर सकते हैं कि दो-तीन साल पहले हिंदी लेखिका गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास पर इंटरनेशनल बुकर मिला और उनकी भी किताबें बहुत बड़ी तादाद में बिकीं। इसके अलावा तमाम छोटे-बड़े शहरों में हो रहे 'लिटफेस्ट' हिंदी के लेखकों के लिए एक बड़े अवसर की तरह आ रहे हैं, जहां संवाद-विवाद सब कुछ की गुंजाइश है।

तो हिंदी दिवस पर इस उत्सवधर्मी किस्म के माहौल का जश्न स्वाभाविक है। लेकिन हिंदी को लेकर खुल रहे ये सारे रास्ते उन बंद गलियों की गवाही नहीं देते, जहां हवा कुछ गुमगुमाई है, भाषा कुछ असहाय है, लेखक अपने ही समाज में अजनबी है और किताबें बहुत सारे उपभोक्ता कबाड़ के बीच उपेक्षित सामग्री की तरह पड़ी हुई हैं। हिंदी के साथ सबसे ज्यादा बेईमानी खुद को हिंदी वाला बताने वाले उस मध्यवर्गीय समाज ने की है, जो अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा रहा है। ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक शिक्षा के माध्यमों पर अंग्रेजी का एकाधिकार इतना प्रबल और अपरिहार्य है कि मध्य प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में प्रबंधन और चिकित्सा की हिंदी भाषा में शुरू हुई पढ़ाई लगभग विफल साबित हुई है- या तो यहां छात्र नहीं के बराबर हैं या फिर जो पास करके निकल रहे हैं, उन्हें नौकरी मिलने में मुश्किल हो रही है।

तो हिंदी के जिस विस्तार पर हम खुश हैं, वह एक बोली के रूप में उसका विस्तार है, भाषा के रूप में नहीं। हिंदी भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेलखंडी को घर से विस्थापित कर रही है और अंग्रेजी हिंदी को स्कूल से। जहां तक कृत्रिम मेधा, इंटरनेट, फिल्मों की डबिंग आदि का सवाल है, उसका काम हिंदी ही नहीं, भारत की बीसियों और दुनिया की सैकड़ों भाषाओं में चल रहा है। तो यह हिंदी में क्यों नहीं होगा, जो अंग्रेजी और मंदारिन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है- वह भाषा, जिसे करीब 60 करोड़ लोग बोलते हैं। लेकिन यह हिंदी या तो टीवी-सिनेमा देखने-बनाने के काम आ रही है या फिर राजनीति करने के।

यह टिप्पणी हिंदी के विस्तार की खुशी को कम करने के लिए नहीं की जा रही, यह समझने के लिए लिखी जा रही है कि हम अपनी भाषा की, उसके सम्मान की रक्षा कैसे करें? अगर हम वाकई चाहते हैं कि हिंदी एक स्वस्थ-सशक्त भाषा के रूप में विकसित और अंग्रेजी के वर्चस्व से मुक्त हो, तो इसे ज्ञान-विज्ञान और विशेषज्ञता की भाषा बनाना होगा। इसके लिए संस्थान खोलना पर्याप्त नहीं होगा, बिल्कुल स्कूली स्तर पर यह लड़ाई लड़नी होगी। कहना मुश्किल है कि इसके लिए हमारे भीतर राजनीतिक इच्छाशक्ति कितनी बची है, लेकिन वह पैदा करनी होगी।

बेशक, हिंदी की उपेक्षा की इस लंबी सुरंग के एक सिरे पर रोशनी भी दिखती है। जिन गरीब आदिवासी-दलित घरों के बच्चे पहली बार स्कूल जा रहे हैं, उनकी भाषा हिंदी है। निस्संदेह, ये बच्चे भाषा और साहित्य का चरित्र भी बदलेंगे और दफ्तरों व अन्य संस्थानों तक आएंगे, तो हिंदी को नए सिरे से स्थापित भी कर पाएंगे। इस काम में बाकी भारत को उनके साथ खड़ा होना होगा। 60 करोड़ लोग जब एक आवाज में बोलेंगे और बाकी भारतीय भाषाओं के साथ मेल-मिलाप की शब्दावली विकसित करेंगे, तो हिंदी का असली और सौष्ठव भरा रूप निखरेगा, जिस पर हम गुमान कर सकेंगे। हिंदी का विस्तार सुखद है, लेकिन इस विस्तार को गहराई भी चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

सूखती संवेदनाओं के दौर में 'क्राइंग क्लब' का सहारा

क्षमा शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार

इस साल मार्च में तीन निकट परिजनों की मृत्यु हो गई। दो दिल्ली में, एक दिल्ली से बाहर। हर जगह जाना हुआ। हालांकि, इस बात को बहुत दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन अबकी बार ज्यादा महसूस हुई। वह यह कि किसी की मृत्यु पर दूरदराज से जो नाते-रिश्तेदार आते हैं, वे थोड़ी देर शोक प्रकट करके अपनी-अपनी बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। कई बार तो घर वाले इस दुखद समाचार से जुड़ा वाट्स एप ग्रुप भी बना लेते हैं। इस पर बहुत से लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हैं।

इन दिनों किसी शोक के अवसर पर दूसरे लोगों को तो छोड़िए, अपने बाल-बच्चे, बहन-भाई, यहां तक कि कई बार पत्नी-पति भी नहीं रोते दिखते। कहने को कोई कह सकता है कि रोने से क्या, दुख तो मन में होता है। सही बात है, पर वह मन का दुख ही तो है, जब किसी के बिछुड़ने के शोक में आप फूट पड़ते हैं। क्या वाकई आंसू इतनी बुरी चीज है या कि यह मान लिया गया है कि आंसू कमजोरी की निशानी है, इसलिए उसे किसी के सामने नहीं बहाना चाहिए। पुराने समय में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं, जब पति की मृत्यु पर पत्नी रो नहीं पाई या पत्नी की मृत्यु पर पति खामोश हो गया, तो कहा गया कि इससे उसके दिमाग और दिल पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए दिवंगत व्यक्ति की तमाम करुण बातें याद दिलाकर, उसे रुलाने की कोशिश की गई। अब यह दिखाई नहीं देता। रोने को हमारी कमजोरी का प्रतीक बना दिया गया है। अब ऐसे गाने भी कहां सुनाई देते हैं- *ये आंसू मेरे दिल की जुबान हैं।*

मुंबई, दिल्ली में क्राइंग क्लब बनाए गए हैं। सूरत में 2017 से हैं। महीने में एक बार आप यहां दूसरों के साथ रो सकते हैं।

इन दिनों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि करोड़ों लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्या से परेशान हैं। इसकी वजह शायद यह भी है कि काम के तमाम दवाबों के चलते, हम अपनी नैसर्गिक भावनाओं को व्यक्त करना भूलते जा रहे हैं। सुख-दुख में हंसना, मुस्कराना, कहकहे लगाना, रोना, उदास होना, ये सब ऐसी ही भावनाएं हैं। लेकिन इन दिनों हमारी तमाम भावनाएं 'इमोजी' में सिमट आई हैं। डॉक्टर कहते हैं, रोना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आंसू तमाम विषाक्त तत्वों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही दुखों को कम करने में मदद करते हैं। हमारे तनाव को दूर करते हैं। समझ में नहीं आता कि फिर हम अपनों के सामने रो क्यों नहीं सकते? हम किसी अफसोस के समय भी आंसू नहीं बहा सकते।

कुछ साल पहले तनाव को दूर करने के लिए जापान में 'क्राइंग क्लब' बनाया गया था। इसका नाम है- रुई कत्सू। रुई का मतलब है आंसू और कत्सू का एक्टिविटी या गतिविधि। इसे जापानी उद्योगपति हिरोकी तैराई ने खोला था। उनका कहना था कि रोने के बाद लोग बहुत हल्का और तनाव रहित महसूस करते हैं। इससे पहले हिरोकी तलाक का जश्न मनाने वाला क्लब भी बना चुके हैं। इसी को देखते हुए मुंबई में भी ऐसा ही 'क्राइंग क्लब' शुरू किया गया है। सूरत में तो यह 2017 से है। दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु में भी ऐसा हो रहा है। यहां महीने में एक बार आप दूसरों के साथ मिलकर रो सकते हैं। इन क्लबों की खास बात यह बताई जाती है कि रोने के कारण कोई आपको जज नहीं करेगा, यानी कमजोर नहीं मानेगा। यही नहीं, यहां अजनबियों को आप अपने दुख बता सकते हैं, उनके सामने खूब रो सकते हैं। उनके कंधे पर सिर रख सकते हैं। वे आपकी बातों को धैर्य से सुनेंगे। आपको दिलासा देंगे। यहां कोई आपसे रोने की वजह नहीं पूछेगा। रोने के साथ-साथ भावनाओं में बहकर आप एक-दूसरे का आलिंगन भी कर सकते हैं। शरीर विज्ञान भी मानता है कि रोने से हमारे अंदर तनाव के जो रसायन होते हैं, वे बाहर निकल जाते हैं।

इन क्लबों में 'टीयर थेरेपिस्ट' को भी बुलाया जाता है, जिससे लोग उन दुखों और बातों को याद कर सकें, जिन्हें बहुत दिनों से अंदर छिपाए हैं। उनका बोझ ढो रहे हैं और इसके कारण तरह-तरह के रोगों के शिकार बन रहे हैं। इन क्लबों को चलाने वाले कह रहे हैं कि हम पुरानी परंपराओं को जीवित कर रहे हैं। आंसू को कमजोरी न मानकर उसका सम्मान करना आना चाहिए। जब लोग इकट्ठे मिलकर रोते हैं, तो वे समझते हैं कि उनके दुख अकेले के नहीं हैं। आंसू एक तरह से 'रि-क्रिएशन' का हिस्सा है। हर एक आंसू बहुत सी ऐसी बातों का गवाह है, जो देखी गईं, महसूस की गईं, पर कभी कही नहीं गईं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

आध्यात्मिक पूर्णता

ईश्वर मनुष्य से जो चाहता है, वह है, उसे व्यक्ति में और सामूहिकता में यहां साकार करना- अर्थात ईश्वर को अपने जीवन में प्राप्त करना। योग की प्राचीन व्यवस्था आत्मा और जीवन को समन्वित नहीं कर पाई, न जोड़ पाई; उसने संसार को माया अथवा ईश्वर की क्षणिक क्रीड़ा मानकर रद्द कर दिया। परिणामस्वरूप, जीवन-शक्ति का ह्रास हुआ और भारत का अधःपतन हुआ।

गीता कहती है, *उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम्* अर्थात यदि मैं कर्म न करूं, तो ये लोग विकीर्ण होकर टुकड़े-टुकड़े हो जाएं। भारत के 'ये लोग' बरबाद हो गए हैं। यदि कुछ संन्यासियों, वैरागियों और साधुओं ने आत्मबोध अथवा मोक्ष प्राप्त कर लिया; यदि कुछ भक्त प्रेम के आवेश में, ईश्वर के नशे और आनंद में नाचने लगें और सारी की सारी जाति जीवन से वंचित होकर, बुद्धि से वंचित होकर घोर तमस (अंधकार) की गहराइयों में डूबी रहे, तो फिर यह किस तरह की आध्यात्मिक पूर्णता हुई?

मैं व्यवसाय को कोई बुरी या दूषित वस्तु नहीं मानता, जितना वह प्राचीन आध्यात्मिक भारत में माना जाता था।... सभी कुछ निर्भर करता है उस भावना पर, जिससे एक चीज की जाती है; उन सिद्धांतों पर, जिन पर वह निर्मित होती है और उस उपयोग पर, जिसमें उसे लगाया जाता है। मैंने राजनीति की है, अत्यंत उग्र प्रकार की क्रांतिकारी राजनीति, *घोरं कर्म* और मैंने युद्ध का समर्थन किया है, उसके लिए आदमी भी भेजे हैं, यद्यपि राजनीति सदैव और प्रायः एक बहुत साफ उद्यम नहीं है, न ही युद्ध को कर्म का एक आध्यात्मिक मार्ग कहा जा सकता है। पर कृष्ण अर्जुन को एक भयंकर युद्ध को चलाने के लिए कहते हैं और उसके उदाहरण द्वारा लोगों को हर प्रकार के मानव कार्य, 'सर्वकर्माणि' करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। क्या तुम दावा करते हो कि कृष्ण अनाध्यात्मिक आदमी थे और अर्जुन को दी गई उनकी सलाह भूल थी या सिद्धांत में गलत थी?

...मैं नहीं मानता कि एक संन्यासी की जीवन पद्धति आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अपरिहार्य है या सिर्फ उसके ही अनुरूप है। आध्यात्मिक आत्मस्वामित्व के मार्ग का, आध्यात्मिक आत्मदान और ईश्वर की शरणागति के पथ का अपना स्थान है, जिसमें कर्म या किसी प्रकार के कार्य अथवा ईश्वर द्वारा मांगे गए सभी प्रकार के कार्यों के मध्य अहं और कामना का त्याग करना होता है।... भारतीय शास्त्रों और परंपरा में, *महाभारत* में तथा अन्यत्र, जीवन से संन्यास की आध्यात्मिकता और कर्म के आध्यात्मिक जीवन, दोनों के लिए स्थान दिए गए हैं। कोई यह नहीं कह सकता कि एक ही केवल भारतीय परंपरा है और जीवन तथा सब प्रकार के कार्यों, 'सर्वकर्माणि' की स्वीकृति अभारतीय, यूरोपीय या पाश्चात्य और अनाध्यात्मिक है।

यदि कुछ संन्यासियों और वैरागियों ने आत्मबोध अथवा मोक्ष प्राप्त कर लिया; और सारी की सारी जाति बुद्धि से वंचित होकर घोर तमस में डूबी रहे, तो यह कैसी आध्यात्मिक पूर्णता हुई?

श्री अरविंद

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

प्राचीन काल में भारत अध्यात्म व व्यापार में विश्व का नेतृत्व करता था। 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' का प्रमुख आयाम ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, जिस पर वैश्विक उथल-पुथल का कम से कम प्रभाव पड़े।

घातक रूढ़िवादी सोच आज भी कायम

बेंगलुरु में एक 18 वर्षीय छात्रा की मौत ने पूरे समाज को झकझोर दिया है। उसने एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने के लिए पीरियड्स रोकने की दवा ली थी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि गहरी चेतावनी है कि मासिक धर्म को रोकने या बदलने वाली दवाएं कितनी घातक हो सकती हैं। ऐसे में, यह सवाल उठना लाजिमी है कि क्या थोड़ी सुविधा या सामाजिक दबाव किसी इंसान की जान से अधिक महत्वपूर्ण है? यह सवाल आज न केवल स्वास्थ्य के लिहाज से, बल्कि सामाजिक सोच और सरकारी नीतियों की दृष्टि से भी अत्यंत प्रासंगिक हो गया है।

यह केवल एक महिला के व्यक्तिगत स्वास्थ्य से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था व सरकारी नीतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, तो इन हॉर्मोनल दवाओं का गलत या बिना डॉक्टर की सलाह के सेवन करना बेहद खतरनाक होता है, मगर दिक्कत यह है कि भारत जैसे देश में अब भी धार्मिक अवसरों, शादी-ब्याह और परीक्षाओं के दौरान महिलाओं पर मासिक धर्म रोकने का दबाव डाला जाता है। इसके कारण वे ऐसी दवाएं लेने को मजबूर होती हैं। जबकि, डॉक्टर मानते हैं कि मासिक धर्म को रोकने वाली गोलियों का सेवन शरीर में गंभीर बदलाव तो ला ही सकता है, मौत के मुंह में भी धकेल सकता है। बेंगलुरु की घटना बता रही है कि हमारे समाज में मासिक धर्म से जुड़ी झिझक कितनी गहरी है। महिलाएं यह सोचकर ऐसी दवाएं खा लेती हैं कि यह आसान उपाय है, लेकिन तात्कालिक राहत के बावजूद उनका यह निर्णय गंभीर बीमारियों की जड़ बन सकता है।

सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के लिए बेहतर होगा कि महिलाएं अपने मासिक धर्म को प्राकृतिक रूप से स्वीकार करें और केवल आपात स्थिति में, वह भी डॉक्टर की सलाह पर ही दवा लें। जागरूकता अभियान इस समस्या के समाधान का सबसे अहम हिस्सा है। स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म से संबंधित शिक्षा को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए, ताकि किशोरावस्था से ही लड़कियां समझ सकें कि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, जिसको रोकने का प्रयास उचित नहीं। इन अभियानों का मकसद केवल खतरे के बारे में बताना नहीं, बल्कि सुरक्षित विकल्पों, जैसे सेनेटरी पैड, मेंस्ट्रुअल कप और स्वस्थ जीवनशैली की जानकारी देना भी होना चाहिए। इतना ही नहीं, महिलाओं पर दबाव कम करने के लिए सामाजिक अभियान चलाया जाना भी जरूरी है, तभी समाज का भला हो सकेगा।

डॉ नीलू तिवारी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम
पीरियड्स और रूढ़ियां

अपनी सेहत को लेकर सजग नौजवान

कैफे से बाहर निकलते हुए जब मैं पार्किंग लॉट में पहुंची, तो एक लड़की कुछ दूरी पर किसी की स्कूटी पर बैठी हुई थी और कुछ घबराई हुई लग रही थी। इतनी देर में उस स्कूटी के मालिक आ गए और उन्होंने लड़की को स्कूटी से उतरने के लिए कहा। यह सुनकर वह लड़की और घबरा गई। मैं उस लड़की से बात करना चाह रही थी, पर इतने में स्कूटी वाले का एक और दोस्त वहां आ गया। उसने लड़की से बात करने की कोशिश की, तो वह धीमी आवाज में कुछ कहने लगी, 'खून', 'डेट्स', 'पीरियड्स', 'सॉरी'...। उस लड़के ने बात समझ ली और उसने लड़की को शांत रहने के लिए कहा। वह अपने दोस्त को किनारे ले लगा और कुछ समझाने लगा। तब तक मैं भी वहां पहुंच गई, तो उसने बिना किसी झिझक के मुझसे मदद मांगी। उसने कहा, 'मैम, मुझे लगता है कि उस लड़की को पहली पीरियड्स हुई है और वह अकेली और घबराई हुई है। आप प्लीज उसका ध्यान रखें, तब तक मैं सेनेटरी पैड लेकर आता हूं।' मैं वहां स्तब्ध खड़ी थी और मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, 'हां, ठीक है।'

इस पूरी घटना पर उस लड़के की संवेदनशीलता और सकारात्मक नजरिये को देखकर मैं हैरान थी। मैं उस लड़की के पास गई और उसे शांत कराया, मैंने उससे कहा कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। थोड़े समय बाद वह लड़का भी वापस आ गया और मैं उस लड़की को अपने साथ वाशरूम लेकर गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि कई बार हम महिलाओं के नजरिये में भी फर्क हो जाता है। कई बार हम महिलाएं ही 'मासिक धर्म' जैसी आम और प्राकृतिक चीजों को इतना जटिल बना देती हैं कि पुरुष इसको लेकर असहज हो जाते हैं। मासिक धर्म कोई पाप या समस्या नहीं है। यह तो हमारा समाज है, जिसने इस पर संस्कारों और न जाने किन-किन चीजों की चादरें डाल दी हैं। उस लड़के ने जो किया, उससे मैं इतना तो जान गई कि हमारे समय के लड़कों में भी इसको लेकर जागरूकता बढ़ी है, जो अच्छी बात है। उस घटना से मुझे एहसास हुआ कि एक लड़का भी सेनेटरी पैड खरीद सकता है और एक लड़की भी सेनेटरी पैड को अखबारों में लपेटे और काली प्लास्टिक में छिपाए बिना कहीं ले जा सकती है। आज मासिक धर्म के बारे में सार्वजनिक रूप से बात करना पाप नहीं है। उस लड़के ने मुझे सिखाया कि मासिक धर्म को लेकर समाज में जितनी संकीर्ण सोच है, उसमें हम महिलाओं का भी दोष उतना ही है, हमें साथ मिलकर ही इसको बदलना होगा निस्संदेह, नई पीढ़ी पुरानी सोच को बदल रही है और वह इसमें सफल भी रहेगी।

रैंडम रिफ्लेक्शंस ऑन रिलेशनशिप

https://t.me/AllNewsPaperPaid

सुंदर आचरण सुंदर शरीर से अच्छा है

फर्जी राजनीति

राजनीतिक दलों के लिए नियमन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग और विधि आयोग को नोटिस दिया जाना एक सही कदम है। इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया है। ऐसे लोग केवल पैसा उगाहने या अपना रसूख कायम करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल गठित करते हैं और चुनाव लड़ते अथवा लड़वाते हैं। राजनीतिक दलों के नियमन की मांग करने वाली याचिका के अनुसार काले धन को सफेद करने वालों के साथ अलगाववादी तत्व भी फर्जी राजनीतिक दलों का गठन करने लगे हैं और इनमें से कुछ अपनी राजनीतिक सक्रियता के नाम पर पुलिस सुरक्षा भी हासिल कर लेते हैं। इसे महज आरोप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल में आयकर विभाग की छापेमारी में कई फर्जी राजनीतिक दल पता चले। कुछ समय पहले अकेले उत्तर प्रदेश में 20 ऐसे पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का मामला सामने आया था, जो दानदाताओं से चंदा लेकर उसका एक हिस्सा अपने पास रखकर शेष राशि दानदाताओं को वापस कर देते थे। इस प्रक्रिया में कालेधन और टैक्स चोरी के पैसे का इस्तेमाल होता था। इसे राजनीति की आड़ में किए जाने वाले घोटाले के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। राजनीतिक दल गठित करके गैर कानूनी काम करने का धंधा इसीलिए फल-फूल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना संगठन बनाकर उसे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है। देश में ऐसे न जाने कितने राजनीतिक दल हैं, जो कागजी हैं और जो एक अकेले व्यक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। यह ठीक है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ तो ठोस नियम-कानून होने चाहिए। चुनाव आयोग अपने यहां हजारों की संख्या में पंजीकृत राजनीतिक दलों के दर्जे को तब तक समाप्त नहीं कर सकता, जब तक वे छह वर्ष तक कोई चुनाव न लड़ें। कागजी दलों के लिए इस शर्त का दुरुपयोग करना बहुत आसान है। कागजी राजनीतिक दल इसलिए गठित होते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट के साथ कई विशेषाधिकार भी मिलते हैं। यदि राजनीति करने के नाम पर की जानी वाली मनमानी पर रोक लगानी है तो चुनाव आयोग को अधिकार संपन्न बनाना होगा। यह ठीक नहीं कि कोई मान्यता प्राप्त दल कितनी भी देशघाती हरकत करे, चुनाव आयोग के पास उसकी मान्यता खत्म करने का अधिकार नहीं। यह भी विचित्र है कि अपने देश में संगीन आरोपों में जेल में बंद लोग भी चुनाव लड़ने में समर्थ हैं, पर मामूली मामले में भी जेल गया कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता।

सजा अकेले भुगतनी है

मिथिलांचल में एक कहावत है-चोरबा के अर्जल सब कोय खाय, असगर चोरबा फांसी जाय। भाव यह कि व्यक्ति चोरी के माध्यम से जो कुछ अर्जित करता है, उसका भोग स्वजन करते हैं। मित्र और करीबी करते हैं। लेकिन, चोर को जब सजा मिलती है तो वह उसे अकेले भुगतता है। सीख यह कि चोरी से बचें। लेकिन, सीख कौन ले रहा है। चोरी का स्वरूप बदल गया है। अब यह रिश्वतखोरी के रूप में है। देखिए कि कहावत कहां-कहां चरितार्थ हो रही है। बड़े-बड़े लोग जेल जा रहे हैं। सजा काट रहे हैं। कोई इस कष्ट में साथ नहीं दे रहा है। लेकिन, चोरी-रिश्वतखोरी के माध्यम से अर्जित धन का भोग उनके स्वजन आराम से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार की शिकायत बढ़ी है। भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी तेज हुई है। सरकारी निगरानी एजेंसियां जहां कहीं हाथ रखती हैं, कोई न कोई पकड़ में आ ही जाता है। मगर, धर-पकड़ की कार्रवाई से रिश्वतखोरों का मनोबल नहीं टूटता है। असल में यह केवल कानून का मामला नहीं है। लोकलाज का भी मामला है। अगर यह समाप्त हो जाए तो गलत काम करने से व्यक्ति को कोई कानून नहीं रोक सकता है। पता नहीं पत्नी, बच्चे और घर के दूसरे लोगों को यह देख सुनकर कैसा लगता होगा। कार्यालय सहायक से लेकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तक रिश्वतखोरी के आरोप में जेल जा रहे हैं। क्या अगली बार रिश्वत लेने से पहले आप उपरोक्त कहावत का स्मरण करेंगे?

चोरी का स्वरूप बदल गया है। अब यह रिश्वतखोरी के रूप में है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या भारत के प्रति बदले हुए दिख रहे ट्रंप के रवैये पर भरोसा किया जा सकता है?

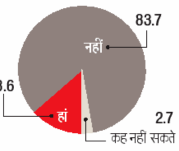

आज का सवाल
क्या भारत ने कतर में इजरायली हमले की निंदा करके सही किया?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

जरूरी है हर मतदाता का सत्यापन

आशुतोष झा

यदि चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख मृत, स्थानांतरित लोगों के नाम हटा दिए तो इतना उबाल क्यों? यह लोकतंत्र पर मंडराता खतरा कैसे था?

इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अपने साथ आंधी-तूफान भी लाते हैं, लेकिन गर्द के बैठने के साथ सब स्पष्ट दिखाई भी देता है और स्थायी भी हो जाता है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। चुनावी लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची होती है और उसे दुरुस्त रखने के लिए बिहार में एसआइआर की शुरुआत हुई तो विवाद खड़ा हो गया। कुछ दलों की ओर से इसे सीधे-सीधे लोकतंत्र पर खतरा बताया गया, पर आरोप-प्रत्यारोप, अदालतों में हुए विश्लेषण और राजनीतिक मंचों पर दिए गए भाषणों के बीच यह तथ्य निकलकर सामने आया कि एसआइआर के जरिये मतदाता सूची का गहन परीक्षण जरूरी है और यह कैसे किया जाए, इसका अधिकार चुनाव आयोग को है। इस विवाद से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि बिहार ही नहीं पूरे देश के मतदाताओं को इसकी जानकारी हो गई कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो उन्हें क्या करना है। वे यह भी समझ गए कि यह काम नेताओं के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में राजनीतिक दलों की ओर से जितने प्रतिवेदन आए, उनमें अधिकांश दूसरों के नाम कटवाने के लिए ही थे। इस विवाद से यह भी स्पष्ट हो गया कि पूरे देश में एसआइआर हो और मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र को आटोमेटिक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी शुरू हो। इसके लिए नगर निगम से लेकर विदेश और गृह मंत्रालय तक को चुनाव आयोग से संबंधित डाटा शेयर करना होगा।

देश के अलग-अलग हिस्सों में एसआइआर की प्रक्रिया 20-25 वर्षों के अंतराल में होती है। अब चुनाव आयोग ने जता दिया है कि देश में एक साथ एसआइआर कराया जाएगा। इस पर राजनीतिक दलों का रुख देखना रोचक होगा। हाल में इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एसआइआर को रुकवाने के लिए जिस तरह की दलीलें दी गईं, उन्हें देखते हुए मान लेना चाहिए कि विपक्षी दलों की ओर से इसका विरोध ही किया जाएगा। हालांकि इस संवैधानिक प्रक्रिया को रोक पाना अब किसी के वश में नहीं है, पर पारदर्शिता की इस मुहिम को अभी राजनीतिक बवंडर के कई क्रम से गुजरना होगा।

यह बहुत ही अचंभित करने वाला था कि बिहार में एसआइआर की जिस प्रक्रिया पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इसमें कई लोगों और खासतौर से गरीबों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपनी ओर से कोशिश करें कि जिनके नाम गलत तरीके से कटे हैं, उनके नाम जोड़े जाएं तो अधिकतर प्रतिवेदन नाम कटवाने के ही आए। सबसे हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की रही। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उसने 89 लाख प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन सारे नाम कटवाने वाले थे। फिर अगर चुनाव आयोग ने 65 लाख मृत, स्थानांतरित और अनुत्तरित लोगों के नाम हटा दिए तो इतना उबाल क्यों? यह लोकतंत्र पर मंडराता खतरा कैसे था? विपक्षी दलों का रुख अभी भी नहीं बदला है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कमर कस कर रास्ता रोकने को तैयार है। एसआइआर की असली परीक्षा बंगाल में ही होगी। ध्यान रहे कि पिछले 15-20 वर्षों में पूरे देश में चुनावी हिंसा खत्म हो गई, लेकिन बंगाल अभी अपवाद है। यहां घुसपैठियों ने कई जिलों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। कई जगह चुनाव भारतीय वोटरों के हाथों से निकलकर घुसपैठियों के हाथों नियंत्रित हो गया है। राज्य में पुलिस और अन्य अधिकारियों का भी जिस तरह राजनीतिकरण हुआ है, उसे देखते हुए एसआइआर के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। संभव है गृह मंत्रालय को भूमिका निभानी पड़े। अच्छा होगा सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप हो। बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया का पुख्ता पालन हो जाए तो शेष देश में उसकी राह आसान हो जाएगी और उस बहस पर भी अंकुश लगेगा, जिसे संकीर्ण राजनीतिक कारणों से चलाने की कोशिश हो रही है।

यह अच्छा नहीं कि हर साल प्रदेशों में होने वाले चुनावों के वक्त देश विवादों में उलझा रहे, इसलिए भी एक साथ एसआइआर की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि मतदाता सूची के शुद्धीकरण और अपडेशन की प्रक्रिया बदली जाए। घर-घर जाकर हर एक वोटर की पड़ताल तो सही है, लेकिन आटोमेशन की भी शुरुआत होनी चाहिए और राजनीतिक दलों की ओर से अड़ंगा लगाना बंद होना चाहिए। जरूरत को देखते हुए हर व्यक्ति अपने आधार को वर्तमान पते के अनुसार अपडेट करता है। अच्छा हो कि आधार से मतदाता सूची जुड़ जाए। इससे एक से ज्यादा स्थानों पर मतदाता रजिस्टर ही नहीं होंगे। सिर्फ आधार से वोटर कार्ड को जोड़ना पर्याप्त नहीं। नागरिकता देना भले ही गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, लेकिन मतदाता सूची में नाम शामिल करने से पहले नागरिकता की पुष्टि करने का अधिकार चुनाव आयोग से छीना भी नहीं जा सकता। खासकर जब तक पूरे देश में एनआरसी न हो जाए और देश के नागरिकों का रजिस्टर न तैयार हो जाए। विपक्ष इसके भी आड़े खड़ा है। देश को अपने नागरिकों और अवैध तरीके से आए लोगों के बारे में जानकारी होनी ही चाहिए।

बिहार में जिन लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनमें से 22 लाख तो मृत थे। देश से हर साल औसतन दो लाख लोग नागरिकता छोड़कर विदेश में बस रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों से संपर्क में रहता तो है, लेकिन डाटा शेयरिंग की आटोमेटिक व्यवस्था नहीं है। जाहिर है कि जब सही आंकड़े आएंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उस वक्त जो भी विपक्ष में होगा, वह उसे तूल देगा। फिलहाल देश में लगभग 98 करोड़ वोटर हैं। वर्षों से मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण है और इसके लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और राजनीतिक दलों के साथ एक हद तक मतदाता भी। उचित यह होगा कि इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष एक साथ हों और उनमें व्यापक बहस हो। यह सुनिश्चित हो कि केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही सूची में शामिल हों और अपडेशन के लिए आटोमेटिक प्रक्रिया हो।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)
response@jagran.com

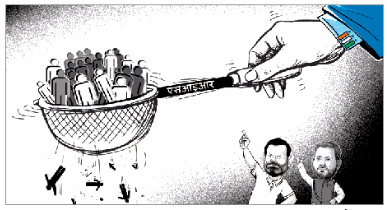

अवधेश राजपूत

सिगरेट स्त्री की आजादी का प्रतीक कैसे

क्षमा शर्मा

उस विचार को क्या कहा जाए, जो सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तु के सेवन को भी प्रगतिशीलता से जोड़ता है

किताब के बहाने धूमपान की पैरवी ● एक्स

बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधती राय की किताब 'मदर मैरी कम्स टू मी' आई है। बताते चलें कि अरुंधती की मां का नाम भी मैरी राय था। वह कैथोलिक ईसाई स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थीं। कुछ अखबारों ने इस पुस्तक के बहुत से अंश छापे हैं। इन अंशों में अरुंधती ने अपनी मां की विकट आलोचना की है। जैसे ही इस किताब का मुखपृष्ठ प्रकाश में आया, डिजिटल मीडिया में बवाल मच गया। इस पुस्तक के आवरण पर एक लड़की का सिगरेट पीते चित्र छपा है। इसके समर्थक कहने लगे कि मात्र मुखपृष्ठ देखकर किसी किताब के बारे में निर्णय क्यों देना चाहिए। सिगरेट लड़कियां पिएं या न पिएं, यह उनकी मर्जी है। आप मारल पुलिसिंग करने वाले कौन होते हैं। नैतिकता के सारे प्रश्न स्त्रियों पर ही क्यों लादे जाते हैं। यह वह जमाना नहीं कि लड़कियां किसी की आलोचना से डर जाएंगी। इसके बाद से बहुत-सी लड़कियों और स्त्रियों ने सिगरेट पीते हुए अपने चित्र फेसबुक पर लगाए। यहां तक कि मुक्तिबोध और राजेंद्र यादव को भी बीच में ले आया गया कि उनकी तो किसी ने आलोचना नहीं की, जबकि मुक्तिबोध का बीड़ी पीते हुए चित्र उनकी पुस्तक के आवरण पर ही छपा था और राजेंद्र यादव का भी सिगार पीते हुए चित्र छपा था।

तमाम विरोधियों ने कहा कि सवाल लड़कियों के सिगरेट पीने न पीने का नहीं है, सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसे प्रगतिशीलता और स्त्रीवाद से जोड़ना अच्छा नहीं है। यदि लड़के भी ऐसा करते हैं, तो वे आलोचना से परे नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आखिर अरुंधती अपने अलगाववादी विचारों के लिए ही जानी जाती हैं। वह कश्मीर के लोगों का आवाहन कर चुकी हैं कि इस भूखे-नंगे हिंदुस्तान से अलग हो जाओ। कुछ दिनों पहले यह लेखिका अपने मोहल्ले के पान वाले के पास गई थी। देखा कि एक के बाद एक लड़कियां सिगरेट खरीद और पी रही हैं। पान वाले से पूछा तो उसने कहा अब लड़कियां बहुत ज्यादा सिगरेट खरीदती हैं। किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत से डाक्टर बार-बार कहते रहे हैं। यह आज लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का एक बड़ा कारण बन रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य की चिंता सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी करनी चाहिए, लेकिन उस विचार को क्या कहा जाए, जो खान-पान को भी प्रगतिशीलता से जोड़ता है और सवाल उठाने वालों को रूढ़िवादी, पितृसत्ता का प्रतीक आदि कहता है। कौन नहीं जानता कि किसी उत्पाद को बेचने के लिए प्रकाशकों और लेखकों द्वारा मिलकर कैसी-कैसी मार्केटिंग रणनीतियां बनाई जाती हैं। प्रकाशकों के लिए किताब एक उत्पाद ही है, जिसे उन्हें खूब बेचना है और भारी मुनाफा कमाना है। इसीलिए किसी खास बात को प्रगतिशीलता और किसी बात को रूढ़िवादिता से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करते वक्त अपने ही उस विचार का कतई ध्यान नहीं रखा जाता, जिसमें चुनाव की बात की जाती है। चुनाव में भी आखिर उस चीज को कैसे अच्छा माना जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। मार्केटिंग से जुड़ी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कभी कहा था कि हम चाहें तो जहर को भी अमृत बनाकर बेच दें। बस, बेचना आना चाहिए।

बहुत पहले सिगरेट बनाने वाली एक कंपनी के मालिक जार्ज वाशिंगटन हिल को महसूस हुआ कि उसकी बिक्री उतनी नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए। उन दिनों अमेरिका में स्त्री अधिकारों की बातें खूब हो रही थीं। वाशिंगटन हिल को जैसे समस्या का हल मिल गया। उन दिनों अमेरिका में भी स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती थीं। वे एक मशहूर व्यक्ति एडवर्ड बर्नेज के पास पहुंचे। उन्होंने सिगरेट को स्त्री समानता और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक ताकतवर औजार की तरह पेश किया। अमेरिका की बहुत-सी अमीर स्त्रियों को पैसे देकर इस बात के लिए मनाया कि वे सड़क पर सिगरेट पीती हुई निकलें। आखिरकार 1929 में न्यूयार्क में रविवार के दिन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्रियां सिगरेट पी रही थीं। इस रैली को नाम दिया गया- टार्चेज आफ फ्रीडम। जैसा कि होना था, रैली को मीडिया में खूब जगह मिली और सिगरेट स्त्रियों के बीच छा गई। स्त्री स्वातंत्र्य के नाम पर यह अन्य देशों में भी जा पहुंची। वाशिंगटन हिल के पौ बारह हो गए।

कभी अपने यहां भी सिगरेट के ऐसे विज्ञापन टीवी और अखबारों में आते थे, जिनमें सिगरेट पीने वाले को बेहद शक्तिशाली और असली मर्द बताया जाता था। बाद में सरकार ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी। हाल में जब तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया, तो इसका मकसद भी तंबाकू उत्पादों से दूर रखने की मंशा से किया गया होगा। किसी पुरानी फिल्म में जब कोई सिगरेट पीता दिखाई देता है, तो नीचे वैधानिक चेतावनी आती है, जिसमें लिखा रहता है कि धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसी भारत में एक किताब इसलिए चर्चा पा रही है कि उस पर सिगरेट पीती लड़की का चित्र छपा है। नीचे कोई वैधानिक चेतावनी भी नहीं लिखी। हो सकता है कि किताब के विवाद से लेखिका और उनके प्रकाशक को लाभ हो। इसे ही जहर बेचना कहते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गुरु, नेता और प्रशासक

गुरुजन ज्ञान से, प्रशासक न्याय से और नेता समुचित दिशा-निर्देशन से समाज को सुमति और सुगति प्रदान करते हैं। यदि ये तीनों अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करें, तो समाज में आध्यात्मिक समुत्थान, समरसता, विचारों में पारदर्शिता और राष्ट्रीय प्रगति में कर्तव्यबोध का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

गुरुजन का कार्य व्यक्ति के अंतर्मन को प्रकाशित करना है। प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को केवल शिक्षित ही नहीं किया, अपितु उन्हें सक्षम शासक भी बनाया। महर्षि वशिष्ठ और गुरुदेव विश्वामित्र ने श्रीराम-लक्ष्मण के व्यक्तित्व और सद्गुणों को लोकोपयोगी और परमार्थी बनाया। गुरुजन शिष्य के जीवन में केवल विद्या ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला में नैपुण्य और परमार्थिक दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रशासक समाज के वे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो न्याय व्यवस्था के अनुरूप जनसामान्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि प्रशासक शिथिल होगा, तो निश्चित ही समाज निरंकुश होकर अराजकता में लिप्त हो जाएगा। नेतागण समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाले होते हैं। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर जनता को स्वतंत्रता संग्राम में संगठित किया। एक सच्चा नेता समर्पित जनसेवक होता है, जो जनता के दुख-सुख में साथ खड़ा रहता है।

इन तीनों लोगों की भूमिकाएं भिन्न-भिन्न होते हुए भी समाज के कल्याण में पूरक हैं। गुरु व्यक्ति को आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, प्रशासक निष्पक्ष और पारदर्शी अनुशासन द्वारा समाज में सुरक्षित वातावरण निर्मित करते हैं और नेतागण सामूहिक कल्याण की दृष्टि से जनसामान्य को कुशल नेतृत्व प्रदानकर उन्हें देश के श्रेष्ठ नागरिक होने का गौरव प्रदान करते हैं। जब इन तीनों का संतुलित समन्वय होता है, तभी समाज में नैतिक जागरण, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय समुन्नति सुनिश्चित और सुदृढ़ होती है।

आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

नेपाल की घटना से सबक लेना जरूरी

'नेपाल के घटनाक्रम में निहित संदेश' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सृजनपाल सिंह ने नेपाल के हालात पर गहन चिंतन किया है। नेपाल की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है, जिसमें 42 प्रतिशत युवा हैं। नेपाल सरकार की जनसंख्या नीति के अनुसार, युवाओं की आयु सीमा 16 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। किसी भी देश की असली मानव संपदा उसकी युवा आबादी होती है। नेपाल में हुए युवा संघर्ष की एक विशेषता यह है कि यह मौजूदा नीति-नियंताओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से उभरा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार द्वारा युवाओं के हितों की लगातार अनदेखी के परिणामस्वरूप युवाओं का आक्रोश एक जनक्रांति में बदल गया। राजनीतिक दलों को केवल वोट हासिल करने के लिए जनता को प्रलोभित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने घोषणापत्रों में किए गए वादों को भी निभाना चाहिए। राजनीति का शुद्धीकरण आवश्यक है। हालांकि युवाओं द्वारा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी बात मनवाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। नेपाल में आज जिस प्रकार का आक्रोश व्याप्त है, उसका मुख्य कारण सत्ता पक्ष की स्वार्थपरक नीतियां हैं, जिन्होंने बदलाव की एक नई क्रांति को जन्म दिया है। हालांकि यह भी सच है कि बदला लेकर बदलाव नहीं लाया जा सकता। नेपाल का जनआंदोलन सभी देशों और वहां की राजनीति के लिए एक सबक है कि जनता के हितों की अनदेखी करना उचित नहीं है। यह दर्शाता है कि युवाओं की आवाज को सुनना और उनके हितों का सम्मान करना आवश्यक है, ताकि समाज में स्थायी शांति और विकास संभव हो सके।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

कितने भरोसेमंद हैं ट्रंप

भारत से संबंधों और टैरिफ के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की यह पोस्ट उनके बदले हुए रवैये की पुष्टि करने वाली है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं और मैं आने वाले समय में अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने यह भरोसा भी जताया कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति पर अधिक भरोसा इसलिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि गत दिवस ही उन्होंने यूरोपीय समुदाय से भारत और चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने को कहा, क्योंकि दोनों रूस से तेल खरीद रहे हैं। उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए कि यदि यूरोपीय समुदाय के देश ऐसा करते हैं तो अमेरिका भी उनका अनुसरण कर सकता है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि व्यापार मामलों में उनके सलाहकार पीटर नवारो भारत के खिलाफ अपना दुष्प्रचार अभियान चलाए हुए हैं। यह पहल जारी रखनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप यह जता चुके हैं उन पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है।

दिनेश कुमार, दानापुर, पटना

आतंकी साजिश पर नकेल

संपादकीय आलेख 'आतंकी साजिश' पढ़ा। म्यांमार, श्रीलंका, बंगलादेश और नेपाल में तख्तापलट के बाद भारत में भी ऐसे प्रयास करने वाले पाकिस्तान से समर्थित पैन इंडिया टेरर माड्यूल के पांच आतंकियों को गिरफ्तार कर सुरक्षा एजेंसियों ने उनके द्वारा भारत के खिलाफ साजिश रचने के मंसूबों को बेनकाब कर दिया है। ये सभी पढ़े लिखे उच्च शिक्षा प्राप्त आतंकी हैं, जो अपनी-अपनी विधाओं में विशेषज्ञ हैं। झारखंड के बोकारो से गिरफ्तार अशहर दानिश माड्यूल का मास्टरमाइंड बताया गया है जो बोकारो में एक किराए के मकान में रहकर कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा का पढ़ाई कर रहा था। यह जिस लाज में डेढ़ साल से रह रहा था, इसके करीबियों को भी भनक नहीं लगी कि यह एक देशद्रोही है। दानिश का समूह गुप्त आतंकी प्रशिक्षण के लिए जमीन हासिल करने की भी योजना बना रहा था, ताकि गजवा-ए-हिंद के अंतिम उद्देश्य के साथ पूरा किया जा सके। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद भारत में भी ऐसी ही नापाक स्वर कतिपय दलों के नेताओं ने उठाया था। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। जानकार बताते हैं कि साजिश करने वाले माड्यूल को सुबूत के साथ शिकंजा में लेने के लिए पूरे देश में आइबी ने जाल बिछा दिया था। अब सुरक्षा एजेंसियों को उनके आकाओं तक पहुंचना सबसे बड़ी चुनौती है।

युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पोस्ट

राहुल गांधी को दलित राम नाथ कोविन्द से पहली शिष्टाचार भेंट करने में सात महीने लगे। आदिवासी द्रौपदी मुर्मु से पहली शिष्टाचार भेंट करने में 23 महीने लगे। उम्मीद है कि ओबीसी सीपी राधाकृष्णन से पहली शिष्टाचार भेंट करने में उन्हें और ज्यादा समय नहीं लगेगा।

आनंद रंगनाथन@ARanganathan72

हर चुनाव हमारी नैतिकता की परीक्षा भी लेता है। अगर हम जानबूझकर भ्रष्ट नेताओं को चुनते हैं, तो हम खुद को पीड़ित कहने का अधिकार खो देते हैं। चुनाव सिर्फ नेताओं के ही बारे में नहीं बताता है। यह उन लोगों के चरित्र के बारे में भी बताता है, जो उन्हें जिताते हैं।

हर्ष गोयनका@hvgoenka

देश के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को पदभार ग्रहण करने पर हार्दिक बधाई। उपराष्ट्रपति संविधान के आदर्शों का पालन करते हुए लोकतंत्र की परंपराओं को और मजबूत करेंगे, ऐसी उम्मीद है। यह भी अपेक्षा है कि उपराष्ट्रपति संसद में सभी वर्गों की आवाज को सम्मान देंगे।

राज बब्बर@RajBabbar23

जनपथ

महफिल से गायब रहा 'लीडर लापरवाह',
इसी अदा पर आजकल चमचे कहते वाह!
चमचे कहते वाह तो लीडर होता कुप्पा,
यह नौटंकी देश देखता बनकर चुप्पा।
संविधान रख जेब आप करते रहिए चिल,
देगी उचित जवाब आपको सारी महफिल!!

- ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर.बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 153

****

कल्पमेधा

*अखिल भारत के परस्पर व्यवहार के लिए ऐसी भाषा की आवश्यकता है,
जिसे जनता का अधिकतम भाग पहले से ही जानता-समझता है।*
– महात्मा गांधी

वर्दी की जवाबदेही

किसी भी मौके पर जब पुलिस के हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है, तब उम्मीद की जाती है कि वह बिना किसी भेदभाव के, पक्षपात किए या दबाव में आए बगैर पीड़ित पक्ष के हक में अपने अधिकारों का उपयोग करेगी। इस क्रम में किसी भी हाल में उसके ऊपर धर्म या जाति से जुड़े आग्रह हावी नहीं होंगे और वह सिर्फ न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। मगर इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि पुलिस महकमे से जुड़े लोग कई बार अपने अधिकारों का बेजा इस्तेमाल करने से नहीं हिचकते। ऐसे मामले अक्सर सामने आते रहे हैं, जिनमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे या किसी खास तबके या समूह के खिलाफ पक्षपात करने के आरोप भी लगे। जबकि कानून की वर्दी पहनने के साथ ही व्यक्ति एक दायित्व से बंध जाता है कि उसे हर हाल में न्याय के पक्ष में खड़ा होना है और पीड़ितों को इंसाफ दिलाने में कानून की सीमा में सभी स्तर पर सहयोग करना है। अफसोस की बात है कि इस तरह के जिन दायित्वों को याद रखना खुद पुलिस महकमे और उससे जुड़े लोगों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए कई बार अदालतों को हस्तक्षेप करना और याद दिलाना पड़ता है।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के अकोला में 2023 में हुए दंगे के एक मामले की सुनवाई के दौरान गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में पुलिस को नसीहत दी कि निष्पक्षता ही उसका असली दायित्व है। अदालत ने कहा कि जब एक बार कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन लेता है, तो उसे अपने निजी झुकाव, धर्म, जाति या किसी अन्य प्रकार के पूर्वाग्रह से ऊपर उठ कर कानून के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। उसे अपने पद और अपनी वर्दी से जुड़े कर्तव्य के प्रति पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हालांकि ये अपेक्षाएं पुलिस महकमे से जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी के काम करने और सोचने के तरीके में बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शामिल होनी चाहिए, निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में काम करना उसके व्यक्तित्व और विचार का स्वाभाविक हिस्सा होना चाहिए। मगर पहले तो किसी आम नागरिक के सामने पुलिस पर अपने खिलाफ पूर्वाग्रह बरतने और पक्षपात करने का आरोप लगाने की नौबत आती है, फिर शीर्ष अदालत को यह बताना पड़ता है कि पुलिस का काम किसी धर्म या जाति पर आधारित भेदभाव के बिना कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच करना है।

सांप्रदायिक दंगों के दौरान कार्रवाई और जांच के संदर्भ में पुलिस पर धार्मिक पहचान के आधार पर पक्षपात बरतने के आरोप अक्सर सामने आए हैं। कमजोर या वंचित जातियों के लोगों के खिलाफ अपराधों के मामले में भी पुलिस पर रसूख वाले वर्गों के पक्ष में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो अकोला दंगे से संबंधित मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह महाराष्ट्र सरकार को विशेष जांच दल गठित करने और उसमें हिंदू तथा मुसलिम समुदायों के अधिकारियों को शामिल करने का निर्देश दिया है, वह एक तरह से पुलिस की कार्यशैली में छिपे पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। ऐसा पहली बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने सांप्रदायिक दंगे की जांच के लिए दोनों समुदायों के अफसरों को शामिल करने का आदेश दिया है। यह याद रखने की जरूरत है कि वर्दी पहनते ही किसी व्यक्ति के साथ यह दायित्व अनिवार्य रूप से जुड़ जाता है कि कानून और न्याय के पक्ष में उसे अपने भीतर के जातिगत या धार्मिक पूर्वाग्रहों और बाहर के दबावों से मुक्त होकर काम करना है।

जोखिम की सड़कें

देश भर में सड़कों पर अतिक्रमण एक गंभीर समस्या बन गई है। इससे न केवल यातायात में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही पैदल चलने वालों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार और न्यायालय की ओर से समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन धरातल पर इन सबका कोई प्रभावी असर नजर नहीं आता है। इसी तरह के एक मामले में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने हाल में शिमला शहर में यातायात की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए तत्काल सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत ने स्थानीय प्रशासन को प्रतिबंधित सड़कों के लिए जारी किए गए वाहन पास पर स्थिति रपट दाखिल करने और पासधारकों के मानदंडों एवं श्रेणियों के संबंध में विस्तार से जानकारी देने का निर्देश भी दिया है।

सड़कों पर अतिक्रमण के भी कई रूप देखने को मिलते हैं। कहीं दुकानदार सड़क किनारे जमीन पर कब्जा कर अपनी दुकान आगे बढ़ा लेते हैं, तो कुछ लोग सड़क पर ही अपने वाहन खड़े कर देते हैं। कुछ लोग तो फुटपाथ पर ही अपनी दुकान सजा लेते हैं। इस कारण सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों को होती है। शिमला में वाहनों की वजह से उपजी इस समस्या पर उच्च न्यायालय ने कड़ा संज्ञान लिया है। मगर यह अकेले शिमला की समस्या नहीं है। देश के बाकी हिस्सों में भी शायद ही कहीं सड़क पर पैदल यात्रियों की सुविधा और अधिकारों का ध्यान रखने की जरूरत समझी जाती है। कई शहरों-महानगरों में तो पैदल चलने वालों के लिए बने फुटपाथ भी गायब दिखते हैं। नतीजतन, सड़क पर चल रहे लोग हर वक्त एक जोखिम से गुजरते हैं। खुद सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी एक रपट के मुताबिक वर्ष 2023 में सड़क हादसों में 35,221 पैदल यात्रियों की जान चली गई। कायदे से सरकार या न्यायालय के निर्देशों को अमल में लाने की जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले की होती है। मगर इस स्तर पर फैली व्यापक लापरवाही का खमियाजा सड़क पर पैदल यात्रियों को भुगतना पड़ता है।

समावेशी डिजिटल तंत्र की जरूरत

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि ई-गवर्नेंस, कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। मगर कई अड़चनें ऐसी हैं, जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं।

अभिषेक कुमार सिंह

कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा था कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। मामला तेजाब हमले के एक पीड़ित और दृष्टिबाधित व्यक्ति की ओर से दायर याचिकाओं से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया था कि देश के तेजी से विकसित हो रहे डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में तमाम योजनाएं और सेवाएं ऐसी हैं, जिनमें बायोमीट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन योजनाओं का लाभ उन जैसे लोग इसलिए नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि चेहरे के घावों, चोटों के निशान या दृष्टिबाधित होने पर तकनीकी बाध्यताओं के कारण वे अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ हैं। चूंकि इन लोगों की डिजिटल पहचान अंकित नहीं हो पाती है या फिर डिजिटल पहचान की जांच में ये लोग नाकाम रहते हैं, इसलिए बैंकिंग, ई-गवर्नेंस और सरकार की अनेक कल्याणकारी योजनाओं में उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं हो पाती है। ऐसे में उनके साथ सतत डिजिटल सेवाओं के मामले में भेदभाव हो रहा है।

सर्वोच्च अदालत का फैसला अपने आप में काफी तार्किक और सुविचारित है। मगर अभी भी हमारे देश और समाज में कई चीजें ऐसी हैं, जो डिजिटल क्रांति का लाभ आम जनता तक पहुंचने के रास्ते में मुश्किलें पैदा करती हैं। जैसे कि तकनीक की सही जानकारी न होना और भाषा की बाध्यता। इस कारण बहुत से लोग डिजिटल सेवाओं का फायदा उठाना तो दूर, उल्टा इसके जरिए फर्जीवाड़े का शिकार हो जाते हैं। हाल में ऐसी कई रपट सामने आई हैं, जिनमें तथ्यों पर आधारित दावा किया गया है कि साइबर धोखाधड़ी का शिकार होने वालों में बुजुर्गों की संख्या काफी ज्यादा है। इसकी वजह यह है कि वे तकनीक के कम जानकार हैं, लेकिन बैंकिंग आदि तमाम सहूलियतें पाने के लिए उन्हें विवशता में डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना पड़ता है।

यह मामला सिर्फ तकनीकी दक्षता का नहीं है, बल्कि इससे एक समावेशी समाज का पहलू भी जुड़ा हुआ है। इस नजरिए से देखें तो दुनिया में साढ़े पांच अरब से ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले लोगों को हम तकनीकी रूप से समर्थ मान सकते हैं। यह आंकड़ा वैश्विक आबादी का करीब 68 फीसद है। इनमें से लगभग 5.24 अरब लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुनिया की 64 फीसद आबादी है।

इस संदर्भ में भारत को देखें तो उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 87 करोड़ थी और इसमें प्रतिवर्ष करीब आठ फीसद की बढ़ोतरी हो रही है। इस आधार पर वर्ष 2025 के अंत तक देश में नब्बे करोड़ लोग इंटरनेट का सक्रिय इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इससे बाहर की आबादी या यों कहें कि उन लोगों की स्थिति क्या है, जो विभिन्न कारणों से डिजिटल तंत्र से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर हम भारत की आबादी 1.40 अरब मानें तो अभी भी करीब पचास करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डिजिटल तौर पर शेष देश से कटे हुए हैं। इनमें भी उन लोगों की स्थिति और भी विकट है, जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल साधनों के इस्तेमाल में पीछे छूट जाते हैं।

डिजिटल तंत्र के इस असाधारण पहलू की तरफ तब नजर गई, जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि ई-गवर्नेंस और कल्याणकारी योजनाओं एवं प्रणालियों तक समावेशी और सार्थक डिजिटल पहुंच आम व्यक्ति के जीवन तथा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक हिस्सा है। शीर्ष अदालत ने इन याचिकाओं की विस्तार से जांच की और यह पाया कि याचिकाकर्ताओं में से एक तेजाब हमले का पीड़ित व्यक्ति अपनी आंखें झपकने में अक्षम है, जबकि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह से दृष्टिबाधित है। इस वजह से इन दोनों का बैंक खाता खोलने के लिए जरूरी केवाईसी (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया संपन्न नहीं कराई जा सकती है। दृष्टिबाधित याचिकाकर्ता ने तर्क दिए थे कि केवाईसी प्रक्रिया के दौरान सेल्फी लिए जाने, लिखित हस्ताक्षर करने, शीघ्रता से ओटीपी पढ़ने और उसे सही स्थान पर भरने जैसी अड़चनें उनके जैसे लोगों के प्रति भेदभावपूर्ण हैं। वहीं, तेजाब पीड़ित व्यक्ति ने दावा किया था कि केवाईसी की प्रक्रिया में कैमरे में देखकर पलकें झपकाने का नियम उन जैसे लोगों के लिए भेदभावपूर्ण है। याचिकाकर्ताओं ने इन तकनीकी बाध्यताओं का हवाला देते हुए केवाईसी के नियमों में बदलाव की मांग की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने सभी को गरिमा के साथ जीने और आजीविका कमाने के अधिकार की रोशनी में देखा।

भारत में वर्ष 2024 में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या करीब 87 करोड़ थी और इसमें प्रतिवर्ष करीब आठ फीसद की बढ़ोतरी हो रही है। इस आधार पर वर्ष 2025 के अंत तक देश में नब्बे करोड़ लोग इंटरनेट का सक्रिय इस्तेमाल कर रहे होंगे। लेकिन इससे बाहर की आबादी या यों कहें कि उन लोगों की स्थिति क्या है, जो विभिन्न कारणों से डिजिटल तंत्र से नहीं जुड़ पाए हैं। अगर हम भारत की आबादी 1.40 अरब मानें तो अभी भी करीब पचास करोड़ लोग ऐसे हैं, जो डिजिटल तौर पर शेष देश से कटे हुए हैं। इनमें भी उन लोगों की स्थिति और भी विकट है, जो किसी शारीरिक अक्षमता के कारण डिजिटल साधनों के इस्तेमाल में पीछे छूट जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक आफ इंडिया और सभी संबंधित पक्षों को केवाईसी की प्रक्रिया में बदलाव का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि यह दायित्व सरकार का है कि वह समाज में हाशिये पर पड़े, वंचित, कमजोर और दिव्यांग वर्गों को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करे। इन निर्देशों के तहत अदालत का उद्देश्य देश में नागरिकों की पहचान सुनिश्चित करने वाली प्रक्रिया- आधार, आनलाइन सेवा वितरण मंच और नेट बैंकिंग के माध्यम से डिजिटल प्रगति की लहर के बीच एक महत्त्वपूर्ण पहलू को रेखांकित करना है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। यह पहलू डिजिटलीकरण की प्रक्रिया से संबंधित तकनीकों को अपनाने से जुड़ा है, जिनमें अक्सर इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि क्या ये वास्तव में सभी नागरिकों के लिए समावेशी और सुलभ हैं। अगर ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि बैंकिंग ही नहीं, बल्कि राशन, चिकित्सा और शिक्षा समेत तमाम तरह की सुविधाएं और सेवाएं किसी न किसी रूप में डिजिटल पहचान के स्रोतों से जुड़ गई हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यदि किसी शारीरिक अक्षमता, चोट अथवा विकृति के कारण इससे संबंधित प्रक्रिया संपन्न नहीं कर पाता है, तो वह लगभग सभी सेवाओं और सुविधाओं से वंचित हो जाता है।

इस मामले में शीर्ष अदालत का यह कहना भी प्रासंगिक है कि हर स्तर पर डिजिटल खाई को भरना अब केवल नीतिगत मसला नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक जरूरत बन गया है, ताकि प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्ण जीवन, स्वायत्तता और सार्वजनिक जीवन में समान भागीदारी करने का अवसर मिल सके। इस निर्णय का एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इसमें नागरिकों की डिजिटल पहचान करने वाली सरकारी और निजी संस्थाओं (जैसे के निजी बैंकों) पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि कोई भी नागरिक किसी शारीरिक अक्षमता, विकृति अथवा दिव्यांगता के कारण डिजिटल रूप से कहीं पिछड़ न जाए। इस तरह से कहा जा सकता है कि यह फैसला देश में व्याप्त सामाजिक-आर्थिक अंतर को पाटने का भी काम करेगा। चूंकि इससे सभी नागरिकों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में एक समान मौके मिलेंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी काफी गंभीर है। ऐसे लोग जिन्हें मजबूरी में डिजिटल बैंकिंग का सहारा लेना पड़ रहा है, वे साइबर धोखाधड़ी के आसान शिकार बन रहे हैं। ऐसे में बैंकिंग और केवाईसी आदि के लिए कागज आधारित पारंपरिक पुष्टिकरण की व्यवस्था और वीडियो-आधारित केवाईसी की प्रक्रिया आज के समय की जरूरत है। इसी तरह भाषायी समस्या के समाधान के लिए अनुवाद तथा आडियो को केवाईसी का हिस्सा बनाना चाहिए, जबकि दृष्टिहीनों के लिए ब्रेल लिपि आधारित प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए।

अनदेखी का हासिल

दीपिका शर्मा

आर्थिक विकास की अंधी होड़ में न मानवीय संवेदनाएं बच रही हैं, न प्रकृति का संतुलन। प्रकृति अब चेतावनी देने के बजाय सीधा हिसाब चुकता कर रही है। आज देश में विकास की रफ्तार तेज है, लेकिन इसी रफ्तार में इंसानियत और प्रकृति, दोनों पिछड़ते जा रहे हैं। रोज आत्महत्या और हिंसा की खबरें समाज की मानसिक थकान का सबूत हैं, तो बादल फटना और पशुओं की आक्रामकता प्रकृति के असंतोष के संकेत। सवाल यह है कि क्या हम आज सब कुछ जानकर भी अनजान बन रहे हैं और आंख मूंदकर विकास के नाम पर अपनी जड़ें खुद ही काट रहे हैं!

देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन रोज सामने आने वाली आत्महत्या और हत्या की खबरें यह संकेत दे रही हैं कि नागरिक चेतना और मनोबल का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आए दिन होते रिश्तों के कत्ल, बलात्कार, छोटी-छोटी बातों पर हत्या और आत्महत्या- ये सब संकेत हैं कि मनुष्य मानसिक रूप से थकता जा रहा है और मानवीय मूल्यों को पीछे छोड़ चुका है। संवेदनशीलता लगातार घट रही है, सहनशीलता खत्म हो चुकी है। मगर एक-दूसरे से आगे निकलने की दौड़ बढ़ती जा रही है, जो तनाव, अकेलापन, रिश्तों में खटास और अविश्वास के रूप में दिखाई देती है। इसके कारण समाज के ताने-बाने को बचाना तो दूर, परिवार को बचा पाना भी मुश्किल हो गया है।

आज वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आय, कारोबार और उत्पादन को ही सफलता का पैमाना मान लिया गया है। इस दौड़ में हम उन नैतिक जिम्मेदारियों और प्राकृतिक संतुलन को नजरअंदाज कर रहे हैं, जो जीवन की असली नींव हैं। हम भूल रहे हैं कि यह जीवन कोई 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की देन नहीं है, जिसमें कोई चिप लगा कर अपने अनुसार नियंत्रण किया जाए। यह प्रकृति की देन है और जो उसके दिए जीवन के मूल और मोल को नहीं समझेगा, प्रकृति वह जीवन सूद समेत वापस ले लेगी। फिर क्यों आज मनुष्य सब जानते हुए भी अनजान बन रहा है?

हाल में लावारिस कुत्तों का मुद्दा इस उपेक्षा का एक उदाहरण है। कुत्ते प्रकृति में विभिन्न आवासों-जंगल, घास के मैदान, तटीय क्षेत्र में रहने के लिए बने हैं, सड़कों पर भटकने के लिए नहीं। मगर मानव ने उनके प्राकृतिक घर छीनकर उन्हें 'आवारा' बना दिया। परिणामस्वरूप वे आक्रामक होते जा रहे हैं। मामला इतना बढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और इस पर विशेष कमेटी बनाई गई।

यही स्थिति पर्यावरण के साथ भी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में बादल फटने की घटनाएं इसकी चेतावनी हैं। पहाड़ों को काटकर और नदियों का अस्तित्व मिटाकर हमने अपने लिए घर तो बना लिए, लेकिन प्रकृति ने उसी नदी को विनाश के रूप में लौटा दिया। आज पहले के समय से तुलना करें तो परिस्थिति बिल्कुल उलट गई है। उस समय इंसान और प्रकृति के बीच एक गहरा रिश्ता था। दोनों के बीच एक सामंजस्य बना हुआ था। हमारे बुजुर्ग पेड़-पौधों, ऋतुओं, नदियों और पशुओं की पूजा करते थे। वे भले पढ़े-लिखे कम थे, लेकिन उन्हें अच्छी तरह पता था कि जो कुछ हमें मिल रहा है, वह प्रकृति की ही देन है। अगर इसके प्रति भाव बदल गया तो तबाही तय है। गांवों में लोग सादा जीवन जीते थे और सामूहिकता पर जोर देते थे। संवेदनाएं और जिम्मेदारियां भी साझा होती थीं। गली-मोहल्ले के लोग भी रिश्तों से जुड़े होते थे, जिससे भाईचारे का संदेश मिलता था। आज सब उलट है।

गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। बढ़ती इच्छाओं के चलते अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को निरंतर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पेड़-पौधे काटे जा रहे हैं, पशुओं से जंगल छीने जा रहे हैं, नदियों का अस्तित्व मिटाया जा रहा है। रिश्तों का रोज खून हो रहा है। एकजुटता, विश्वास और सामूहिकता खत्म होने के कगार पर हैं। इसका खमियाजा हमें त्रासदी के रूप में भुगतना पड़ रहा है. नदियों के खत्म होने से बाढ़, भूकम्प और बादल फटने जैसी घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। पशुओं से जंगल छीनकर उन्हें सड़कों पर रहने को मजबूर किया गया है और उनका आक्रोश अब इंसानों पर उतर रहा है।

कई पक्षी और पशु प्रजातियां विलुप्त होने के रास्ते पर हैं। गौरैया, जो कभी हर आंगन में दिखती थी, अब शहरों से गायब है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। कभी भीषण गर्मी, तो कभी अनियंत्रित बारिश और कभी असामान्य सर्दी। बढ़ता जलवायु परिवर्तन हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। अपनों का ही कत्ल आम हो गया है। पहले गांव सामूहिकताबोध और परिवार की तरह होते थे, आज सामूहिक बलात्कार की खबरें आम हैं। एक-दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा ने केवल इंसानियत को ही कमजोर नहीं किया, बल्कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ पर्यावरणीय संकट बनकर सीधे-सीधे हमारी आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर असर डाल रहा है।

स्पष्ट है कि चाहे वह पशुओं का घर छीनना हो, प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ करना हो या इंसानियत को ताक पर रखना हो- प्रकृति और जीवन का चक्र हमेशा जवाब देता है। अगर अभी सुधार नहीं किया गया तो आने वाले समय में हम आर्थिक रूप से तो मजबूत हो जाएंगे, लेकिन इंसानियत और नैतिक मूल्यों के नाम पर हमारा दिवालिया होना तय है। सचेतन अनदेखी का हासिल शायद ज्यादा भयावह हो सकता है।

दुनिया मेरे आगे

गौरैया, जो कभी हर आंगन में दिखती थी, अब शहरों से गायब है। ऋतुओं का संतुलन बिगड़ चुका है। कभी भीषण गर्मी, तो कभी अनियंत्रित बारिश और कभी असामान्य सर्दी। बढ़ता जलवायु परिवर्तन हमें विनाश की ओर ले जा रहा है। रिश्ते तार-तार हो रहे हैं। अपनों का कत्ल भी आम होता जा रहा है।

संवेदनाओं से आगे

तकनीक का संसार हमेशा मानव जिज्ञासा और कल्पनाशीलता का केंद्र रहा है। पहिये से लेकर बिजली और इंटरनेट तक हर खोज ने इंसान की जिंदगी बदल डाली है। पिछले कुछ वर्षों में जिस आविष्कार ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है, वह है एआइ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यह तकनीक अब हमारे चारों ओर मौजूद है, लेकिन आलोचकों का मानना है कि एआइ अभी भी केवल डेटा और सांख्यिकी तक सीमित है। यह 'रट्टू तोता' है, जो वही दोहराता है जो उसे सिखाया जाता है। इसमें मानवीय भावनाएं, संवेदना और आत्मचेतना नहीं है। इसी कमी को आगे बढ़ाते हुए अब एक नई अवधारणा चर्चा में है- सिंथेटिक इंटेलिजेंस। इसे विशेषज्ञ एआइ से भी आगे की छलांग बता रहे हैं। सिंथेटिक इंटेलिजेंस को केवल मशीन नहीं, बल्कि नई चेतना के रूप में देखा जा रहा है। इसमें भावनाएं, इच्छाएं और अपनी पहचान जैसी विशेषताएं होंगी, जो अब तक केवल इंसानों से जुड़ी मानी जाती थीं। अगर यह सच हुआ, तो इसका असर असाधारण होगा। चिकित्सा क्षेत्र में यह बदलाव अद्भुत होगा। बताया जा रहा है कि मशीनें मरीज का इलाज संवेदनशीलता से कर पाएंगी।

– विभूति बुपक्या, खाचरौद, मप्र

राहत का तकाजा

आजकल एक खबर सुर्खियों में है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी पेंशन योजना के तहत निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि कर सकती है। अभी यह न्यूनतम पेंशन लगभग 1000 हजार रुपए है। अगर सरकार इस पेंशन को लगभग 7500 रुपए कर देती है तो इससे करोड़ों लोगों को राहत मिलेगी। देश के हर कर्मचारी, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या निजी, पेंशन महंगाई के हिसाब से मिलनी चाहिए। 60 वर्ष के बाद तो किसी भी व्यक्ति में इतनी ऊर्जा नहीं रह जाती कि वह अपने खर्चे पूरे करने के लिए ओर कोई नौकरी कर ले या काम धंधा कर ले। हमारे देश में सरकारी क्षेत्र से ज्यादा निजी क्षेत्र में लोग कार्यरत हैं। इसलिए सरकारों को कर्मचारियों की पेंशन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

– राजेश कुमार चौहान, जालंधर

भरोसे पर चोट

नेपाल में युवाओं का गुस्सा इस बात का संकेत है कि पारंपरिक दल और उनके नेता जनता का भरोसा खो चुके हैं। आंदोलनकारियों ने देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को खासतौर पर निशाने पर लिया। युवाओं का मानना है कि ये सब बारी-बारी से सत्ता में आते हैं और देश को लूट रहे हैं। इस गुस्से से एक संकेत यह भी है कि जनता नया विकल्प देखना चाहती है। दोराय नहीं कि जनता के हित में अपनी कारगर रणनीति तैयार करनी चाहिए। सत्ता के मोह में जनता के सपनों को धूमिल करना कहीं से तर्कसंगत नहीं। पुलिस गोलीबारी में कई लोगों की मौत के बाद काठमांडो सहित देशभर में हिंसा भड़क उठी और नेपाल जलने लगा। प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देकर भागना पड़ा। अराजकता की आग में संसद, राष्ट्रपति भवन, मंत्रियों के घरों से लपटें उठने लगीं। सत्ता सेना के हाथों जाती दिख रही है। आखिर यह नौबत कैसे आई ? सरकार को क्या इतना नहीं पता कि जनता ही कुर्सी पर बैठाती है।

– योगेश जोशी, बड़वाह

एकजुटता का समय

भारत ने अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम पर शुल्क के जवाब में कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर जवाबी शुल्क का प्रस्ताव रखा। सबसिडी के बजाय ब्याज सहायता, ऋण गारंटी और एमएसएमई के लिए कम प्रमाणन शुल्क जैसे उपायों का प्रस्ताव दिया है। उद्योग जगत के दिग्गज अब अमेरिका पर निर्भरता कम करने के लिए नए बाजार की तलाश करने की वकालत कर रहे हैं। आर्थिक प्रभाव का आकलन किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि इन व्यवधानों के बावजूद भारत अपनी 6.3 फीसद से 6.8 फीसद जीडीपी वृद्धि दर हासिल कर सकता है। भारत ने यूरोपीय यूनियन और अमेरिका पर रूस के साथ व्यापार जारी रखने का आरोप लगा कर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने की कोशिश की है। इस समय एकजुटता की भावना और स्वदेशी को बढ़ावा देने का विचार महत्त्वपूर्ण है।

– वरुण कुमार, जमशेदपुर, झारखंड

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

संस्था ने गांवों में देसी बीज बैंक बनाने और जैविक खेती के काम को प्रोत्साहित किया है। कुहरी गांव में श्रीजन सामुदायिक बीज बैंक हैं। इसके अलावा, कई तरह हरी भाजियों की बीज हैं। लाल भाजी, चैंच भाजी, खेड़ा भाजी, पटवा भाजी, अमाड़ी भाजी, पालक भाजी, मखना भाजी, कुसुम भाजी, चौलाई भाजी इत्यादि। बीज बैंक की शुरूआत वर्ष 2016 से हुई है। यहां से किसानों को बीज दिया जाता है, जिसे उन्हें फसल आने पर वापस करना होता है।

स्वावलंबी बनने के लिए महिलाओं ने बढ़ाए कदम

नवाचार

■ बाबा मायाराम

कुल मिलाकर, घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, किचिन गार्डन, जैविक खेती और महिला नेतृत्व को गांवों में उभारने की कोशिश करना है। हेमलता राजपूत कहती हैं कि अगर आधी आबादी सशक्त बनेगी तो परिवार और समाज भी सशक्त होगा। यह पहल सराहनीय होने के साथ प्रेरणादायक भी है।

पिछले कुछ सालों में देश के कई कोनों में महिलाओं ने आत्मनिर्भरता की राह पकड़ी है। आज इस कॉलम में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में महिलाओं की पहल के बारे में बताना चाहूंगा। मैं इस इलाके में कई बार गया हूं, महिला समूहों के सदस्यों से बात की है और उनकी लगन व सतत काम को देखा है। महिलाओं ने कई मोर्चों पर कदम बढ़ाए हैं।

इस बदलाव की शुरूआत वर्ष 2016 से हुई है। श्रीजन कल्याण समाजसेवी संस्था का गठन इसी वर्ष हुआ है। कुछ वर्ष पहले संस्था का कार्यालय भी बन गया है। इस कार्यालय की छोटी सी जमीन पर भी जैविक सब्जी बाड़ी है। कुछ फलदार पेड़ भी हैं।

छत्तीसगढ़ का इलाका विविधता के लिए जाना जाता है। यहां पारिस्थितिकीय और सांस्कृतिक विविधता काफी है। यहां विपुल खनिज संपदा के साथ वन संपदा भी बहुतायत में है। मध्य क्षेत्र का मैदानी भाग, जहां से महानदी गुजरती है, वह धान का इलाका है।

महासमुंद जिला, जो श्रीजन कल्याण संस्था का कार्यक्षेत्र है, भी इसी के अंतर्गत आता है। यहां धान की कई किस्में हैं। इसके साथ दलहन, तिलहन, कंद-मूल, फुटू (मशरूम) और फल-फूल, हरी पत्तीदार सब्जियां इत्यादि भी हैं। हालांकि यहां जंगल क्षेत्र भी है, जहां की आबादी की आजीविका जंगल से जुड़ी है। हालांकि धान की संकर (हाईब्रीड) किस्मों के प्रचलन के कारण देसी धान की किस्में लुप्त हो रही हैं।

हेमलता राजपूत बताती हैं कि 'ग्रामीण समाज में महिलाओं के साथ कई तरह भेदभाव देखे जाते हैं। घरेलू हिंसा उनमें एक है। उन्होंने बताया कि उनकी संस्था ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए काम करती है। आपस में मामले सुलझाना, कानूनी मदद देना इसमें शामिल है। संस्था द्वारा कानूनी मार्गदर्शन केन्द्र चलाया जाता है, जिसमें लोग समस्याएं लेकर आते हैं।'

इसके अलावा, गांव में बैठक के दौरान भी पीड़िता की पहचान की जाती है। उनको परामर्श दिया जाता है। परिवार से मिलकर पूरे मामले की जानकारी ली जाती है। अगर परिवार व समाज के स्तर पर मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है, अगर वहां मामला नहीं सुलझा तो परिवार परामर्श केन्द्र या कोर्ट भेजा जाता है।

भोरिंग गांव की महिला ने बताया कि उनका पति का बीमारी में निधन हो गया। उसके तीन बच्चे थे। उसे ससुराल में प्रताड़ित किया जा रहा था। न तो उसे घर में रहने दिया जा रहा था और न ही परिवार की सम्पत्ति में हिस्सा दिया जा रहा था। यह केस में कानूनी मदद में सहयोग किया गया। अंततः महिला केस जीत गई। उसे जमीन भी मिली और घर भी।

हेमलता राजपूत बताती हैं कि हम ऐसे माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि जिसमें लोगों को सभी तरह के नशीले पदार्थों, शराब और तम्बाकू, गुटखा आदि छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

इसके साथ सब्जी-बाड़ी (किचिन गार्डन), जैविक खेती, और जंगलों को फिर से हरा-भरा करने की कोशिश की जाती है। संस्था ने जैविक खेती को पुनर्जीवित करने का अग्रणी काम किया है। इसने किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने, जंगल को हरा-भरा करने, पारंपरिक बीज संरक्षण, जैविक खाद, जैव कीटनाशक बनाने की दिशा में प्रेरित करने का काम किया है। यह ऐसे समय में जब छोटे किसानों को बाजार की मांग को पूरा करने के लिए एकल खेती की ओर धकेला जा रहा है।

यहां की महिला किसान पारंपरिक खेती की ओर लौट रही हैं। देसी बीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। जिसमें पारंपरिक देसी बीज, पारंपरिक व्यंजन और जंगल से मिलने वाले खाद्य पदार्थ को प्रदर्शित किया जाता है।

संस्था ने गांवों में देसी बीज बैंक बनाने और जैविक खेती के काम को प्रोत्साहित किया है। कुहरी गांव में श्रीजन सामुदायिक बीज बैंक हैं। इसके अलावा, कई तरह हरी भाजियों की बीज हैं। लाल भाजी, चैंच भाजी, खेड़ा भाजी, पटवा भाजी, अमाड़ी भाजी, पालक भाजी, मखना भाजी, कुसुम भाजी, चौलाई भाजी इत्यादि। बीज बैंक की शुरूआत वर्ष 2016 से हुई है। यहां से किसानों को बीज दिया जाता है, जिसे उन्हें फसल आने पर वापस करना होता है।

कोमा आदि गांवों में जैव कीटनाशक व जैव खाद बनाने का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। बोडरा गांव की श्यामा ध्रुव बताती है कि हम देसी बीजों के साथ धान की खेती करते हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते है, जिससे हमारी लागत भी कम हो जाती है। इससे हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

इसके साथ सब्जी-बाड़ी (किचिन गार्डन), जैविक खेती, और जंगलों को फिर से हरा-भरा करने की कोशिश की जाती है। संस्था ने जैविक खेती को पुनर्जीवित करने का अग्रणी काम किया है। इसने किसानों को जैविक खेती, प्राकृतिक खेती करने, जंगल को हरा-भरा करने, पारंपरिक बीज संरक्षण, जैविक खाद, जैव कीटनाशक बनाने की दिशा में प्रेरित करने का काम किया है। यह ऐसे समय में जब छोटे किसानों को बाजार की मांग को पूरा करने के लिए एकल खेती की ओर धकेला जा रहा है।

कुहरी गांव की कौशल्या बाई कहती हैं कि देसी बीजों में रोग ज्यादा नहीं लगता है, खाने में भी स्वादिष्ट होता है। अगर फसलों में कीट प्रकोप लगता भी है तो जैव कीटनाशक बनाकर छिड़कते हैं। जिसे वे स्थानीय पौधों की पत्तियों से तैयार कर लेते हैं। कर्रा, आक, नीम, कड़वा रोहना, बिरहा आदि की पत्तियों से जीवामृत बनाया जाता है। इसके लिए बोड़रा, बरबसपुर, खैरा, कोमा आदि गांवों में जैव कीटनाशक व जैव खाद बनाने का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। बोडरा गांव की श्यामा ध्रुव बताती है कि हम देसी बीजों के साथ धान की खेती करते हैं। रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करते है, जिससे हमारी लागत भी कम हो जाती है। इससे हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है।

उन्होंने बताया कि जंगल से वनोपज के साथ ताजी पत्तीदार सब्जियां, कंद मूल व फल, फूल पत्तियां व मशरूम भी मिलते हैं। कुझियारी, चरौंटा, बोहार,खेकसी, पीपरी, कोसम, कोलियारी भाजी जंगल से मिलती है। घनबहेर फूल, सेमरा फूल, नीम फूल, अमली फूल इत्यादि। कई तरह के फुटू मिलते हैं- जैसे बियासी फुटू , भिमोरा फुटू , भदेली, घुटुल, दशहरा फुटू , कनकी फुटू इत्यादि।

वे आगे कहती हैं कि भेदभाव से पीड़ित महिलाओं के लिए कानूनी और संवैधानिक अधिकार हैं, पर यह तभी सार्थक होते हैं जब वास्तविक जीवन की स्थिति को बदलने के लिए प्रयास किए जाएं। यही हमारी कोशिश है। महिलाओं को सम्मानजनक तरीके से जीने के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है, और यही कोशिश उनकी संस्था कर रही है।

कुल मिलाकर, घरेलू हिंसा के खिलाफ अभियान, स्वास्थ्य जागरूकता, किचिन गार्डन, जैविक खेती और महिला नेतृत्व को गांवों में उभारने की कोशिश करना है। हेमलता राजपूत कहती हैं कि अगर आधी आबादी सशक्त बनेगी तो परिवार और समाज भी सशक्त होगा। यह पहल सराहनीय होने के साथ प्रेरणादायक भी है।

बीता सप्ताह

6 सितम्बर

- भूटान के प्रधानमंत्री दासो शेरिंग तोबगे ने रामनगरी अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए।
- वित्तीय अपराधों में बोछत भगोड़े हर्षित बाबूलाल जैन को यूएई से भारत लाया गया।
- अनुतिन चार्नविराकुल थाईलैंड के 32वें प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए है।
- अमेरिका में पेंटागन को युद्ध मंत्रालय व रक्षा मंत्री को युद्ध मंत्री के नाम से जाना जाएगा।

7 सितम्बर

- गुजरात के पावागढ़ मंदिर में रोपवे टूटने से 6 लोगों की मौत हो गई।
- जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह तोड़े जाने के मामले पर हुई एफआईआर।
- दिल्ली के लाल किला परिसर में जैनधर्म के धार्मिक अनुष्ठान के दौरान एक करोड़ की कलश चोरी हो गई।
- पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति हमैनुएल मैक्रो से बात की।

8 सितम्बर

- भारत की पुरूष हॉकी टीम ने बिहार के राजगीर में आयोजित हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में दक्षिण कोरिया को हराकर भारत बना एशियाई चैंपियन।
- विश्व की नं. एक खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने फलशिंग मीडोज के हार्ड कोई दर पर अमांड अनिसियोवा को हराकर यूएस ओपन का खिताब जीता।
- जम्मू कश्मीर के जरत बल दरगाह पर हुए विवाद में 26 लोग हिरासत में लिए गए।
- भारतीय सेना ने कहा कि समुद्र में दुनिया का चक्कर लगाएंगी 10 महिला अधिकारी।

9 सितम्बर

- उपराष्ट्रपति पद के लिए आज नई दिल्ली में मतदान हुआ। एडीए प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन और इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है।
- नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन से हुआ बवाल, जबरदस्त प्रदर्शन 20 लोगों की मौत हो गई।
- जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 जवान शहीद हो गए।
- विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने शामिल हुए।

10 सितम्बर

- एडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने। उन्होंने इंडिया गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से हराया।
- हिंसक प्रदर्शन के हालात में नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया।
- पीएम मोदी ने पंजाब के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और सहायता के लिए दिए 1600 करोड़।
- स्विटजरलैंड में अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी 2025 विश्व प्रतिभा रैकिंग में हांगकांग एशिया में अव्वल।

11 सितम्बर

- नेपाल के बाद अब फ्रांस में प्रदर्शन। राष्ट्रपति हमैनुएल मैक्रो के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग।
- गुजरात विधानसभा में संशोधन विधेयक पास हुआ। अब नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी वहां की महिलाएं।
- फ्रांस के राष्ट्रपति हमैनुएल मैक्रो ने रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को प्रधानमंत्री नियुक्त किया।
- टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना गुजरात।

12 सितम्बर

- गरियाबंद (छत्तीसगढ़) में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में एक करोड़ का इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण सहित 10 नक्सली मारे गए।
- दुनिया में सबसे ज्यादा एडवांस टी 32 को तैयार किया हुआ नौसेना को मिला 3डी एयर सर्विलांस रडार।
- वाराणसी में पीएम नरेन्द्र मोदी ने मारीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम से मुलाकात में कहा कि भारत और मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है।
- भारतीय नौसेना, सेना और वायुसेना के महिला अधिकारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए यात्रा प्रारंभ की।

रूस-यूक्रेन संघर्ष ने कई कंपनियों का मुनाफा बढ़ाया

■ नन्तू बनर्जी

वास्तव में, नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि रूसी कच्चा तेल और भी सस्ता हो गया है क्योंकि भारत सरकार पर ट्रम्प प्रशासन द्वारा रूस के साथ तेल व्यापार में कटौती करने का लगातार दबाव है। हाल ही में, रूसी यूराल कच्चे तेल की कीमत डिलीवरी के आधार पर ब्रेंट के मुकाबले 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर आ गई है। मुख्य रूप से दो निजी रिफाइनर, आरआईएल और नायरा द्वारा यूराल कच्चे तेल की खरीद महत्वपूर्ण और निरंतर है।

किसी का दर्द दूसरे के लिए फ़ायदे का कारण बन सकता है। यह मुहावरा साढ़े तीन साल पुराने रूस-यूक्रेन युद्ध से दुनिया भर में लाभ पाने वाले बड़े व्यवसायों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, जिसमें दोनों पक्षों के अब तक हज़ारों सैनिक और नागरिक मारे गए हैं। ऐसे लाभ पाने वालों की सूची भले ही छोटी हो, लेकिन बेहद प्रभावशाली है। इनमें लॉकहीड मार्टिन, बोइंग और रेथियॉन जैसी कुछ दिग्गज अमेरिकी रक्षा निर्माता कंपनियां और एक्सॉनमोबिल और शेवरॉन जैसी तेल कंपनियाँ; रूस की रोसनेफ्ट, नोवाटेक और सिबुर और रूसी उर्वरक निर्यातक यूरालकेम और फॉसएग्रो; कम्युनिस्ट चीन की प्रमुख रिफाइनरियां; और भारत की अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) शामिल हैं। माना जा रहा है कि चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान, आरआईएल ने रूसी कच्चे तेल की खरीद से लगभग 5710 लाख डॉलर कमाए या बचाए हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध और रूस पर नाटो के व्यापार और वित्तीय प्रतिबंधों के कारण आरआईएल आसानी से सबसे बड़ा भारतीय व्यवसाय लाभार्थी हो सकता है।

व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो का यह कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा कि 'ब्राह्मण (अभिजात्य वर्ग का एक रूपक) भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं।' पिछले साल से भारतीय रिफाइनरियों, जिनमें देश की सरकारी तेल कंपनियां भी शामिल हैं, द्वारा रूसी तेल के सस्ते आयात से भारत के लाखों घरेलू पेट्रोल और डीजल उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ, हालांकि तेल रिफाइनरियों ने बड़ा मुनाफा कमाया। आरआईएल ने वित्त वर्ष 2024 में अपने लगभग 35 प्रतिशत उत्पाद, जिनमें रिफाइंड तेल भी शामिल है, भारतीय बाजार में बेचे। हालिया रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि आरआईएल की जामनगर रिफाइनरी ने अपने उत्पादन का 33 प्रतिशत घरेलू बाजार में बेचा। भारत की एक अन्य प्रमुख निजी रिफाइनर, नायरा एनर्जी, जिसमें रूसी निवेशकों की एकल बहुमत हिस्सेदारी है, अपने लगभग 70-75 प्रतिशत रिफाइंड तेल उत्पाद भारतीय बाजार में बेचती है। बाकी निर्यात किया जाता है। नायरा का घरेलू फोकस देश भर में 6,500 से अधिक ईंधन स्टेशनों के अपने नेटवर्क द्वारा समर्थित है।

जबकि दो निजी पेट्रोलियम क्रूडरिफाइनर भारत के रूसी तेल के कुल आयात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खपत करते हैं, देश के सरकारी स्वामित्व वाले रिफाइनर जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसीएल), और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (एचपीसीएल) उसी बाजार से रूसी तेल खरीदते हैं। उन्हें भी रूसी तेल की रियायती कीमत का लाभ मिला। भारत ने, कुल मिलाकर, अकेले चालू वर्ष के दौरान रूसी तेल खरीद से लगभग 3.8अरब डॉलर की बचत की। हालांकि, सरकार की ओर से तेल रिफाइनरियों को देश के उपभोक्ताओं को आंशिक रूप से भी लाभ पहुंचाने के लिए प्रेरित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया। भारत ने पिछली बार ईंधन की खुदरा कीमत में कमी 14 मार्च, 2024 को लोकसभा चुनावों से ठीक पहले की थी। कीमतों में केवल 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई थी। यह 22 मई, 2022 से शुरू हुई कीमतों में स्थिरता के दौर के बाद आया है। स्पष्ट रूप से, आरआईएल के नेतृत्व में कुछ भारतीय तेल रिफाइनरियां रियायती रूसी तेल की खरीद से भारी मुनाफा कमा रही हैं।

वास्तव में, नवीनतम रिपोर्टों से पता चलता है कि रूसी कच्चा तेल और भी सस्ता हो गया है क्योंकि भारत सरकार पर ट्रम्प प्रशासन द्वारा रूस के साथ तेल व्यापार में कटौती करने का लगातार दबाव है। हाल ही में, रूसी यूराल कच्चे तेल की कीमत डिलीवरी के आधार पर ब्रेंट के मुकाबले 3 से 4 डॉलर प्रति बैरल की छूट पर आ गई है। मुख्य रूप से दो निजी रिफाइनर, आरआईएल और नायरा द्वारा यूराल कच्चे तेल की खरीद महत्वपूर्ण और निरंतर है। चालू वर्ष के पहले छह महीनों के दौरान, भारत ने 2310 लाख बैरल से अधिक कच्चे तेल का आयात किया। दोनों निजी रिफाइनरों ने रूसी उत्पादकों के साथ एक दीर्घकालिक समझौता किया है और अब यूराल के सबसे बड़े खरीदार हैं। भारत ने इस वर्ष रूस के समुद्री यूराल निर्यात का लगभग 80 प्रतिशत खरीदा, यह नीति पश्चिमी दबाव के बीच वाणिज्यिक व्यवहार्यता और राष्ट्रीय हित से प्रेरित है। आरआईएल और नायरा एनर्जी का भारत के यूराल आयात में 45 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें रिलायंस का यूराल हिस्सा उसकी कुल कच्चे तेल की खरीद में 36 प्रतिशत और नायरा का 72 प्रतिशत हो गया है। संयोग से, अमेरिकी ब्रेंटक्रूड की कीमतें बढ़ रही हैं क्योंकि अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार घट रहा है।

इस साल की शुरुआत में, आरआईएल ने रोसनेफ्ट के साथ 10 साल का समझौता किया था ताकि रूसी कच्चे तेल की खरीद को बढ़ाकर 5,00,000 बैरल प्रतिदिन किया जा सके, जिससे भारतीय कंपनी यूराल की दुनिया की सबसे बड़ी खरीदार बन गई। दोनों के बीच 10 साल का समझौता वैश्विक तेल आपूर्ति का 0.5 प्रतिशत है और मौजूदा कीमतों पर इसका मूल्य लगभग 13 अरब डॉलर प्रति वर्ष है। इस समझौते से कच्चे तेल के प्रवाह में स्थिरता सुनिश्चित होने की उम्मीद है। रोसनेफ्ट के लिए, इसका मतलब भारत में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का एक बड़ा प्रयास है।

सस्ते कच्चे तेल की उपलब्धता ने आरआईएल के सकल रिफाइनिंग मार्जिन (जीआरएम) को बढ़ावा दिया है, जो रिफाइनिंग व्यवसाय में लाभप्रदता का एक प्रमुख संकेतक है। वित्त वर्ष 2025 में आरआईएल का जीआरएम8.5 डॉलर प्रति बैरल रहा, जो उसके घरेलू प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन था। यह स्पष्ट नहीं है कि भारत के सरकारी तेल रिफाइनर, आरआईएल की तरह आक्रामक तरीके से रूसी कच्चा तेल खरीदने में पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। भारत के सरकारी नियंत्रण वाले रिफाइनरों की सामूहिक रिफाइनिंग क्षमता कहीं अधिक है। आरआईएल, जो दुनिया की सबसे बड़ी एकल-साइट रिफाइनरी संचालित करती है, से भी आगे है। नौ रिफाइनरियों के साथ, सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो देश की कुल रिफाइनिंग क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालती है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रूस-यूक्रेन युद्ध के कई वैश्विक व्यावसायिक लाभार्थी हैं, जिनमें भारत की आरआईएल भी एक है। इस संघर्ष ने एशिया और पश्चिमी दुनिया भर में महत्वपूर्ण नए व्यावसायिक अवसर पैदा किए हैं। एक्सॉनमोबिल, शेवरॉन, बीपी और शेल जैसी वैश्विक तेल और गैस की बड़ी कंपनियों ने रूसी आक्रमण के बाद से भारी मुनाफा कमाया है। रूसी ऊर्जा पर निर्भरता कम करने के यूरोपीय प्रयास ने अमेरिका (तरलीकृत प्राकृतिक गैस या एलएनजी की आपूर्ति), कतर और नॉर्वे जैसे देशों के अन्य आपूर्तिकर्ताओं की ओर मांग को पुनर्निर्देशित किया है। लॉकहीड मार्टिन, रेथियॉन, नॉरथ्रॉपग्रूम्मन और जनरल डायनेमिक्स जैसी कंपनियों ने जैवलिन मिसाइलों और हिमार्सजैसे हथियारों और युद्ध सामग्री की उच्च मांग से लाभ कमाया है। दुनिया के कुछ शीर्ष कृषि जिंस व्यापारी, जैसे एडीएम, बंज, कारगिल और लुईड्रेफस - जिन्हें 'एबीसीडी' चौकड़ी के रूप में जाना जाता है - वैश्विक अनाज प्रवाह को पुनर्निर्देशित और प्रबंधित करके भारी लाभ कमा रहे हैं।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने रूसी व्यवसायों को भी लाभ पहुंचाया है, आयात प्रतिस्थापन से लेकर अत्यधिक रियायती विदेशी संपत्तियों के अधिग्रहण तक, क्योंकि पश्चिमी संचालक रूसी बाजार से बाहर निकल गए थे। रूसी अरबपतियों ने ऊर्जा, खुदरा और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में पश्चिमी कंपनियों द्वारा छोड़ी गई ऐसी संपत्तियों को हासिल करके लाभ कमाया। फार्मास्यूटिकल्स, खुदरा और विनिर्माण सहित रूसी उद्योग, विदेशी प्रतिस्पर्धियों के बाहर निकलने से पैदा हुए बाजार के खालीपन को भरकर विकसित हुए हैं। साइबर सुरक्षा फर्मकैस्परस्की लैब ने मौजूदा विदेशी कंपनियों से सॉफ्टवेयर अवसंरचना विकास का कार्यभार संभाला।

रूसी खुदरा विक्रेता ग्लोरियाजीन्स ने एचएंडएम और ज़ारा जैसी कंपनियों द्वारा खाली किए गए प्रमुख खुदरा स्थानों का अधिग्रहण करके विस्तार किया। व्यापार प्रवाह के पुनर्गठन ने कई देशों के लिए अवसर भी पैदा किए हैं। पश्चिम एशियाई ऊर्जा उत्पादकों के निर्यात राजस्व और आर्थिक लाभ में वृद्धि देखी जा रही है। तुर्की यूरोपीय आयातों के लिए एक संभावित ऊर्जा केंद्र और रूसी ऊर्जा के पुनर्निर्यात का केंद्र बन गया है। रूसी तेल की अपनी खरीद बढ़ाने के अलावा, चीन ने यूरोप को तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की अपनी खेप भी मुनाफे पर बेची है। ज़ाहिर है, ये व्यापारिक प्रतिष्ठान अपने व्यावसायिक लाभ के लिए रूस-यूक्रेन युद्ध को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहेंगे।

अमेरिका की तरफ झुकाव से भारत को नुकसान

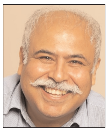
जगदीश रत्तनानी

तथ्य यह है कि ट्रम्प के प्रति तमाम प्रकार की सहनशीलता दिखाने के बावजूद भारत को दंडित किया गया तब यह स्पष्ट होना चाहिए कि अति उत्साह का प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं होता है, यहां तक कि कई बार प्रतिकूल भी होता है। खासकर उन परिस्थितियों में जब इसे किसी दी गई वैश्विक व्यवस्था में शामिल होने की हताशा के रूप में देखा जाता है। यह मानता है कि झुकाव एक तरफ है या दूसरी ओर।

यह कहना-सुनना असामान्य नहीं है विदेश नीति नैतिक सिद्धांतों के बारे में नहीं बल्कि राष्ट्रीय हितों के बारे में होती है। डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से सावधानीपूर्वक पोषित वैश्विक समझौतों को देखते हुए- व्यापार से लेकर जलवायु परिवर्तन तक को अमेरिकी विदेश नीति में प्रधानता दी है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अल्पकालिकता को, जिसे सबसे संकीर्ण तरीके से परिभाषित किया गया है, आज अमेरिकी विदेश नीति का प्रधान बिंदु है। यह जरूरी नही है कि उपद्रवी और अक्सर अशालीन ट्रम्प की नीतियां अमेरिकी परंपराओं के साथ ताल-मेल बिठाती हों। यह बात इससे स्पष्ट हो जाती है कि 1970 के दशक में पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की टिप्पणी (निक्सन युग के राजनयिक अलेक्जेंडर हैग ने कहा कि 'मैंने किसिंजर से यह कहते सुना था कि कि अमेरिका का कोई स्थायी मित्र या स्थायी दुश्मन नहीं है, केवल उसके हित हैं।' दूसरे, प्रशासन अलग स्वर में बोल सकते हैं लेकिन उनके कार्यों का आशय या प्रभाव अलग नहीं रहा है। यहां हम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता बराक ओबामा पर विचार करें जिन्होंने ड्रोन हमलों में किसी भी अन्य राष्ट्रपति की तुलना में अफगानिस्तान में अधिक लोगों को मार डाला। 1939 में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर परिभाषित अपनी पुस्तक ('द ट्वेंटी इयर्स क्राइसिस: 1919-1939') में ईएच कैर ने 'नैतिक सिद्धांतों की आड़ में हितों को छिपाने' की राजनीतिक आवश्यकता के बारे में बात की। यह एक सदी पुराना अवलोकन है जो अमेरिकी विदेश नीति परिचालन वास्तविकताओं में एक स्थायी अंतर्दृष्टि बनी हुई है।

वर्तमान संदर्भ में अमेरिकी नीति का अचानक लबादा हटने और उसके नंगेपन को देखते हुए सवाल यह है कि भारत कैसे प्रतिक्रिया देता है? यह एक सकारात्मक संकेत है कि भारत अमेरिकी मांगों के आगे नहीं झुका है। ये ऐसी मांगें हैं जिन्हें देश पूरा नहीं कर सकता है; न ही करना चाहिए। अमेरिका लंबे समय से, खास तौर पर कृषि और डेयरी आयात पर नियंत्रण हटाने के संदर्भ में दबाव डाल रहा है। भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल के आयात को लेकर अमेरिका हमेशा भुनभुनाता रहा है। यह भुनभुनाहट भारत को अपने बाजारों को अमेरिका के लिए और भी अधिक खोलने के लिए प्रेरित करने के लिए है। अब जब उसे दिख रहा है कि भारत झुकता नहीं है, तो उसने 50 प्रतिशत टैरिफ का हमला किया है जो सभी देशों के मुकाबले सबसे खराब व्यवहार में से एक है। ऐसे में यह सवाल जरूरी है वे कौन से सबक हैं जो सबसे अलग हैं? अमेरिका से उभरने वाले नए और बुरे खतरों को देखते हुए कि आईटी और अन्य सेवाओं को जल्द ही टैरिफ का सामना करना पड़ेगा।

इसके अलावा, जैसे-जैसे भारत महत्वपूर्ण प्रति-संतुलन का प्रयास करता है और नए गठबंधनों पर काम करता है एवं साझेदारियों पर फिर से विचार करता है, इससे संबंधित प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि देश इस मजबूत जकड़ से छूटने का प्रबंधन कैसे करता है। सबसे महत्वपूर्ण घटना 1 सितंबर को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बहुत ही स्पष्ट भागीदारी थी। चीन के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ तस्वीर में क्या भारत ने अमेरिका को कोई महत्वपूर्ण संदेश नहीं दिया? क्या यह अमेरिकी राष्ट्रपति की दुविधापूर्ण मनस्थिति का प्रतीक नहीं है जहां वे किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, विचार के प्रति अनिर्णायक और अस्थिर रहे हैं? एक पल में हां करने और अगले ही पल मना करने जैसी प्रतिक्रिया तुरंत नहीं दी थी? पहले उन्होंने शिकायत की थी कि भारत और रूस चीन से हार गए हैं और फिर अमेरिका और भारत के बीच एक विशेष संबंध पर जोर दिया जिसका मोदी ने तुरंत स्वागत किया। लेकिन जैसा कि शशि थरूर ने बिल्कुल सही पूछा है- 'क्या भारत ट्रम्प द्वारा किए अपमान और टैरिफ को भूल सकता है?'

तथ्य यह है कि ट्रम्प के प्रति तमाम प्रकार की सहनशीलता दिखाने के बावजूद भारत को दंडित किया गया तब यह स्पष्ट होना चाहिए कि अति उत्साह का प्रदर्शन कभी भी अच्छा नहीं होता है, यहां तक कि कई बार प्रतिकूल भी होता है। खासकर उन परिस्थितियों में जब इसे किसी दी गई वैश्विक व्यवस्था में शामिल होने की हताशा के रूप में देखा जाता है। यह मानता है कि झुकाव एक तरफ है या दूसरी ओर। भारत पहले ही एक तरफ अति उत्साही होकर अपनी उंगलियां जला चुका है।

'नमस्ते ट्रम्प' या 'हाउडी मोदी' जैसी बातों को व्यक्तिगत केमिस्ट्री कहना और फिर उसे बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना, उस पर अधिक जोर देना या पूरे दिल से अमेरिका के साथ जुड़ने की घटनाओं ने भारत पर दोहरी मार की है। उदाहरण के लिए जिस तरह से भारत ने जून 2025 में गाजा में युद्धविराम का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव से परहेज किया वह भारत के पक्ष में नहीं रही। उसने भारतीय हितों की रक्षा नहीं की और भारत को सिद्धांत पर खड़ा नहीं किया- न तो यथार्थवादी और न ही आदर्शवादी के रूप में दिखाया। नुकसान भारत का ही ज्यादा हुआ है। संयोग से एससीओ के पूरे समूह ने जून के प्रस्ताव के लिए मतदान किया जिसका शीर्षक था- 'नागरिकों की सुरक्षा तथा कानूनी और मानवीय दायित्वों को बनाए रखना'। ब्रिक्स देशों, एससीओ ब्लॉक या वास्तव में दक्षिण एशिया (भारत के अलावा) में से किसी ने भी भाग नहीं लिया जो एससीओ देशों के प्रति भारतीय अभिविन्यास में एक असंयोजन की ओर इशारा करता है।

कुछ हलकों का यह तर्क सीमित अपील करने वाला है कि टैरिफ के मामले में भारत दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगा और भारत की बात स्वीकार की जाएगी क्योंकि वह एक आर्थिक महाशक्ति है जो जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। बेशक भारत में सबकी रुचि है लेकिन इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है कि पश्चिमी व्यवसायों के लिए इसका बाजार कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है। निर्यात के मामले में भारत के पास विविधता भरा एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है और वह अमेरिका पर अत्यधिक निर्भर है जिसके कारण वह भारत को निचोड़ सकता है और धमकी दे रहा है।

यह दिलचस्प है कि भारत ने ट्रम्प की हरकतों के जवाब में 'रणनीतिक स्वायत्तता' की नीति पर निर्माण करने के लिए महात्मा गांधी का उपयोग किया है। ट्रम्प के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को एक अनाम शीर्ष सरकारी प्रवक्ता के हवाले से इन शब्दों में समझाते हुए कहा गया है- 'हमने गांधीवादी सत्याग्रह मॉडल का पालन किया है .., तुमने हमें मारा। निश्चित रूप से यह हमें दर्द देता है लेकिन हम पलटवार नहीं करेंगे। न ही हम आदेश का पालन करेंगे या किसी बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर करेंगे। इसमें उच्च नैतिक आधार तक पहुंचने के संकेत हैं लेकिन गांधीवादी सत्याग्रह भारत से और भी बहुत कुछ मांगेगा। जब इजरायल गज़ा में खून बहा रहा है तब यह भारत को इजरायल के साथ गठबंधन करने के बारे में चुनौती देगा। यह कई अन्य कठिन सवाल उठाएगा जिनका अगर पालन किया जाए तो अभी भी गांधी के सामने झुकने वाली दुनिया में भारत को साहस और गर्व के साथ खड़ा होने में मदद मिलेगी।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। सिंडिकेट:द बिलियन प्रेस)

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

चिंतन

कब, कैसे कर पाएंगे हम आधी आबादी की सुरक्षा

देश में महिला सुरक्षा या सम्मान की बात आते ही एक के बाद एक न जाने कितने दावे किए जाते हैं। कितने तरह के कानून की दुहाई दी जाती है, लेकिन बात जब भी धरातल की होती है और एक के बाद महिलाओं के प्रति अपराध की बात आती है तो लगता है कि बहुत कुछ किया जाना शेष है। दिल्ली में निर्भया हत्याकांड के बाद केंद्र सरकार ने कानून में आमूलचूल बदलाव किए। दावा किया गया कि अब कोई भी महिलाओं के खिलाफ अपराध करने से पहले सौ बार सोचेगा, लेकिन हुआ क्या। हर रोज समाचार पत्रों के पन्नों पर ऐसी खबरों की भरमार नजर आती है। 'नारी 2025' नामक राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट ने इस मुद्दे पर चौकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं, जो महिला सुरक्षा की स्थिति को लेकर गंभीर सवाल उठाते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार देश की लगभग 40 फीसदी महिलाएं अपने शहरों में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करतीं। यह आंकड़ा शहरों के सार्वजनिक स्थानों, ऑफिस, स्कूल, कॉलेज और ट्रांसपोर्ट में महिलाओं की सुरक्षा की मौजूदा स्थिति का दर्दनाक सच बयान करता है। रिपोर्ट में रांची, श्रीनगर, कोलकाता, दिल्ली, फरीदाबाद, पटना और जयपुर को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर माना गया है। दिल्ली और फरीदाबाद में लगभग 42 प्रतिशत महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं, वहीं, कोहिमा को महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर माना गया, जहां 80 फीसदी से ज्यादा महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, आइज़ोल, गंगटोक, ईटानगर और मुंबई भी अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं। अगर उत्पीड़न के आंकड़े को देखें तो 2024 में 7 फीसदी महिलाओं ने उत्पीड़न का सामना किया, जिसमें 18-24 साल की युवा महिलाओं का जोखिम सबसे अधिक था। दुःखद बात ये भी है कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की आधिकारिक रिपोर्टिंग बहुत कम होती है। केवल 22 प्रतिशत महिलाएं अपने अनुभवों की रिपोर्ट पुलिस को देती हैं, और केवल 16 फीसदी मामलों में कार्रवाई होती है। यही कारण है कि महिला सुरक्षा में भारत की रैंकिग 177 देशों की सूची में 124वां स्थान है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए शर्म की बात है। अब वीरवार के ही एक समाचार को देखें जिसमें एक महिला को उसी शख्स के हाथों सरेआम अपमान झेलना पड़ा, जिसके साथ उसने सात फेरे लिए थे। जिसने जीवन भर उसकी सुरक्षा का वादा किया। ऐसा भी नहीं कि पति और पत्नी अशिक्षित या पिछड़े इलाके से थे। पत्नी स्कूल में टीचर है और हैवान बन बैठा पति कॉलेज में लेक्चरर है। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को सरेआम बेइज्जत किया। उसने अपनी पत्नी के गले में चप्पलों की माला डाली, उसके साथ मारपीट की और सड़क पर परेड कराई। यही नहीं इस शर्मसार करने वाली पूरी घटना का वीडियो भी बनाया। पति को अपनी पत्नी पर शक था कि उसके किसी और के साथ प्रेम संबंध हैं। अब इसे आप क्या कहेंगे। जब रखवाला ही हैवानियत करने लगे तो किससे उम्मीद करेंगे। एक ऐसा देश जहां साल में दो बार नवरात्र पर माता के रूप में महिलाओं को पूजा जाता है, उसी देश में महिला सुरक्षा की हालात ये है। अगर किसी को यह लगता हो कि सख्त कानून बनाने से महिलाओं के खिलाफ अपराध खत्म हो जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। इसके लिए हमें नई पीढ़ी को संस्कारवान बनाना होगा। उन परंपराओं का पालन करना होगा, जो हमारी संस्कृति ने हमें दी हैं। एकल परिवार से हटकर कुटुंब व्यवस्था की ओर लौटना होगा तभी हम आधी आबादी को सुरक्षित रख पाएंगे।

विश्लेषण

राजेश माहेश्वरी

राधाकृष्णन के सामने अवसर और चुनौतियां भी कम नहीं

चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राजनीतिक गलियारों में सीपीआर के नाम से ख्यात राधाकृष्णन को सत्तारूढ़ राजग ने जब प्रत्याशी बनाया, तभी से उनकी जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन विपक्षी खेमे ने बी. सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में उतार कर इस मुकाबले को रोमांचक बनाने का प्रयास किया। विपक्षी मोर्चे ने तमिल बनाम तेलुगु अस्मिता का मुद्दा उछालकर राजग की प्रमुख सहयोगी तेलुगु देसम पार्टी के सामने धर्मसंकट खड़ा करने के साथ ही अक्सर विधायी मामलों पर सरकार का समर्थन करने वाली वाइएसआर कांग्रेस और एक अन्य दल बीआरएस के समक्ष राजनीतिक दुविधा बढ़ाने का दांव चला था। हालांकि नतीजे यह बताते हैं कि विपक्ष की यह आकांक्षा पूरी नहीं हो पाई। भारत के पंद्रहवें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन शपथ ले चुके हैं। नए उपराष्ट्रपति के रूप में राधाकृष्णन के समक्ष चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। राज्यसभा के सभापति के रूप में उन्हें संतुलन साधने का प्रयास करना होगा। उनके पूर्ववर्ती धनखड़ आरंभिक स्तर पर उच्च सदन में विपक्ष को बहुत स्पेस नहीं देते थे, पर विपक्ष के आक्रामक तेवरों के बाद उन्हें रवैया कुछ बदलना पड़ा। सरकार और उनके बीच अविश्वास की खाई बढ़ने में उनका बदला हुआ रवैया भी एक पहलू बन गया था। चूंकि सदन के सभापति से दलगत या वैचारिक आग्रह से ऊपर उठकर कार्यवाही के संचालन की अपेक्षा की जाती है, इसलिए राधाकृष्णन को इस मोर्चे पर कोई मध्य मार्ग तलाशना ही होगा। राज्यसभा के सभापति पद पर भले ही कोई प्रत्यक्ष काम न दिखे, लेकिन इसकी अपनी संवैधानिक भूमिका होती है। प्रोटोकॉल में उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर पर आते हैं। देश-विदेश में उनका नाम होता है और इस लिहाज से यह पद अहम है। चुनौतियों की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति को सत्ता और विपक्ष के बीच तटस्थ रहना होता है। विपक्ष अक्सर इस पद पर आसीन लोगों के खिलाफ पक्षपात का आरोप लगाता रहता है। राधाकृष्णन को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। राज्यसभा में सांसदों के बीच तीखी नोक-झोंक और अव्यवस्था उपराष्ट्रपति की भूमिका को मुश्किल बना देती है। कई मौकों पर ऐसा हुआ है जब विपक्षी सांसदों के निलंबन जैसे कदमों से विवाद हुआ है। राधाकृष्णन को ऐसी स्थिति में धैर्य और कड़ाई का संतुलन बनाना होगा। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक गरिमा का प्रतीक होता है। इस पद पर आसीन व्यक्ति को अपने कर्मों के द्वारा इस गरिमा की रक्षा के लिए बहुत ध्यान देना होता है। राधाकृष्णन को इस गरिमा को बनाए रखना होगा। राधाकृष्णन के सामने सबसे बड़ी कसौटी होगी सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन बनाना। उनकी आरएसएस और बीजेपी में काम करने की मजबूत पृष्ठभूमि है, और अच्छा सियासी अनुभव है। लेकिन यही पृष्ठभूमि विपक्ष के लिए संदेह का कारण भी बन सकती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके नेतृत्व में राज्यसभा की कार्यवाही अधिक समावेशी हो सकेगी और सदन में जन सरोकारों से जुड़ा अधिक कार्य हो सकेगा। यह निर्विवाद सत्य है कि संसद की विश्वसनीयता अध्यक्ष की दलीय सीमाओं से परे सम्मान अर्जित करने की क्षमता पर निर्भर करती है। सीपी राधाकृष्णन का उप राष्ट्रपति पद के लिए चुना जाना विपक्ष के लिए एक सबक जैसा भी है। जो उसे याद दिलाता है कि प्रतीकात्मक मुकाबले एक सुसंगत रणनीति का विकल्प नहीं हो सकते। यह भी एक हकीकत है कि राधाकृष्णन ऐसे वक्त में यह पद संभाला है जब सरकार और विपक्ष के बीच असहमति की खाई ज्यादा गहरी नजर आती है। पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ के समय में सरकार और विपक्ष के बीच वैचारिक मतभेद के साथ मनभेद भी बढ़ा है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपने पूर्ववर्ती की कार्यप्रणाली के मद्देनजर नये उपराष्ट्रपति को अपनी कार्यशैली में व्यापक सुधार करना होगा। आने वाले समय में उन्हें पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर विधायी कार्यों को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। इन तमाम चुनौतियों के बीच सी.पी. राधाकृष्णन के सामने उपराष्ट्रपति के तौर पर संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने का सुनहरा अवसर भी है। उनकी भूमिका न केवल संसद की कार्यवाही को सुचारू बनाने की है, बल्कि देश की संवैधानिक और कूटनीतिक गरिमा को बढ़ाने की भी है। अगर वह निष्पक्षता, धैर्य और संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सत्ता और विपक्ष के बीच संतुलन साधने में कामयाब होंगे, और इस पद के लिए एक नजीर बनेंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि राधाकृष्णन उच्च सदन की गरिमा और गौरव को नयी ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

पड़ोस

प्रमोद भार्गव

अस्थिरता के दौर से गुजरता नेपाल

नेपाल जब से कम्युनिस्ट देश बना है, तब से चीन के दबाव के चलते यहां लगातार अस्थिरता बनी हुई है। इस बार नेपाल भीषण संकट में है। यह संकट इसलिए बढ़ा, क्योंकि राजशाही खत्म होने के बाद संघीय सरकार से युवाओं को अपेक्षा थी कि देश में राजनीतिक स्थिरता तो कायम होगी ही, सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगारों की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन 17 साल के गैर राजतांत्रिक नेपाल में 15 सरकारें तो बदलीं, परंतु हालात नहीं बदले। इसी बीच राजशाही और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगें भी उठती रही हैं। चीनी लिप्सा के प्रतिरोध में भी यह संकट देखा जा रहा है। अतएव इस तत्काल के संकट को किसी एक दृष्टिकोण से देखा जाना भूल होगी।

भारत का पड़ोसी देश नेपाल जब से कम्युनिस्ट देश बना है, तब से चीन के दबाव के चलते यहां लगातार अस्थिरता बनी हुई है। इस बार नेपाल भीषण संकट में है। यह संकट इसलिए बढ़ा, क्योंकि राजशाही खत्म होने के बाद संघीय सरकार से युवाओं को अपेक्षा थी कि देश में राजनीतिक स्थिरता तो कायम होगी ही, सरकारी नौकरियों और अन्य रोजगारों की संभावना भी बढ़ेगी। लेकिन 17 साल के गैर राजतांत्रिक नेपाल में 15 सरकारें तो बदलीं, परंतु हालात नहीं बदले। इसी बीच राजशाही और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांगें भी उठती रही हैं। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से जनता को पता चला कि मंत्री और उनके परिजन देश-विदेश में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके बच्चे विदेशों में अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। ब्रांडेड सामान के साथ फाइव स्टार जीवन विदेशों में व्यतीत कर रहे हैं।

इस वैभव की पृष्ठभूमि में सरकारी स्तर पर फैले भ्रष्टाचार को मुख्य कारण माना। जबकि गरीब युवा प्रतिदिन तीन हजार से ज्यादा की संख्या में पलायन करने को विवश हो रहे हैं। इस आंदोलन को पहले दक्षिणपंथी करार देने की कोशिशें हुईं, लेकिन वास्तव में यह आक्रोश उस कुंठा के चलते उपजा जो नेताओं और उनके परिजनों के वीडियो में भोग-विलास का जीवन जीते हुए दिखा। नेपाल में हिंसा और अराजकता इस हद तक फैली कि आंदोलनकारियों ने संसद भवन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रियों तक के घर जला दिए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पत्नी को जिंदा जला दिया। देश की सत्ता की इस राख में 22 युवाओं की सेना और पुलिस की गोलाबारी में हुईं मौतों की राख भी मिल गई। इस आंदोलन को सोशल मीडिया के साथ खासतौर से जेन-जी पर पाबंदी माना जा रहा है। हालांकि यह रोक युवाओं का आक्रोश देखने के बाद हटा ली गई थी। जेन-जी यानी जेनरेशन-जेड का बोध कराने वाली वह पीढ़ी है, जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है। यानी वर्तमान में ये आंदोलनकारी किशोर एवं युवा हैं। इस आग में घी डालने का काम सुदन गुरुंग और बालेन शाह ने जेन-जी पर उपस्थिति दर्ज कराकर कर दिया। सुदन ओली सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और परिवारवाद की मुहिम पूर्व से ही चला रहे थे। कुछ नेताओं की बढ़ती संपत्ति के विरुद्ध भी मोर्चा खोले हुए थे। इसी बीच 4 सितंबर को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो राजधानी काठमांडू के महापौर बालेन शाह सक्रिय हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया एक्सेस किया और लिखा, 'कल की रैली जेन-जी की रैली है। इस रैली में कोई भी पार्टी, नेता, सांसद एवं कार्यकर्ता को निजी लाभ के लिए शामिल होने की जरूरत नहीं है। उम्र के कारण मैं जा नहीं सकता, लेकिन मेरा पूरा समर्थन है।' बालेन के चाहने वाले लाखों में हैं। देखते-देखते आंदोलन की दशा और दिशा तय हो गई और लाखों युवा आंदोलन के लिए काठमांडू की सड़कों पर उतर आए। संसद और राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, प्रधानमंत्री आवास पर पत्थरबाजी की और पूरे शहर में ऐसा तांडव मचाया कि सेना और पुलिस को नियंत्रण के लिए संयुक्त अभियान चलाना पड़ा । नेपाल के इतिहास में इसे बड़ी तख्तापलट की घटना के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले

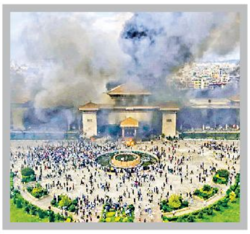

बांग्लादेश और श्रीलंका में भी इसी तरह का जनआक्रोश फूट चुका है। वहां की सरकारें अपदस्थ हुई हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र घोषित किए जाने की मांग भी लंबे समय से उठ रही है। वहां अनेक संगठन सड़कों पर उतरकर राजशाही के पक्ष में आंदोलन कर चुके हैं। इस मांग को मुख्य रूप से राष्ट्रवादी राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी कर रही है। यह नेपाल की पांचवीं सबसे बड़ी पार्टी है। इस दल के प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ की मांग है कि नेपाल में राजशाही की पुनर्बहाली हो और इसे हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। नेपाल को 2007 में पंथनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया था। नतीजतन 2008 में राजशाही व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी। 2008 में नेपाल के गणराज्य बनने के बाद से कारोबारी दुर्गा प्रसाई आंदोलन को हवा दे रहे हैं। एक समय प्रसाई के प्रधानमंत्री प्रचंड और ओली के साथ घनिष्ठ संबंध थे, लेकिन बाद में वे दोनों के आलोचक हो गए। इसी समय राजशाही के दौर में गृहमंत्री रहे कमल थापा ने हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए नया गठबंधन बना लिया है। पूर्व नरेश ज्ञानेंद्र शाह भी एकाएक सक्रिय होकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में भागीदारी करने लगे हैं। वह मंदिरों में होने वाली पूजा में शामिल हो रहे हैं। दरअसल नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी का चीन की गोद में बैठना और भारत विरोधी अभियान चलाना देश की जनता को नागवार गुजर रहा है। नेपाल के मुसलमान भी देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्ष में हैं। समाज के कुछ नेताओं का मानना है कि हिंदू राष्ट्र का दर्जा खत्म होने के बाद से नेपाल में ईसाई मिशनरियां ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। मिशनरी इस स्थिति का फायदा उठाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करवा रही हैं। यूसीपीएन माओवादी के मुस्लिम मुक्ति मोर्चा भी मिशनरियों के बढ़ते प्रभाव को स्वीकार नहीं करता है। राष्ट्रवादी मुस्लिम मोर्चा भी देश की धर्मनिरपेक्ष पहचान नहीं चाहता है। 80 फीसद मुस्लिम आबादी देश की हिंदू पहचान बहाल करने के पक्ष में हैं। गौरतलब है कि राजनीतिक दलों के बीच नए संविधान में देश की धर्मनिरपेक्षता की पहचान खत्म करने को लेकर सहमति बनी थी। इसके बाद से यह मांग और तेज हो गई है। देश के सभी समुदाओं के लोग मानते हैं कि पुरानी हिंदू पहचान की बहाली का कोई विकल्प नहीं है। धर्मनिरपेक्षता हिंदू-मुस्लिम एकता तोड़ने की साजिश है। नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना तो हो गई, लेकिन लचर नेतृत्व के चलते यह देश अपना अस्तित्व खोने की कगार पर आ खड़ा हुआ है। इसी चिंता से यह आक्रोश उपजा है।

नेपाल और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों के तहत ऐतिहासिक पारगमन व्यापार समझौते समेत 10 समझौतों की शुरुआत करके नेपाल ने चीन से रिश्ते मजबूत कर लिए हैं। चीन और नेपाल के बीच तिब्बत के रास्ते रेलमार्ग बनाने पर भी संधि हुई है। चीन ने काठमांडू से करीब 200 किमी दूर पोखरा में क्षेत्रीय हवाई अड्डा निर्माण के लिए नेपाल को 21000 डॉलर का सस्ती ब्याज दर पर ऋण दिया है। मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर हुए हैं। नेपाल में तेल और गैस की खोज करने पर भी चीन सहमत हुआ है। इसके लिए वह नेपाल को आर्थिक और तकनीकी मदद देने को राजी है। चीन ने नेपाल में अपने व्यावसायिक बैंक की शाखाएं भी खोल दी हैं। नेपाली बैंक भी अपनी शाखाएं चीन में खोल रहे हैं। संस्कृति, शिक्षा, भाषा और पर्यटन जैसे मुद्दों पर भी चीन का दखल नेपाल में बढ़ गया है। अर्से से इन्हीं कुटिल कूटनीतिक चालों के चलते कम्युनिष्ट विचारधारा के पोषक चीन माओवादी नेपालियों को अपनी गिरफ्त में लेकर अपनी साम्राज्यवादी लिप्सा को आगे बढ़ा रहा है। इस चीनी लिप्सा के प्रतिरोध में भी यह संकट देखा जा रहा है। अतएव इस तत्काल के संकट को किसी एक दृष्टिकोण से देखा जाना भूल होगी।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

लोभ के कारण संसार में समस्त पापों की उत्पत्ति

संकलित
दर्शन

लोभ के कारण संसार में समस्त पापों की उत्पत्ति होती है। इस लोभ का ही दूसरा नाम लालच है। लालच से सारे गुण नष्ट हो जाते हैं और उनका स्थान ग्रहण कर लेते हैं-क्रोध, द्वेष, मान, माया आदि। शायद ही कोई ऐसा पाप बचता हो जो लालच से पैदा न होता हो। कोई ऐसा दुर्गुण शेष नहीं रहता जो लालची व्यक्ति में न हो। जब सारे दुर्गुण, सारे पाप किसी व्यक्ति के हृदय में बैठ जाएँ तो उसका सर्वनाश होना स्वाभाविक ही है। इसलिए लालच को सभी महा-आत्माओं ने तमाम संकटों की जननी और तमाम अनर्थों का आश्रय कहा है। जिस मनुष्य के अन्तःकरण में लालच का दैत्य एक बार प्रवेश कर गया, उसके लिए फिर जघन्य-से-जघन्य पाप कर डालना असम्भव नहीं रहता। आज का मानव दिन-ब-दिन अधिकाधिक लालची, लोभी होता जा रहा है। अपनी यश-लिप्सा, संसार के समस्त सुख-साधनों और उनकी प्राप्ति के माध्यम-अर्थ-धन की सिद्धि में वह इतना बेहोश हो जाता है कि अपने जन्मदाता माँ-बाप की हत्या करने से भी नहीं चूकता। पग-पग पर आजीवन सुख-दुःख के सहभागी सहोदर की दैहिक-लीला को नष्ट करके भी यदि उसकी लालची भूख को क्षणिक तृप्ति मिलने की सम्भावना हो तो वह जघन्य पाप करने में भी नहीं झिझकता।

- कांतिलाल मांडोत

ऐसे काम न करें, जिससे गलत लोगों की ताकत बढ़े

संकलित
प्रेरणा

बाल कृष्ण माखन चोरी की लीला कर रहे थे। गोकुल के लोग इस वजह से काफी परेशान थे। एक दिन गांव के नंद बाबा और यशोदा के पास पहुंचे और कान्हा की शिकायत करने लगे। नंद बाबा ने कृष्ण से पूछा कि तुम माखन चोरी क्यों करते हो, जबकि हमारे घर में तो बहुत माखन है। कृष्ण ने कहा कि आप लोग मेहनत से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर के रूप में दुष्ट कंस को दे देते हैं और इस वजह से गांव के बच्चों को माखन नहीं मिलता है। आपके इस काम से कंस की ताकत लगातार बढ़ रही है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं तोड़-फोड़ करता रहूंगा। ताकि ये माखन कंस के पास न पहुंचे और गांव के बच्चों को मिल सके। कंस गांव के लोगों से कर के रूप में दुध, मक्खन वसूला करता था। कृष्ण ने देखा की लोग अपने बच्चों को न देकर कर के रूप में मक्खन कंस को देते हैं। कृष्ण ने इस बात का विरोध किया। ताकि लोग अपनी ताकत समझ सके और मिलकर कंस का विरोध कर सके। इस कथा में श्रीकृष्ण ने संदेश दिया है कि हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए, जिनकी वजह से गलत लोगों की ताकत बढ़ती है। और व हम पर हावी हो जाए।

अंतर्मन

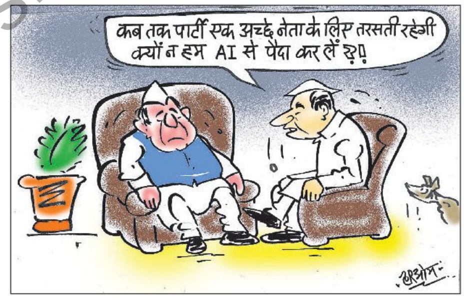

आज की पाती

घोटालेबाजों पर हो सख्त कार्रवाई

हीरा कारोबारी भगौड़े मेहुल चौकसी को बेल्जियम से वापस लाने के लिए भारत की तमाम जांच एजेंसियों ने पूरा जोर लगाया हुआ है। मेहुल चौकसी और उसके भतीजे नीरव मोदी ने पंजाब नैशनल बैंक में लगभग 13500 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। अब यह भारत की कैसी ऋण प्रणाली है जिसमें चौकसी और मोदी जैसे बड़े-बड़े कारोबारियों को बड़ी ही आसानी से बैंकों से ऋण प्राप्त हो जाता है। लेकिन अगर उन्हीं बैंकों से किसी आम नागरिक, किसान या गरीब व असहाय व्यक्ति ने अपने जीवन को सुधारने के लिए ऋण की नाममात्र रकम ही क्यों न लेनी हो, उससे सैकड़ों औपचारिकताएं पूरी करवाने के साथ-साथ गारंटर भी मुहैया करवाना पड़ता है।

- महेश शर्मा, दुर्ग

ट्रेंड

बाढ़ स्थिति की समीक्षा

उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति को लेकर बैठक की। राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान को देखकर बहुत पीड़ा हुई है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। हम हर जरूरी इंतजाम तेजी से सुनिश्चित करने में जुटे हैं।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

नेपाल आंदोलन

कुछ लोग नेपाल आंदोलन का नाम लेकर भारत में राजशाही का सपना देख रहे हैं, वे असल में लंबे समय से लोकतंत्र के विरोध में मन में दबाए बैठी भावनाओं को बाहर निकाल रहे हैं। इनको ये समझना चाहिए कि यहां राजशाही के लिए जगह नहीं है।

-डॉ. रामदास अठावले, राज्यसभा सांसद

राधाकृष्णन को बधाई

सी.पी. राधाकृष्णन को आज भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर हार्दिक बधाई! पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में लोकतंत्र की मर्यादा, संवाद की संस्कृति और राष्ट्रहित का संकल्प और सशक्त होगा तथा भारत की गौरवपूर्ण यात्रा को नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

विनम्र नहीं, निडर रहें

जीवन में, आपको हमेशा विनम्र लेकिन निडर रहना चाहिए। सफलता में कभी भी अहंकार को जन्म नहीं देना चाहिए। इससे रक्षात्मक या अति सतर्क होने की प्रवृत्ति भी नहीं आनी चाहिए।

- अनिल अग्रवाल, उद्यमी

अपने विचार
हरिभूमि कायार्लय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से aapkepatra.haribhoomi@gmail.com पर भेज सकते हैं।

करंट अफेयर

एलन मस्क की स्टारलिंक को लेबनान ने दिया लाइसेंस

लेबनान ने संकटग्रस्त देश में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए एलन मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस जारी किया है। सूचना मंत्री पॉल मोरकोस ने बृहस्पतिवार रात मंत्रिमंडल बैठक के बाद यह घोषणा की। मोरकोस ने कहा कि स्टारलिंक मस्क की एक अन्य कंपनी स्पेसएक्स की ओर से संचालित उपग्रहों के माध्यम से पूरे लेबनान में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगी। मस्क ने तीन महीने पहले लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन से फोन पर बात की थी और देश के दूरसंचार तथा इंटरनेट क्षेत्रों में काम करने की दिलचस्पी जताई थी। मंत्रिमंडल बैठक के दौरान सरकार ने देश के बिजली और दूरसंचार क्षेत्रों के लिए नियामक प्राधिकरणों की स्थापना की घोषणा की।

लेबनान में भ्रष्टाचार से ग्रस्त ऊर्जा क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण की स्थापना करना अंतरराष्ट्रीय संगठनों की एक प्रमुख मांग रही है। बिजली क्षेत्र के लिए नियामक प्राधिकरण की नियुक्ति लगभग 20 वर्ष पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन देश की प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा बार--बार विलंब किया जाता रहा। इस कदम को लेबनान के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के रूप में देखा जा रहा है, जो इस छोटे भूमध्यसागरीय देश में हर साल एक अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक की बर्बादी करता है।

ऑफ बीट

सोशल मीडिया से बच्चे सीख रहे हैं एआई का उपयोग

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) निबंध लेखन, भाषाओं का अभ्यास और गृह कार्य पूरा करने के तरीकों को तेजी से बदल रही है। शिक्षक भी अब पाठ योजना, मूल्यांकन और फीडबैक के लिए एआई उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन यह बदलाव इतनी शीघ्रता से हो रहा है कि स्कूल, विश्वविद्यालय और नीति-निर्माता इसके साथ कदम मिलाने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं। इस तेज बदलाव के बीच अक्सर एक बुनियादी सवाल छूट जाता है-छात्र और शिक्षक वास्तव में एआई का उपयोग सीख कैसे रहे हैं? वर्तमान में यह सीखना अधिकांशतः अनौपचारिक तरीकों से हो रहा है। छात्र टिकटॉक या डिस्कॉर्ड पर सुझाव साझा करते हैं या चैटजीपीटी से निर्देश लेते हैं। शिक्षक स्टाफ रूम में आपस में चर्चा करते हैं या लिंक्डइन पर जानकारी हासिल करते हैं। हालांकि यह नेटवर्क जानकारी तेजी से फैलाते हैं, लेकिन इसमें पूर्वाग्रह, निगरानी या समानता जैसे गहरे मुद्दों पर विचार नहीं होता। यहीं पर औपचारिक शिक्षक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जिज्ञासा से आगे बढ़कर शोध से पता चला है कि अधिकतर शिक्षक एआई के लिए तैयार नहीं हैं। हालिया अध्ययन में पाया गया कि कई शिक्षकों को एआई उपकरणों की विश्वसनीयता और नैतिकता का आकलन करने का कौशल प्राप्त नहीं है।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 178

संकट के मुहाने पर नेपाल

समूचे नेपाल को एकदम ठप कर देने वाली हिंसा ने भले ही वहां के सत्ताधारी प्रतिष्ठान को चकित कर दिया हो लेकिन यह संकट कम से कम एक दशक से पनप रहा था। इसके मूल में नेपाली युवाओं की वह निराशा है जो सरकार की आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर तैयार कर पाने में नाकामी से उपजी है। भ्रष्टाचार ने हालात को और बुरा बना दिया। नेपाल के सार्वजनिक जीवन का कमोबेश हर क्षेत्र भ्रष्टाचार का शिकार है। नेपाल की आधी से अधिक आबादी 30 वर्ष से कम आयु की है। काठमांडू में विरोध प्रदर्शन करने वाले आबादी के इस अहम हिस्से को जेनजी के नाम से जाना जाता है। यह अपेक्षाकृत अधिक शिक्षित और वैश्विक माहौल से अवगत युवा हैं। नेपाल में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले अच्छी खासी संख्या में हैं और ऐसे में सरकार द्वारा 26 मीडिया प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंध लगाने के बाद जो प्रदर्शन पहले छात्रों द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से शुरू किया गया था जल्दी ही उसमें असामाजिक तत्वों की घुसपैठ हो गई। इस व्यापक प्रतिबंध का कारण यह बताया गया कि व्हाट्सऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे ये प्लेटफार्म पंजीकृत होने के लिए नेपाल के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तय समयसीमा का मान रखने में नाकाम रहे थे।

ऐसे में प्रतिबंध को लेकर हिंसक प्रतिक्रिया हुई और करीब 20 लोगों की जान चली गई। सत्ताधारी कुलीन वर्ग ने जमीनी हकीकतों को समझने में गलती कर दी थी। यह गलत आकलन अपने आप में बताता है कि इस लोकतांत्रिक गणराज्य की सत्ता संरचना में कितनी खामियां हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) और नेपाली कांग्रेस के रूप में दो सबसे बड़े दलों के सत्ताधारी गठबंधन में उम्रदराज कुलीनों का वर्चस्व था। यह गठबंधन अपने ही लोगों से लगातार दूर होता जा रहा था। ये कुलीन वर्ग ही समय-समय पर सत्ता में आते और जाते रहे। खड्ग प्रसाद ओली (73 वर्ष) जिन्हें हिंसा के बाद अचानक प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा उन्हें 2024 में चुना गया था और यह उनका चौथा कार्यकाल था। वह तब सत्ता में आए जब उनकी पार्टी ने पुष्प कमल दहल 'प्रचंड' (70 वर्ष) के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। प्रचंड तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। सत्ता की साझेदारी की ताजा व्यवस्था के तहत ओली को 2027 में अगले चुनाव तक नेपाली कांग्रेस के शेर बहादुर देउबा के साथ बारी-बारी से प्रधानमंत्री का पद संभालना था। देउबा पांच बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इस बीच अर्थव्यवस्था बहुत हद तक विदेश से भेजी जाने वाली राशि पर निर्भर हो गई जो नेपाल के सकल घरेलू उत्पाद का करीब एक चौथाई है। इसमें भारत का बहुत अधिक योगदान है। संयोगवश इस बार भारत उस दोषारोपण से मुक्त है जिसका सामना उसे अक्सर करना पड़ता है।

कानून और व्यवस्था कायम करने का काम अब सेना के पास है और एक पूर्व न्यायाधीश को अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है। इस प्रकार नेपाल का भविष्य अनिश्चितता का शिकार है। सत्ताधारी दल विफल रहे हैं। वर्ष 2008 में बेदखल राजशाही की वापसी तो मुमकिन नहीं नजर आती, हालांकि उसकी प्रतिनिधि राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी प्रदर्शनकारियों की नाराजगी से बचने में कामयाब रही है। नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव के प्रतीक दो लोकप्रिय दावेदार अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक हैं बालेन साह (35 वर्ष) जो पूर्व रैपर और काठमांडू के सफल मेयर रहे हैं। दूसरे हैं रवि लामिछाने (51 वर्ष) जो टीवी प्रस्तोता और पूर्व मंत्री हैं और जिन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा हुई थी और जो जेल पर हमले के बाद रिहा हो गए हैं। राजनीतिक व्यवस्था इन दोनों पर कितना भरोसा जताएगी यह देखना होगा।

अजय मोहंती

एआई को जल्दी अपनाने वाली कंपनियों को लाभ

जिन कंपनियों में स्थायी खर्च अधिक है उन्हें अपनी कारोबारी प्रक्रियाओं में एआई टूल्स को अपनाने से सबसे अधिक लाभ होगा। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं आकाश प्रकाश

मार्जिन विस्तार का स्वर्ण युग (गोल्डन एज ऑफ मार्जिन एक्सपेंशन या गेम) एक ऐसा सिद्धांत था जिसे अल्टीमीटर कैपिटल के ब्रैड गर्स्टनर ने विभिन्न ट्वीट और पॉडकास्ट के जरिये प्रचलित किया। उन्हें खासतौर पर अक्टूबर 2022 में मेटा को लिखे खुले पत्र के लिए जाना जाता है जिसमें उन्होंने शेयर बाजार में कमजोर चल रही कंपनी से कहा था कि कंपनी को फिट बनने, लागत कम करने और अपने मूल काम पर ध्यान देने की जरूरत है। इस सलाह पर अमल करके कंपनी पिछले तीन साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले टेक्नॉलजी शेयरों में शामिल है। आर्टिफिशल इंटेलिजेंस यानी एआई में भरोसा करने वाले तथा ओपनएआई के निवेशक गर्स्टनर मानते हैं कि अब वक्त आ गया है कि सभी बड़ी टेक कंपनियां और मोटे तौर पर सभी कंपनियां अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए एआई का इस्तेमाल करें। उन्हें लगता है कि एआई के प्रभावी इस्तेमाल से उत्पादकता में काफी इजाफा होगा क्योंकि कंपनियों को कर्मचारियों की तादाद कम करने में मदद मिलेगी जबकि राजस्व बढ़ेगा।

एआई ने पहले ही ग्राहक सेवा और प्रोग्रामिंग में अपनी काबिलियत साबित कर दी है और जैसे-जैसे प्रौद्योगिकी परिपक्व होगी और उद्यम इसके साथ अधिक सहज होते जाएंगे, उसका इस्तेमाल समय के साथ बढ़ता जाएगा। हर रोज हमें कोई न कोई नया ऐप्लीकेशन देखने को मिलता है और स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर रक्षा तक हर जगह इनका इस्तेमाल हो रहा है। एआई को अपनाने और इस्तेमाल करने की लागत भी तेजी से कम हो रही है। लार्ज लैंग्वेज मॉडलों की बात करें तो छह मॉडलों में से कम से कम तीन ओपन सोर्स हैं।

उत्पादकता और मार्जिन की बात करें तो इसके प्रमाण के रूप में गर्स्टनर बताते हैं कि कैसे 7 बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी कम कर दी है। वह एक चार्ट दिखाते हैं जो बताता है कि 2011 से 2021 के बीच इन कंपनियों के कर्मचारी सालाना 25 फीसदी की दर से बढ़ रहे थे। वर्ष 2020 में 45 फीसदी की वृद्धि के साथ यह उच्चतम स्तर पर पहुंचा। उस समय कोविड ने उपभोक्ताओं के व्यवहार को बदल दिया था। लेकिन बीते तीन सालों में यह वृद्धि घटकर केवल 2 फीसदी रह गई है।

बहरहाल, विगत तीन महीनों में सात बड़ी कंपनियों का राजस्व अभी भी 15-20 फीसदी की दर से बढ़ रहा है जबकि इस बीच कर्मचारियों की संख्या नहीं बढ़ी है। इसके चलते मार्जिन विस्तार की गुंजाइश बढ़ी। पिछली तिमाही में ही अल्फाबेट का राजस्व 14 फीसदी, मेटा का 22 फीसदी और माइक्रोसॉफ्ट का 18 फीसदी बढ़ा। परिचालन मार्जिन की बात करें तो अल्फाबेट का परिचालन मार्जिन 32.5 फीसदी, मेटा का 43 फीसदी और माइक्रोसॉफ्ट का 45 फीसदी रहा। इन सभी में इजाफा हुआ। इन कंपनियों द्वारा अपना पूंजीगत व्यय अनुमान 75-80 अरब डॉलर तक बढ़ाने तथा शोध एवं विकास लागत बढ़ाने के बावजूद उनका परिचालन मार्जिन बढ़ा। कॉरपोरेट बोर्डरूम इस बदलाव को लेकर पूरी तरह सजग हैं, और अधिकांश सर्वेक्षणों से यह स्पष्ट होता है कि शीर्ष प्रबंधन का मानना है कि उनकी कंपनियां एआई के उपयोग से उत्पादकता में कम से कम 20 फीसदी तक वृद्धि देख सकती हैं। अधिकतर प्रबंधकों का मानना है कि भविष्य में उन्हें कम कर्मचारियों की आवश्यकता होगी।

कर्मचारियों की संख्या में इस कमी का क्या असर होगा? अब यह स्पष्ट है कि हर कंपनी को एआई टूल्स को अपनाना होगा। उन्हें अधिक उत्पादक बनना होगा वरना वे नाकाम हो जाएंगी। वही कंपनियां विजेता साबित होंगी जिनके पास मूल्य तय करने की क्षमता होगी और जिनका कद इतना बड़ा होगा कि उन्हें अपनी लागत बचत को पूरी तरह ग्राहकों के साथ साझा नहीं करना होगा।

यदि कंपनियां इन लागत बचतों में से कुछ को बनाए रख सकें और मार्जिन विस्तार दिखा सकें, तो उनके वैल्यूएशन में सुधार होगा और उन्हें मजबूत निवेशक समर्थन प्राप्त होगा। हालांकि, ऐसी मूल्य निर्धारण क्षमता कुछ ही कंपनियों के पास होती है। अधिकांश कंपनियां इन लागत बचतों को मूल्य कटौती के माध्यम से प्रतिस्पर्धा में गंवा देंगी। यदि पूरा उद्योग अधिक उत्पादक बन रहा है, तो यह किसी तरह से नहीं हो सकता कि कंपनियां इन बचतों को अपने पास रख पाएंगी। संभावना तो यह है कि एआई का उपयोग एक मूलभूत आवश्यकता बन जाएगा यानी सिर्फ प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए भी इसे अपनाना अनिवार्य होगा।

यह संभव है कि हमें तमाम उद्योगों और उत्पादों में अपस्फीति का सामना करना पड़े। इससे ग्राहकों को लाभ होगा और मुद्रास्फीति में कमी आएगी। ऐसे में हमें उन कंपनियों पर दांव लगाना होगा जिनके पास कीमतों में लचीलापन हो ताकि कीमतों में कमी के बावजूद मात्रा ज्यादा होने से मुनाफा बढ़ सके। बाजार मात्रा आधारित वृद्धि को अत्यधिक महत्त्व देंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों का मानना होगा कि एआई-प्रेरित अपस्फीति के युग में, मूल्य निर्धारण को एक रणनीतिक साधन के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता केवल कुछ चुनिंदा कंपनियों के पास होगी विशेष रूप से उन कंपनियों के पास जिनका ग्राहकों पर मजबूत नियंत्रण है।

अच्छी निवेश रणनीति यह हो सकती है कि भारी तयशुदा खर्च या भारी भरकम एसजीऐंडए बजट वाली कंपनियों पर दांव लगाया जाए। यह भी एक तथ्य है कि यदि आप एक स्थापित कंपनी हैं और किसी एआई-आधारित स्टार्टअप से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, तो यह चुनौतीपूर्ण होगा। स्टार्टअप की लागत संरचना पारंपरिक कंपनियों से मूल रूप से अलग होती है।

उदाहरण के तौर पर, अल्फाबेट को ओपनएआई से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। ये दोनों कंपनियां लार्ज लैंग्वेज मॉडल के क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी हैं। अल्फाबेट के पास जेमिनी है और ओपनएआई के पास चैटजीपीटी। अल्फाबेट में लगभग 1,80,000 कर्मचारी हैं, जबकि ओपनएआई के पास केवल 7,000 कर्मचारी हैं। ऐसे में कौन-सी संस्था अधिक चुस्त होगी और किसकी ओवरहेड लागत कम होगी? यदि कोई स्टार्टअप शुरुआत से ही एआई टूल्स का उपयोग करके अपना व्यवसाय और स्टाफ संरचना तैयार करता है, तो वह संरचनात्मक लागत लाभ प्राप्त कर सकता है।

इसका श्रम शक्ति में शामिल हो रहे युवाओं पर भी गहरा असर होगा। अधिकांश विकसित देशों में नए कॉलेज स्नातकों के लिए बेरोजगारी दर आबादी के औसत से अधिक है। शुरुआती नौकरियों में एआई जगह बना रहा है। इससे सामाजिक तनाव बढ़ेगा। अधिकांश युवाओं को नौकरियां नहीं मिलेंगी जबकि एआई के जानकारों को मुंहमागी कीमत मिल सकती है।

एआई के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि की चर्चा के बीच, भारतीय आईटी सेवा उद्योग की दिशा भी केंद्र में आ गई है। यह अच्छी तरह स्थापित हो चुका है कि कोडिंग में एआई का उपयोग स्पष्ट रूप से प्रभावी है। यह प्रोग्रामर्स की उत्पादकता को कम से कम 25-30 फीसदी तक बढ़ा देता है। ऐसे में एंटरप्राइज ग्राहक यह अपेक्षा करेंगे कि इस 25 फीसदी उत्पादकता का लाभ उन्हें मिले। यदि ग्राहक अपने कर्मचारियों की संख्या घटा रहे हैं, तो क्या वे अब भी 2,000 लोगों वाली आईटी सेवा परियोजनाओं में रुचि लेंगे? बहरहाल, मेरा विश्वास है कि हमारे आईटी सेवा क्षेत्र के दिग्गज अनुकूलनशील हैं और वे एआई के उपयोग और उसे अपनाने के इर्दगिर्द नई सेवा श्रेणियां विकसित करने के रास्ते खोज लेंगे, फिर भी यह संभव है कि कुछ वर्षों तक हमें एक अस्थायी अंतराल का सामना करना पड़े, जहां नई सेवाएं मौजूदा व्यवसाय में आई गिरावट की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगी।

हर कंपनी को एआई टूल्स का उपयोग करना होगा और अपनी कारोबारी प्रक्रिया को बुनियादी रूप से बदलना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो वे बच नहीं सकेंगी। देश के कारोबारी जगत में इसका संकेत नजर आने लगा है। जो कंपनियां शुरू में इसे अपना रही हैं वे मजबूत लागत नियंत्रण दिखा रही हैं और उनका राजस्व अच्छा है। हर किसी को ऐसा ही करना होगा।

(लेखक अमांसा कैपिटल से जुड़े हैं)

राजनीतिक उथलपुथल में नेपाल का हाल-बेहाल

सियासी हलचल
आदिति फडणीस

इस सप्ताह के आरंभ में पूरे नेपाल को 40 घंटे से अधिक समय तक उग्र आक्रोश का सामना करना पड़ा जिसने संपत्ति को इतना नुकसान पहुंचाया जिसका आकलन कर पाना मुश्किल है। उदाहरण के लिए सिंह दरबार जिसे 1908 में काठमांडू में निजी आवास के लिए बारीक शैली में बनाया गया था और जिसे बाद में सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में तब्दील कर दिया गया था, वह अब पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। सर्वोच्च न्यायालय, नेपाल की संसद के अधिकांश हिस्से, नेपाल के 77 जिलों में से अधिकांश के मुख्य विकास अधिकारियों के कार्यालयों (सीडीओ) का भी यही हाल है।

निजी कारोबार मसलन भाट भटेनी (नेपाल का इकलौता संगठित खुदरा चेन), हिल्टन होटल, आधा दर्जन मंत्रियों के आवास तथा अन्य ढांचे भी बरबाद हो चुके हैं। 20 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है जिनमें सबसे युवा बच्चे की उम्र 13 वर्ष थी। नेपाल शोकग्रस्त है लेकिन इसके साथ ही उसमें एक किस्म की उत्सुकता भी है। विनाश और हत्याओं का यह सिलसिला जारी रह सकता था। इसके अचानक रुक जाने की वजह नेपाल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में निहित है। देश के नागरिकों की औसत आयु महज 25 वर्ष है और आबादी का 68 फीसदी हिस्सा कृषि कार्य में संलग्न है। युवा यकीनन बागी हो सकते हैं, परंतु उनको अपने पालतू पशुओं की भी देखभाल करनी है, खेतों को सींचना है, सोयाबीन और मक्के की छंटाई भी करनी होती है।

सुजीव शाक्य जो खुद को मजाक में सीईओ (चीफ इटर्नल ऑप्टिमिस्ट यानी मुख्य शाश्वत आशावादी) कहते हैं, वह नेपाल इकनॉमिक फोरम के संस्थापक हैं। यह फोरम काठमांडू में निजी क्षेत्र का आर्थिक नीति एवं शोध संस्थान है। वह कहते हैं कि चुनौतियों के बावजूद नेपाल की अर्थव्यवस्था अच्छी हालत में है। वर्ष 2004 से उसका सकल घरेलू उत्पाद छह गुना बढ़ा है और वह 2004 के 7 अरब डॉलर से बढ़कर 2024 में 44 अरब डॉलर हो चुका है। निजी क्षेत्र की ऋण वृद्धि के मामले में नेपाल दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विगत 20 साल में विदेश से रेमिटेंस के रूप में नेपाल में आने वाला धन 2 अरब डॉलर से बढ़कर 20 अरब डॉलर हो चुका है। इससे आम नेपाली परिवारों की खपत और उनके निवेश में सुधार हुआ है। सामाजिक संकेतकों में भी सुधार हुआ है तथा जीवन प्रत्याशा 1990 के 54.77 वर्ष से बढ़कर 2024 में 72 वर्ष हो चुकी है। प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन करीब 100 फीसदी है और साक्षरता दर 2000 के 59 फीसदी से बढ़कर 2024 में 76 फीसदी पहुंच गई है। 81 फीसदी नेपाली नागरिकों के पास अपना घर है और हर पांच में से चार नेपाली परिवारों का कम से कम एक सदस्य देश के बाहर रह रहा है या काम कर रहा है।

असल समस्या राजनीति में निहित है। यही एक रास्ता है जिसके जरिये तेजी से समृद्धि हासिल की जा सकती है। हाल के दिनों में जिस तरह के घोटाले सामने आए, वह भी बहुत कुछ बताता है। जेनजी आंदोलन से जुड़े नेताओं में से एक को 50,000 से अधिक लोगों की भीड़ ने जेल से रिहा करा लिया जहां वह कर्ज डिफॉल्ट के कम से कम पांच मामलों में सुनवाई की प्रतीक्षा कर रहे थे। इन मामलों में सहकारी बैंकों से कर्ज लिया गया था लेकिन उसे चुकाया नहीं गया था। वह देश के गृह मंत्री बने। एक अन्य पूर्व गृह मंत्री को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने शुल्क लेकर नेपाली नागरिकों को नकली भूटानी शरणार्थी के रूप में दस्तावेज प्रदान किए, ताकि उन्हें अमेरिका में पुनर्वास में मदद मिल सके।

वर्तमान उथल-पुथल के दौरान इस्तीफा देने वाले एक और गृह मंत्री पर मानव तस्करी में भूमिका को लेकर जांच चल रही थी। हर दिन 400 से अधिक नेपाली नागरिक विदेश में नौकरी पाने के बाद त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होते हैं। इस हवाई अड्डे पर आव्रजन अधिकारी की नियुक्ति गृह मंत्रालय के नियंत्रण में होती है और यह पद अत्यंत प्रतिष्ठित माना जाता है। यह नियुक्ति कई सहायक व्यवसायों को बनाए रखती है जैसे ट्रैवल एजेंट, पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारी, और नकली दस्तावेज तैयार करने वाले विशेषज्ञ।

जेनजी आंदोलन के उभार और उसके आगे बढ़ने की एक वजह उन कुलीन युवाओं के प्रति नाराजगी भी है जो विशेषाधिकार प्राप्त परिवारों में जन्मे हैं। लेकिन पूरा मामला इससे कहीं अधिक जटिल है। विरोध प्रदर्शन एक नाकाम दिख रही व्यवस्था के खिलाफ है और इसके निशाने पर वे लोग हैं जिन्होंने किसी तरह इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद की है।

हमें पता है कि जेनजी किसके खिलाफ हैं। मगर वे क्या चाहते हैं और वे कौन हैं? किसी भीड़ को समझना आसान नहीं है। इसमें एक स्वयंसेवी संगठन के समान 'जेनजी' है, टीवी प्रस्तोता रवि लामिछाने की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जिसकी स्थापना 2022 में हुई थी और जो 2023 में 20 से अधिक संसदीय सीट जीतकर सत्ता में आई। इसमें काठमांडू के विवादास्पद मेयर बालेन साह के समर्थक शामिल हैं और राजा ज्ञानेंद्र के स्वयंभू समर्थक दुर्गा प्रसाई जैसे लोग भी जो खुद ऋण की देनदारी चूकने पर जेल गए और फिलहाल जमानत पर रिहा हैं। काठमांडू से आ रही खबरों के मुताबिक जब अंतरिम सरकार को लेकर चर्चा छिड़ी तो जेनजी के कुछ सदस्यों ने प्रसाई के साथ एक टेबल पर बैठकर बात करने से इनकार कर दिया। इन विरोधाभासों का प्रबंधन नेपाल की प्रधानमंत्री और सेना को करना है। आगे की राह आसान नहीं है।

आपका पक्ष

नेपाल में युवा आंदोलन से सबक लेने की जरूरत

नेपाल में हालिया घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को अनसुना करना और उनकी शिकायतों का गलत ढंग से निपटारा करना बड़े जन आंदोलनों का रूप ले सकता है। आज का दौर सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का है। एक छोटी-सी घटना भी पलक झपकते पूरे देश में फैल जाती है और लोग उसके समर्थन या विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारें समय की मांग के अनुरूप अपनी नीतियों को लचीला बनाएं और जनता से नियमित संवाद बनाए रखें, विशेषकर युवाओं से। नेपाल का उदाहरण हमारे लिए चेतावनी की घंटी है। जब युवा वर्ग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी से जूझते हुए देखता है कि सत्ताधारी वर्ग उनकी तकलीफों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो वह सड़कों पर उतर आता है। श्रीलंका और बांग्लादेश के हालात भी गवाही देते हैं कि उपेक्षित जनता एक समय बाद अपने नेताओं को सत्ता से बेदखल करने से नहीं हिचकती। भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश में भले ही ऐसी स्थिति की आशंका न हो, लेकिन हमें सचेत रहना होगा। अब समय आ गया है कि हमारे नेता यह समझें कि जनता पहले जैसी सहनशील नहीं रही। सोशल मीडिया ने सबको जागरूक बना दिया है। नेपाल का संदेश साफ है, जनता को नजरअंदाज कर शासन नहीं चल सकता।

विभूति बुपक्या, खाचरौद

नेपाल में सरकार के खिलाफ आंदोलन में संसद जलाए जाने के बाद इसकी सुरक्षा में तैनात नेपाल के सशस्त्र पुलिस बल

परमाणु शक्तिः विकास की आड़ में मौत का सौदा

परमाणु ऊर्जा को 'स्वच्छ' और 'हरित' कहकर सराहा जाता है, क्योंकि यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में कार्बन उत्सर्जन कम करता है। विश्व ऊर्जा परिषद के अनुसार, यह वैश्विक बिजली का 10 प्रतिशत हिस्सा देता है और 2023 तक 2.5 गीगाटन कार्बन डाईऑक्साइड रोकने में सहायक रहा है। मगर इस चमक के पीछे परमाणु कचरे का अंधकार छिपा है। यह कचरा जिसमें यूरेनियम-238 और प्लूटोनियम-239 जैसे तत्त्व लाखों वर्षों तक रेडियोधर्मी रहते हैं धरती और भावी पीढ़ियों के लिए घातक खतरा है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) के मुताबिक हर साल 10,000 टन यह जहरीला कचरा पैदा होता है, जिसका सुरक्षित प्रबंधन लगभग असंभव है। अधिकांश देश इसे अस्थायी भंडारण में रखते हैं जैसे अमेरिका की हनफोर्ड साइट पर 56 मिलियन गैलन कचरा रखा गया है। फिनलैंड की ओनकॉलो परियोजना गहरे भूगर्भीय भंडारण की दिशा में कदम है मगर भूकंप या मानवीय भूलों से सुरक्षा की गारंटी नहीं है। फुकुशिमा (2011) और चेर्नोबिल (1986) जैसे हादसों ने इसके खतरों को उजागर किया जहां कैंसर और आनुवंशिक रोगों ने कई पीढ़ियों को प्रभावित किया। यह कचरा आतंकवादियों के लिए भी खतरा है, क्योंकि प्लूटोनियम से 'डर्टी बम' बन सकता है। समाधान के लिए परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता कम कर सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना होगा।

प्रो. आरके जैन, बड़वानी

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार सुबह राष्ट्रपति भवन में चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई। राधाकृष्णन 11 सितंबर, 2030 तक इस पद पर बने रहेंगे। वह इस प्रतिष्ठित पद पर आसीन होने वाले तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

दैनिक जागरण

सुंदर आचरण सुंदर शरीर से अच्छा है

फर्जी राजनीति

राजनीतिक दलों के लिए नियमन की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से चुनाव आयोग और विधि आयोग को नोटिस दिया जाना एक सही कदम है। इस मामले की प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्होंने राजनीति को धंधा बना लिया है। ऐसे लोग केवल पैसा उगाहने या अपना रसूख कायम करने के उद्देश्य से राजनीतिक दल गठित करते हैं और चुनाव लड़ते अथवा लड़वाते हैं। राजनीतिक दलों के नियमन की मांग करने वाली याचिका के अनुसार काले धन को सफेद करने वालों के साथ अलगाववादी तत्व भी फर्जी राजनीतिक दलों का गठन करने लगे हैं और इनमें से कुछ अपनी राजनीतिक सक्रियता के नाम पर पुलिस सुरक्षा भी हासिल कर लेते हैं। इसे महज आरोप नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हाल में आयकर विभाग की छापेमारी में कई फर्जी राजनीतिक दल पता चले। कुछ समय पहले अकेले उत्तर प्रदेश में 20 ऐसे पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों का मामला सामने आया था, जो दानदाताओं से चंदा लेकर उसका एक हिस्सा अपने पास रखकर शेष राशि दानदाताओं को वापस कर देते थे। इस प्रक्रिया में कालेधन और टैक्स चोरी के पैसे का इस्तेमाल होता था। इसे राजनीति की आड़ में किए जाने वाले घोटाले के अलावा और कुछ नहीं कह सकते।

राजनीतिक दल गठित करके गैर कानूनी काम करने का धंधा इसीलिए फल-फूल रहा है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपना संगठन बनाकर उसे राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत कराने के लिए स्वतंत्र है। देश में ऐसे न जाने कितने राजनीतिक दल हैं, जो कागजी हैं और जो एक अकेले व्यक्ति द्वारा ही संचालित होते हैं। यह ठीक है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में किसी को भी राजनीतिक दल बनाने और चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन इसके कुछ तो ठोस नियम-कानून होने चाहिए। चुनाव आयोग अपने यहां हजारों की संख्या में पंजीकृत राजनीतिक दलों के दर्जे को तब तक समाप्त नहीं कर सकता, जब तक वे छह वर्ष तक कोई चुनाव न लड़ें। कागजी दलों के लिए इस शर्त का दुरुपयोग करना बहुत आसान है। कागजी राजनीतिक दल इसलिए गठित होते हैं, क्योंकि उन्हें टैक्स में छूट के साथ कई विशेषाधिकार भी मिलते हैं। यदि राजनीति करने के नाम पर की जानी वाली मनमानी पर रोक लगानी है तो चुनाव आयोग को अधिकार संपन्न बनाना होगा। यह ठीक नहीं कि कोई मान्यता प्राप्त दल कितनी भी देशघाती हरकत करे, चुनाव आयोग के पास उसकी मान्यता खत्म करने का अधिकार नहीं। यह भी विचित्र है कि अपने देश में संगीन आरोपों में जेल में बंद लोग भी चुनाव लड़ने में समर्थ हैं, पर मामूली मामले में भी जेल गया कोई व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता।

बचे रहें युवा

हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी नशा तो नहीं कर रहे हैं? इस बात का पता लगाने के लिए शिक्षा विभाग सक्रिय हुआ है। पुलिस विभाग की सुझाई किट में पेशाब की बूंदें डाल कर तत्काल पता लगाया जा सकेगा कि किसी ने नशीली चीज का सेवन किया है अथवा नहीं। रोग जब बढ़ने लगे तो उपचार की तरफ सक्रियता बढ़ती ही है, रोकथाम भी आवश्यक हो जाती है। यह कदम उन किशोरों, युवाओं के लिए कारगर होगा जो इस दलदल में धंसते जाते हैं किंतु अभिभावक या अध्यापक पता नहीं लगा पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में चिट्टे समेत कितनी नशीली वस्तुओं ने समाज के बड़े भाग को अपने चंगुल में लिया है, इसके कई आंकड़े रहस्य नहीं हैं। इस समस्या से जुड़ा एक पक्ष यह है कि जब तक किसी के आदी होने का पता चलता है, बहुत देर हो चुकी होती है। अच्छी बात यह है कि राज्य का ध्यान पीड़ितों के पुनर्वास पर भी है। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए अधिनियम भी है। अब जो कदम उठाया जा रहा है, यह उस वर्ग के लिए है, जो इस खतरे की दहलीज पर खड़ा है। उसे बचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण कार्य है। अभी संस्थान प्रमुखों से अपेक्षा की गई है कि वे इस किट के प्रयोग का वातावरण बनाने के लिए अभिभावकों को विश्वास में लें। जाहिर है, इस प्रक्रिया के कुछ मानक होंगे, जिनका पालन किया ही जाएगा। आशा है, जिस सदिच्छा के साथ यह प्रयोग किया जा रहा है, उसका उतना ही प्रभावी परिणाम भी आए।

नशा करने वाले विद्यार्थियों का पता लगने से गिरफ्त में आए किशोरों एवं युवाओं को बचाने में मदद मिलेगी

जरूरी है हर मतदाता का सत्यापन

आशुतोष झा

यदि चुनाव आयोग ने बिहार में 65 लाख मृत, स्थानांतरित लोगों के नाम हटा दिए तो इतना उबाल क्यों? यह लोकतंत्र पर मंडराता खतरा कैसे था?

अवधेश राजपूत

इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अपने साथ आंधी-तूफान भी लाते हैं, लेकिन गर्द के बैठने के साथ सब स्पष्ट दिखाई भी देता है और स्थायी भी हो जाता है। बिहार में चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। चुनावी लोकतंत्र की स्वच्छता के लिए सबसे जरूरी मतदाता सूची होती है और उसे दुरुस्त रखने के लिए बिहार में एसआइआर की शुरुआत हुई तो विवाद खड़ा हो गया। कुछ दलों की ओर से इसे सीधे-सीधे लोकतंत्र पर खतरा बताया गया, पर आरोप-प्रत्यारोप, अदालतों में हुए विश्लेषण और राजनीतिक मंचों पर दिए गए भाषणों के बीच यह तथ्य निकलकर सामने आया कि एसआइआर के जरिये मतदाता सूची का गहन परीक्षण जरूरी है और यह कैसे किया जाए, इसका अधिकार चुनाव आयोग को है। इस विवाद से एक बड़ा लाभ यह हुआ कि बिहार ही नहीं पूरे देश के मतदाताओं को इसकी जानकारी हो गई कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना है तो उन्हें क्या करना है। वे यह भी समझ गए कि यह काम नेताओं के भरोसे नहीं हो सकता, क्योंकि बिहार में राजनीतिक दलों की ओर से जितने प्रतिवेदन आए, उनमें अधिकांश दूसरों के नाम कटवाने के लिए ही थे। इस विवाद से यह स्पष्ट है कि पूरे देश में एसआइआर हो और मतदाता सूची एवं मतदाता पहचान पत्र को आटोमेटिक व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी शुरू हो। इसके लिए नगर निगम से लेकर विदेश और गृह मंत्रालय तक को चुनाव आयोग से संबंधित डाटा शेयर करना होगा।

देश के अलग-अलग हिस्सों में एसआइआर की प्रक्रिया 20-25 वर्षों के अंतराल में होती है। अब चुनाव आयोग ने जता दिया है कि देश में एक साथ एसआइआर कराया जाएगा। इस पर राजनीतिक दलों का रुख देखना रोचक होगा। हाल में इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एसआइआर को रुकवाने के लिए जिस तरह की दलीलें दी गईं, उन्हें देखते हुए मान लेना चाहिए कि विपक्षी दलों की ओर से इसका विरोध ही किया जाएगा। हालांकि इस संवैधानिक प्रक्रिया को रोक पाना अब किसी के वश में नहीं है, पर पारदर्शिता की इस मुहिम को अभी राजनीतिक बवंडर के कई क्रम से गुजरना होगा।

यह बहुत ही अचंभित करने वाला था कि बिहार में एसआइआर की जिस प्रक्रिया पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि इसमें कई लोगों और खासतौर से गरीबों के नाम काट दिए गए हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों से कहा कि वे अपनी ओर से कोशिश करें कि जिनके नाम गलत तरीके से कटे हैं, उनके नाम जोड़े जाएं तो अधिकतर प्रतिवेदन नाम कटवाने के ही आए। सबसे हास्यास्पद स्थिति कांग्रेस की रही। पार्टी की ओर से दावा किया गया कि उसने 89 लाख प्रतिवेदन दिए हैं, लेकिन सारे नाम कटवाने वाले थे। फिर अगर चुनाव आयोग ने 65 लाख मृत, स्थानांतरित और अनुत्तरित लोगों के नाम हटा दिए तो इतना उबाल क्यों? यह लोकतंत्र पर मंडराता खतरा कैसे था? विपक्षी दलों का रुख अभी भी नहीं बदला है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस कमर कस कर रास्ता रोकने को तैयार है। एसआइआर की असली परीक्षा बंगाल में ही होगी। ध्यान रहे कि पिछले 15-20 वर्षों में पूरे देश में चुनावी हिंसा खत्म हो गई, लेकिन बंगाल अभी अपवाद है। यहां घुसपैठियों ने कई जिलों की जनसांख्यिकी को बदल दिया है। कई जगह चुनाव भारतीय वोटरों के हाथों से निकलकर घुसपैठियों के हाथों नियंत्रित हो गया है। राज्य में पुलिस और अन्य अधिकारियों का भी जिस तरह राजनीतिकरण हुआ है, उसे देखते हुए एसआइआर के लिए विशेष तैयारी करनी होगी। संभव है गृह मंत्रालय को भूमिका निभानी पड़े। अच्छा होगा सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप हो। बंगाल में एसआइआर की प्रक्रिया का पुख्ता पालन हो जाए तो शेष देश में उसकी राह आसान हो जाएगी और उस बहस पर भी अंकुश लगेगा, जिसे संकीर्ण राजनीतिक कारणों से चलाने की कोशिश हो रही है।

यह अच्छा नहीं कि हर साल प्रदेशों में होने वाले चुनावों के वक्त देश विवादों में उलझा रहे, इसलिए भी एक साथ एसआइआर की जरूरत है। यह भी जरूरी है कि मतदाता सूची के शुद्धीकरण और अपडेशन की प्रक्रिया बदली जाए। घर-घर जाकर हर एक वोटर की पड़ताल तो सही है, लेकिन आटोमेशन की भी शुरुआत होनी चाहिए और राजनीतिक दलों की ओर से अड़ंगा लगाना बंद होना चाहिए। जरूरत को देखते हुए हर व्यक्ति अपने आधार को वर्तमान पते के अनुसार अपडेट करता है। अच्छा हो कि आधार से मतदाता सूची जुड़ जाए। इससे एक से ज्यादा स्थानों पर मतदाता रजिस्टर ही नहीं होंगे। सिर्फ आधार से वोटर कार्ड को जोड़ना पर्याप्त नहीं। नागरिकता देना भले ही गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता हो, पर मतदाता सूची में नाम शामिल करने से पहले नागरिकता की पुष्टि करने का अधिकार चुनाव आयोग से छीना भी नहीं जा सकता। खासकर जब तक पूरे देश में एनआरसी न हो जाए और देश के नागरिकों का रजिस्टर न तैयार हो जाए। विपक्ष इसके भी आड़े खड़ा है। देश को अपने नागरिकों और अवैध तरीके से आए लोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।

बिहार में जिन लगभग 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उनमें से 22 लाख तो मृत थे। देश से हर साल औसतन दो लाख लोग नागरिकता छोड़कर विदेश में बस रहे हैं। फिलहाल चुनाव आयोग प्रदेश के पासपोर्ट कार्यालयों से संपर्क में रहता तो है, लेकिन डाटा शेयरिंग की आटोमेटिक व्यवस्था नहीं है। जाहिर है कि जब सही आंकड़े आएंगे तो भ्रम की स्थिति पैदा होगी और उस वक्त जो भी विपक्ष में होगा, वह उसे तूल देगा। फिलहाल देश में लगभग 98 करोड़ वोटर हैं। वर्षों से मतदाता सूची त्रुटिपूर्ण है और इसके लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेदार है और राजनीतिक दलों के साथ एक हद तक मतदाता भी। उचित यह होगा कि इस मुद्दे पर सत्तापक्ष और विपक्ष एक साथ हों और उनमें व्यापक बहस हो। यह सुनिश्चित हो कि केवल भारतीय नागरिकों के नाम ही सूची में शामिल हों और अपडेशन के लिए आटोमेटिक प्रक्रिया हो।

(लेखक दैनिक जागरण के राजनीतिक संपादक हैं)
response@jagran.com

सिगरेट स्त्री की आजादी का प्रतीक कैसे

क्षमा शर्मा

उस विचार को क्या कहा जाए, जो सिगरेट जैसी हानिकारक वस्तु के सेवन को भी प्रगतिशीलता से जोड़ता है

बुकर पुरस्कार से सम्मानित अरुंधती राय की किताब 'मदर मैरी कम्स टू मी' आई है। बताते चलें कि अरुंधती की मां का नाम भी मैरी राय था। वह कैथोलिक ईसाई स्त्रियों को तलाक का अधिकार दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थीं। कुछ अखबारों ने इस पुस्तक के बहुत से अंश छापे हैं। इन अंशों में अरुंधती ने अपनी मां की विकट आलोचना की है। जैसे ही इस किताब का मुखपृष्ठ प्रकाश में आया, डिजिटल मीडिया में बवाल मच गया। इस पुस्तक के आवरण पर एक लड़की का सिगरेट पीते चित्र छपा है। इसके समर्थक कहने लगे कि मात्र मुखपृष्ठ देखकर किसी किताब के बारे में निर्णय क्यों देना चाहिए। सिगरेट लड़कियां पिएं या न पिएं, यह उनकी मर्जी है। आप मारल पुलिसिंग करने वाले कौन होते हैं। नैतिकता के सारे प्रश्न स्त्रियों पर ही क्यों लादे जाते हैं। यह वह जमाना नहीं कि लड़कियां किसी की आलोचना से डर जाएंगी। इसके बाद से बहुत-सी लड़कियों और स्त्रियों ने सिगरेट पीते हुए अपने चित्र फेसबुक पर लगाए। यहां तक कि मुक्तिबोध और राजेंद्र यादव को भी बीच में ले आया गया कि उनकी तो किसी ने आलोचना नहीं की, जबकि मुक्तिबोध का बीड़ी पीते हुए चित्र उनकी पुस्तक के आवरण पर ही छपा था और राजेंद्र यादव का भी सिगार पीते हुए चित्र छपा था।

तमाम विरोधियों ने कहा कि सवाल लड़कियों के सिगरेट पीने न पीने का नहीं है, सवाल स्वास्थ्य से जुड़ा है। इसे प्रगतिशीलता और स्त्रीवाद से जोड़ना अच्छा नहीं है। यदि लड़के भी ऐसा करते हैं, तो वे आलोचना से परे नहीं हैं। यह भी कहा गया कि आखिर अरुंधती अपने अलगाववादी विचारों के लिए ही जानी जाती हैं। वह कश्मीर के लोगों का आवाहन कर चुकी हैं कि इस भूखे-नंगे हिंदुस्तान से अलग हो जाओ। कुछ दिनों पहले यह लेखिका अपने मोहल्ले के पान वाले के पास गई थी। देखा कि एक के बाद एक लड़कियां सिगरेट खरीद और पी रही हैं। पान वाले से पूछा तो उसने कहा अब लड़कियां बहुत ज्यादा सिगरेट खरीदती हैं। किसी भी तरह से तंबाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुत से डाक्टर बार-बार कहते रहे हैं। यह

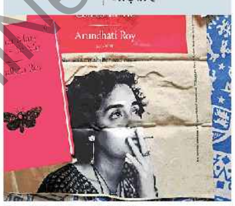

किताब के बहाने धूमपान की पैरवी। एक्स

आज लोगों में कैंसर जैसी घातक बीमारी का एक बड़ा कारण बन रहा है। लिहाजा स्वास्थ्य की चिंता सिर्फ लड़कों को ही नहीं, लड़कियों को भी करनी चाहिए, लेकिन उस विचार को क्या कहा जाए, जो खान-पान को भी प्रगतिशीलता से जोड़ता है और सवाल उठाने वालों को रूढ़िवादी, पितृसत्ता का प्रतीक आदि कहता है। कौन नहीं जानता कि किसी उत्पाद को बेचने के लिए प्रकाशकों और लेखकों द्वारा मिलकर कैसी-कैसी मार्केटिंग रणनीतियां बनाई जाती हैं। प्रकाशकों के लिए किताब एक उत्पाद ही है, जिसे उन्हें खूब बेचना है और भारी मुनाफा कमाना है। इसीलिए किसी खास बात को प्रगतिशीलता और किसी बात को रूढ़िवादिता से जोड़ दिया जाता है। ऐसा करते वक्त अपने ही उस विचार का कतई ध्यान नहीं रखा जाता, जिसमें चुनाव की बात की जाती है। चुनाव में भी आखिर उस चीज को कैसे अच्छा माना जा सकता है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। मार्केटिंग से जुड़ी एक वरिष्ठ अधिकारी ने कभी कहा था कि हम चाहें तो जहर को भी अमृत बनाकर बेच दें। बस, बेचना आना चाहिए।

बहुत पहले सिगरेट बनाने वाली एक कंपनी के मालिक जार्ज वाशिंगटन हिल को महसूस हुआ कि उसकी बिक्री उतनी नहीं हो रही, जितनी होनी चाहिए। उन दिनों अमेरिका में स्त्री अधिकारों की बातें खूब हो रही थीं। वाशिंगटन हिल को जैसे समस्या का हल मिल गया। उन दिनों अमेरिका में भी स्त्रियां सिगरेट नहीं पीती थीं। वे एक मशहूर व्यक्ति एडवर्ड बर्नेज के पास पहुंचे। उन्होंने सिगरेट को स्त्री समानता और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ एक ताकतवर औजार की तरह पेश किया। अमेरिका की बहुत-सी अमीर स्त्रियों को पैसे देकर इस बात के लिए मनाया कि वे सड़क पर सिगरेट पीती हुई निकलें। आखिरकार 1929 में न्यूयार्क में रविवार के दिन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्त्रियां सिगरेट पी रही थीं। इस रैली को नाम दिया गया- टार्चेज आफ फ्रीडम। जैसा कि होना था, रैली को मीडिया में खूब जगह मिली और सिगरेट स्त्रियों के बीच छा गई। स्त्री स्वातंत्र्य के नाम पर यह अन्य देशों में भी जा पहुंची। वाशिंगटन हिल के पौ बारह हो गए।

कभी अपने यहां भी सिगरेट के ऐसे विज्ञापन टीवी और अखबारों में आते थे, जिनमें सिगरेट पीने वाले को बेहद शक्तिशाली और असली मर्द बताया जाता था। बाद में सरकार ने ऐसे विज्ञापनों पर रोक लगा दी। हाल में जब तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया, तो इसका मकसद भी तंबाकू उत्पादों से दूर रखने की मंशा से किया गया होगा। किसी पुरानी फिल्म में जब कोई सिगरेट पीता दिखाई देता है, तो नीचे वैधानिक चेतावनी आती है, जिसमें लिखा रहता है कि धूमपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन उसी भारत में एक किताब इसलिए चर्चा पा रही है कि उस पर सिगरेट पीती लड़की का चित्र छपा है। नीचे कोई वैधानिक चेतावनी भी नहीं लिखी। हो सकता है कि किताब के विवाद से लेखिका और उनके प्रकाशक को लाभ हो। इसे ही जहर बेचना कहते हैं।

(लेखिका साहित्यकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

गुरु, नेता और प्रशासक

गुरुजन ज्ञान से, प्रशासक न्याय से और नेता समुचित दिशा-निर्देशन से समाज को सुमति और सुगति प्रदान करते हैं। यदि ये तीनों अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करें, तो समाज में आध्यात्मिक समुत्थान, समरसता, विचारों में पारदर्शिता और राष्ट्रीय प्रगति में कर्तव्यबोध का सुंदर समन्वय दृष्टिगोचर होता है।

गुरुजन का कार्य व्यक्ति के अंतर्मन को प्रकाशित करना है। प्राचीन काल में आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को केवल शिक्षित ही नहीं किया, अपितु उन्हें सक्षम शासक भी बनाया। महर्षि वशिष्ठ और गुरुदेव विश्वामित्र ने श्रीराम-लक्ष्मण के व्यक्तित्व और सद्गुणों को लोकोपयोगी और परमार्थी बनाया। गुरुजन शिष्य के जीवन में केवल विद्या ही नहीं, बल्कि उन्हें जीवन जीने की कला में नैपुण्य और परमार्थिक दृष्टि प्रदान करते हैं। प्रशासक समाज के वे महत्वपूर्ण अंग हैं, जो न्याय व्यवस्था के अनुरूप जनसामान्य के अधिकारों की रक्षा करते हैं। यदि प्रशासक शिथिल होगा, तो निश्चित ही समाज निरंकुश होकर अराजकता में लिप्त हो जाएगा। नेतागण समाज और राष्ट्र को दिशा देने वाले होते हैं। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के बल पर जनता को स्वतंत्रता संग्राम में संगठित किया। एक सच्चा नेता समर्पित जनसेवक होता है, जो जनता के दुख-सुख में साथ खड़ा रहता है।

गुरु व्यक्ति को आत्मशक्ति प्रदान करते हैं, प्रशासक निष्पक्ष और पारदर्शी अनुशासन द्वारा समाज में सुरक्षित वातावरण निर्मित करते हैं और नेतागण सामूहिक कल्याण की दृष्टि से जनसामान्य को कुशल नेतृत्व प्रदानकर उन्हें देश के श्रेष्ठ नागरिक होने का गौरव प्रदान करते हैं। जब इन तीनों का संतुलित समन्वय होता है, तभी समाज में नैतिक जागरण, सामाजिक एकता और राष्ट्रीय समुन्नति सुनिश्चित और सुदृढ़ होती है।

आचार्य नारायण दास

सिंथेटिक इंटेलिजेंस की नई दुनिया

रंजना मिश्रा

तकनीकी क्रांति के इस दौर में सिंथेटिक इंटेलिजेंस का आगमन समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है

आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआइ तकनीक हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है, लेकिन तकनीक की दुनिया में सिंथेटिक इंटेलिजेंस (एसआइ) अपनी जगह बना रही है। जहां एआइ तकनीक मानव-जैसी बुद्धिमत्ता की नकल करती है, वहीं एसआइ का लक्ष्य एक ऐसी बुद्धिमत्ता का निर्माण करना है जो पूरी तरह से नई और स्वतंत्र हो। यह केवल डाटा पर आधारित नहीं है, बल्कि यह खुद से सोच सकती है, भावनाएं महसूस कर सकती है और रचनात्मकता दिखा सकती है। यदि एआइ को एक कुशल कारीगर माना जाए जो हमारे निर्देशों का पालन करता है, तो एसआइ एक कलाकार है जो खुद से कुछ नया रच सकता है।

इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन क्षेत्रों में देखा जा सकता है जहां मानवीय संवेदनशीलता और भावनात्मक समझ की आवश्यकता होती है। चिकित्सा के क्षेत्र में एसआइ तकनीक केवल बीमारी का निदान नहीं करेगी, बल्कि वह मरीज की भावनाओं को भी समझेगी और उसके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सबसे उपयुक्त उपचार सुझाएगी। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रत्येक छात्र के लिए एक व्यक्तिगत शिक्षक बन सकती है। यह छात्र के सीखने की गति, उसकी रुचियों और कमजोरियों को पहचानकर उसे प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएगी। यह तकनीक सिर्फ एक पाठ्यपुस्तक नहीं होगी, बल्कि हर कदम पर छात्र का मार्गदर्शन करेगी। तकनीकी क्रांति के इस दौर में एसआइ का आगमन समाज के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। यह हमें उन समस्याओं का हल खोजने में मदद कर सकती है जो आज तक अनसुलझी हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, बीमारियों का इलाज और अंतरिक्ष में जीवन की खोज। यह हमारे जीवन को आसान बना सकती है, जिससे हम उबाऊ और दोहराव वाले कामों से मुक्त हो सकें और अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सकें।

हालांकि इस तकनीक के साथ कुछ गंभीर नैतिक और दार्शनिक चुनौतियां भी जुड़ी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हम एक ऐसी मशीन बनाते हैं जिसमें अपनी चेतना हो, तो क्या उसके अधिकार भी होने चाहिए? क्या हम उसे सिर्फ एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? यदि एक एसआइ को अपनी मर्जी से निर्णय लेने की आजादी दी जाती है, तो क्या वह मशीन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाएगी? क्या वह हमारे मूल्यों और नैतिकता के अनुरूप काम करेगी? इन सवालों के जवाब आज हमारे पास नहीं हैं, लेकिन जैसे-जैसे हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, हमें इन पर गंभीरता से विचार करना होगा। हमें एक ऐसा नैतिक और कानूनी ढांचा तैयार करने की जरूरत है, जो इस तकनीक के सुरक्षित और मानवतावादी उपयोग को सुनिश्चित करे। **(लेखिका तकनीकी मामलों की जानकार हैं)**

मेलबाक्स

नेपाल की घटना से सबक लेना जरूरी

'नेपाल के घटनाक्रम में निहित संदेश' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में सृजनपाल सिंह ने नेपाल के हालात पर गहन चिंतन किया है। नेपाल की जनसंख्या लगभग तीन करोड़ है, जिसमें 42 प्रतिशत युवा हैं। नेपाल सरकार की जनसंख्या नीति के अनुसार, युवाओं की आयु सीमा 16 से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है। किसी भी देश की असली मानव संपदा उसकी युवा आबादी होती है। नेपाल में हुए युवा संघर्ष की एक विशेषता यह है कि यह मौजूदा नीति-नियंताओं के खिलाफ स्पष्ट रूप से उभरा है। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सरकार द्वारा युवाओं के हितों की लगातार अनदेखी के परिणामस्वरूप युवाओं का आक्रोश एक जनक्रांति में बदल गया। राजनीतिक दलों को केवल वोट हासिल करने के लिए जनता को प्रलोभित करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें अपने घोषणापत्रों में किए गए वादों को भी निभाना चाहिए। राजनीति का शुद्धीकरण आवश्यक है। हालांकि युवाओं द्वारा संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर अपनी बात मनवाना लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। नेपाल में आज जिस प्रकार का आक्रोश व्याप्त है, उसका मुख्य कारण सत्ता पक्ष की स्वार्थपरक नीतियां हैं, जिन्होंने बदलाव की एक नई क्रांति को जन्म दिया है। हालांकि यह भी सच है कि बदला लेकर बदलाव नहीं लाया जा सकता। नेपाल का जनआंदोलन सभी देशों और वहां की राजनीति के लिए एक सबक है कि जनता के हितों की अनदेखी करना उचित नहीं है। यह दर्शाता है कि युवाओं की आवाज को सुनना और उनके हितों का सम्मान करना आवश्यक है, ताकि समाज में स्थायी शांति और विकास संभव हो सके।

पवन कुमार मुरली, गुरुग्राम

फिजियोथेरेपिस्ट की भूमिका

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के हालिया निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम के आगे डाक्टर की उपाधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इसका मुख्य कारण यह बताया गया है कि फिजियोथेरेपिस्टों को मेडिकल डाक्टर के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदाता होते हैं, जो शारीरिक गतिशीलता और कार्य क्षमता को सुधारने में मदद करते हैं। वे मांसपेशियों, हड्डियों, जोड़ों, हृदय और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याओं का आकलन करते हैं और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बनाते हैं। वे व्यायाम चिकित्सा से लोगों को स्वस्थ बनाए रखते हैं। क्या फिजियोथेरेपिस्टों की पहचान को छीनना उचित है, जबकि वे स्वास्थ्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं? डाक्टर का अर्थ केवल रोग या दर्द से छुटकारा दिलाना नहीं है, बल्कि एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखने में मदद करना भी है। यदि एक फिजियोथेरेपिस्ट यह कार्य पूरी निष्ठा से कर रहा है, तो उसकी उपाधि छीनने का निर्णय उचित नहीं है।

सुनील वर्मा, बादली, दिल्ली

युवाओं को राजनीति में आना होगा

आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां की सबसे बड़ी शक्ति है-युवा वर्ग। देश की लगभग आधी आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यही कारण है कि भारत को 'यंग नेशन'' कहा जाता है। यदि यह युवा वर्ग राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए, तो देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती हैं। युवा वर्ग तकनीकी रूप से सक्षम है, समस्याओं को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखता है और समाज में बदलाव लाने का साहस रखता है। आज की राजनीति को स्वच्छ छवि, पारदर्शिता और ईमानदारी की आवश्यकता है। यदि योग्य और शिक्षित युवा आगे आएं, तो न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, बल्कि समाज में समानता, रोजगार, शिक्षा और विकास जैसे मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक काम हो सकेगा। यह भी सच है कि राजनीति आसान रास्ता नहीं है। यहां चुनौतियां हैं, संघर्ष है और त्याग की भावना भी चाहिए, लेकिन यदि युवा पीछे हटते रहेंगे, तो वही पुराना ढर्रा चलता रहेगा। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाने और देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए युवाओं का राजनीति में आना अनिवार्य है।

देवांश पांडेय, पयागपुर, बहराइच

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

13 hindi nd-06_page 02.qxd 9/12/2025 7:03 PM Page 1

क्रास वोटिंग
विवाद का विषय

इन दिनों, राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे सहज और दोषरहित कहा जा सके। हाल ही में हुआ उपराष्ट्रपति चुनाव भी इसका अपवाद नहीं है। एनडीए उम्मीदवार ने भले ही अच्छे अंतर से जीत हासिल की हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में क्रॉस-वोटिंग और खरीद-फरोख्त के आरोप अभी भी चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति का पद काफी हद तक औपचारिक होता है। गुप्त मतदान से तय होता है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। हालाँकि यह एक औपचारिकता है, लेकिन यह शक्ति और एकता के प्रदर्शन के साथ-साथ अन्य जगहों पर होने वाले आगामी चुनावों का पूर्वाभास भी हो सकता है।

भारत के अगले उपराष्ट्रपति के रूप में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के चुनाव ने एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है, जिसमें विपक्षी सांसदों द्वारा क्रॉस-वोटिंग के आरोप चुनाव के बाद की चर्चाओं में छाए हुए हैं। जहाँ भाजपा इस जीत का जश्न ₹एक विनम्र और कुशल देशभक्त₹ के लिए जनादेश के रूप में मना रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी आंतरिक एकता और विश्वसनीयता के सवालों से जूझ रही है। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले - एनडीए के कुल 438 सांसदों (वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों के समर्थन सहित) से 14 ज्यादा। इसके विपरीत, विपक्षी उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को केवल 300 वोट ही मिले, जबकि विपक्षी दल ने 315 सांसदों के समर्थन का दावा किया था।

इस विसंगति ने तुरंत क्रॉस-वोटिंग की आशंकाओं को जन्म दिया, जो 15 मतपत्रों के खारिज होने से और बढ़ गईं। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने इस घटनाक्रम को ₹विश्वास का गंभीर उल्लंघन₹ बताया। चूँकि उपराष्ट्रपति चुनाव गुप्त मतदान

के माध्यम से होता है और पार्टी व्हिप लागू नहीं होता, इसलिए तकनीकी रूप से सांसद अपनी अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने के लिए स्वतंत्र हैं।

फिर भी, व्यवहार में, सांसद शायद ही कभी पार्टी लाइन का उल्लंघन करते हैं - जिससे कथित क्रॉस-वोटिंग बिहार और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले विपक्ष के लिए विशेष रूप से नुकसानदेह साबित हो रही है। नुकसान की भरपाई के लिए, विभिन्न भारतीय ब्लॉक दलों के नेताओं ने किसी भी विश्वासघात से इनकार करने की कोशिश की। राजद के तेजस्वी यादव ने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी के सभी नौ सांसदों ने गठबंधन उम्मीदवार का समर्थन किया था, जबकि तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोट खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया गया, जबकि उन्होंने कहा कि सभी 41 तृणमूल सांसदों ने विपक्षी उम्मीदवार का समर्थन किया।

इस रहस्य को और बढ़ाते हुए, 15 में से सात अवैध वोटों में भी यही पैटर्न देखा गयाः एनडीए उम्मीदवार के लिए चिह्नित मतपत्र, लेकिन गलत तरीके से डाले गए। दो पर सही का निशान था, और एक पर कोई आकृति लिखी हुई थी - जिससे जानबूझकर की गई तोड़फोड़ का संदेह पैदा होता है।

विपक्ष के लिए, इस घटना ने एकजुट मोर्चे के रूप में पेश की जा रही छवि में दरार को उजागर कर दिया है। भाजपा के लिए, यह मनोबल बढ़ाने वाला है जो एक विखंडित विपक्ष के उसके उस कथन को पुष्ट करता है जो एकजुट कार्रवाई करने में असमर्थ है। राज्य चुनावों के मँडराते हुए, उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस-वोटिंग को लेकर विवाद संसद की दीवारों से परे भी गूँजने की संभावना है। लेकिन अंततः, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक नुकसान है, जहाँ हर चुनाव संदिग्ध हो जाता है, और सांसदों का आचरण - साथ ही आरोप-प्रत्यारोप - उड़ते हैं, जिससे धन-बल और कदाचार की भूमिका को हवा मिलती है।

छात्रों का शिक्षा हेतु विदेश पलायन

बढ़ती हुई धन-प्रेषण राशि प्रतिभा पलायन की लागत को छिपा नहीं सकती, क्योंकि भारतीय छात्र जितना भेजते हैं, उससे कहीं ज्यादा विदेश में खर्च करते हैं। वीजा प्रतिबंधों, उच्च जीवन-यापन लागत और विदेशों में कम वेतन वाली नौकरियों के साथ, भारत को अपनी प्रतिभा को बनाए रखने के लिए चुनौतियों और अवसरों, दोनों का सामना करना पड़ रहा है।

दिनेश एन जोशी
लेखक, टिप्पणीकार हैं।

भाशकों से अपने देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में सीमित सीटों के कारण भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने को मजबूर हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक प्रतिभा पलायन हो रहा है। अपने देश में रहकर योगदान देने के बजाय, बड़ी संख्या में विशेषाधिकार प्राप्त छात्र कॉलेज के लिए विदेश जाना पसंद कर रहे हैं। हाल के वर्षों में, शिक्षाविदों का एक बड़ा वर्ग यह तर्क दे रहा है कि यह वास्तव में एक अच्छी बात है। वे कहते हैं, 'विदेश से आने वाला धन तेजी से बढ़ रहा है।'

वे आंशिक रूप से सही हैं, लेकिन वे व्यापक तस्वीर को नहीं समझ पा रहे हैं। हालाँकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा धन-प्रेषण प्राप्त करने वाला देश है और यह वास्तव में सच है कि धन-प्रेषण 2010-11 में 55 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 118.7 बिलियन डॉलर हो गया है, लेकिन आंकड़े केवल आंशिक रूप से ही कहानी बयां करते हैं। सबसे पहले, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में धन-प्रेषण 2000 से लगभग 3 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। दूसरे, भारतीय छात्र अब शिक्षा के लिए विदेश में जो खर्च कर रहे हैं, वह तेजी से बढ़ा है। कुछ अनुमानों के अनुसार, 2025 तक भारतीय विदेश जाने वाले छात्रों का कुल खर्च 70 अरब डॉलर तक पहुँच सकता है - यह आँकड़ा वापस भेजे जा रहे धन की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है।

तीसरा, और सबसे महत्वपूर्ण, यह तर्क एक महत्वपूर्ण परिकल्पना पर विचार करने में विफल रहता हैः क्या होता अगर ये छात्र यहीं रहना चुनते? मेरा तर्क दोतरफा है। पहला, अगर छात्र यहीं रुक जाते, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ज्यादा फायदा होता - दूसरे शब्दों में, धन प्रेषण से होने वाले आर्थिक और बौद्धिक पूँजी ह्रास की भरपाई नहीं होती, और दूसरा, कई बार विदेश में रहने की बढ़ती लागत और दुनिया भर में हाल के प्रवासी-विरोधी रुझानों को देखते हुए, छात्रों के लिए भारत में ही रहना कहीं बेहतर भी होगा।

पहले मैं दूसरे दावे पर बात करूंगा। विदेश मंत्रालय के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, 2025 में 18 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे हैं - जो कि दो साल पहले के 13 लाख छात्रों की तुलना में काफी ज्यादा है। हालाँकि, यह आंकड़ा एक महत्वपूर्ण विवरण छिपाता है।

भारतीय छात्रों (जो शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले सभी भारतीय छात्रों का एक तिहाई हिस्सा हैं) के लिए शीर्ष तीन गंतव्य देशों - कनाडा, अमेरिका और यूके - में आव्रजन उपायों को कड़ा करने की पृष्ठभूमि में भारी गिरावट देखी गई है, जिसमें छात्र प्रवेश पर सीमा और आश्रित वीजा पर प्रतिबंध शामिल हैं। इस पर विचार करेंः 2023 से 2024 तक, कनाडा में 32 प्रतिशत की गिरावट देखी गई, परमिट 2.78 लाख से घटकर 1.89 लाख हो गए, संयुक्त राज्य अमेरिका में 34 प्रतिशत की कमी देखी गई, एफ1 वीजा 1.31 लाख से घटकर 86,110 हो गए, और यूके में 26 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई, इसी अवधि के दौरान भारतीयों को जारी किए गए प्रायोजित छात्र वीजा 1.20 लाख से घटकर 88,732 हो गए।

हालांकि कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह एक बुरा संकेत है लेकिन क्या आप्रवासी विरोधी बयानबाजी और वीजा पर अंकुश वास्तव में छात्रों को विदेश जाने से रोकेंगे, या वे बस अपनी यात्रा का गंतव्य बदल देंगे? मुझे लगता है कि यह निश्चित रूप से हो सकता है। कई भारतीय जो विदेश जाते हैं, उन्हें वास्तव में अपनी कॉलेज शिक्षा पर खर्च किए गए हजारों डॉलर का अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है। पहला, कई लोग अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद बेरोजगार हैं या कम रोजगार वाले हैं। दूसरा, जिन्हें नौकरी मिलती है उन्हें समान कौशल वाले अमेरिकियों और यूरोपीय लोगों की तुलना में कम वेतन मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर, 2004 के एच-1बी वीजा सुधार अधिनियम ने वेतन स्लैब का पुनर्गठन किया और दो वेतन स्तर डाले, एक क्षेत्र में किसी व्यवसाय के लिए सर्वेक्षण किए गए कुल वेतन के 34वें और 50वें प्रतिशतक पर, उच्चतम (67वें प्रतिशतक) से नीचे।

तीसरा, उनके आकर्षक वेतन पैकेज में ई-एसओपी और अन्य वेरिएबल्स शामिल होते हैं जो वास्तव में उन्हें मिलने वाली राशि का हिस्सा नहीं होते, और विदेश में रहने का खर्च भारत में रहने के खर्च से काफी ज्यादा है। किराया, किराने का सामान और यात्रा, ये सभी उनके खर्च का एक बड़ा हिस्सा हैं, और जो बचता है वह उनके परिवारों को वापस भेज दिया जाता है। हालांकि आइवी लीग संस्थानों में दाखिला लेने वाले भारतीय छात्र शायद भारत में नहीं रुकना चाहेंगे, लेकिन कई अन्य लोगों को यहीं रोकना आसान काम होगा। कम से कम प्रयासों से, भारत प्रतिभाओं को बनाए रखने में सक्षम होगा जो न केवल आने वाले वर्षों के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों में दिखाई देंगी, बल्कि इस प्रक्रिया में अनुसंधान एवं विकास को भी आगे बढ़ाएंगी।

सहयोग का एक विशेष रूप से आशाजनक क्षेत्र शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में भारत और यूएई के बीच बढ़ती साझेदारी है। यूएई भारतीय पेशेवरों के लिए एक शीर्ष गंतव्य बन गया है, जहाँ स्वास्थ्य सेवा, इंजीनियरिंग और आईटी सहित विभिन्न क्षेत्रों में कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों का विस्तार हो रहा है। शिक्षा के लिहाज से, दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए सहयोगी कार्यक्रमों, आदान-प्रदान पहलों और छात्रवृत्तियों की सक्रिय रूप से खोज कर रहे हैं। भारतीय विश्वविद्यालय और संस्थान संयुक्त अरब अमीरात में अपने परिसर स्थापित कर रहे हैं, जिससे संबंध और मजबूत हो रहे हैं। भारतीय छात्रों के लिए, यह विश्वस्तरीय शिक्षा के लिए एक आकर्षक और नजदीकी विकल्प प्रदान करता है, साथ ही संयुक्त अरब अमीरात की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी प्रदान करता है।

भारत में प्रतिभाओं को बनाए रखने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला, अधिक गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करना और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि विदेश से स्नातक करने के बाद भारतीय अपने देश लौट आएँ। दूसरे उद्देश्य के संदर्भ में, भारत पहले से ही प्रतिभा पलायन को रोकने की प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालयों से पीएचडी प्राप्त भारतीय छात्रों के नेतृत्व में सबसे अत्याधुनिक, डीप टेक और अग्रणी टेक स्टार्ट-अप अब भारत में जड़ें जमा रहे हैं। हमारे स्टार्ट-अप एक दशक पहले केवल 400 से बढ़कर आज 1.3 लाख हो गए हैं, और इनमें से लगभग 50 प्रतिशत टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं।

यहीं पर राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका विशेष मान्यता की पात्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और देवेंद्र फडणवीस तथा धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं के प्रयासों ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षा और रोजगार भारत की विकास गाथा के मूल में बने रहें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस राज्य स्तर पर शैक्षिक सुधारों को आगे बढ़ाने, कौशल विकास और उद्योग-अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जबकि प्रधान ने शिक्षा मंत्री के रूप में उच्च शिक्षा को मजबूत करने और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सशक्त बनाने वाली पहलों को आगे बढ़ाया है।

इसका एक हालिया उदाहरण मुंबई को एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाने के लिए उठाए गए कदम हैं, जिसके तहत महाराष्ट्र में परिसर स्थापित करने के लिए पांच विश्व-प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को आशय पत्र सौंपे गए हैं। प्रधानमंत्री द्वारा नवाचार और उद्यमिता पर जोर दिए जाने के साथ, उनके संयुक्त नेतृत्व ने भारत के प्रतिभा पलायन को प्रतिभा लाभ में बदलने की नींव रखी है।

भारत एक तकनीकी क्रांति के मुहाने पर खड़ा है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), बिग डेटा, ऊर्जा परिवर्तन, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी), क्वांटम कंप्यूटिंग, जीनोमिक्स, 3डी प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, ड्रोन और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में अपार अवसर प्रस्तुत करता है। इन सभी क्षेत्रों को सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, भारत एआई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों के माध्यम से गति दी है।

हालांकि, कुछ समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। सबसे बड़ी समस्या घरेलू फंडिंग की है, जिसे तेजी से बढ़ाने की जरूरत है। जरा सोचिए - भारतीय स्टार्ट-अप्स ने 2024 में 12 अरब डॉलर से ज्यादा जुटाए, लेकिन इसका लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्रोतों से आया। एक और समस्या रॉयल्टी का भुगतान है। भारत में हर साल लगभग 24,000 पीएचडी स्नातक तैयार होते हैं, लेकिन देश ने 2024 में केवल 1.5 अरब डॉलर कमाते हुए 14.3 अरब डॉलर की आईपीआर रॉयल्टी का भुगतान किया, जो एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है जिसे और अधिक नवाचार से भरा जा सकता है।

पहली चुनौती ज्यादा कठिन लगती है– गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों का निर्माण। हालाँकि आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान कुशल पेशेवर तैयार कर रहे हैं और आइवी लीग कॉलेजों के बाद दूसरे स्थान पर हैं, फिर भी भारत में ऐसे विश्वविद्यालयों की कमी है।

एक और चुनौती पाठ्यक्रम में बदलाव की है, जो अनुसंधान और उद्योग की जरूरतों को जोड़ने के लिए पहले से ही चल रहा है। इसमें डेटा साइंस, बायोटेक, स्वच्छ ऊर्जा, एआई और एमएल आदि क्षेत्रों में कौशल की कमी को दूर करना शामिल होगा। इसके लिए उद्योगों को आगे आना होगा और सरकार का सहयोग करना होगा।

भारत में स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ विकल्प

आजीवन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहार एक सरल, संतुलित, वनस्पति-समृद्ध आहार है। सब्ज़ियाँ, फल, साबुत अनाज, दालें, फलियाँ और मेवे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक बीमारियों से बचाते हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं।

राजीना शाहीन
लेखिका, एक फिजीशियन हैं।

छोटे फिजिशियन एसोसिएशन फॉर न्यूट्रिशन के सदस्य के रूप में, मैं जो सबसे आम सवाल सुनता हूँ, वह सरल लेकिन महत्वपूर्ण हैः अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा आहार क्या है? हर साल, नए आहार चर्चा में आते हैं - कीटो, कम कार्ब, उच्च प्रोटीन, आंतरायिक उपवास - लेकिन इनमें से ज्यादातर को लंबे समय तक बनाए रखना मुश्किल होता है। जब विशेषज्ञ आहारों को ध्यान से देखते हैं, सुरक्षा, पोषण, आहार की आसानी और समग्र स्वास्थ्य परिणामों को ध्यान में रखते हुए, तो एक दृष्टिकोण सामने आता हैः पौधों से भरपूर, संतुलित आहार खाना।

पौधे-आधारित खाद्य पदार्थ स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अधिक सब्ज़ियाँ, फल, अनाज, दालें और मेवे खाने से हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और फाइबर मिलते हैं जो उसे मजबूत बने रहने के लिए आवश्यक हैं। अध्ययनों से पता चलता है कि पौधों से भरपूर आहार हृदय रोग, मधुमेह और यहाँ तक कि कुछ कैंसर के जोखिम को कम करता है। यह वजन को भी नियंत्रित रखता है और दवाओं की आवश्यकता को कम करता है।

सब्ज़ियों, फलों, साबुत अनाज, दालों, फलियों और मेवों पर केंद्रित आहार हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और हमें बीमारियों से बचाता है।

प्रमाण लगातार दशार्ते हैं कि पादप-आधारित आहार हृदय रोग, टाइप 2 मधुमेह, मोटापा, कुछ प्रकार के कैंसर, उच्च रक्तचाप और यहाँ तक कि अवसाद जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को आधा कर सकते हैं। जो लोग रोजाना पादप-आधारित खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका वजन सामान्य रहने, रक्त शर्करा के बेहतर नियंत्रण और आगे चलकर कम दवाओं की आवश्यकता होने की संभावना अधिक होती है। दूसरी ओर, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों, तले हुए खाद्य पदार्थों, मीठे पेय

पदार्थों और अत्यधिक मांसाहारी भोजन का अत्यधिक सेवन व्यक्ति को दीर्घकालिक बीमारियों का शिकार बना सकता है।

इससे दिल का दौरा, स्ट्रोक, मधुमेह संबंधी जटिलताएँ, कैंसर, गुर्दे की बीमारी और कई वर्षों बाद जीवन प्रत्याशा कम हो सकती है। भारत में, अच्छी खबर यह है कि पादप-आधारित भोजन व्यवहार्य और कम खचीर्ला है। हमारी पारंपरिक थाली में पहले से ही अधिकांश ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो दीर्घकालिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करते हैं। आज मुख्य मुद्दा यह है कि बहुत से लोग घर के खाने की बजाय प्रसंस्कृत, तले हुए भोजन और मिठाइयों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बदलाव के प्रभाव बहुत बड़े हैं। रोजाना एक या दो साल तक फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड और मीठे पेय पदार्थों का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, रक्त शर्करा बढ़ सकती है और लीवर व किडनी पर दबाव पड़ सकता है।

दशकों से, यह मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग और कुछ कैंसर के जोखिम को बढ़ाता रहा है। दूसरी ओर, सरल, सब्ज़ियों पर आधारित आहार पर लौटने से इन बीमारियों को रोका जा सकता है और यहाँ तक कि पुरानी बीमारियों के शुरूआती चरणों को भी उलट दिया जा सकता है।

ग्रामीण या संसाधन-विहीन वातावरण में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, पादप-आधारित आहार की वकालत करना व्यवहार्य और प्रभावी है।

कुछ सरल कदम हैं, जैसे परिवारों को मौसमी साग-सब्ज़ियों के साथ छोटे किचन गार्डन उगाने के लिए प्रोत्साहित करना, हर भोजन में स्थानीय रूप से उपलब्ध दालों और फलियों को शामिल करने पर जोर देना, पैकेज्ड खाद्य पदार्थों के बजाय नाश्ते के रूप में फल खाने का सुझाव देना और रोगियों को पारंपरिक तेलों का संयम से उपयोग करने की सलाह देना। छोटे-छोटे बदलाव भी, अगर समय के साथ दोहराए जाएँ, तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में गहरा अंतर ला सकते हैं।

इन बुनियादी बातों - दाल, सब्ज़ियाँ, साबुत अनाज, फल, मेवे और पारंपरिक तेलों - पर लौटकर हम पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं को रोक सकते हैं, अपने समुदायों को ऊजार्वान बना सकते हैं और भारतीय थाली को स्वास्थ्य, दीघार्यु और कल्याण के लिए एक शक्ति में बदल सकते हैं। वनस्पति-आधारित भोजन सरल, टिकाऊ और बीमारियों से बचाव में सिद्ध है। डॉक्टरों और नागरिकों, दोनों के लिए, यह आजीवन स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा विकल्प बना हुआ है।

अंततः, आजीवन स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहार एक सरल, संतुलित, वनस्पति-समृद्ध आहार है। सब्ज़ियाँ, फल, साबुत अनाज, दालें, फलियाँ और मेवे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक बीमारियों से बचाते हैं और समग्र स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। भारत में, यह किफायती और व्यावहारिक दोनों है, क्योंकि हमारी पारंपरिक थाली में पहले से ही ये खाद्य पदार्थ होते हैं।

प्रसंस्कृत, तली हुई और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को कम करके और प्राकृतिक, घर में पके भोजन की ओर लौटकर, हम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं, दीघार्यु बढ़ा सकते हैं और वनस्पति-आधारित भोजन को स्थायी स्वास्थ्य का आधार बना सकते हैं।

आप की बात

दिवास्वप्न देख रहे सनातन विरोधी

बांग्लादेश और नेपाल की घटना के बाद भारत में बैठे सनातन और राष्ट्रविरोधी तत्व जो कि स्वाभाविक है कि मोदी विरोधी होंगे ही दिवास्वप्न देख रहे हैं। जिनमें तेजस्वी यादव, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, संजय रावत सहित कांग्रेस के तमाम नेता सम्मिलित हैं। ये लोग अपने इस कुत्सित स्वप्न को अपने तक ही संजोकर नहीं रखे हुए बल्कि प्रेस के सामने भी उजागर कर रहे हैं। इन सत्ता लोलुपों को यह नहीं पता कि बांग्लादेश और नेपाल में जो उपद्रव हुए वो वहां के अल्पसंख्यकों के विरोध में और बहुसंख्यकों के पक्ष में हुए हैं। यदि भारत में ऐसा हुआ तो विपक्ष के नेता यह समझ लें कि सबसे पहले जो गाज गिरेगी वो इनके वोटबैंक पर और इन पर पड़ेगी । नेपाल में जो आन्दोलन खड़ा हुआ है वो नेपाल को पुनः हिन्दू राष्ट्र बनाने के लिए हुआ है। भारत में यदि ऐसा हुआ तो वह मोदी सरकार को और अधिक मजबूत बनाएगा।साथ ही सनातन विरोधियों और राष्ट्रविरोधियों का जो हाल नेपाल में हुआ वह सब भारत में आश लगाए बैठे मोदी विरोधियों ने नंगी आंखों से देखा है। अब प्रश्न उठता है कि सबसे पहले कौन पिटेगा और कौन देश छोड़कर भागेगा? इसकी यदि प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाई जाए तो कांग्रेस नेतृत्व सबसे ऊपर होगा। अतः अच्छा ही होगा यदि विपक्ष यह स्वप्न ना देखे कि भारत में भी नेपाल जैसा 'कुछ' होवे।

- **डॉ नरेन्द्र टोंक**, मेरठ

हिन्दी की उपेक्षा क्यों?

हिन्दी दिवस पर पूरे भारत में हिन्दी प्रयोग के प्रचार प्रसार पर असंख्य कार्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी का गुणगान होगा । शासकीय व निजी संस्थाओं के मंचों से हिन्दी की प्रगति के गीत गाए जाएंगे व राजकोष से इन कार्यक्रमों के निमित्त अकूत धन भी उड़ाया जाएगा । यद्यपि वर्तमान केन्द्र सरकार द्वारा उच्चतम स्तर पर हिन्दी प्रयोग का प्रयास प्रशंसनीय है तथापि शिक्षा, व्यवसाय और सरकारी/निजी तन्त्र में हिन्दी की अवनति सतत दृश्यमान है । सुप्रीम कोर्ट हिन्दी अपनाने को तैयार नहीं, अधिकारी वर्ग अंग्रेजी में ही अभ्यस्त है, हिन्दी पत्रकारिता की भाषा में हिन्दी का जैसा बाजारी स्वरूप है वह चिंतनीय है । नई शिक्षा नीति के भाषा सम्बन्धी प्रकरण में प्राथमिक शिक्षा में हिन्दी/मातृभाषा की अनिवार्यता का जो दिशानिर्देश प्रस्तावित था, उसे भाजपा शासित राज्यों ने ही अस्वीकार कर दिया लगता है क्योंकि हरियाणा उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों में हिन्दी माध्यम के सरकारी स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम बना कर उन्नत शिक्षा की उपलब्धि का दंभ किया जा रहा है । राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों को भी अंग्रेजी माध्यम करना मन को विचलित करता है । पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक ही नहीं महाराष्ट्र में भी हिन्दी के हिंसक विरोध के स्वर हिन्दी संस्कृत के भविष्य पर प्रश्न चिह्न अंकित करते हैं ।

- **जय प्रकाश गुप्ता**, अंबाला कैंट

जन उपेक्षा का परिणाम

नेपाल में हालिया घटनाक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को अनसुना करना और उनकी शिकायतों का गलत ढंग से निपटारा करना बड़े जन आंदोलनों का रूप ले सकता है। आज का दौर सूचना प्रौद्योगिकी और सोशल मीडिया का है। एक छोटी-सी घटना भी पलक झपकते पूरे देश में फैल जाती है और लोग उसके समर्थन या विरोध में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि सरकारें समय की मांग के अनुरूप अपनी नीतियों को लचीला बनाएं और जनता से नियमित संवाद बनाए रखें, विशेषकर युवाओं से। नेपाल का उदाहरण हमारे लिए चेतावनी की घंटी है। जब युवा वर्ग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अवसरों की कमी से जूझते हुए देखता है कि सत्ताधारी वर्ग उनकी तकलीफों की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो वह सड़कों पर उतर आता है। श्रीलंका और बांग्लादेश के हालात भी गवाही देते हैं कि उपेक्षित जनता एक समय बाद अपने नेताओं को सत्ता से बेदखल करने से नहीं हिचकती। भारत जैसे लोकतांत्रिक और स्थिर देश में भले ही तत्काल ऐसी स्थिति की आशंका न हो, लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि यहां भी जनता की शिकायतें अनसुनी करने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। हमारे विधायक और सांसद संसद या विधानसभा के कामकाज में अक्सर बाधा डालते हैं। सदन की कार्यवाही कई-कई दिन तक ठप रहती है।

- **विभुक्ति बुपक्या**, उज्जैन

ट्रंप की निजी खुन्नस का नतीजा

कहा जा रहा है कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध कम्पनी जैफरीज ने यह दावा किया है कि भारत पर थोपा गया बेतहाशा टैरिफ राष्ट्रपति ट्रम्प की निजी खुन्नस का नतीजा है जो कि आगे चल कर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के लिए घातक है। कम्पनी के अनुसार ट्रम्प का ये कदम उनके सहयोग के विपरित है एवं अमेरिका के राष्ट्रीय हितों में भी सही नही है। इसी तरह से अमेरिकी अर्थशास्त्री रिचर्ड वोल्फ का कहना है कि अमेरिका आज भारत के खिलाफ एक बड़े दबंग की तरह व्यवहार कर रहा लेकिन ऐसा करके वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। कह सकते हैं कि भारत को धमकाने से वह ब्रिक्स को पश्चिमी देशों के लिए एक आर्थिक विकल्प बनने की दिशा में धकेल रहा है। रिचर्ड वोल्फ का कहना है कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा देश है एवं आज भारत को यह बताना कि उसे क्या करना चाहिए यह तो एक तरह से एक चूहे का अपने एक साथी को मुक्का मारने जैसा है एवं उनका यह भी कहना है कि अगर अमेरिका भारत के लिए अपने दरवाजे बन्द कर देता है तो भारत को अपने निर्यात बेचने के लिए अन्य जगह मिल जायेगी और इस कदम से केवल ब्रिक्स देशों को मजबूती मिलेगी, अतः कहा जा सकता है कि भारत पर 50% टैरिफ लागू करना अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यक्तिगत खुन्नस का ही नतीजा है।

- **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid